कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका

(महोबा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की
वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु
प्रस्तुत
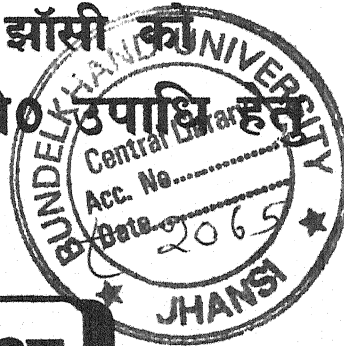
शोध-प्रबन्ध

वर्ष-2005-06

शोध निदेशक
डॉ० बी०एल० शर्मा
विभागाध्यक्ष-वाणिज्य
वीरभूमि राजकीय स्नात०महा०
महोबा

शोधार्थिनी
कु० अनीता देवी चौरसिया
एम०काम० वाणिज्य संकाय
गाँधी नगर-महोबा

शोध केन्द्र
वाणिज्य विभाग
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महोबा (उ०प्र०)

डॉ. बी.एल. शर्मा
एम०काम०, एम०फिल० पी-एच०डी०
यू०जी०सी०-नेट

वाणिज्य विभाग
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, महोबा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कु० अनीता चौरसिया ने मेरे निर्देशन में "कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका" (महोबा जिले के विशेष सन्दर्भ में) शीर्षक पर पी-एच०डी० की उपाधि हेतु शोध कार्य किया है।

कु० अनीता चौरसिया ने विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार अभीष्ट समयावधि तक उपस्थित रहकर शोध ग्रन्थ स्वयं सम्पन्न किया है और यह इनकी मौलिक कृति है। मौलिक ग्रन्थ की भाषा एवं कार्य शोध स्तरीय है। अतः मैं इसे विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत करने की सहर्ष संस्तुति करता हूँ।

मैं कु० अनीता चौरसिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

30/3/2006

(डॉ० बी०एल० शर्मा)
विभागाध्यक्ष-वाणिज्य
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, महोबा

आभार

प्रस्तुत शोध कार्य "कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की भूमिका" मूल रूप से पिछड़े एवं ग्रामीण अंचल की ज्वलनत समस्याओं को रेखांकित करने की दिशा में किया गया अकिंचन प्रयास है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के पर्यवेक्षक डॉ० बी एल शर्मा विभागाध्यक्ष वाणिज्य वीर भूमि राजकीय महाविद्यालय महोबा का आभार शब्दों मे व्यक्त करना मेरे लिए असम्भव सा है। उनके अनवरत प्रोत्साहन, सुस्पष्ट मार्गदर्शन शोध सम्बंधी जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण एवं सम्यक् निराकरण आदि के अभाव में, मैं इस कार्य की पूर्णता को प्राप्त न कर पाती। मै श्रृद्धेय डॉ० शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में, मैं श्री राजेन्द्र शर्मा शाखाप्रबन्धक छत्रसाल ग्रामीण बैंक व फतेहपुर बजरिया की मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने शोध कार्य मे अत्यन्त महत्वपूर्ण शोध सामग्री के संकलन में अमूल्य सहयोग प्रदान किया। समय समय पर उनसे हुए गवेषणात्मक विमर्श के आंकड़ों को खोजने मे बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

प्रो० एस० पी० गुप्ता प्राचार्य वीर भूमि राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय महोबा जिन्होंने शोध कार्य हेतु आवश्यक सामग्री शोध केन्द्र मे उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान की का आभार प्रकट न करना अकृतज्ञता होगी।

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय झांसी के रीडर डॉ० डी० सी० अग्रवाल, डॉ एम एस निगम, डॉ० आर० पी० सक्सेना जिनका कि विषय ज्ञान मेरे लिए अत्यन्त लाभप्रद रहा को धन्यवाद ज्ञापित करना अपना नैतिक कर्तव्य समझती हूं।
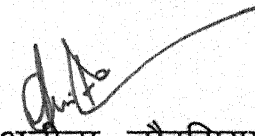
मैं डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय प्रवक्ता वाणिज्य महोबा व राजीव गांधी डी०ए०वी० महाविद्यालय बांदा के प्राचार्य डॉ० रामभरत सिंह तोमर की भी आभारी हूं। जिनका मुझे समय समय पर सहयोग मिलता रहा।

शोध प्रबन्ध के प्रेरणाश्रोत मेरे पापा श्री पूरन लाल चौरसिया जी का मै विशेषतया उल्लेख करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने अथक परिश्रम द्वारा उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराने तथा इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया उनकी अविरल प्रेरणा एवं सतत् आर्शीवाद के द्वारा ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरे मस्तिष्क में शोध अभिरूचियों का स्वाभाविक परिणाम है। मेरे लिए मेरी मम्मी श्रीमती रोहिणी देवी जी का उल्लेख न करना अतिश्योक्ति होगी जिनके प्रोत्साहन व आर्शीवाद के द्वारा ही मैं इस कार्यसम्पन्न कर पायी हूँ।

मैं अपनी दीदी सुनीता, छोटी बहन अर्चना व छोटे भाइयों अशोक व प्रवीण का उल्लेख करना भी आवश्यक समझती हू जिन्होंने अपने पूर्ण परिश्रम द्वारा टंकण आदि की व्यवस्था में सहयोग कर मुझे इस कार्य के सम्पादन में पूर्ण सहयोग दिया।

इसके अतिरिक्त इस कार्य को संपन्न करने मे शोधार्थिनी को जिन विविध स्त्रोतो से सहयोग प्राप्त हुआ ऐसे सभी प्रशासकीय विभागों से सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। विशेष रूप से सांख्यकीय अधिकारियों जनपद महोबा एवं सभी विकास खण्ड अधिकारी तथा चयनित ग्रामो के पंचायत प्रधानो का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होने विषय वस्तु सम्बंधी आंकड़े एवं सूचनाये एकत्र करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

अन्त मे शोध प्रबन्ध के आकर्षक एवं सुस्पष्ट टंकण हेतु मैं अज़ीमुन निसॉ जी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होने समय पर तथा सुस्पष्ट टंकण कार्य करते हुए शोध ग्रन्थ को सुसज्जित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

(कु0 अनीता चौरसिया)
एम0काम0 वाणिज्य संकाय
गांधी नगर, महोबा

विषय – सूची

पृष्ठ संख्या

तालिका सूची

ग्राफ सूची

मानचित्र जनपद — महोबा
महोबा
चरखारी
कुलपहाड़
पनवाड़ी
जैतपुर
कबरई
संकेत
1. जनपद सीमा
2. तहसील सीमा
3. वि० ख० सीमा
4. जनपद मुख्यालय
5. तहसील मुख्यालय
6. वि० ख० मुख्यालय
7. नदियाँ
8. रेलवे लाईन
9. सड़कें

अध्याय प्रथम

1. शोध समस्या का परिचय
2. अध्ययन का महत्व
3. शोध समस्या का स्वरूप वर्तमान प्रासंगिकता एंव समस्या के स्रोत
4. अध्ययन के उद्देश्य
5. अध्ययन विधि
6. परिकल्पना

अध्याय – प्रथम
शोध समस्या का परिचय

प्राक्कलन :–

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् दूरस्थ ग्रामीण अंचलो मे ग्रामीण बैंको को स्थापित करना जो ग्रामीण समस्याओं के पहचान एवं स्थानीय सोच मे तारतम्य स्थापित कर सके और जिसमे सरकार संस्थाओं जैसे गुण व व्यापारिक बैकों के समान व्यवसाय संगठन का गुण हो, जमाओं को गतिशील बनाने की योग्यता हो, केन्द्रीय मुद्रा बाजार में पहुँच हो। लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की वित्तीय आवश्यकताओं तथा कृषकों को परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वर्ष 1972 मे आर.जी.सरैया की अध्यक्षता मे एक बैकिंग आयोग का गठन किया गया साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना का सुझाव दिया । इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करके एम.नरसिम्हम् की अध्यक्षता मे गठित समिति ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने को उचित बताया। इस प्रतिवेदन के आधार पर भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। इस अध्यादेश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों मे 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्थापना की गयी। आज ग्रामीण बैंक प्रत्येक गांव के आर्थिक जीवन का सबल आधार बन गया है। महोबा जनपद में छत्रसाल ग्रामीण बैंक दिनांक 30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ और बैंक को इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने का गौरव प्राप्त है। बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप मे सम्मिलित है चूंकि छत्रसाल ग्रामीण बैंक हमारे महोबा की छत्रसाल वंशावली से जुड़ा हुआ है जिसका शासनकाल 1650 से 1732 ई0 तक चला।

अध्ययन का महत्व :–

एक अर्द्धविकसित देश में औद्योगिक एवं कृषि विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं का महत्व विकसित देशों की अपेक्षा और भी अधिक है क्योंकि अंग्रेजी शासक एवं शासकों की नीतियों के कारण स्वतंत्रता के पूर्व भारत में वित्तीय संस्थाओं का समुचित विकास नहीं हो सका। स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि की आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 1951 मे प्रो0 गाडगिल

की अध्यक्षता में भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट 1954 से प्रकाशित हुयी[1]। समिति की सिफारिशों के अनुसार कृषि को उदारतापूर्वक ऋण सहायता देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दो कोषों राष्ट्रीय साख दीर्घकालीन कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थरीकरण कोष) की स्थापना की गयी। इन कोषों से राज्य सरकार की गारण्टी पर केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों तथा ग्रामीण बैंको को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण तथा कृषि साख दीर्घकालीन कोष से राज्य सरकारों को सहकारी बैंक के अंश खरीदने कृषि विकास के उद्देश्यो से ग्रामीण बैकों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करने तथा केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्र खरीदने एवं राष्ट्रीय कृषि साख स्थरीकरण कोष की सहायता से ग्रामीण बैको को सूखे बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने की सुविधा दी जाती रही है। ग्रामीण साख के क्षेत्र मे भारतीय रिजर्व बैंक का यह महत्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार भारत मे ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु सहकारी संस्थाओ का व ग्रामीण बैको का विकास किया गया है। यद्यपि वित्तीय संस्थाओ के रूप मे सर्वप्रथम व्यापारिक बैंको की स्थापना की गयी, किन्तु कृषि विकास की दृष्टि से इनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा। व्यापारिक बैकों की साख एवं ऋण नीति कृषि के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से उपयुक्त न थी। इसका कारण भारतीय कृषि का असंगठित एवं जीवन निर्वाह स्वरूप था। व्यापारिक बैंकों ने राष्ट्रीयकरण से पूर्व कृषि क्षेत्र को साख की दृष्टि से उपेक्षित रखा और बैंक की शाखाओं का विस्तार अधिकांशतः उन्हीं स्थानों मे हुआ जो विकसित थे इनके द्वारा साख सुविधायें केवल बड़े उद्योगो तथा पूँजीपतियों को प्रदान की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषकों के विकास की इनके द्वारा उपेक्षा हुयी जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे विकास के लिए कृषि विकास तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति मे सुधार आवश्यक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् व्यापारिक बैंकों की ऋण नीति में व्यापक परिवर्तन हुए है। जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग एवं छोटे व्यवसायों के साख के संदर्भ मे प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापारिक बैंको के लिए कुछ निश्चित लक्ष्य एवं उपलक्ष्य निश्चित करके उनकी सहभागिता निर्धारित की गयी। जून 1970 से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में प्राथमिक साख समितियों को वित्तीय सहायता देने की योजना आरम्भ की गयी। चूंकि बैंकों के

राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग के पक्ष मे साख का प्रवाह बढ़ाना भी था जिससे निर्धनता उन्मूलन की नीति द्वारा सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके निःसंदेह सरकार की ग्रामीण साख विस्तार नीति के परिणामस्वरूप ग्रामीण साख की उपलब्धता मे व्यापक विस्तार हुआ है। लेकिन बैकिंग सुविधाओं का लाभ फिर भी ग्रामीण धनी काश्तकारों तक ही सीमित रहा है, क्योंकि ग्रामीण निर्धन वर्ग पर्याप्त परिसम्पत्ति के अभाव और ब्याज की ऊंची दरों के कारण बैकिंग साख सुविधाओं का लाभ नही उठा सका है।

"ग्रामीण निर्धन वर्ग की साख सम्बंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के कार्यकारी दल (1975) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्थापना की सिफारिश की ताकि ये बैंक व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैको के प्रयासो के पूरक के रूप मे वित्त पोषण का कार्य करे। इस दल की सिफारिशो के आधार पर 1975 मे 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।" धीरे धीरे इन बैंको का विकास एवं विस्तार हो रहा है।

कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वह महाजनों तथा साहूकारों के चंगुल मे फंसा था। जिसका कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था यह स्थिति देश के विकास में बाधक थी। कृषि व्यवसाय जो देश का मुख्य व्यवसाय है की स्थिति सुधारने हेतु कृषि वित्त की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत मे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना कृषकों की स्थिति सुधारना सामाजिक विषमता दूर करना तथा रोजगार के अवसरों मे वृद्धि करना था। इसलिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना एवं उनके विकास को महत्व दिया गया।

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ मे शोध कार्य के वर्तमान सन्दर्भ में अत्यन्त प्रासंगिकता है सारांशतः वर्तमान शोध कार्य के प्रासंगिकता को अग्रांकित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

1. जनपद मे इस प्रकार की शोध समस्या का चयन प्रथम बार किया गया है अब यह बहुत ही समसामयिक नव प्रवर्तनकारी है।

2. यह सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय समस्यायें जैसे बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अतः इस जनपद का अध्ययन अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।

3. महोबा जनपद के लिए कोई भी सामाजिक आर्थिक अनुसंधान निश्चित रूप से वास्तविक तथ्यों से छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकार, योजनाकारों, नीति नियन्ताओं, आम जनता को अवगत कराने का प्रयास है ताकि महोबा जनपद मे कई नियोजित विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन अत्यधिक ग्रामीण भारतीय संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद ग्रामीण जनता की गरीबी के क्या कारण है। इन्हें स्पष्ट किया जा सके तथा छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने महोबा जनपद मे कृषि सुविधाओं के विस्तार गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के जीवन स्तर के उन्नयन हेतु क्या-क्या वित्तीय सुविधायें उपलब्ध कराई है तथा यह बैंक इस कार्य मे कहां तक सफल हुआ है इसका अध्ययन प्रस्तुत शोध विषय की प्रासंगिकता स्वयं बयान करता है।

4. वर्तमान शोध समस्या की इस रूप मे भी प्रासंगिकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस शोध अध्ययन से लाभ प्राप्त कर यह निश्चय कर सके कि कुशल एवं प्रभावी ग्रामीण बैकिंग व्यवसाय के लिए किस प्रकार सार्थक नीतियां बनाई जायें।

शोध समस्या का स्वरूप, वर्तमान प्रासंगिकता एवं समस्या के स्त्रोत :—

कृषि एवं ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण समस्या है और इसके वर्तमान 21वीं शताब्दी मे आर्थिक चिन्तन को केन्द्र बिन्दु माना गया है। किसी भी तरह की कोई भी आर्थिक क्रिया हो उसका वित्त से घनिष्ठ सम्बंध होता है। कृषकों को उर्वरक,बीज, कृषि यन्त्र एवं कीटनाशक दवाइयां खरीदने लगान और मजदूरी का भुगतान करने मे भूमि मे संरचनात्मक सुधार करने, कृषि तकनीकी मे नवीनीकरण करने, विभिन्न उपभोग योग्य वस्तुओं की प्राप्ति एवं पुराने ऋणो के पुर्नभुगतान हेतु वित्त की आवश्यकता होती है अधिकांशतः कृषक अपने निजी आय स्त्रोंतो द्वारा कृषिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाते है जिसके परिणामस्वरूप कृषि साख की समस्या का उदय होता है। कृषि वित्त का स्वरूप औद्योगिक तथा व्यापारिक वित्त के स्वरूप से काफी भिन्न होता है। क्योंकि यदि ऋण का उद्देश्य उत्पादन मे वृद्धि कर व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि करना हो तो इस प्रकार का विनियोग माना जायेगा और इसका अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा किन्तु ऋण का अनुत्पादन तथा अनावश्यक कार्यो के लिए दुरूपयोग करना भविष्य मे विपत्ति का कारण बन जाता है दुर्भाग्यवश भारतीय किसान विवाह, मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि जैसे अनुपादक कार्यो के लिए तथा अपने उपभोग पर व्यय करने के लिए ऊंची ब्याज दर पर बड़ी मात्रा के ऋण प्राप्त कर

लेता है इस प्रकार कृषि साख की वास्तविक समस्या ऋण की विधि इसके सम्बंध मे अनियमितताओं तथा उसकी दुरूपयोग पूर्ण या अनुपात्दक व्यय विधि से सम्बंधित है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मूलतः परम्परावादी रहा अतः उस समय कृषि साख की आवश्यकता बहुत कम थी जिसकी पूर्ति मुख्यतः निजी साधनो से हो जाती थी। नियोजन काल मे कृषि साख की मांग से तीव्र गति से परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है जिसका प्रमुख कारण कृषि की नवीन तकनीकि का प्रादुर्भाव है सामान्य रूप से कृषकों को तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है।

1. अल्पकालीन व मौसमी साख :-

खेती के चालू खर्चो यथा बीज, उर्वरक, मजदूरी तथा किसान के घरेलू व्यय आदि को चलाने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है।

कृषि में अस्थायी सुधार करने, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने कृषि हेतु उपयोगी पशु खरीदने आदि के लिए मध्यमकालीन ऋण की आवश्यकता होती है।

2. दीर्घकालीन साख :-

भूमि खरीदने, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, कृषि सम्बंधी यंत्र खरीदने तथा पुराने ऋणों को चुकाने आदि के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है।

कृषि साख के स्त्रोत :-

भारत में कृषि साख के आकार से सम्बंधित समय समय पर अलग अलग अध्ययन किये गये है एडवर्ड मैक्लागन, एम0 एल0 डार्लिंग , पी0 जे0 टामस, केन्द्रीय बैकिंग जांच समिति तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के प्रयास मुख्य रूप से उल्लेखनीय रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और सम्बद्ध क्रियाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों से साख आपूर्ति होती है। सामान्यतः कृषि की आपूर्ति करने वाले अभिकरणों को दो भागों मे बांटा जा सकता है।

1. गैर-संस्थागत स्त्रोत :-

गैर संस्थागत स्त्रोतों मे ग्रामीण साहूकार महाजन, सम्बंधी भू-स्वामी एवं दलाल इसके प्रमुख रांघटक तत्व रहे है। इनकी अत्यधिक ऊंची ब्याज दरो निर्दयतापूर्वक वसूली समय पर आवश्यकता की पूर्ति न करना वित्त का यह स्त्रोत कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए न काफी सिद्ध हुआ है।

2. संस्थागत साख के स्त्रोत :-

तेजी से बदलते हुए आर्थिक एवं परिवर्तनशील कृषि ढांचे के अनुरूप साख की आपूर्ति करने तथा निजी क्षेत्रो की दोषपूर्ण और शोषणकारी नीति के फलस्वरूप 1901 के अकाल आयु ने कृषि साख के निजी स्त्रोत में निहित दोषों को दूर करने के लिए वैकल्पिक ऋण साधनो की स्थापना पर जोर दिया था । कृषि साख के संस्थागत ढांचे मे सरकार सहकारी समितियों और व्यापारिक बैकों को मुख्यतया सम्मिलित किया जाता है योजनाकाल मे ग्रामीण और कृषि साख की संरचना मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तथापि ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त साख की आवश्यकता लगातार बनी रही है यह अनुभव कियागया है कि ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो लघु एवं सीमान्त कृषकों भूमिहीन, श्रमिको, ग्रामीण शिल्पकारों और खेतिहर मजदूरों के पास समान्तर प्रतिभूति के लिए ठोस आधार न होने के कारण संस्थागत स्त्रोत से अपेक्षित ऋण सहायता नही मिल पाती है इसी को ध्यान मे रखते हुए 30 जुलाई सन् 1975 को श्री नरसिम्हम् समिति की रिपोर्ट तथा संस्तुतियों के आधार पर 20 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये।

संस्थागत साख संरचना के क्षेत्र मे ग्रामीण बैंक अपेक्षाकृत अधिक नवीन संगठन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रस्तावना में यह कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से कृषि उद्योग व्यापार और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य उत्पादक क्रियाओं की प्राप्ति के लिए विशेषकर लधु एवं सीमान्त कृषको पेशेवर ग्रामीण शिल्पकारों, खेतिहर मजदूरों लघु उद्यमियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को साख सुविधायें प्रदान की जायेगी। यह माना गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तत्कालीन साख के विकल्प के रूप मे नही बल्कि अनुपूरक आधार पर कार्य करेगें तथा उनमे ग्रामीण संस्थाओं और व्यापारिक बैकों के गुण निहित होंगे।

चयनित शोध समस्या का स्वरूप :—

महोबा जनपद फरवरी 1995 से जिले के रूप में स्थापित हुआ इससे पूर्व यह हमीरपुर जनपद का अंग था यह 25^0–26^0 अक्षांश से और 79^0 से 80.5^0 पूर्वी अक्षांश पर स्थित है इसके उत्तर मे हमीरपुर जनपद दक्षिण मे म०प्र० पूर्व मे बांदा जनपद तथा पश्चिम मे झांसी जनपद की सीमायें मिलती है।

महोबा जनपद के एक बड़े भू-भाग मे कठोर पत्थर की चट्टानें पायी जाती है तथा जनपद मे चरखारी पनवाड़ी और जैतपुर, कबरई में कुल 4 ब्लाक है।यहां की मिट्टियों में मुख्यतः मार

(Mar) काबर (Kabar) रान्कर (Rankar) परवा (Paruwa) मुख्य रूप से पायी जाती हैं। इस जनपद मे कृषि जोत मे संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत 60.38 प्रतिशत है।, 26.35 प्रतिशत भूमि कृषि कार्यो मे संलग्न है, 1.78 प्रतिशत कृषि से सम्बंधित सहायक क्रियाओं मे संलग्न है।सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कृषि जोतो का आकार छोटा है तथा वाणिज्यिक एवं नकदी फसलो के बोये जाने का क्षेत्र मात्र 5.62 प्रतिशत है सिंचाई सुविधाओ का पर्याप्त अभाव है, भूमि की उर्वरा शक्ति कम है तथा औद्योगिक विकास की दर लगभग शून्य है उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बाद स्वदेशी उद्योग धंधे लगातार बन्द हो रहे है जिससे उसमे लगे श्रमिक बेकारी की समस्या से जूझ रहे है। जनपद मे आधारभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है तथा विद्युत उत्पादन की दर नगण्य है।

इस प्रकार महोबा जनपद की अर्थव्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुयी कही जा सकती है जिससे गरीबी का दुश्चक्र क्रियाशील है अध्ययनगत् विषय के चयन का महत्वपूर्ण निहितार्थ यही है कि जनपद के कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप मे छत्रसाल ग्रामीण का क्या योगदान है अर्थात् यह बैंक जनपद की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दूर करने मे कहां तक सफल हुआ है तथा उसके समक्ष क्या–क्या चुनौतियां है ? तथा जिन्हे कैसे दूर किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तावित शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. जनपद महोबा मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद के विकास मे योगदान का वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करना।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक के प्रबन्ध, प्रशासन एवं संगठन पर प्रकाश डालना।
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में छत्रसाल ग्रामीण बैंक के विकास का विवरण प्रस्तुत करना।
4. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की पूंजी निक्षेप एवं सुरक्षित कोषों का विवरण प्रस्तुत करना।
5. छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्न उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यो हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का विश्लेषण करना।
6. छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋणो की वसूली तथा बकाया ऋणों की समस्या पर

प्रकाश डालना।

7. छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा कोषों के निवेश का विवरण प्रस्तुत करना।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लाभ एवं हानि का अध्ययन करना।

9. छत्रसाल ग्रामीण बैंक के समक्ष आ रही कठिनाइयों एवं समस्याओं को प्रकाश मे लाना तथा उन्हे हल करने की दृष्टि से व्यवहारिक सुझाव देना।

10. प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोबा जनपद के लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, कलाकारों, पेशेवर शिल्पकारों, लघु उद्यमियों एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों से ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने मे कहां तक सफल रहे है।

11. इस अध्ययन का उद्देश्य इन बैंको के संगठनात्मक वित्तीय ढांचे एवं क्रिया विधि का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकालना भी है कि यह बैंक अपनी स्थापना के उद्देश्यों में कहां तक सफल हुए है।

12. इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की क्रियाविधि में सुधार की क्या संभावनायें हैं ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे आदमियों की बैंक की अपनी वर्तमान रूपरेखा को बनाये रखे तथा क्षेत्रीय और कार्यात्मक साख अन्तराल को पूरा करने, कमजोर वर्गो की आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने और स्थानीय जमाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य में सफल हो सके।

13. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा जनपद का अध्ययन हेतु चयन व्यष्टि स्तर पर तथ्यों के विश्लेषण के लिए किया गया है। ताकि यह अध्ययन हेतु चयन व्यष्टि स्तर पर आर्थिक लाभदायक हो सके तथा व्यष्टि स्तर पर प्रभावी योजनायें बनाकर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयास किया जाये तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें।

अध्ययन विधि :—

1. समंको का संग्रहण –

प्रस्तुत शोधकार्य पूर्णतः द्वितीयक समंको पर आधारित है समंक जिला महोबा के क्षेत्रीय छत्रसाल ग्रामीण बैंको के विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेखों, प्रतिवेदनों तथा प्रकाशनों से संग्रहित किये गये हैं। इसके साथ ही जिला सांख्यकीय पत्रिका जनपद महोबा के विभिन्न संस्करणो से सामग्री संग्रहीत की गयी है। इसके साथ ही प्राथमिक समंकों का संकलन प्रश्नावली

के माध्यम से यादृच्छिक प्रतिचयन के माध्यम से किया गया है ।

2. समंकों का विश्लेषण–

अध्ययनगत् विवेचन हेतु विभिन्न स्त्रोतों एवं उपकरणो द्वारा संकलित समंको के विश्लेषण मे निम्नांकित सांख्यकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

चिट्ठा विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, आय व्यय खाता विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण, कार्यशील पूंजी प्रबन्ध विश्लेषण, ग्राफ एवं रेखाचित्र प्रदर्शन प्रविधि आदि का उपयोग किया गया है।

पाश्चात्य देशों मे इन पद्धतियों का प्रयोग साख विश्लेषण के लिए प्रारम्भ हुआ था सन् 1914 तक साख प्रदान करने वाले केवल वित्तीय विवरणों की वस्तुस्थिति पर विश्वास करके साख प्रदान करते थे परन्तु धीरे-धीरे इन विवरणों मे प्रदत्त समंको का विश्लेषण महत्वपूर्ण माना जाने लगा और इनके लिए अनेक विधियों का विकास हुआ।

अनुपात विश्लेषण –

बैकिंग जगत मे इनके तथ्यों का व्यक्तिगत रूप मे कोई महत्व नही होता है। इनके आधार पर कोई भी उचित निष्कर्ष उस समय तक नही निकाला जा सकता है जब तक कि विभिन्न मदों के बीच कोई सम्बंध स्थापित न किया जाये दो या दो से अधिक मदों के बीच एक तर्कयुक्त व नियमबद्ध पद्धति के आधार पर सम्बंध स्थापना का परिणाम ही अनुपात कहलाता है।

अनुपात विश्लेषण से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है प्रमुख रूप से प्रबन्ध के आधारभूत कार्य योजना समन्वय, नियंत्रण संवहन एवं पूर्वानुमान के कार्य मे सहायता पहुॅचना ही अनुपात विश्लेषण का उद्देश्य होता है। इस तकनीकि के अन्तर्गत लेखांकन अनुपातों का निर्धारण अनुपातों की गणना निकाले गये अनुपातों की प्रमापित अनुपातों से तुलना, अनुपातों का निर्वहन अनुपातो के आधार पर प्रक्षेपित वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल होता है। इसके अतिरिक्त अनुपात वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के मध्य पारस्परिक संख्यात्मक सम्बंध को व्यक्त करता है।

तुलनात्मक विवरण –

तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के इस प्रकार बनाये गये विवरण होते है जो विभिन्न तत्वों पर विचार करने के लिए समय परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए किये

जाते हैं। विश्लेषण हेतु तुलनात्मक विवरणों को तैयार करते समय इस बात को ध्यान मे रखा जाता है कि किसी संस्था के जितने समय के वित्तीय इतिहास का अध्ययन किया जाता हो उस समय के दौरान समंको एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतिकरण की विधियों मे भिन्नता न हो।

तुलनात्मक विवरणों मे तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक विवरण, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण आदि महत्वपूर्ण व इन तुलनात्मक विवरणों मे वित्तीय आंकड़ों एवं सूचनाओं को निम्न प्रकार से दिखलाया जाता है।

1. निरपेक्ष अंको मुद्रा मूल्य के रूप में
2. निरपेक्ष अंको मे वृद्धि या कमी के रूप में
3. निरपेक्ष अंको में हुयी वृद्धि या कमी के प्रतिशत के रूप में
4. समान आकार वाले विवरणों के रूप में

वित्तीय विवरणों को तुलनात्मक रूप मे प्रस्तुत करके दो वित्तीय विधियों मे हुए परिवर्तनों की जानकारी तथा वित्तीय स्थिति एवं संचालन के परिणामों की दिशा ज्ञात की जा सकती है।

प्रवृत्ति विश्लेषण –

प्रवृत्ति विश्लेषण सामान्य रूप मे एक साधारण रूख को कहते है। बैंकिंग तथ्यों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रवृत्ति अनुपात या प्रतिशत एवं बिन्दुरेखी पत्र या चार्ट पर अंकित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत लाभ हानि खाते या चिट्ठे के किसी भी मद के सम्बंध मे उसकी प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है अथवा तीन चार वर्षो के अन्तर्गत उस मद मे क्या परिवर्तन हुए है अर्थात् उसमें प्रतिवर्ष कमी हुयी है अथवा वृद्धि हुयी इसे हम प्रवृत्ति विश्लेषण के द्वारा ज्ञात कर सकते है इसके आधार पर पिछले पांच वर्षो के लाभ की राशि को एक जगह रखकर हम देख सकते है कि प्रतिवर्ष उसमे कितनी वृद्धि या कितनी कमी हो रही है और उसके आधार पर अगले वर्ष के लिए लाभ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

आय व्यय खाता विश्लेषण –

गैर-बैकिंग संस्थाओं एवं अन्य पेशेवर व्यक्तियों द्वारा वित्तीय वर्ष की शुद्ध आय एवं हानि ज्ञात करने के लिए आय व्यय खाता तैयार किया जाता है प्रस्तुत शोध कार्य बैकिंग सस्थान से सम्बंधित है अतः आय व्यय खाता विश्लेषण खाता पद्धति के स्थान पर लाभ हानि खाता विश्लेषण

पद्धति को निष्कर्ष आगणन हेतु प्रयुक्त किया गया है।

कार्यशील पूंजी विश्लेषण –

जिस प्रकार वित्तीय प्रबन्ध मे पूँजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो मे किया है उसी प्रकार व्यवसायिक जगत मे कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादास्पद है। कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्तियों का योग मानते हैं। जबकि कुछ व्यक्ति चालू दायित्वों पर चालू सम्पत्तियों के आधिकय को कार्यशील पूंजी मानते है।

परिकल्पना –

इस अध्ययन मे निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा ।

1. यह कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सहकारी समितियों द्वारा छोड़े गये साख अन्तराल को पूरा किया है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था के उन कमजोर वर्गो को वित्तीय सुविधाये उपलबध कराने मे सक्षम सिद्ध हुए है जिन्हें सहकारी समितियां साख सुविधायें उपलब्ध कराने मे असफल रही।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का वित्तीय ढांचा संतोषप्रद है तथा वह ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्गो की साख सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने मे सक्षम है।

4. यह कि जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा उपलबध करायी गयी वित्तीय सहायता से इस बैंक द्वारा लाभान्वितों का जीवन स्तर आर्थिक रूप से निश्चय ही उन्नत हुआ है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनपद महोबा का व्यवसाय इसकी स्थापना वर्ष से निरन्तर प्रगति पर है। इस बैंक ने जनपद की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास तथा निर्धन वर्ग के लोगो की आर्थिक स्थिति सुधारने मे पर्याप्त योगदान किया है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थव्यवस्था मे गरीबी उन्मूलन मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

अध्याय द्वितीय

(भाग-अ)

कार्यक्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा जिले की अर्थव्यवस्था
2. जनपद का जननांकीय विश्लेषण (जन्म, मृत्यु, वैवाहिक स्थिति एवं स्वास्थ्य सम्बंधी दशाओं मे परिवर्तन का अध्ययन)
3. जनसंख्या का आर्थिक आधार का वर्गीकरण
4. जनपद की कृषि एवं मानसून आधारित अर्थव्यवस्था
5. जनपद में रोजगार का स्वरूप

अध्याय—द्वितीय (भाग—अ)
कार्यक्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं

आज के इस प्रगतिशील युग की मुख्य समस्या आर्थिक विकास की समस्या है वर्तमान आर्थिक जगत में आर्थिक विकास का विचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा अधिकांश अर्थशास्त्रियों द्वारा किये जाने वाले चिन्तन का यह एक केन्द्र बिन्दु बना हुआ है आर्थिक विकास जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट होता है का अर्थ है – अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना। विस्तृत अर्थ मे आर्थिक विकास से अभिप्राय राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करके निर्धनता को दूर करना तथा सामान्य जीवन स्तर मे सुधार करना है। आर्थिक विकास की एक सर्वमान्य परिभाषा देना अत्यन्त कठिन है क्योकि आर्थिक विकास मे अभिरूचि रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द की परिभाषा विकास के भिन्न भिन्न आधारो को दृष्टि मे रखकर देने का प्रयास किया है एक सम्प्रदाय के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ कुल राष्ट्रीय वास्तविक आय मे वृद्धि करना है तो दूसरी विचारधारा के लोगों ने प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय मे की जाने वाली वृद्धि को आर्थिक विकास की संज्ञा दी है। प्रथम सम्प्रदाय मे प्रो0 साइमन कुजनेट्स मायर एवं बाल्डीवन तथा ए0जे0यंगसन आदि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि इसके विपरीत प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानने वाले अर्थशास्त्रियों मे डॉ0 बैजमरिन हिगोन्स, हार्वे लिर्बस्टीन, डब्ल्यू आर्थर लुईस एच0एफ0 विलियमसन तथा जैकब वाइनर आदि नाम आते हैं। इस सम्बंध में अनेक लेखकों की परिभाषाएं निम्नलिखित है मायर एवं बाल्डविन के अनुसार – "आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है।"[1]

प्रो0 लुईस के शब्दों में – "आर्थिक विकास का अर्थ, प्रतिव्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि से लगाया जाता है।"

प्रो0 यंगसन के विचारानुसार – "आर्थिक प्रगति से आशय किसी समाज सें संबन्धित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि करना है।"[2]

1- Economic development is a process where by an economy's real national increases over a long period of time. - Meir & Baldwin

2- Ecomonic progress is an increase of the power to achieve economic aims of the cummunity concerbed. - Youngson

प्रो0 विलियमसन के अनुसार – "आर्थिक विकास अथवा वृद्धि से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनो का उपयोग, प्रतिव्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि के लिए करते हैं।"[3]

प्रो0 डी0 ब्राइट सिंह की दृष्टि में "आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय एक देश के समाज मे होने वाले उस परिवर्तन से लगाया जाता है जो अल्प विकसित स्तर से उच्च आर्थिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होता है।"[4]

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जहां मायर एवं बाल्डविन ने आर्थिक विकास मे वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की बात कही है वही विलियमसन तथा लुईस द्वारा प्रतिव्यक्ति उत्पादन अथवा आय मे वृद्धि का समर्थन किया गयाहै इन सभी परिभाषाओं मे तीन महत्वपूर्ण बाते समान रूप से परिलक्षित हाती है –

1. आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसका अर्थ कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों के कार्यशील रहने के रूप मे लगाया जाता है।
2. आर्थिक विकास का सम्बंध वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है।
3. आर्थिक विकास का सम्बंध अल्पकाल से न होकर दीर्घकाल से होता है।

आर्थिक विकास की प्रकृति का यदि हम अध्ययन करें तो आर्थिक विकास का स्वभाव अर्थशास्त्र के स्थैतिक एवं गत्यात्मक स्वरूपों पर आधारित है इससे स्टैटिक शब्द का सामान्य अर्थ है स्थिर रहना तथा डायनामिक शब्द का अर्थ है गतिमान होना इसी प्रकार भौतिक शास्त्र मे भी स्थैतिक शब्द से अभिप्राय विश्राम की अवस्था से होता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द का आशय गतिहीन अवस्था से नही होता बल्कि उस अवस्था से होता है जिसमे परिवर्तन तो हो परन्तु इन परिवर्तनों की गति अत्यन्त कम हो। गत्यात्मक अथवा प्रावैगिक के अन्तर्गत परिवर्तन प्रकृति का चिरंतन नियम है।

3- Economics develoment or growth refer to the process where by the people of the country or region come to utilize the resources available to bring about a sustained increse in per capita roduction of foods and sovices. - Williamson & Buttrick

4- Economic growth means the tranformation of society of a country from a state of under development to a high level of economic achievement. - Prof. D.Bright Singh

दिन के बाद रात दुख के बाद सुख धूप के बाद छांव तथा जन्म के बाद मृत्यु का होना अवश्यमभावी है। सत्यता तो यह है कि वास्तविक जीवन मे पूर्ण स्थैतिक अवस्था कही देखने को नही मिलती है परिवर्तनशीलता की इस प्रवृत्ति को ही गत्यात्मक अर्थशास्त्र कहते है अतः आर्थिक विकास की प्रकृति मूलतः गत्यात्मक है।

आर्थिक विकास की समस्या :–

आर्थिक विकास जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारणा (समस्या) है और इसे वर्तमान शताब्दी में आर्थिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु माना जाता है । मायर एवं बाल्डलिन का भी कहना है कि "राष्ट्रों की निर्धनता का अध्ययन राष्ट्रों के धन के अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है।"[1] यद्यपि आर्थिक विकास का प्रश्न सभी प्रकार के देशों के लिए समान रूप से महत्व रखता है किन्तु विकास शील देशों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि आर्थिक विकास के द्वारा वे अपनी सामान्य दरिद्रता और आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पा सकते हैं।

इसमें कोई सन्देह नही है कि आर्थिक विकास के अध्ययन ने वाणिकवादियों सहित एडम स्मिथ से लेकर सभी अर्थशास्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया था लेकिन उनकी रूचि मुख्यतः पश्चिमी देशों के आर्थिक विकास और उनकी समस्याओं तक केन्द्रित बनी रही। 20वीं शताब्दी के मध्यान्तर काल के बाद से अर्थशास्त्रियों ने विकासशील देशो के आर्थिक विकास मे अधिक रूचि लेना शुरू कर दिया।

आज का विश्व मुख्यतया दो भागों – अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच बंट चुका है। सभी देश सामान्य रूप से न तो समृद्धशाली है और न ही उनके आर्थिक विकास के तौर तरीकों मे कोई समानता पाई जाती है एक तरफ विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी जापान आदि आर्थिक समृद्धि के शिखर पर विराजमान है और उनके निवासियों को उन्नतजीवन के सभी अवसर उपलब्ध है। दूसरी तरफ पूर्वी एशिया के वे देश शामिल है जिनके निवासियों को मात्र जीवित रहने का अवसर प्राप्त है।

मोटे तौर पर विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग विकसित देशों मे वास करता है।

---

1. A Study of poverty of Nations has even more urgency than a study of the wealth of Nations.

और यह देश विश्व की कुल उपज का 4/5 भाग उपभोग करते है इनका उत्पादन इनकी जनसंख्या के अनुपात मे अधिक तेजी से बढ़ा है जिससे इनकी प्रतिव्यक्ति आय काफी ऊंची है। इसके विपरीत अल्पविकसित देशो मे जनसंख्या के भारी दबाव के कारण प्रतिव्यक्ति आय बहुत नीची है।

इसके साथ ही आर्थिक विकास में विषमता आने के अनेक ऐसे उत्तरदायी कारण है जिनके कारण आर्थिक विकास तेजी से नही हो पाता है इनके लिए मुख्य रूप से निर्धन देशो मे आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण और आर्थिक प्रयासों का अभाव होना है। इसके अलावा राजनीतिक दशायें और परम्परागत दृष्टिकोण ने भी निर्धनता व विषमताओं को बढ़ावा दिया है इसका एक प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी प्रभाव (Demonstration Effect) का लागू होना है यह प्रभाव गरीब देशों के लोगों मे उन्नत देशों के उपभोग स्तर का अनुकरण करने की लालसा पेदा करके उनकी उपभोग वृद्धि (Propensity to consume) को बढ़ावा है जिससे बचत व पूंजी निर्माण की दर घट जाती है ड्यूजनबरी द्वारा प्रतिपादित यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि "व्यक्तिगत उपभोग तरीके स्वतंत्र नही बल्कि परस्पर सम्बद्ध होते है।" इस दृष्टि से एक व्यक्ति की बचत प्रवृत्ति उसकी वास्तविक आय के निरपेक्ष स्तर पर निर्भर नही करती बल्कि उन लोगों के सापेक्ष आय स्तर पर निर्भर करती है जिनके वह सम्पर्क में आता है।

आर्थिक विकास की आवश्यकता तथा महत्व :-

आर्थिक पिछड़ेपन की विषमताओं के परिवेश मे आधुनिक विश्व की मुख्य समस्या आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेरित होना है। हां इसमे कोई सन्देह नही कि आर्थिक विकास का सम्बंध मुख्यतया अल्प विकसित देशो से ही लगाया जाता है क्योंकि धनी कहे जाने वाले राष्ट्र प्रगति के सभी पड़ाव पार कर चुकने के बाद विकास की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके है जबकि पिछड़े हुए देशो का आर्थिक विकास आज भी सीमित है। निर्धनता, बेकारी, पूंजी का अभाव, घटिया जीवन स्तर असन्तुलित विकास तथा आर्थिक पिछड़ापन इन देशों की प्रमुख समस्यायें है जबकि भूख उत्पीड़न, नैराशय दुख रोग और शोषण इन लोगों के मुख्य आभूषण हैं।

आज विश्व का प्रत्येक अल्पविकसित देश और उसका निवासी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहता है ताकि अपनी जीवन की संध्या आने से पूर्व तक वह अपनी और अपने बच्चों की जिन्दगी को खुशहाल बना सके। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह किसी सम्पत्ति का स्वामी

हो अगर विलासमयी नही हो तो आरामदायक जीवन अवश्य व्यतीत कर सके और इन सबका एक ही उपाय है – तीव्र आर्थिक विकास।

आर्थिक विकास किसी भी देश के लोगों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण का एक सशक्त माध्यम है। आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है जिससे मांग बढती है फलस्वरूप उत्पादन तथा निवेश बढ़ता है पूँजी निर्माण को गति मिलती है जिससे उत्पादकता व आय का स्तर बढ़ने से आर्थिक विकास का प्रवाह अविराम गति से बहने लगता है। देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारालेना आवश्यक है या दूसरे शब्दों मे आर्थिक नियोजन आर्थिक विकास का ही रूप है नियोजित विकास के अन्तर्गत जहां एक ओर राष्ट्रीय आय, उत्पादकता, रोजगार, आत्मनिर्भरता, पूंजी निर्माण व सामाजिक कल्याण मे वृद्धि होती है उसके दूसरी ओर निर्धनता, विषमताओं सामाजिक लागतों असन्तुलित विकास, बेकारी एकाधिकारी प्रवृत्तियां शोषण उत्पीड़न व्यापार चक्र व बाजार की अपूर्णताओं मे कमी आती है।

प्रो0 लुईस का मत है कि आर्थिक सम्पन्नता मनुष्य के आर्थिक व सामाजिक कल्याण के लिए अत्यन्त आवश्यक है अब समाज के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है तो शोषण उत्पीड़न और अनैतिक तत्व स्वतः ही लुप्त हो जाते है और उनके स्थान पर स्नेह सहयोग सद्भावना और आत्मीयता जन्म लती है विधाता ने किसी को चोर के रूप मे पेदा नही किया। भूख की पीड़ा, सामाजिक सम्मान का न मिलना और जीवन के अभाव ही मनुष्य को इस कार्य के लिए प्रेरित करते है। प्रो0 लुईस ने इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है यद्यपि बीमारों, अपाहिजों दुर्भाग्य के मारों, विधवाओं एवं अनाथों के भरण पोषण की इच्छा आदिम समाज की अपेक्षा सभ्य समाज में अधिक नही पाई जाती लेकिन आज के इस समाज मे इस काम के लिए अधिक साधन अवश्य जुटाये जा सकते है। अभाव अमानवता को जन्म देते है जबकि सम्पन्नता की उत्प्रेरक शक्ति है।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था :–

विश्व के देशों को दो भागों मे बांटा गया है। विकसित तथा अल्पविकसित अथवा धनी तथा निर्धन राष्ट्र। निर्धन देशों को कई नामों से पुकारा जाता है जैसे निर्धन Poor पिछड़े Backword अल्पविकसित Under development अविकसित Undeveloped और विकासशील Developing देश।

अल्प विकास व अल्पविकसित देश को परिभाषित करना काफी कठिन है प्रो0 सिंगर का भी मत है कि "एक अल्पविकसित देश जिराफ की भांति है जिसका वर्णन करना कठिन है लेकिन जब हम उसे देखते है तो समझ जाते है।"[1] वैसे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के अनेक मानदण्ड प्रस्तुत किये गये है जैसे निर्धनता, अज्ञानता, निम्न प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का कुवितरण, जनसंख्या भूमि अनुपात, प्रशासनिक अयोग्यता सामाजिक विप्रंगठन इत्यादि चूंकि हमारा भारत देश भी अल्पविकसित देशों की श्रेणी में आता है इसकी कुछ प्रचलित परिभाषायें निम्नलिखित हैं।

प्रो0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 सिंगर का मत है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास समय को बर्बाद करना है फिर भी किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ प्रचलित परिभाषाओं को प्रस्तुत किया जाये।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विज्ञप्ति के अनुसार – "अल्प विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिम यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना मे कम है।"[2]

प्रो0 मेकलियोड के अनुसार "एक अल्पविकसित देश वह देश अथवा क्षेत्र है जिसमें उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना मे उपज एवं पूंजी का अपेक्षाकृत कम अनुपात है परन्तु जहां विकास की संभावनायें विद्यमान है। और अतिरिक्त पूंजी को लाभजनक कार्यो में विनियोजित किया जा सकता है।"[3]

प्रो0 जे0 आर0 हिक्स के शब्दो में "एक अल्पविकसित देश वह देश है जिसमें औद्योगिकीय और मौद्रिक साधनों की मात्रा, उत्पादन एवं बचत की वास्तविक मात्रा की भांति कम होती है जिसके फलस्वरूप प्रति श्रमिक को औसत पुरस्कार उस राशि से बहुत कम मिलता है जो प्राविधिक विकास

1- An under developed country is like Giraffe difficult to describe vut you know on when you see one. - H.W.Singer.

2- An under development country is one in which percapita real income is iow when compared wti the per capita seal income of U.S.A Canadam Austrilia and western Euroe - U.N.O Report.

3- Under development country is a country or region with a relatively iow ratio of capital and enterpreneusship to other factors or production vut with resonably good prospects that additional capital could be profitably invested. - A.N. Mcleod.

की अवस्था मे उसे प्राप्त हो पाता है।"[4]

प्रो0 ऑस्कर लैंज की दृष्टि मे एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा देश की कुल श्रम शक्ति को आधुनिक तकनीकी के आधार पर उपयोग करने के लिए पर्याप्त नही है।"[5]

प्रो0 रागनर नर्कसे ने भी एक अल्पविकसितदेश को इसी आधार पर परिभाषित किया है।

जैकब वाइनर के अनुसार "अल्पविकसित देश वह दोष है जिसमें अधिक पूंजी अथवा अधिक श्रम शक्ति अथवा अधिक उपलब्ध साधनों अथवा इन सबको उपयोग करने की पर्याप्त संभावनायें हो जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और यदि प्रति व्यक्ति आय पहले से ही काफी अधिक है तो रहन-सहन के स्तर को कम किये बिना अधिक जनसंख्या का निर्वाह किया जा सके।"[6]

आर्थिक विकास आर्थिक जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है और इसे वर्तमान शताब्दी मे आर्थिक चिन्तन का केन्द्र बिन्दु माना जाता है।

आज के प्रगतिशील युग में प्रत्येक व्यक्ति समाज एवं क्षेत्र विशेंष एवं राष्ट्र की इस दौड़ में एक दूसरें से आगे निकलने के लिए निरन्तर प्रगति शील है। परन्तु प्रश्न यह है कि आर्थिक विकास की कसौटी अथवा मानदण्ड क्या है साधारणतया आर्थिक विकास के मापन हेतु विकास वादी अर्थशास्त्रियों ने निम्न मापदण्ड प्रस्तुत कियें है।

1. राष्ट्रीय आय कृषि मानदण्ड

इस माप के अन्तर्गत लोगों का यह मानना है कि राष्ट्रीय आय विकास का श्रेष्ठतम सूचक

4- An under development country is one in which the technological and monetary ceilings all as low as practically to coincide with the actual level of output and savings with the result that the average remuneration per unit of labour is lower than what it could be if known technology were applied to known resources. - J.R.Hicks.

5- An under development economy is an economy in which the available stock of capital foods is not sufficient to employ the total available labour force on the basis of moredern technigues of production - Oskar lange.

6- An under develoment country is country which has goods potentil prospects for using more capital or more labour or more available resources or all these to support its present popultion on a higher level of living or if its per capital income level is already fairly high to support a larger population on a not lower level of living. - Ja cov Viner.

है क्योकि राष्ट्रीय वास्तविक आय में वृद्धि ही सही आर्थिक विकास की परिचायक है।

2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मानदण्ड

इस मत को मानने वाले आधुनिक समय के अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष सम्बंध प्रति व्यक्ति आय से होता है न कि राष्ट्रीय आय से इसलिए जनता के आर्थिक कल्याण व जीवन स्तर में वृद्धि की दृष्टि से किसी देश का आर्थिक विकास तभी माना जायेगा जब उसकी प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होगी।

महोबा जनपद की कुछ मूलभूत विशेषताओं की मैने निमनलिखित वर्गो में व्यक्त किया है

1. निर्धनता –

जनपद की अधिकांश जनसंख्या निर्धनता के कुचक्र मे फंसी हुयी है। कारण कृषि का मानसून पर निर्भर रहना एवं रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता तथा कृषि का असमान वितरण है।

2. महोबा जनपद मे प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से अन्य विकसित जनपदों से कम है।

3. जनसंख्या का भारी दबाव कृषि एवं अन्य उपलबध संसाधनों पर स्पष्ट दिखायी देता है।

4. प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद उनका विदोहन हो पाना भी इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण है।

5. जनपद के औद्योगिक विकास की शून्यता भी आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है।

6. यहां की अधिकांश जनता अदृश्य बेरोजगारी की शिकार है।

7. इस क्षेत्र के श्रम की उत्पादकता का स्तर निम्न होना भी आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारण है।

8. इस क्षेत्र मे आधारभूत संरचना का अभाव है। यथा परिवहन बैकिंग बीमा शैक्षिक संस्थायें तकनीकी संस्थान एवं गोदामो का अभाव।

9. इस क्षेत्र मे अल्प आय एवं नगण्य बचत के कारण पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। जिससे क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु दीर्घकालीन योजनाओं के क्रियान्वयन मे पूंजी की कमी महसूस

होती है।

10. सामाजिक आर्थिक चेतना का अभाव – जनपद के लोगों मे आर्थिक चेतना का अभाव है तो दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उदासीनता है ये दोनो ही तत्व आर्थिक जड़ता व पिछड़ेपन को कैसे बढ़ावा देते है व इसके फलस्वरूप श्रम उत्पादकता का निम्न स्तर साधन अगतिशीलता विशिष्टीकरण का अभाव उद्यमशीलता की कमी और आर्थिक अज्ञानता आदि दोष उत्पन्न होते है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा जिले की अर्थव्यवस्था –

भारत में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का कुछ भू–भाग सम्मिलित होता है इस क्षेत्र में उ0प्र0 के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश का दतिया, दमोह, पन्ना, टीकमगढ छतरपुर, नरसिंहपुर एवं सागर इत्यादि जिले सम्मिलित किये जाते है इस शोध ग्रन्थ मे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा जनपद को चयनित किया गया है क्योंकि प्रस्तुत शोध की सुधरती दशा महोबा जनपद की है महोबा जनपद झांसी इलाहाबाद रेलमार्ग पर झांसी से इलाहाबाद की ओर 137 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। महोबा को जनपद के रूप में 11 फरवरी 1995 को मान्यता प्राप्त हुयी तब से लेकर अद्यतन महोबा जनपद विकास की ओर अग्रसारित है।

ऐतिहासिक दृष्टि से महोबा जनपद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। परन्तु महोबा जनपद की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है तथा जनपद में संपूर्ण कृषि वर्षा पर आधारित है जनपद मे सिंचाई की विशेष समस्या है।

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3072 वर्ग कि0मी0 है। जनपद में कृषि योग्य बंजर भूमि 13.09 हे0 है तथा कृषि अयोग्य भूमि 10.304 हे0 है जनपद महोबा नवसृजित चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आता है। 11 फरवरी सन् 1995 से पूर्व यह जनपद हमीरपुर जनपद का एक अंग था वर्तमान मे महोबा जनपद मे तीन तहसीलों तथा चार विकास खण्ड है । जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 299589 हे0 है। खरीफ मे मात्र 59354 हे0 मे खेती की जाती है । जबकि रबी 190215 हे0 में बुआई होती है तथा जनपद में 180 हे0 खेत्र खेती के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार जनपद की सबसे सघनता 12 प्रतिशत है । जनपद मे चार प्रकार की भूमि तथा मार,काबर, पडुआ तथा रॉकड़ पाई जाती है महोबा उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं मध्य प्रदेश के उत्तर मे स्थित है, पहाड़, नदी,

मैदान, जंगल, पेड़, जलवायु इत्यादि भूगोल के अभिन्न अंग है इनके आधार पर भौगोलिक प्रदेश विभाजित किये जाते है महोबा का अधिकांश भाग पठारी है । जिले की भौगोलिक विषमता के आधार पर 4 भागों मे बांटा जाता है।

1. उत्तर का मैदानी भाग
2. पठारी भाग
3. पहाड़ी क्षेत्र
4. जंगली क्षेत्र

जनपद में सिंचाई के साधन सीमित है। लगभग 91100 हे0ए0 कृषि योग्य क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत आता है जबकि 58 प्रतिशत क्षेत्रों मे वर्षा पर आधारित खेती की जा सकती है।

जनपद की नहरों की लम्बाई 455 कि0मी0 है जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित है वर्षा से जलाशय एवं जल उपलब्ध होने पर नहरें रोस्टर के अनुसार चलायी जाती है।

जनपद महोबा की जननांकीय विशेषताओं के आधार पर विश्लेषण –

आर्थिक प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी के अतिरिक्त श्रम की भी नितान्त आवश्यकता होती है। एक सक्रिय साधन होने के कारण उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र मे श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है इसकी पूर्ति देश मे जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है जनसंख्या का आकार साक्षर व्यक्तियों की संख्या तहसीलों की संख्या ग्रामों की संख्या व अन्य आधारभूत संरचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को तालिका नं0 1 मे दर्शाया गया है जोकि अग्रलिखित है :–

तालिका—1

जनपद का जननांकीय विश्लेषण

जनपद की जनसंख्या साक्षरता ग्राम आबादी के सांख्यकीय आंकड़ों की तालिका

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग कि0मी0	1991	3071.0
2.1	जनसंख्या		2001	708831
2.1.1	पुरूष	संख्या ह0 में	"	379795
2.1.2	स्त्री	"	"	329036
2.1.3	योग	"	"	708831
2.1.4	ग्रामीण	"	"	464.29
2.1.5	नगरीय	"	"	117.69
2.16	अनुसूचित जाति	"	"	155.00
2.1.7	अनुसूचित जन जाति	'	"	0.05
2.2	साक्षर व्यक्तियों की संख्या	"	"	
2.2.1	कुल	"	"	170.86
2.2.2	पुरूष	"	"	130.25
2.3.3	स्त्री	"	"	40.60
3	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	"	2003—04	
3.1	लोकसभा	"	"	1
3.2	विधानसभा	"	"	2
4	तहसीलों की संख्या	संख्या	"	3
5	सामुदायिक विकासखण्ड	"	"	4
6	न्याय पंचायत	"	"	39

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
7	ग्राम पंचायत	संख्या	2003—04	247
8	ग्रामों की संख्या			
8.1	आबाद ग्रामों की संख्या	"	1991	435
8.2	गैर आबाद ग्रामों की संख्या	"	"	86
8.3	वन ग्राम	"	"	0
8.4	कुल ग्राम	"	"	521
9	नगर समूह	"	"	5
10	नगर निगम	"	2003—04	0
11	नगर पालिका परिषद	"	"	2
12	छावनी क्षेत्र	"	"	0
13	नगर पंचायत	"	"	3
14	सेन्सस टाउन	"	1991	0
15	पुलिस स्टेशन	"	"	
15.1	ग्रामीण	"	2003—04	5
15.2	नगरीय	"	"	5
16	बस स्टेशन / बस स्टाप	"	"	8
17	रेलवेस्टेशन हाल्टसहित	"	"	7
18	रेलवे लाइन की लं0	"	"	
18.1	बड़ी लाइन	कि0मी0	"	0
18.2	छोटी लाइन	"	"	75
19	डाकघर	संख्या	"	92

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
19.1	नगरीय	संख्या	2003—04	8
19.2	ग्रामीण	"	"	84
20	तारघर	"	"	4
21	टेलीफोन कनेक्शन	"	"	7444
22	व्यवसायिक बैंक	"	"	17
22.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	"	"	0
22.2	अन्य	"	"	.
23	ग्रामीण बैंक शाखायें	"	"	18
24	सहकारी बैंक शाखायें	"	"	11
25	सहकारी विकास बैंक	"	"	
	की शाखायें	"	"	2
26	सस्ते गल्ले की दुकान	"	"	288
26.1	ग्रामीण	"	"	55
26.2	नगरीय	"	"	
27	बायो गैस संयत्र	"	"	918
28	शीत भण्डार	"	"	0
29	कृषि	"	"	
29.1	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	हजार हे0	2002—03	239
29.2	एकबार से अधिक	"	"	0
	बोया गया क्षेत्रफल	"	"	20
29.3	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	"	"	89

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
29.4	सकल सिंचित क्षेत्रफल	हजार हे0	2002—04	90
29.5	कृषि उत्पादन	,,	,,	
29.5.1	खाद्यान्न	हजार मी0टन	,,	179
29.5.2	गन्ना	,,	,,	62
29.5.3	तिलहन	,,	,,	7
29.5.4	आलू	,,	,,	3
30	जलवायु			
30.1	वर्षा			
30.1.1	सामान्य	मि0मी0	2003	—
30.1.2	वास्तविक	,,	,,	—
30.2	तापमान			
30.2.1	उच्चतम	सेटीग्रेड	2001—02	47.2
30.2.2	न्यूनतम	,,	,,	5
31	सिंचाई		,,	
31.1	नहरों की लम्बाई	कि0मी0	,,	455
31.2	राजकीय नलकूप	संख्या	,,	3
31.3	व्यक्तिगत नलकूप	,,	,,	2893
32	पशुपालन	,,	1997	
31.1	कुल पशुधन	,,	2003—04	418748
32.2	पशु चिकित्सालय	,,		9
32.3	पशुधन सेवा केन्द्रसंख्या	संख्या	2003—04	12
32.4.1	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	,,	,,	4

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
33	सहकारिता	संख्या	2003—04	
3.1	प्रारम्भिक कृषि ऋण			
	समितियां	''	''	42
33.2	समितियों के सदस्य	संख्या हजार	''	80.43
34	उद्योग	''	''	
34.1	औद्योगिक अधिनियम	''	''	
	1948 के अन्तर्गत	''	''	
	पंजीकृत कार्यरत	''	''	
	कारखाने	संख्या	2000—01	31
34.2	लघु औद्योगिक इकाइयां	''	2003—04	70
34.2.1	संख्या	''	''	217
34.2.2	कार्यरत व्यक्ति	''	''	
35	शिक्षा	''	''	
35.1	प्राथमिक विद्यालय	''	''	720
35.2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	''	''	184
35.3	माध्यमिक विद्यालय	''	''	37
35.4	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	''	''	87
35.5	महाविद्यालय	''	''	2
35.6	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	"	"	1
35.7	विश्वविद्यालय	''	"	0
35.8	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	''	"	2
35.9	पोलीटेक्निक	"	"	1
			''	

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
35.10	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	संख्या	2003–04	
36.1	जन स्वास्थ्य	"	"	
36.1.1	चिकित्सालय एवं औषधालय	"	"	
36.1.1	ऐलोपेथिक	"	"	6
36.1.2	आयुर्वेदिक	"	"	11
36.1.3	होम्योपैथिक	"	"	6
36.1.4	यूनानी	"	"	1
36.2	प्राथमिक स्वा0केन्द्र	"	"	14
36.3.1	सामुदायिक स्वा0केन्द्र	"	"	3
36.3.2	परिवार एवं मातृ शिशु	"	"	
	कल्याण केन्द्र	"	"	4
36.3.3	परिवार एवं मातृ शिशु	"	"	
	कल्याण उपकेन्द्र	"	"	127
36.4	विशेष चिकित्सालय	"	"	
36.4.1	क्षय	"	"	
36.4.2	कुष्ठ	"	"	
36.4.3	संक्रामक रोग	"	"	
37	पक्की सड़कों की लम्बाई	"	"	
37.1	कुल सड़कों की लम्बाई	"	2002–03	972
37.2	लोक निर्माण द्वारा	कि0मी0	2002–03	924
38	विद्युत	"	"	–

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
38.1.1	विद्युतीकृत कुल ग्राम	संख्या	2003–04	265
38.1.2	विद्युतीकृत आबाद ग्राम	"	"	265
38.2	विद्युतीकृत नगर	"	"	5
38.3	विद्युतीकृत अनु जाति	"	"	
	बस्तियां	"	"	263
38.4	विद्युतीकरण से असेवित	"	"	
	अनु जाति बस्तियों की	"	"	
	संख्या	"	"	0
39	नल / हेण्डपंप इण्डिया			
	मार्क – 2 लगाकर जल			
	संपूर्ति के अन्तर्गत लाये			
	गये	"	"	
39.1	ग्राम			435
39.2	नगर			5
39.3	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या	"	"	0
39.4	नल हैण्डपंप द्वारा			
	पेयजल आपूर्ति से			
	असेवित अनु जाति			
	बस्तियों की संख्या	"	"	
40	मनोरंजन	"	"	7
40.1	सिनेमागृह	"	"	

क्र0सं0	मद	इकाई	अवधि	विवरण
1	2	3	4	5
	सिनेमागृह में सीटों की			
	संख्या	संख्या	2003–04	3325
	वस्तु उत्पाद खण्डों से कुल	"		
	शुद्ध उत्पाद	"	"	
	1980–81 के भावों पर	करोड़ में	1999–00	477.39
42	वस्तु उत्पाद खण्डों से	"	2000–01	429.29
	कुल शुद्ध उत्पाद	"	2001–02	503.50
	प्रचलित भावों पर	"	2002–03	594.01
43	राष्ट्रीय बचत मे शुद्ध	लाख में	1999–00	672.67
	जमाधन	"	2002–03	862.68
44	जिला सेक्टर योजना कुल			
	व्यय परिव्यय	"	2004–05	1362.0
44.1	परिव्यय	हजार रू0	"	176900.00
44.2	वास्तविक व्यय	"	"	83395.00

स्त्रोत – सांख्यकीय पत्रिका महोबा के विविध अंक

तालिका 1.0 मे जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तहसीलों की संख्या, सामुदायिक विकासखण्ड न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्रामों की संख्या, नगर समूह नगर निगम नगरपालिका परिषद, छावनी क्षेत्र, नगरपंचायत सेन्सस टाउन पुलिस स्टेशन बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, डाकघर, तारघर, फोन, बैंक ग्रामीण बैंक शाखाये सहकारी बैंक शाखाये, सस्ते गल्ले की दुकान, कृषि, जलवायु सिंचाइ, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सड़कें, विद्युत, नल / हेण्डपंप, इण्डिया मार्क – 2, मनोरंजन, वस्तु उत्पाद खण्डों से कुल शुद्ध उत्पाद, वस्तु उत्पाद खण्डों से कुल शुद्ध उत्पाद, राष्ट्रीय बचत मे शुद्ध जमा धन, जिला सेक्टर योजना पर कुल व्यय परिव्यय, आदि विषयों पर जनपद कुछ वर्षो की संख्या दी गयी है जिससे ज्ञात होता है कि सन 1991 से 2005 तक इनकी कितनी संख्या थी व जनपद महोबा की उक्त विषयों से सम्बंधित क्या स्थिति थी।

महोबा जनपद से सम्बंधित उक्त सारिणी का अवलोकन करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि जनपद मे साक्षरता का प्रतिशत औसत से बहुत कम है। जनपद मे साक्षरता का प्रतिशत 29. 36 प्रतिशत है। जो कि निश्चय ही जनपद के पिछड़ेपन की ओर इंगित करता है। जनपद की स्त्री साक्षरता की दर 15.23 प्रतिशत है। जनपद मे संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक संस्थागत वित्त प्रदान करने के क्षेत्र मे कार्यरत है जनपद मे इसकी शाखायें 18 थी पर अब 17 है तथा प्रस्तुत शोध कार्य छत्रसाल ग्रामीण बैंक पर ही है।

जनपद मे ग्रामीण क्षेत्र मे 35.4 प्रतिशत कर्मकार तथा नगरीय क्षेत्र मे 28.4 प्रतिशत है इसमें 51.31 प्रतिशत कृषक, 29.5 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.4 प्रतिशत पशुपालन एवं वृक्षारोपण 06 प्रतिशत खान खोदने 2.2 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग 1.9 प्रतिशत गैर पारिवारिक उद्योग 1.4 प्रतिशत निर्माण कार्य 4.4 प्रतिशत व्यापार वाणिज्य 1.5 प्रतिशत यातायात से संग्रहण एवं संचार तथा 5.8 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों मे संलग्न है। वर्ष 2001 के मुख्य कर्मकरों मे विभिन्न कर्मकरों के प्रतिशत को ग्राफ द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ग्राफ –1

मुख्य कर्मकरों मे विभिन्न कर्मकरों का प्रतिशत

जनपद – महोबा

वर्ष – 2001 (लाख संख्या में)
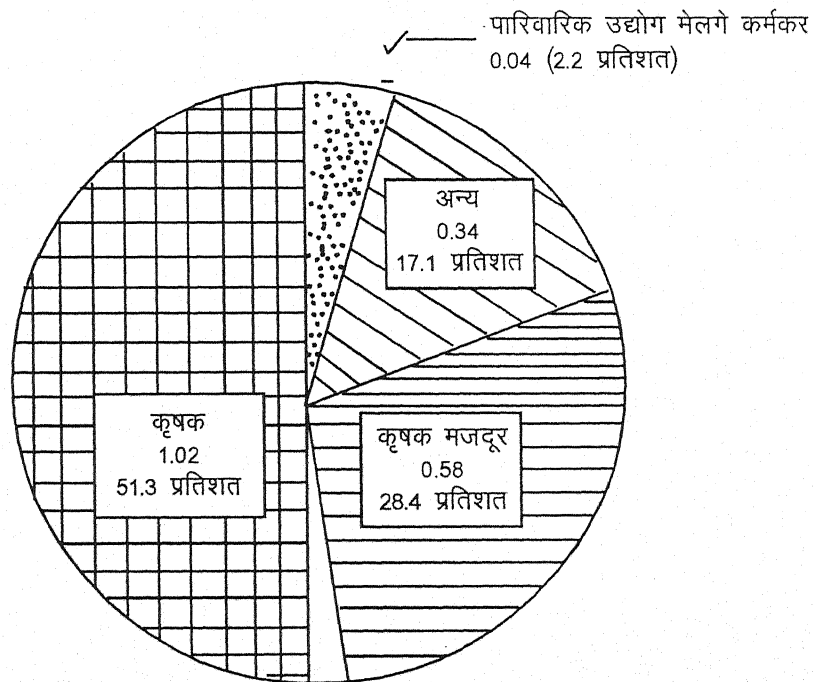
योग मुख्य कर्मकर– 1.98 (100.00 प्रतिशत)

महोबा जिले की जनसंख्या का वर्गीकरण

जनपद में साक्षरता दर की तुलना

तालिका–1.1

महोबा जिले की जनसंख्या सन् 1991 मे 581979 थी जो कि सन् 2001 मे बढ़कर 708831 हो गयी। एक तालिका के अनुसार –

वर्ष / वर्ग	महोबा		बांदा	
	1991	2001	1991	2001
जनसंख्या	581979	708831	1266143	1500253
पुरूष	1000	1000	–	1000
स्त्रियां	845	866	–	860
साक्षरता दर	–	–	37.33 %	54.85 %
पुरूष	36.49 %	66.83%	53.06%	17.90%
महिला	19.09%	35.57 %	69.89%	37.10 %

स्त्रोत – जिले का भूगोल

वर्ष 1995 से पूर्व महोबा हमीरपुर जनपद का एक परगना था। महोबा जिले मे स्त्रियों की दशा संतोषप्रद नही है। लड़कियों की मृत्युदर अधिक है। यहां महिलाओं की संख्या पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है। महोबा मे सन् 1991 मे 1000 पुरूषों पर 845 स्त्रियां थी जबकि 2001 मे 1000 पुरूषो पर 866 महिलायें है। इससे पता लगाया जा सकता है कि दिनों दिन महिलाओं की दशा में सुधार हो रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में महोबा एक पिछड़ा जिला है। यहां उच्च शिक्षा के लिए आज भी छात्रों को दूसरे जनपदों की शरण लेनी पड़ती है। यहां 1991 मे साक्षरता दर 36.49 प्रतिशत थी जो कि 2001 में बढ़कर 66.83 हो गयी है। 1991 मे महिलाओं की साक्षरता दर 19.09 प्रतिशत थी जो कि 2001 में बढ़कर 35.57 प्रतिशत हो गयी । इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझने लगी है एवं लड़कियों को शिक्षा दिलाने की ओर ठोस कदम भी उठा रही है।

इसी प्रकार यदि हम अन्य जिला बांदा की महोबा से तुलना करें तो बांदा की जनसंख्या 2001 मे महोबा से 791422 अधिक है जो कि 53 प्रतिशत अधिक है यानि दुगने से अधिक है बांदा मे महोबा की अपेक्षा 1000 पुरूषों मे 860 महिलायें है जबकि महोबा मे महिलाओं की संख्या अधिक है। बांदा की साक्षरता दर पुरूषों मे 2001 मे 17.90 प्रतिशत है तथा महिलाओं की 37.10 प्रतिशत है यह दर महोबा की अच्छी दशा की सूचक है वहां साक्षरता दर अधिक है बांदा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत है। महोबा की तरह बांदा मे भी मृत्युदर अधिक है अतः जनसंख्या की दृष्टि मे महोबा बांदा की अपेक्षा कम है परन्तु साक्षरता मे कई गुना आगे है।

महोबा जनपद मे अनेक धर्मो के मानने वाले लोग रहते हैं परन्तु अधिकतर लोग हिन्दू एवं इस्लाम धर्म के मानने वाले है। जिले की अधिकांश जनसंख्या गॉवों मे रहती है। यहां के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खाली समय मे घरेलू उद्योग धंधे, दुकानदारी दुगध व्यवसय करते है। मुर्गी पालन, मछली पालन का भी काम होता है और महोबा जिले की भाषा बुन्देलखण्डी है।

तालिका–1.2

जनपद में जनगणना के अनुसार प्रति दशक आबाद ग्रामो की संख्या, जनसंख्या तथा प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर

जनगणना वर्ष	आबाद ग्रामों की संख्या	जनसंख्या		प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर		
		कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7
1951	399	256477	220535	—	—	—
1961	403	304424	266211	18.7	20.7	6.3
1971	408	380307	334824	24.9	25.8	19.0
1981	412	468565	378963	23.2	13.2	97.0
1991	415	581976	464291	24.2	22.5	31.4
2001	418	708831	531623	23.9	–	–

स्त्रोत – सांख्यकीय पत्रिका जिला महोबा, 2003

ग्राफ – 1.1

जनपद की जनसंख्या में जनगणना के अनुसार 1951 से प्रतिदशक जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रतिशत अन्तर

कुल जनसंख्या — प्रतिदशक प्रतिशत अन्तर

जनपद-महोबा
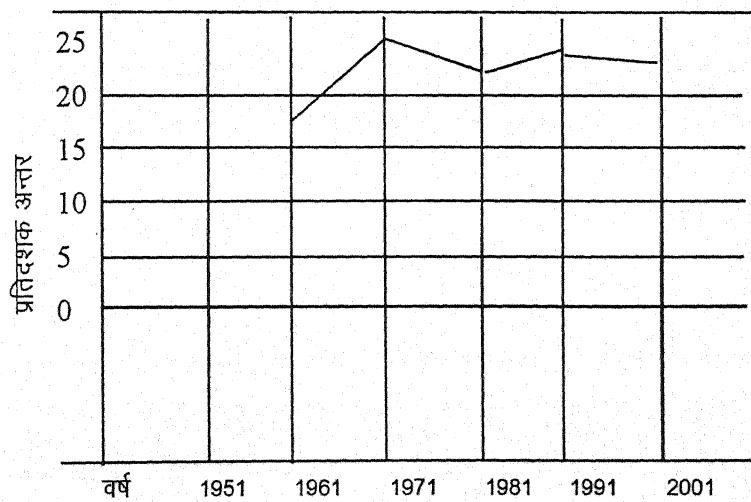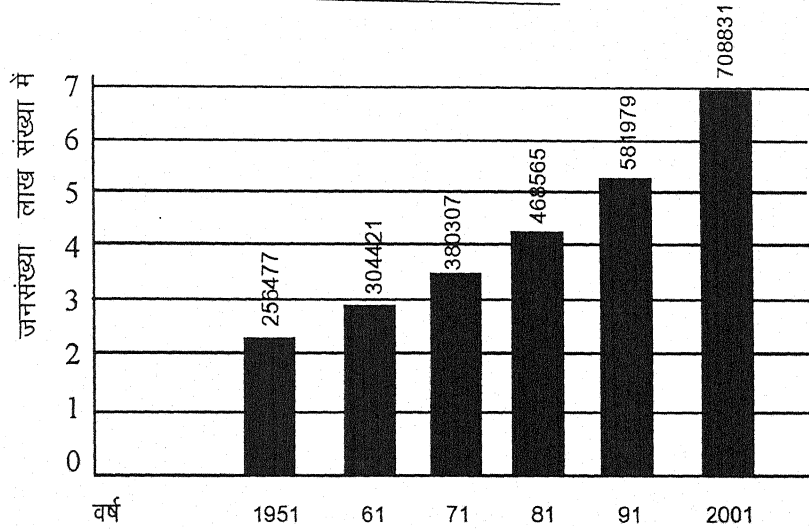
जनसंख्या का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण :—

महोबा जिले की जनसंख्या के आर्थिक आधारों के अन्तर्गत यहां के विकास खण्ड निम्न है जिसके लिए हमारी सरकार ने अग्रांकित प्रयास किये है तथा हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में एक नियोजन अधिकारी डीपीओ की नियुक्ति की है। डीपीओ जिले की उन्नति के लिए अनेक कार्य करता है। डीपीओ के कार्यालय को जिला नियोजन कार्यालय कहते है। प्रत्येक विकास क्षेत्र मे एक ब्लाक कार्यालय होता है। जिसमे एक बीडीओ ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर होता है। बीडीओ की सहायता के लिए कई एडीओ लिपिक, ग्रामसेवक, एक पंचायत सेवक, चपरासी आदि कर्मचारी होते है। विकास खण्डों के कार्यो की निगरानी के लिए जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी समय समय पर विकास खण्ड का दौरा करते है एवं क्षेत्रीय समस्याओं को निपटाने मे मदद करते हैं।

ब्लाक के अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र का समन्वित विकास करने के लिए तरह-तरह के कार्य करते है। गांव के लोगों को खेती की उन्नतिशील विधियां बताते है स्वरोजगार केलिए राज्य से कर्ज दिलाते है। फसलों के लिए दवा, खाद बीज, इत्यादि की मुफ्त व्यवस्था करवाते है। गाँवो की सड़कों, कुँओं, तालाबों, पंचायतों के कार्यो का निरीक्षण करते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे लोगों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा सुधारने का कार्य विशेष रूप से करते है।

ब्लाक —

कार्य की सुविधा के अनुसार महोबा जिले को 4 ब्लाकों मे विभाजित किया गया है।

कबरई, पनवाड़ी, चरखारी, जैतपुर,

कबरई ब्लाक —

कबरई ब्लाक महोबा जिले के अन्तर्गत पूर्वी हिस्से मे फैला है। कबरई महोबा का एक महत्वपूर्ण ब्लाक है । इसका मुख्यालय महोबा मे है। यहां पर क्रेशर द्वारा पत्थर तोड़ने का काम ज्यादातर होता है। अतः इसे पत्थर नगरी कहते है। पिपरा माफ, श्रीनगर, मकरबई, कबरई देहात पसवारा, सिजहरी, पहराभण्डार, पचपहरा, सुरहा, थरौन, यहां की प्रमुख न्याय पंचायतें हैं । चिरौफ, दुढैया, इमलिया, कैमाहा, ज्योरिया, डिपरिया, पहाड़ियां आदि इस ब्लाक के प्रमुख गांव हैं ।

पनवाड़ी ब्लाक :–

पनवाड़ी एतिहासिक महत्व का ब्लाक है । यह पांडवों के निर्वासन काल की शरणस्थली है महाभारत काल में इसका नाम पाण्डवपुरी था। यह कीचक एवं बैराठ से सम्बंधित है। यहां का हाथी दरवाजा प्रसिद्ध है। किल्हौवा, कोटराकनकुआ, सइया, रूटीकला, पनवाड़ी, भरवाहा, पहाड़िया, बैदों यहां की न्याय पंचायतें है। साकर खगरी, तुर्रा, नटर्रा, किल्हौवा, बुडेरा, नौगवां फंदना, ब्यारजो इत्यादि प्रमुख गांव है।

चरखारी ब्लाक –

चरखारी अपने पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे बुन्देलखण्ड का ग्रीष्मकालीन पयर्टन केन्द्र भी कहते हैं। चरखारी मे ऐंचाना, गुढ़ा, सूपा, बमरारा, बम्हौरीकला, रिवई खरेला देहात यहां की न्याय पंचायते हैं।

जैतपुर ब्लाक –

महोबा जिले के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मे जैतपुर ब्लाक स्थित है जैतपुर ब्लाक के पूर्व में कबरई ब्लाक, उत्तर मे चरखारी ब्लाक एवं पनवाड़ी ब्लाक स्थित है। जैतपुर ब्लाक के दक्षिण में छतरपुर जिला एवं पश्चिम मे टीकमगढ़ स्थित है। जैतपुर ब्लाक की न्याय पंचायतों का नाम जैतपुर अजनर, कुड़ई, अकोना, महुआ बांध मगारा डाग, खमा, बुधवारा लाड़पुर है इस ब्लाक के प्रमुख ग्राम कुडई बसरिया, मंगरिया, जैलवारा, पुरर, पचना, गड़ौरा भुजपुरा अमानपुरा छितवारा है।

इसके अतिरिक्त महोबा के जनपद बन जाने के बाद से महोबा का विकास तीव्र गति से हो रहा है। महोबा दूरदर्शन रिले केन्द्र संचालित हो चुका है।

चिकित्सा, पेयजल, दूरभाष, विद्युत, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र मे सुविधाएं बनी है महोबा ने वर्ष 1995–96 के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

महोबा जिले में 3 तहसीलें हैं।

1–महोबा, 2–चरखारी, 3–कुलपहाड़

महोबा जिले का औद्योगिक विकास –

आर्थिक पिछड़ेपन की दृष्टि से जो स्थान भारत के मानचित्र में राज्यों तथा बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश का है वही बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे महोबा जनपद का है। जनपद मे

पानी की कमी है अधिकांश भूमि उपजाऊ है। औद्योगिक विकास शून्य है। नौकरी की प्राप्ति एक सपना है। देहातों से पलायन अधिक है। श्रमिक जीविका विहीन है। पड़ोसी जिलों के उद्योग धंधे भी मन्दी के शिकार हुए हैं। सड़कों का नितान्त अभाव है। विद्युत आपूर्ति सीमित ही नही व्यवधान–प्रधान है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि महोबा जनपद आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है। अतः इसकी आर्थिक विकास मे ग्रामीण बैंक की भूमिका को नकारा नही जा सकता। लेकिन इस जनपद के आर्थिक विकास के मार्ग मे आने वाली बाधायें कई प्रकार की है जिनमे से कुछ निम्न है राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, बाजार की अपूर्णतायें।

महोबा जनपद के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न उपायों को किया जाना चाहिए।

1. आधारभूत संरचना का निर्माण –

जनपद में आर्थिक विकास की नींव अर्थात् यातायात से संचार के साधन शक्ति शिक्षा सिंचाई जैसे साधनो का विकास करना चाहिए इन साधनों का विकास जितना शीघ्र होगा महोबा जनपद का विकास उतना ही तीव्र होगा।

2. साहसिक योग्यता का विकास –

तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ साथ जनपद मे साहसिक योग्यता अर्थात् ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र मे उद्यमशीलता का विकास किया जाना आवश्यक है। जब तक जनपद में जोखिम उठाने वाला वर्ग उपलबध नही होगा तब तक पूंजी का निर्माण नवीन नगदी फसलों का उत्पादन तथा भारी उद्योगों की स्थापना नही हो सकती अतः इस हेतु जनपद मे सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशासन सम्बंधी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना –

आर्थिक विकास का दूसरा नाम पूंजी निर्माण है। अतः पूंजी का निर्माण करने के लिए जनपद की जनता में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाये कृषि उत्पादक मे वृद्धि की जाये अदृश्य बेरोजगारी को कम किया जाये सहकारी सहायता तथा विदेशी पूंजी की सहायता प्राप्त की जाये।

4. श्रम सम्बंधी सुधार –

जिले में औद्योगीकरण की तेजी लाने के लिए यह आवश्यक है कि श्रमिको से सम्बंधित समस्याओं का तुरन्त समाधान किया जाये।

5. कच्चे माल एवं प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण एवं सर्वोपयुक्त उपयोग –

जनपद मे उपलब्ध संसाधनो का सरकारी सहायता एवं देखरेख मे उचित सर्वेक्षण किया जाना तथा उपलब्ध संसाधनो का प्रभावशाली उपयोग करना जनपद के आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।

6. तकनीकी का विकास –

जनपद मे कृषि की स्थिति सिंचाई की सुविधाओं प्राकृतिक संसाधनो के विदोहन एवं औद्योगीकरण के उन्नयन के लिए नवीन तकनीकी का विकास करना अत्यन्त आवष्यक है।

7. उपयुक्त सरकारी नीतियां –

आर्थिक विकास के प्रति उपरोक्त सभी उपाय तब तक फलदायक नही हो सकते जब तक कि सरकारी नीतियां क्षेत्र के विकास के उत्प्रेरक न हो अतः सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश के पिछड़े जिलो को चिन्हित कर उनके समुचित विकास हेतु दीर्घकालीन एवं प्रभावी योजनायें बनाये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषको पशुपालकों छोटे एवं लघु उद्यमियो पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सुदीर्घकालीन आर्थिक रूप से उपयोगी योजनायें लागू करें तथा जनपद मे कार्यरत वित्तीय संस्थान उपर्युक्त उपायों एवं तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करें तो निःसंदेह जनपद को विकसित जिलों की श्रेणी मे खड़ा किया जा सकता है।

जनपद कृषि एवं मानसून आधारित अर्थव्यवस्था –

महोबा मध्य प्रदेश से लगा हुआ जनपद है जिसका कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 299589 हे0 है ओर 218486 हे0 मे ही कृषि की जाती है जनपद मे सिंचाई के साधनों सेमात्र 42 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। खरीफ तो पूर्णतः वर्षा पर आश्रित है। खरीफ मे 59354 हे0 मे खेती की जाती है जो कि कुल कृषि भूमि का मात्र 36.81 प्रतिशत है।

महोबा जिले की 82 प्रतिशत जनसंख्या गांवो मे निवास करती है यहां कृषि ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। भौगोलिक विषमता सिंचाई के साधनो का अभाव तथा नई तकनीकी की कमी के कारण कृषि के क्षेत्र मे पिछड़ापन है।

महोबा जिले की अत्यधिक जनसंख्या खेती के काम मे लगी हुयी है। खेती वर्षा पर निर्भर है एवं वर्षा मानसून पर। महोबा में वर्षा का अभाव कभी कभी कृषि को नष्ट कर देता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है कभी कभी भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। जैसा कि 1966 मे आधी एवं ओलावृष्टि से 14 हजार पान की पारियां अर्थात् लगभग 200 एकड़ मे लगभग 21 करोड़ रूपये की हानि हुयी गर्मी अधिक पड़ने के कारण लोग सूती वस्त्रों का एवं साफी का विशेष रूप से लोग प्रयोग करते हैं। धूल भरी आंधी और जनसामान्य को बेचैन कर देता है।

जून 2001 मे महोबा का तापमान 46.0 डिग्री सेन्टीग्रेड रिकार्ड किया गया। जिले के अनेक कुंए तालाब पोखर सूख जाते हैं। महोबा जिले मे जाड़ा सामान्य पड़ता है। परन्तु कभी कभी हाड़ कांपने वाला जाड़ा व पाला पड़ जाता है। पाला के प्रभाव के कारण फसले नष्ट हो जाती है जाड़ा का सामना न कर पाने के कारण अनेक गरीब लोग एवं पशुपक्षी काल कवलित हो जाते हैं।

महोबा जनपद की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत यहां की मिट्टियों प्राकृतिक वनस्पति मानसून महोबा की झीलें, तालाब बांध यहां की नदियों जलवायु मौसम व सिंचाई के साधनो व कृषि का अध्ययन इस अध्याय के अन्तर्गत करेंगें क्योंकि कोई देश हो या जनपद वहां की कृषि व मानसूनो से सम्बंधित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उपर्युक्त जानकारी होना आवश्यक है तभी वहां की संभावनाओ और असम्भावनाओं और आर्थिक अर्थव्यवस्था का सही सही विवेचन किया जा सकता है। और वहां की स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है इस संदर्भ मे सर्वप्रथम हम महोबा जनपद की मिट्टियों का अध्ययन करेगें।

महोबा जिले मे ग्रामीण परिवेश एवं आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण कृषि परम्परागत ढंग से की जाती है आधुनिक कृषि यन्त्रों एवं तकनीकी का कम प्रयोग किया जाता है अतः यहां प्रति हे0 उत्पादन कम होता है महोबा जिले मे होने वाली फसलों को तीन भागों मे बांटा गया है।

1. रबी की फसल –

इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। यह शीतकाल के प्रारम्भ मे अक्टूबर नवम्बर मे बोयी जाती

है एवं फरवरी मार्च तक काट ली जाती है इस फसल मे गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, अलसी, मटर प्रमुख है रबी मे सामान्यतः 169562 हे0 मे खेती की जाती है परन्तु 1996–97 मे 190246 हे0 मे खेती की गयी।

2. जायद की फसल –

खरीफ एवं रबी की प्रमुख फसलों के मध्य मे ये फसलें वर्ष में दो बार उगायी जाती है।

क. वर्षा एवं शीत ऋतु के मध्य जेसे तोरिया, तिलहन, राई सरसों इत्यादि।

ख. ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के मध्य जेसे चारा, मेथी, खरबूजे, तरबूज, ककड़ी, सिंघाड़ा, भसीड़ा केसरू आदि।

ग. जायद की फसलों मे महोबा का पान विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि पान की खेती के लिये अच्छी एवं उपजाऊ जमीन है व पानी की पर्याप्त उपलब्धता है ।

3. खरीफ की फसल –

इसे वर्षा ऋतु की फसल भी कहते है यह वर्षा के आरम्भ मे जून जुलाई तक बोई जाती है और वर्षा की समाप्ति पर काट ली जाती है मुख्य फसलें जवार, बाजरा, तिल, सांवा,मक्का, सन काकुन, मूंग, उड़द, रिउछा है। यह फसल हमारे जिले के दक्षिणी भाग में अधिक होती है । यहां कोदो, सांवा, कालातिल अधिक होता है सन् 1996–97 मे 63199 हे0 मे खरीफ की फसल उगायी गयी।

जनपद मे कृषि कार्य हेतु सिंचाई के साधनो का वर्गीकरण –

फसल को कृत्रिम बनावटी ढंग से पानी लगाने को सिंचाई कहते हैं महोबा जिले की वर्षा मानसूनी होने के कारण अनिश्चित है। वर्षा साल भर न होकर केवल जून से सितम्बर तक चार महीने ही होती है। अतः हमारे जिले मे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। महोबा जिले के प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2,98,427 हे0 है। जिसमे से सकल सिंचित क्षेत्र 640604 हे0 है। यहां का अधिकतर क्षेत्र पठारी है तथा कृषि की अच्छी उपज के लिए कृषि के साधनो का प्रायः अभाव पाया जाता है तथा हमारे जिले मे प्रमुख रूप से निम्नांकित सिंचाई के साधन प्रयोग मे लाये जाते हैं।

कुँए, तालाब, झील, नलकूप, पम्पिंग सेट, हैण्डपंप, लिफ्ट सिंचाई, बांध, नदियां, नहरें आदि हैं ।

झीलों एवं तालाबों द्वारा सिंचाई –

हमारे जिले में ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण गड्ढों में बरसाती पानी भर जाता है । स्थानीय रूप से पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। महोबा जिले मे अनेक झीलें एवं तालाब है जिनसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इससे नहरे भी निकाली गयी है।

कुँओ द्वारा सिंचाई –

महोबा जिले मे प्राचीन काल से कुँआं सिंचाई का प्रमुख साधन रहा है । कुँए से रहट एवं चरसे द्वारा सिंचाई की जाती है कुछ कुओं में पम्पिंग सेट भी लगाये गये हैं। कुँए द्वारा अन्य छोटी जगहों में सिंचाई की जाती है।

नलकूप द्वारा सिंचाई –

जिले का जल स्तर अत्यधिक नीचा होने के कारण नलकूप सिंचाई का उपयुक्त साधन है। सिंचाई की जरूरत पड़ने पर नलकूप द्वारा तुरन्त पानी निकाला जा सकता है।

नहरों द्वारा सिंचाई –

महोबा में नहरों की लम्बाई 455 कि0मी0 है। नहरे भी जिलों की सिंचाई का प्रमुख साधन है। नहरें उन क्षेत्रों में सिंचाई का प्रमुख साधन होती है जहां भूमि समतल हो एवं नदियों में वर्ष भर पानी सुलभ हो।

ग्राफ –1.2
विभिन्न साधनों द्वारा स्त्रोतवार सिंचित क्षेत्रफल
वर्ष 2004–05

वर्ष – 2001 (लाख संख्या में)
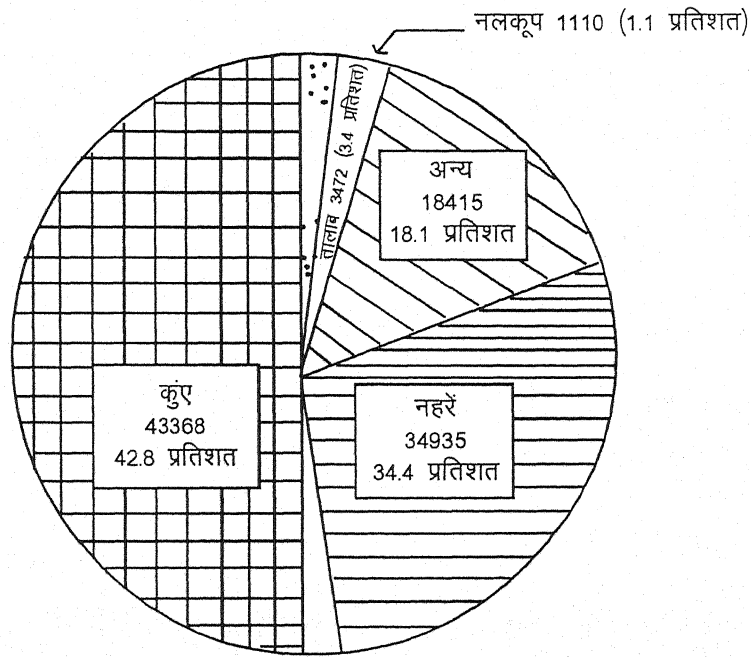
कुल सिंचित क्षेत्र – 101400

मौसम व जलवायु

महोबा जिले की जलवायु मानसूनी है अतः यहां पर्णपाती वन अधिकतम पाये जाते हैं। कृषि पर वहां के मानसूनों का भी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमे उस स्थान के मौसम और जलवायु का भी अध्ययन करना आवश्यक है।

जैसा कि हम जानते है कि तापमान वायुदाब हवा की गति हवा मे नमी की मात्रा बादलों की स्थिति कभी एक सी नही रहती है ये प्रतिफल बदलते रहते हैं।

किसी भी स्थान के मौसम को निर्धारित करने में तापमान वायुदाब वर्षा एवं आद्रता की मात्रा प्रमुख भूमिका अदा करते है मौसम को 3 तत्व प्रभावित करते हैं।

तापमान, वायुदाब, वर्षा एवं आद्रता की मात्रा

हमारे जिले में प्रमुख रूप से तीन मौसम या ऋतुएँ होती है।

शीत ऋतु –

हमारे जिले में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। कभी कभी तापमान 6.20 डिग्री फारनेहाइट तक गिर जाता है। 1990–91 मे नयूनतम तापमान 2.40 डिग्री तथा 1991–92 में 4.60 डिग्री सेंटीग्रेट रिकार्ड किया गया है। 2001 मे 4 उिग्री सें0 तक तापमान गिर गया।

ग्रीष्म ऋतु –

ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक रहती है। यहाँ गरमी ज्यादा पड़ती है लू चलती है ग्रीष्म ऋतु मे पानी की कमी हो जाती है विशेषकर पाठा क्षेत्र मे 1991–92 मे उच्चतम तापमान 58.80 डिग्री सें0 रिकार्ड किया गया । जून 1995 मे तापमान 59.50 डिग्री सें0 रिकार्ड किया गया। जून 1998 मे भी तापमान 58.50 डिग्री सें0 रिकार्ड किया गया। मई 2001 मे 48 डिग्री सें0 तक तापमान रिकार्ड किया गया।

वर्षा ऋतु –

हमारे जिले में जुलाई अगस्त एवं सितम्बर के तीन महीने वर्षा ऋतु के माने जाते हैं। इस समय वातावरण हरा भरा एवं मनोहर हो जाता है। मानसूनी वर्षा होने के कारण कभी अनावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि से अकाल पड़ जाता है वास्तविक वर्षा 1990–91 मे 190 0मी0 तथा 1991–92 मे 846 मि0मी0रिकार्ड की गयी।

हमारे जिले की जलवायु का समाज पर प्रभाव –

हमारे जिले की 82 प्रतिशत जनसंख्या कृषि आधारित है। खेती वर्षा पर एवं वर्षा मानसून पर निर्भर है। हमारे जिले मे वर्षा का अभाव कभी कभी कृषि को नष्ट कर देता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है भूखों मरने की नौबत आ जाती है गर्मी अधिक पड़ने के कारण लोग सूती वस्त्रों एवं साफी का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं।

महोबा की नदियां –

महोबा जिले की अधिकतर नदियां बरसाती है। गर्मी के मौसम मे इनका पानी कम हो जाता है या सूख जाता है महोबा मे निम्नांकित नदियां हैं।

धसान नदी –

धसान नदी विन्ध्याचल पर्वत से निकलती है यह महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील मे बहती है। इसका बहाव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर है।

उर्मिल नदी –

यह नदी बेलाताल से निकलती है महोंबा से बहती हुयी हमीरपुर जिले मे चली जाती है बरसात के दिनो मे सहायक नालों से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है।

वर्मा नदी –

यह नदी कुलपहाड़ के अजनर नामक स्थान के समीप स्थित पहाड़ियो से निकलती है चरखारी तहसील मे बहती हुयी हमीरपुर जिले मे प्रवेश करती है।

श्याम नदी –

यह कबरई से निकलती है और हमीरपुर की ओर जाती है यह बरसाती नदी है गर्मियों मे सूख जाती है।

अर्जुन नदी –

यह भी बरसाती नदी है गर्मियों में सूख जाती है यह कुलपहाड़ से निकलकर हमीरपुर के राठ तहसील में वर्मा नदी से मिल जाती है।

सीह नदी –

यह एक छोटी बरसाती नदी है जो हमारे जिले के चरखारी तहसील से निकलकर मोदाहा

तहसील के चन्द्रावल नदी मे मिल जाती है।

छतेस नदी –

महोबा की यह भी एक प्रमुख नदी है।

महोबा जनपद की मिट्टियां –

मिट्टी पृथ्वी के स्थलीय भाग की ऊपरी परत है। इस परत की गहराई कुछ सेन्टीमीटर से लेकर दो मीटर तक होती है मिट्टी की इसी पतली परत से जीवधारियों को भोजन मिलता है मिट्टी एवं कृषि का अभिन्न सम्बंध होने के कारण मिट्टी का अध्ययन आवश्यक है। महोबा जनपद के मुख्य रूप से निम्नलिखित मिट्टियां पायी जाती है।

मार मिट्टी (काली मिट्टी) –

यह मिट्टी काले रंग की होती है। अतः इसे काली मिट्टी भी कहते है यह महीन कणों वाली चिकनी एवं उपजाऊ होती है मार मिट्टी नदियों के तटीय मैदान कबरई के पश्चिमी भाग एवं मध्य क्षेत्र मे विशेष रूप से पायी जाती है।

काबर मिटटी –

काबर मिट्टी भी काली मिट्टी की एक किस्म है जो मार मिट्टी की अपेक्षा छोटे कणों,वाली चिकनी उपजाऊ एवं लसदार है। महोबा के उत्तरी सिरे पश्चिमी हिस्से एवं दक्षिणी भाग में विशेष रूप से पायी जाती है।

पडुवा मिट्टी –

यह मिट्टी हलके भूरे रंग एवं पीले रंग की होती है इससे बालू का अंश अधिक होता है यह महोबा के पूर्वी मैदान भाग कबरई के पास विशेष रूप से पायी जाती है।

राकड़ मिट्टी –

राकड़ मिट्टी लाल रंग की होती है । यह कंकरीली पथरीली मिट्टी है यह जैतपुर में विशेष रूप से मिलती है।

ऊसर मिट्टी –

यह मिट्टी अनुपजाऊ है यह मिट्टी विशेष रूप से पनवाड़ी एवं चरखारी के ब्लाकों में पाई जाती है।

महोबा की प्राकृतिक वनस्पति (मानसून) –

महोबा जिले की जलवायु मानसूनी है। अतः यहां पर्णपाती वन अधिकता से पाये जाते है । महोबा जिले के शुष्क हिस्से मे मरूस्थलीय वनस्पति पायी जाती है इस तरह जिले में दो प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पायी जाती है।

पर्णपाती वन –

महोबा जिले में उच्च क्षेत्र के अतिरिक्त सर्वत्र पर्णपाती वन पाये जाते है। ग्रीष्म ऋतु में यह वन अपनी पत्तियां गिरा देते है। इन वृक्षों में नीम, आम, महुआ, बरगद, पीपल, इमली खैर, जामुन, गूलर, अशोक, साल सागौन, तेंदू, शरीफा, आंवला एवं फूलों के वृक्ष आते है।

झाड़ियां –

महोबा जिले की उच्च भूमि पर वर्षा की कमी के कारण कांटेदार झाड़ियां एवं घने वन पाये जाते है। इन जंगलो मे बबूल, करौदा बेर इत्यादि के वृक्ष पाये जाते है।

वन संसाधन –

प्राकृतिक वनस्पति के अतिरिक्त महोबा के वनो से अन्य कीमती वस्तुंए भी प्राप्त होती है इनमें इमारती लकड़ी, औषधियां, जड़ी बूटी, बबूल की गोंद, शहद, चमड़ा रंगने के काम मे आने वाली बबूल की छाल आदि प्रमुख हैं।

जीव जन्तु –

महोबा जिले में विविध प्रकार के जीव जन्तु पशु पक्षी पाये जाते हैं।

वनों में नमी निकलती रहती है जिससे वायुमण्डल का तापमान कम हो जाताहै एवं वर्षा होती है वन वर्षा के जल को सोख लेते है जिससे भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरने नही पाता वनो से पत्तियां गिरकर सड़ गलकर भूमि मे समाती रहती है जिससे

भूमि उपजाऊ हो जाती है वन सुन्दर एवं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करते है जिससे पर्यटन स्थानों का विकास होता है।

महोबा के झीलें, तालाब एवं बांध –

जनपद की कृषि कार्य हेतु यहां की झील तालाब, व बाँधो का वर्गीकरण निम्न है –

जल के उस हिस्से को जो चारों ओर स्थल से घिरा हो तालाब कहते हैं बहुत बड़े तालाब को झील कहते है सिंचाई आदि की सुविधा हेतु बांध बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता है और अपनी सुविधानुसार खर्च किया जाता है।

झील –

मझगवां झील कुलपहाड़ के समीप अजनर ग्राम में स्थित है यह तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा है वहाँ बांध बनाकर नहरें निकाली गयी है।

तालाब निम्न है –

बीजानगर – इसे ब्रम्ह चन्देलों नामक व्यक्ति ने बनवाया था।

बेलाताल – यह जैतपुर ग्राम मे स्थित है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा होने के कारण मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है।

रतन सागर – 104.68 एकड़ क्षेत्र में फैला चरखारी का सबसे बड़ा तालाब है।

कल्याण सागर – इसे वीर वर्मन ने बनवाया था।

मदन सागर – इसे मदन ब्रम्ह ने बनवाया था।

रहिलिया सागर – इसे राहिल देव वर्मन ने बनवाया था।

दिसरापुर तालाब – इसे आल्हा ऊदल के पिता दस्सराज ने बनवाया था

विजय सागर – इसे विजय ब्रम्ह ने पूरा करवाया था।

कीर्ति सागर – इसे कीर्ति वर्मन ने बनवाया था । महोबा में निम्न बाधों से नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है।

अर्जुन बांध –

यह बांध अर्जुन व बधौरी नदी में चरखारी के पास बनाया गया है।

कबरई बंधया चन्द्रावति बांध – यह बांध चन्द्रावल नदी पर बांधा गया है।

सिलारपुर बांध – यह बांध बरानाला और करपटिया नदी पर सिलारपुर ग्राम मे बना हुआ है।

जनपद मे रोजगार का स्वरूप –

प्रदेश की सरकार ने महोबा कों खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया है। महोबा जिला दक्षिण के पठारी भाग मे स्थित है। इस भाग मे अधिक मात्रा मे खनिज पदार्थ पाये जाते है हमारे जिले के प्रमुख खनिज उद्योग धंधे निम्नांकित है –

1. क्रेशर उद्योग –

महोबा की पहाड़ियां चट्टानों से बनी है इससे उच्च कोटि का ग्रेफाइट पाया जाता है कबरई मे सबसे ज्यादा 0216 क्रेशर लगाये गये है यहां चट्टानों से मिट्टी बनाई जाती है जो भवन तथा सड़क बनाने के काम मे लायी जाती है इस उद्योग मे बहुत से लोगों को रोजगार मिला है क्रेशर उद्योग मे कबरई का महत्वपूर्ण स्थान है।

2. गौरा पत्थर का दस्तकारी काम –

महोबा मे कारीगरों द्वारा गौरा पत्थर से तरह तरह की वस्तुएं तथा सुन्दर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। महोबा जिले मे चरखारी के समीप गौरहारी नामक स्थान पर गौरा पत्थर पाया जाता है सरकारी संरक्षण न मिल पाने के कारण महोबा मे इस उद्योग का ठीक से विकास नही हो पा रहा है।

3. बालू उद्योग –

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण महोबा मे नदी नालों मे उत्तम श्रेणी की बालू पायी जाती है बालू का प्रमुख स्त्रोत उर्मिल एवं छतेसर नदियां है।

4. मोरम उद्योग –

महोबा जिले मे लाल रंग की मोरम पहाड़ियां पायी जाती है जिनसे मोरम खोदकर इन्हे बेंचा जाता है घर बनाने के लिए सीमेण्ट के स्थान पर मोरम का प्रयोग किया जाता है।

5. पीतल का मूर्ति निर्माण व्यवसाय –

बुन्देला राजाओं तथा मराठा शासकों के समय मे श्रीनगर नामक बस्ती मे पीतल के सिक्कों की ढलाई तोप बनाने का काम किया जाता था अब यहां पर पीतल की मूर्तियां बनाने का काम होता है।

महोबा जिले मे चूना पत्थर बालू ग्रेनाइट के अतिरिकत ग्रेफाइट, सोपस्टोन, जिप्सम, पायरो प्रिसाइड इत्यादि खनिज के भण्डार भी पाये जाते है। परन्तु अभी औद्योगिक स्तर पर दोहन नही हो रहा है।

महोबा जिले मे उद्योग धंधो की स्थिति –

महोबा जिले का धरातल पठारी होने के कारण यहां का जीवन अत्यन्त कष्टप्रद है इस क्षेत्र का आर्थिक विकास न होने के कारण यह उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाको मे आता है यहां की सांस्कृतिक एवं सभ्यता को बुन्देलखण्डीय कहा जाता है अशिक्षा कुरीतियां एवं बेरोजगारी के कारण यहां अपराध की बाहुल्यता है इस क्षेत्र मे धार्मिक उन्माद एवं अन्ध विश्वास भी पाया जाता है।

महोबा जिले में उद्योग की स्थिति न के बराबर है यहां पर कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित नही है तथा कुछ इलाकों मे लघु एवं कुटीर उद्योग ही थोड़ी सी मात्रा में पाये जाते है जिले के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक उन्नति का होना अत्यन्त आवश्यक होता है महोबा मे धरातल पठारी ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीला है यहां आवागमन के साधनो का अभाव है या अपेक्षाकृत कम है तथा वायुयान की कोई सुविधा का न होना भी बड़े बड़े उद्योगों के स्थापित होने में एक समस्या बन कर सामने आता है।

महोबा जिले मे अत्यन्त निम्न स्तर की तकनीकी एवं विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी यहां पर ग्रेनाइट उद्योग बड़ी ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस धरातल मे पहाड़ी पहाड़, ऊबड़ खाबड़ धरातल ग्रेनाइट नीम नाइस चट्टानों एवं लाइम स्टोन का अद्भुत समन्वय है यहां की ग्रेनाइट उद्योग से यहां के बेराजगारों को कार्य मिल जाता है जिससे उनका आर्थिक स्तर भी ठीक ठाक हो जाता है यहां के उद्योग से बनने वाले ग्रेनाइट की कई जगहों पर मांग की जाती है। यहां का यह उद्योग पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है।

महोबा का पान –

महोबा जिले में अधिकतर पान की कृषि होती है और यहां पर किसानो के रोजगार का साधन पान कृषि है जिसको बेचकर किसान अपनी आजीविका चलाता है और महोबा का पान रोजगार का साधन होने के साथ साथ पूरे देश मे प्रसिद्ध है।

महोबा जिले की 82 प्रतिशत जनसंख्या गाँवो मे निवास करती है तथा कृषि पर आधारित है और महोबा मे सबसे अधिक पान की कृषि होती है । संस्कृत मे पान को ताम्बूल कहते है। वेदो मे ताम्बूल का वर्णन विभिन्न रूपो मे हुआ है। आध्यात्मिक प्रकरणों मे देवी देवताओं का पूजन अर्चन इत्यादि विधान मानव संस्कार स्वास्थ्य और औषधि विज्ञान मे ताम्बूल को प्रमुखता दी गयी है।

लबों की शान महोबा का पान अत्यन्त करारा एवं स्वादिष्त होता है इसी कारण यहां के पान ने देश के प्रेमियों के साथ ही साथ खाड़ी अमीरों एवं पाकिस्तान के रईसों को भी मोह रखा है।

पान का वास्तविक नाम पाइपर वितिल है। यह पाइपरेसी कुल का पौधा है जो एक बेल लता के रूप मे आता है यह द्विबीज पत्ती होता है। पान को कफनाशक माना जाता है। किंवदन्तियों के अनुसार पान की उत्पत्ति पाताल लोक या नागलोग से हुयी जिसको आधुनिक युग मे मलेशिया इंडोनेशिया सुमात्रा जावा मालद्वीप एवं अन्य पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है। कहावत है कि नागलोग के राजा वासुकि ने अपनी कन्या के दहेज मे नागबेल (पान) कों भेंट स्वरूप दिया था। इसी कारण महोबा मे नागपंचमी के अवसर पर हजारों पान कृषको द्वारा नागदेव, तसक देव डेढ़ा देव जाखदेव की पूजा पान बरेजों पर सामूहिक रूप से की जाती है। पहुवा गर्म हवाओं लू से बचाव एवं सिंचाई की सुविधा करने हेतु पान बरेजों को मदन सागर कीरत सागर तथा अन्य तालाबों पोखरों के किनारे किनारे लगाया जाता है।

पान की शुरूआत –

महोबा मे चन्देल कालीन एक राजा द्वारा धार्मिक अनुष्ठान मे आवश्यकता पड़ने पर पान की बेल को उदयपुर बासवाडा राजस्थान से यहां मंगाकर गौरखगिरि या गोखाड

पहाड़ के पश्चिम भू–भाग पर रोपित किया गया जहां आज भी नागोरियां पर श्री नागदेव का मंदिर स्थित है चन्देल काल से स्थापित पान व्यवसाय को महोबा मे निरन्तर व्यवसायिक रूप मिलता गया।

आज भी शेरपुर, चन्देरा, लौड़ी, महाराजपुर, बलदेवगढ, पिपट, पनागर, मलहरा, दिदवारा बारीगढ़ से पान को टोकरे बैलगाड़ियों घोड़े, ऊंटो द्वारा यहां आते है और इनकी कटाई छटाई करके रेल द्वारा दिल्ली सूरत मुम्बई व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मंडियों जैसे पाकिस्तान के विभिन्न शहरों तक भेजे जाते है।

महोबा के छठवें दशक के अन्त तक लगभग 150 एकड़ क्षेत्र मे पान मे कृषि होती थी सरकार ने पान की खेती के विकास के लिए द्विवार्षिक योजना चलायी व अनुसंधान केन्द्र की स्थापना से कृषको को पान के रोगों की कीटनाशक दवाओं से आर्थिक लाभ हुआ एवं खेती बढ़कर लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में होने लगी है। पान की खेती के प्रसार से प्रान्त सरकार ने भी पान की खेती उन्नत व प्रगतिशील बनाने हेतु एक पान शोध केन्द्र खोला है जो चरखारी मार्ग पर स्थित है।

<u>पान की किस्में</u> –

वैज्ञानिक दृष्टि से पान की 5 या 6 किस्में होती है जैसे मीठा, कपूरी, सांची, खासी, बंगला, देशावरी या देशी।

<u>1.</u> <u>देशी पान या देशावरी</u> –

इसमे देशी बिलहरी एवं जैसवारी पानों के आकार रंग तथा सुगन्धित तेलों की मौजूदगी के अनुसार रखा गया है इस पान मे करारापन कम रेशे हलकी कड़वाहट एवं स्वाद अच्छा होता है पत्ता गोल व नुकीला होता है।

<u>2.</u> <u>बंगला पान</u> –

इस समूह मे बंगला पानो की सभी किस्में आती है बंगला पान का पत्ता हृदय के आकार का गोलाई लिए होता है। इसका स्वाद कडुवा व चिरचिरा होता है यह औषधियों के काम मे अधिक इस्तेमाल होता है।

<u>3.</u> <u>कपूरी पान</u> –

यह हलका कड़ुवा रहता है। लम्बा व हलके पीले रंग का होता है।

4. सांची पान –

यह पान हरा अधिक रेशेदार, चिरपरा एवं मोटा होता है।

5. खासी पान –

यह पान छोटा एवं कसौला होता है।

पान के विकास की अन्य योजनायें –

1. प्रदेश सरकार का एक पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चरखारी रोड पर स्थित है।

2. राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (सी एस आई आर) द्वारा संचालित एक अनुसंधान केन्द्र छतरपुर मार्ग पर है। अब इस अनुसंधान को प्रदेश सरकार के पान प्रयोंग एवं प्रशिशण केन्द्र से संचालित किया जा चुका हैं।

कृषि क्षेत्र में रोजगार की सुविधायें –

भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान देश है। कृषि राज्य का विषय है एवं राज्य सरकारों के कृषि विभाग द्वारा ही प्रशासित है। कृषि मे कैरियर की दृष्टि से भी रोजगार की प्रबल संभावनायें है एवं समानान्तर एलाइड एग्रीकल्चर साइंसेज यथा हार्टिकल्चर डेरी, विकास फिशरीज के अन्तर्गत भी पर्याप्त कैरियर सुविधाये उपलब्ध है।

वर्तमान मे कृषि विभाग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मे कृषि से सम्बंधित कार्य हेतु उ0प्र0 तराई बीज विकास निगम, कृषि औद्योगिक निगम भूमि सुधार निगम तथा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान एवं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कार्यरत है। जो प्रदेश मे विभिन्न कृषि निवेशों के उत्पादन तथा वितरण एवं कषि से सम्बंधित अन्य कार्यो मे कृषि उत्पादन बढाने मे योगदान कर रहे है उपरोक्त सभी संस्थाओं मे कृषि स्नातकों के लिए विभिन्न स्तर के पद हैं।

उपरोक्त संस्थानों कें अतिरिक्त ग्रामो से लेकर जिला स्तर पर अनेक पद कृषि विभाग के अन्तर्गत आते है जिससे मुख्यतः 'ख' संवर्ग के अन्तर्गत जिला कृषि अधिकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि सहायक या कृषि इंस्पेक्टर भूमि संरक्षण अधिकारी एवं कृषि उत्पादन से सम्बंधित अन्य कार्य आते है। कृषि व्यवसाय के

कर्मचारियों का तीन चौथाई हिस्सा कृषि स्नातकों के लिए कृषि विकास सम्बंधी विभिन्न योजनाओं मे राज्य सरकार द्वारा ही भरा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र मे अनुसंधान निर्देशन एवं उन्नयन हेतु केन्द्रीय संस्था है।

कृषि क्षेत्र में डिग्री कोर्स विभिन्न कृषि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, मे उपलब्ध है जिनमे इण्टरमीडियेट स्तर पर कृषि विज्ञान अथवा भौतिकी रसायन एवं जीव विज्ञान के छात्र प्रवेश ले सकते है बी एस सी कृषि विज्ञान के अन्तर्गत पढ़ाये जाने वाले विषयों में पादप संरचना विज्ञान कृषि रसायन विज्ञान कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि वन्स्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, पादप एवं पशु व्याधि बागवानी पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी प्रमुख है।

कृषि क्षेत्र मे स्नातकों के लिए बाटेनिकल, असिस्टेन्ट, डेमान्स्ट्रेटर एवं लैब असिस्टेन्ट जैसे पदों के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग से कृषि सम्बंधी अनेक प्रकार के पद विज्ञापित होते है कृषि विज्ञान में परास्नातकों के लिए कृषि वनस्पति विज्ञन मे विशेषताप्राप्त छात्रों को बॉटनिस्ट, प्लान्ट पेथेलाजिस्ट, वैज्ञानिक एग्रोलॉजिस्टर, असिस्टेन्ट क्यूरेटर रिसर्च असिस्टेन्ट एवं रिसर्च आफीसर्स जैसे पदों मे सेवा नियोजित होने के अवसर उपलब्ध होते है। बानिस्ट किसी क्षेत्र विशेष मे विशेषता प्राप्त कर सकते है। यथा प्लान्ट टैक्सोनोमी, प्लाण्ट, प्लाण्ट मार्फालाजी, हिस्टालॉजी प्लाण्ट इकालॉजी, पैलियोबोटनी, माइकालॉजी एवं सिटोजेनेटिक्स आदि।

कृषि रसायन विज्ञान मे विशेषता प्राप्त छात्रों को सायल कैमिस्ट, एग्रीकल्चरल कैमिस्ट सॉयल सर्वे असिस्टेन्ट कैमिकल असिस्टेन्ट एवं एनालाइजर जैसे पदों हेतु अवसर प्राप्त होते है । जिनके प्रमुख कार्य मिट्टी के गुणो एवं स्थितियों का तथा उर्वरक एवं खादो के मिट्टी पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना है।

कीट विज्ञान के विशेषज्ञ इन्टामालाजिस्ट, रिसर्च असिस्टेन्ट या रिसर्च आफीसर के व्यवसायो में जा सकते है एवं आगे इंसेक्ट टैक्सिकॉलाजी, इंसेक्ट फिजियोलाजी या इंसेक्ट टेक्सोनामी की प्रशाखाओं में विशेषता हासिल कर सकते हैं।

इसी प्रकार कृषि अभियांत्रिकी कृषि अर्थशास्त्र भूमि संरक्षण एवं कृषि सांख्यिकीय के क्षेत्रों में पृथक पृथक विशेषज्ञों हेतु अनेक प्रकार के पद होते है।

इसके अतिरिक्त राइबोजियम कल्चर से सम्बंधित प्रयोग शालाओं मे कल्चर पैकेटो के उत्पादन से जुड़े कार्मिको मे कृषि विज्ञान विशेषज्ञों की मांग होती है। कृषि सम्बंधी पाठ्यक्रमो को संचालित करने वाले कुल 13 संस्थान है जो कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, इटावा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, नगर पंतनगर इटावा राठ हमीरपुर नई दिल्ली व जबलपुर यूनिवर्सिटियो मे है।

आई0टी0 में रोजगार के अवसर –

आज का युग कम्प्यूटर युग है जिसे सूचना तकनीकी का युग कहा जाता है आज कम्प्यूटर के बिना कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से हो पाना संभव नही है। आज कम्प्यूटर का उपयोग शिक्षा व्यवसाय विज्ञान, गणित, मनोरंजन एवं वैज्ञानिक अनुसंधानो मे किया जा रहा है कम्प्यूटर का सर्वाधिक उपयोग सूचना तकनीकी आई टी एम मे किया जा रहा है एनीमेसन, ऑडियो, वीडियो तथा विज्ञापन फिल्मों मनोरंजन के क्षेत्र में दूरसंचार तथा एडीटिंग जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है कम्प्यूटर का उपयोग आंकड़ों को इकट्ठा करने उन्हे प्रोसेस करने तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाये प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्टरनेट का ऐसा क्षेत्र. है जिसकी जरूरत आज आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी कम्पनियों के लिए बनी हुयी है आज जबकि प्रत्येक क्षेत्र मे रोजगार के अवसर निरन्तर घट रहे है वही पर कम्प्यूटर के क्षेत्र में रोजगार के असंख्य अवसर उत्पन्न हो रहे है।

हमारा महोबा जिला बुन्देलखण्ड का एक अति पिछड़ा जिला है यहां के अधिकतर लोग मजदूर श्रेणी के है तथा कृषि पर आधारित कार्य करते है। यहां के छात्र-छात्राओं मे विलक्षण प्रतिभा रहने के बावजूद जानकारी तथा सुविधा नही होने के कारण आई टी को अपना कैरियर के रूप मे नही अपना पा रहे है आई0 टी0 आई0 के क्षेत्र मे छात्र-छात्राओ की सुविधा के अनुसार कई कोर्स उपलब्ध है जैसे डी0सी0ए0, पी0जी0डी0सी0ए0, पी0जी0डी0एच0एम0,बी0सी0ए0,एम0सी0ए0,एम0सी0एम0,तथा एम0एस0सी0,आई0टी0।

डी0सी0ए0 –

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है इसे करने की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिऐट है। यह डिप्लोमा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है जो ओ लेबल के समकक्ष होता है डीसीए करने के बाद छात्र डाटा इण्ट्री आपरेटर डाटा प्रोसेसर तथा कम्प्यूटर जाब करने मे सक्षम होता है।

सूच्य है कि जिले मे राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है जिले के ऐसे गरीब छात्र छात्राये जो प्रशिक्षण शुल्क देने मे सक्षम नही है उनके लिए डीसीए कोर्स करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा जनपद में सन् 2005–2006 में इस योजना के तहत 62 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

<u>पी0जी0डी0सी0ए0–</u>

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है इसे करने की न्यूनतम योग्यता स्नातक है। यह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो बी लेबिल के समकक्ष होता है पीजीडीसीए करने के बाद छात्र यदि और पढ़ना चाहे तो उसे एम सी आई टी के द्वितीय वर्ष मे प्रवेश मिल जाता है तथा सहायक प्रोग्रामर कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री आपरेटर, डाटा प्रोसेसर तथा कम्प्यूटर जाब करने मे सक्षम होता है महोबा जनपद में राष्ट्रीय समविकास योजना के अतर्गत सत्र 2005–2006 में 40 छात्र/छात्रा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है।

जनपद में रोजगार के स्वरूपों के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कियें गयें कार्यो को एक सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो कि निम्नवत् है।

तालिका-1.3

जनपद में रोजगार का स्वरूप

जनपद में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा किया गया कार्य

क्र0सं0	मद	2000–2001	01–2002	02–03	03–04	04–05
1.	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	1	1	1	1	1
2.	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की सं0	8072	8042	8152	8940	9423
3.	वर्ष मे पंजीकृत अभ्यर्थियों की सं0	1521	14470	1619	2723	2089
4.	सूचित रिक्तियों की संख्या	15	17	32	10	30
5.	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	6	17	2	9	09

स्त्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका

अध्याय द्वितीय

(भाग - ब)

<u>आधारभूत संरचना की उपलब्धता</u>

१. परिवहन की व्यवस्था

२. विद्युत व्यवस्था

3. स्वास्थ्य सेवायें

४. शिक्षण सस्थाएं

५. जल संसाधन

६. दूरसंचार सेवायें

७. प्रौद्योगिकी संस्थान

८. बैकिंग सुविधा

९. डाक सेवा

१०. बीमा

११. प्रशासनिक व्यवस्था

१२. भण्डारगृह सुविधा

अध्याय–द्वितीय (भाग–ब)
आधारभूत संरचना की उपलब्धता

आधारभूत संरचना वे संसाधन है। जिनके माध्यम से किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाता है। आधारभूत संरचना के अभाव मे टिकाऊ विकास की परिकल्पना दिवास्वप्न के समान है। आधारभूत संरचना ही विकास की नीव का पत्थर है जिस पर उत्तरोत्तर विकास का विशाल महल खड़ा किया जा सकता है। उत्कृष्ट आधारभूत ढांचा जिसमे परिवहन सेवाये, रेलवे, सड़क, पत्तन, सागर, विमान, परिवहन की व्यवस्था के अन्तर्गत इन्हे सड़को की लम्बाई के अन्तर्गत कच्ची व पक्की सड़को मे वर्गीकृत किया गया है। विद्युत परिषद और वितरण संचार सेवाये दूरदर्शन टेलीफोन मोबाइल फोन डाक स्वास्थ्य व स्वच्छता सेवाये शिक्षण संस्थाये जिनमे प्राथमिक, माध्यमिक इण्टर स्नातक परास्नातक संस्थाओं को शामिल किया गया है। जल संस्थान के अन्तर्गत पेयजल कृषि कार्य हेतु सिंचाई आते है। खनिज सम्पदा, प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलिटेक्निक आदि बैंकिग सुविधा बीमा प्रशासनिक व्यवस्था तथा भण्डार गृह सुविधा के अन्तर्गत एफ सी आई सरकारी संस्थानो कृषि उपज आदि को शामिल किया जाता है।

नीतिगत दृष्टिकोण से अब यह एक व्यापक आम सहमति है कि सभी अधारभूत सेवाओं के सीधे तौर पर सरकारी निर्माण से तकनीकी दक्षता, निवेश को पर्याप्त मात्रा प्रयोक्ता प्रभारों के उचित प्रवर्तन और प्रतिर्स्पधात्मिक बाजार ढ़ाचे के सम्बंध मे कठिनाइयां आती है इसके साथ ही एक अनियंत्रित बाजार मे पूरी तरह गैर सरकारी निर्माण के भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नही है। भारत एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा प्राप्त करने की दिशा मे सक्रिय रूप से लगा हुआ है जिसमे निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए पर्याप्त विश्वास व प्रोत्साहन मिल सके परन्तु साथ ही पारदर्शिता और विनिमय के जरिये पर्याप्त अंकुश व सन्तुलन बन सके।

संपूर्ण भारत में आधारभूत संरचना का नितान्त अभाव रहा है जिसमे बुन्देलखण्ड का यह जनपद भी अछूता नही है यहां पर भी आधारभूत संरचना का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है यही कारण है कि जिससे यह जनपद आज भी विकास की दौड़ मे पिछड़ा हुआ है आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया के बाद देश की आधारभूत संरचना मे वृद्धि हुयी है परन्तु फिर भी अभी यह बहुत कम है जनपद की आधारभूत संरचना की उपलब्धता को हम

अग्रलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

1. परिवहन की व्यवस्था 2. विद्युत व्यवस्था 3. स्वास्थ्य सेवायें
4. शिक्षण संस्थायें 5. जल संसाधन 6. दूरसंचार सेवायें
7. प्रौद्योगिकी संस्थान 8. बैकिंग सुविधा 9. डाक सेवा
10. बीमा 11. प्रशासनिक व्यवस्था 12. भण्डारगृह सुविधा

1— परिवहन की व्यवस्था :—

महोबा जिले के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का वर्गीकरण —

जिले का आर्थिक विकास परिवहन के साधनो के बगैर सम्भव नही है। व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक उन्नति को परिवहन के साधनो की आवश्यकता होती है।

हमारे जिले में वायुयान की सुविधा नही है। महोबा का धरातल, पठारी ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीला है यहां आवागमन के साधनों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहां पहुँचने का कोई साधन नही है पुराने जमाने मे लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी,, ऊंट, घोड़ा आदि का प्रयोग करते थे । नदियों में नावों का प्रयोग होता था । अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ट्रेन, बस, ट्रक आदि चलते है। महोबा जनपद मे 7 रेलवे स्टेशन हैं।

हमारे जिले में परिवहन के साधनों में रेल मार्ग का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जिले में मात्र एक रेलवे लाइन है जो कि मध्य रेलवे के अन्तर्गत आती है।

मानिकपुर से झांसी रेल मार्ग —

यह रेल मार्ग हमारे जिले से होकर गुजरता है इस पर कबरई, महोबा, कुलपहाड़ बेलाताल रेलवे स्टेशन आते हैं। यह रेल मार्ग आगे जाकर झांसी से दिल्ली के रेल मार्ग से जुड़ जाता है।

सड़क परिवहन —

1. कच्ची सड़कें 2. पक्की सड़कें

महोबा जिले की प्रमुख सड़के निम्नांकित है —

1.महोबा से चिल्ली मार्ग –

यह कच्ची सड़क है जो महोबा से बम्हौरी, माठा, पसगांव होती हुयी चिल्ली राठ रोड से मिल जाती है।

2.कानपुर से सागर मार्ग –

यह पक्की सड़क है यह सड़क कानपुर, हमीरपुर, कबरई, महोबा होती हुयी सागर तक जाती है।

3.महोबा से चरखारी मार्ग –

यह मार्ग महोबा से बम्हौरी कला होते हुए चरखारी को जाता है।

4.महोबा से राठ मार्ग –

यह मार्ग महोबा, कुलपहाड़, पनवाड़ी, नकरा, पहाड़ी, से होते हुए राठ को जाता है ।

5.महोबा से बांदा मार्ग –

यह मार्ग महोबा से कबरई, रिवई, सुनैचा होते हुए बांदा जाता है।

6.चरखारी से बिंवार मार्ग –

यह मार्ग चरखारी से खरेला गहरौली, इमिलिया, उमरी होता हुआ बिंवार को जाता है।

7.पनवाड़ी से हरपालपुर मार्ग –

यह मार्ग दिदवारा, महोबकंठ राठ आदि नगर होते हुए पनवाडी से हरपालपुर को जाता है।

8.जैतपुर से नौगांव मार्ग –

यह मार्ग अजनर, इन्चौटा, आदि नगर होते हुए जैतपुर से म0प्र0 के नौगांव तक जाता है।

9.चरखारी से सूपा मार्ग –

यह मार्ग रायनगर होते हुए चरखारी से सूपा को और आगे चलकर महोबा राठ मार्ग में मिल जाता है।

जनपद की सड़कों की लम्बाई को एक सारिणी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है ।

तालिका – 2

जनपद की पक्की सडकों की लम्बाई (कि0मी0) I

क्रम0	मद	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5	6
1.	लोकनिर्माण विभाग के अन्तर्गत				
1.1	राष्ट्रीय राज मार्ग	129	129	129	140
1.2	प्रादेशिक राज मार्ग	7	7	7	7
1.3	मुख्य जिला सड़कें	79	79	79	85
1.4	अन्य जिला तथा ग्रामीण सड़कें	469	957	592	692
	योग –	684	1172	807	924
2.	स्थानीय निकायों के अन्तर्गत				
2.1	जिला पंचायत	11	11	11	11
2.2	नगर निगम / नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत/ कैन्ट	37	37	37	37
	योग –	48	48	48	48
3.	अन्य विभागों के अन्तर्गत				
3.1	सिंचाई विभाग	0	0	0	0
3.2	गन्ना विभाग	0	0	0	0
3.3	डी.जी.बी.आर	0	0	0	0
3.4	अन्य विभाग	0	0	0	0
	योग –	–	–	–	–
	कुल योग 1+2+3	932	1220	855	972

तालिका – 2.1

जनपद की पक्की सड़कों की लम्बाई विकासखण्डवार(कि0मी0) II

वर्ष / विकासखण्ड	पक्की सड़कों की लम्बाई कुल	लो0नि0वि0	सब ऋतु योग्य सड़कों में जुड़े ग्रामों की संख्या (जनसंख्या वार)		
			1000 से कम वाले ग्राम	1000 से 1499 वाले ग्राम	1500 से अधिक वाले ग्राम
1	2	3	4	5	6
1999—00	732	684	110	47	75
2000—01	1220	1172	131	61	81
2001—02	855	807	133	78	85
2002—03	972	924	137	86	93
विकासखण्ड वार 2002—03					
1 पनवाड़ी	202	202	35	21	21
2. जैतपुर	195	195	34	18	15
3. चरखारी	217	217	28	14	21
4. कबरई	310	310	40	33	36
योग ग्रामीण	924	924	137	86	93
योग नगरीय	498	0	0	0	0
योग जनपद	972	924	137	86	93

स्त्रोत – जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महोबा
अधि0अधि0 लो0नि0वि0, महोबा

ग्राफ – 2

कुल पक्की सड़कों की लम्बाई

जनपद–महोबा
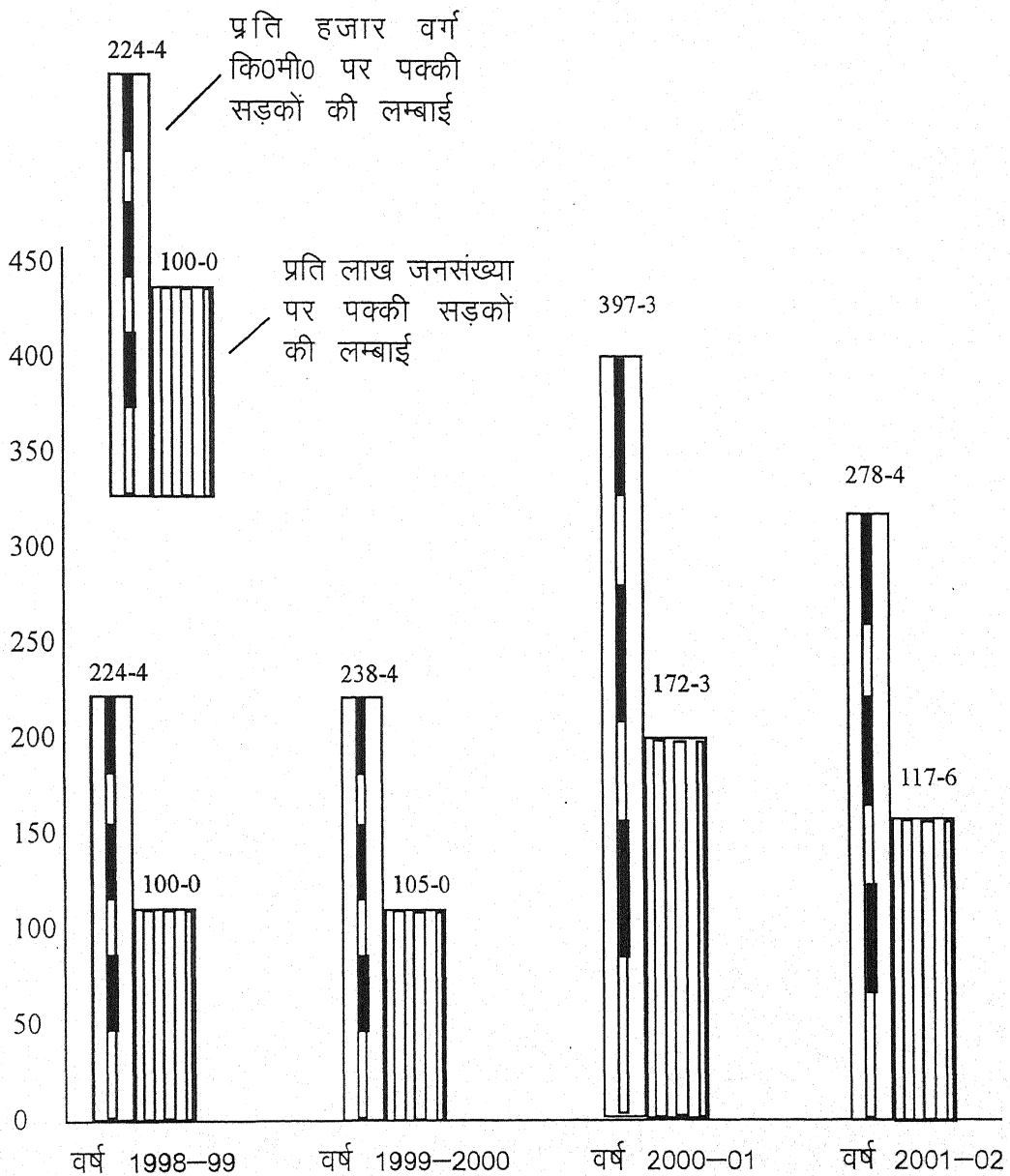
उपर्युक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि जनपद मे पक्की सड़कों की लम्बाई जनसंख्या की अपेक्षा बहुत कम है। आबाद ग्रामों की पहुँच से मुख्य मार्ग काफी दूर है परन्तु केन्द्रीय सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 या इससे अधिक आबादी वाले

ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने का कार्य जनपद में तीव्र गति से हुआ है। तालिका का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उपलब्ध सड़कों की लम्बाई जैतपुर विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों की तुलना मे कम है। 1000 से कम आबादी वाले 133 ग्रामों मे 2002 तक सड़क सुविधा प्राप्त थी वही 1000 से अधिक एवं 1500 से कम आबादी वाले मात्र 78 गांव सड़कों से जुड़े हुए थे इस प्रकार समग्र जनपद मे 296 गॉवों में सड़क सुविधा उपलब्ध थी। जबकि आबाद ग्रामों की संख्या पूरे जनपद मे लगभग 423 है। इस प्रकार आबाद ग्रामों की तुलना मे सड़कों की उपलब्धता वाले गावो का प्रतिशत लगभग 70 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि जनपद मे अभी भी 30 प्रतिशत गॉवों को सड़कों की महती आवश्यकता है ताकि उपलब्ध सड़कों का प्रयोग कर कृषक अपनी उपजों को शहर की मण्डियों तक लाने मे सफल रहें जिससे कि उनको अपनी उपजों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके एवं समय समय पर ग्रामीणो को सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकें। इस सम्बंध मे विस्तृत कार्य योजना बनाकर सरकार को समस्त आबाद ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए साथ ही उपलब्ध सड़को एवं नवनिर्मित की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि आम जनता को उसका पूर्ण लाभ मिल सके। 1998 से 2002 तक सड़कों की लम्बाई को ग्राफ द्वारा पीछे प्रदर्शित किया गया है।

2–विद्युत व्यवस्था :–

विद्युत यानि बिजली की आवश्यकता हमारे जीवन मे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। आज के इस दौर मे बिना विद्युत व्यवस्था के अनेक कार्यो मे रूकावट आती है यदि हमारे शहरों का अवलोकन करें तो वहां विद्युत व्यवस्था काफी सुदृढ़ता लिये हुए है परन्तु यदि हम गांव और बस्तियों की बात करे तो विद्युत व्यवस्था का अच्छा होना या बुरा होना वहां के लिए कोई मायने नही रखता है। आज के इस आधुनिकीकरण दौर मे टीवी जो कि संचार का बहुत बड़ा माध्यम है बिना बिजली के नही चल सकता है। इसके अलावा फ्रिज, बल्ब, पंखे, कूलर आदि बिना सही विद्युत व्यवस्था के नही चल सकती।

परन्तु घरेलू प्रकाश, वाणिज्यिक प्रकाश व्यवस्था, रेल, कृषि हेतु चलित संयत्र आदि के लिए विद्युत की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है निम्नलिखित सारिणी द्वारा जनपद से विभिन्न कार्यो के विद्युत उपभोग को आंका गया है।

तालिका – 2.2

विद्युत

जनपद में विभिन्न कार्यो में उपभोग (हजार कि0वाट घंटा)

क्र0सं0	मद	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	14369	17220	18546	18910	19201	19314
2	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	2951	2990	8054	3370	8394	8448
3	औद्योगिक विद्युत शक्ति	9114	14880	6144	13380	6609	6682
4	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	528	610	2587	1210	2905	3015
5	रेल / ट्रेक्शन	0	0	0	0	0	0
6	कृषि विद्युत शक्ति	8620	15520	3436	5170	3602	3715
7	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्द्धन व्यवस्था	1804	2710	1853	3260	2013	2130
	योग	34398	53530	40620	45300	42724	43324

स्त्रोत :– सांख्यकीय पत्रिका

तालिका – 2.3

विद्युत

जनपद में विभिन्न कार्यो में उपभोग विकासखण्डवार (हजार कि0वाट घंटा) II

वर्ष / विकासखण्ड	एल0टी/एलटीडीएस के अन्तर्गत विद्युतीकृत ग्राम संख्या	विद्युतीकृत अनु0जाति बस्तियो की संख्या	विद्युतीकृत से असेवित अनुजाति बस्तियों की संख्या	ऊर्जीकृत निजी नलकूप / पम्प सेटो की संख्या
1	2	3	4	5
1999–00	250	250	0	574
2000–01	263	263	0	591
2001–02	265	263	0	607
2003–04	272	277	0	635
विकासखण्ड वार				
2002–03				
1 पनवाड़ी	60	59	0	257
2. जैतपुर	66	65	0	107
3. चरखारी	55	35	0	100
4. कबरई	96	96	0	170
योग ग्रामीण	277	277	0	635
योग नगरीय	0	0	0	170
योग जनपद	277	277	0	805

स्त्रोत – 1. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महोबा

2. अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड 2 महोबा

उपर्युक्त सारिणी नं0 2.2 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सन् 2004–05 मे सबसे अधिक घरेलू प्रकाश एवं विद्युत शक्ति में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। सन् 1999 से 2005 तक देखें तो सबसे अधिक खपत इसी मे की जा रही है। 1999 से लेकर अब तक की वृद्धि दर 1999–2000 से 2000–01 तक 16.5 प्रतिशत तथा 2001–02 से 2002–03 तक 1.92 प्रतिशत व 2003–04 से 2004–05 तक यह वृद्धि .58 प्रतिशत हुयी है। इसी प्रकार यदि हम देखे तो सबसे कम विद्युत उपभोग सन् 2000–01 में व इससे पहले सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था मे किया जा रहा है और यह सन् 2004–05 मे सबसे कम विद्युत उपभोग सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्द्धन व्यवस्था मे किया जा रहा है।

इसी प्रकार यदि हम दूसरी सारिणी नं. 2.3 का अवलोकन करें तो सन् 2004–05 मे अनु0जाति की बस्तियों की संख्या 277 है जिसमे करीब 635 नलकूप / पम्पसेटों की संख्या है अब इसका अनुपात देखा जाये तो यह 1:3 की दर से है इससे यदि विकास खण्ड की दृष्टि से देखें तो इसकी संख्या सबसे कम चरखारी मे है यदि हम पनवाड़ी मे देखें तो 56 बस्तिो मे 189 नलकूप अधिक हैं। विद्युतीकृत से असेवित अनु जाति बस्तियों की संख्या यहां नगण्य है।

3. स्वास्थ्य सेवाएं –

मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक महत्व है इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ्य विचारों का विकास होता है अतः जनसंख्या की कार्यक्षमता एवं कुशलता में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें अपना महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। वर्तमान मे स्वास्थ्य सेवाओं को कई रूपों में प्रदान किया जा रहा है जिससे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एलोपैथिक चिकित्सा सेवा, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है।

जनपद में विकासखण्ड वार आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संख्या

तालिका नं. 2.4

वर्ष / विकासखण्ड	आयुर्वेदिक			यूनानी			होम्योपैथिक		
	चिकित्सालय एवं औषधालय	उपलब्ध शैयाओं की संख्या	डाक्टर	चिकित्सालय एवं औषधालय	उपलब्ध शैयाओं की संख्या	डाक्टर	चिकित्सालय एवं औषधालय	उपलब्ध शैयाओं की संख्या	डाक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999–00	10	37	11	1	0	1	6	0	4
2000–01	9	29	10	1	0	1	1	5	4
2001–02	11	41	11	1	0	1	6	2	4
2003–04	11	41	11	1	0	1	7	2	5
2004–05	11	29	10	1	0	1	7	–	4
विकासखण्ड वार									
2003–04									
1 पनवाड़ी	2	4	2	0	0	0	1	0	1
2. जैतपुर	2	4	2	0	0	0	1	0	1
3. चरखारी	2	0	2	0	0	0	2	0	1
4. कबरई	3	0	2	0	0	0	2	0	1
योग ग्रामीण	9	16	8	0	0	0	6	0	4
योग नगरीय	2	25	3	1	0	1	1	2	1
योग जनपद	11	41	11	1	0	1	7	2	5

स्त्रोत – 1 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, महोबा

2. जिला होम्योपैथिक अधिकारी, महोबा

जनपद में विकासखण्ड वार परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र / उपकेन्द्र संख्या

तालिका नं. 2.5

वर्ष / विकासखण्ड	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र
1	2	3
1999—00	4	127
2000—01	4	116
2001—02	4	127
2002—03	4	127
2003—04	4	127
विकासखण्ड वार		
2003—04		
1 पनवाड़ी	1	26
2. जैतपुर	1	24
3. चरखारी	1	34
4. कबरई	1	43
योग ग्रामीण	4	127
योग नगरीय	0	0
योग जनपद	4	127

स्त्रोत — 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

जनपद में ऐलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय संख्या

तालिका 2.6

क्रम	मद	2000–2001	2001–2002	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय सार्वजनिक	21	23	23	23
2	राजकीय विशेष				
2.1	क्षय	0	0	0	0
2.2	कुष्ठ	0	0	0	0
2.3	संक्रामक	0	0	0	0
3	स्थानीय निकाय	0	0	0	0
4	सहायता प्राप्त निजी	0	0	0	0
5	असहायता प्राप्त निजी	0	0	0	0
6	आर्थिक सहायता प्राप्त	0	0	0	0
	योग –	21	23	23	23

स्त्रोत – 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

जनपद में विकासखण्ड वार ऐलोपैथी चिकित्सा सेवा संख्या I

तालिका 2.7

वर्ष / विकासखण्ड	ऐलोपैथिक चिकित्सालय / औषधालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	समस्त उपलब्ध में शैयाओ की संख्या	समस्त मे कर्मचारी		
					डाक्टर	पैरामेडिकल	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1999—00	6	3	14	178	44	200	85
2000—01	7	3	14	160	40	200	85
2001—02	6	3	14	178	44	152	98
2002—03	6	3	14	178	44	152	98
2003—04	6	3	14	178	44	152	98
विकासखण्ड वार							
2003—04							
1 पनवाड़ी	1	1	3	36	8	24	19
2. जैतपुर	1	0	3	12	5	23	16
3. चरखारी	0	0	2	12	7	35	19
4. कबरई	0	0	5	20	4	36	23
योग ग्रामीण	2	1	13	80	24	118	77
योग नगरीय	4	2	1	98	20	34	21
योग जनपद	6	3	14	178	44	152	98

स्त्रोत — 1 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महोबा

जनपद में विकासखण्ड वार ऐलोपैथी चिकित्सा सेवा संख्या II

तालिका 2.8

क्रम सं0	विकासखण्ड	प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय / औषधालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या			प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे उपलब्ध शैयाओं की संख्या		
		2001–02	2002–03	2003–04	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पनवाडी	5.1	4.2	4.2	4.1	30.4	30.4
2	जैतपुर	3.4	3.6	3.6	4.5	10.8	10.8
3	चरखारी	6.6	2.2	2.2	6.8	13.5	13.5
4	कबरई	2.5	3.4	3.4	8.5	13.8	13.8
	समस्त विकासखण्ड	3.1	3.4	3.4	5.3	17.2	17.2

आज के इस वातावरण में जिस प्रकार से व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो रहा है इसका कारण अस्वच्छता, कुपोषण, व भुखमरी है। इन सभी बीमारियों से निपटने के लिए महोबा जनपद मे अनेक प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है जो उक्त सारिणी 2.4 से स्पष्ट होती है। सन् 2003–04 में 11 आयुर्वेदिक चिकित्सालयो मे 11 डाक्टर है अतः 1 चिकित्सालय मे एक डाक्टर की व्यवस्था है। यह संख्या पहले के वर्षो में कम है। इसी प्रकार होम्योपैथिक मे 7 चिकित्सालय मे 5 डाक्टर है जो कि आयुर्वेदिक की संख्या से कम है अतः सरकार को कम से कम 2 अन्य होम्योपैथिक डाक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि हम तालिका 2.7 का अवलोकन करें तो यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या सबसे कम है ऐलोपैथिक चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओ की संख्या 178 है जहां पर 44 डाक्टर व 152 पैरामेडिकल कर्मचारियो की व्यवस्था है। यदि हम विकास खण्डानुसार सन् 2003–04 का अवलोकन करे तो पाते है कि जैतपुर मे डाक्टरों की संख्या सबसे कम 5 है जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य

स्त्रोतः– सांख्यकीय पत्रिका

केन्द्र चरखारी की अपेक्षा जैतपुर मे अधिक है। पनवाड़ी मे केवल 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। सरकार को जैतपुर चरखारी व कबरई मे भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां के लोग इसका लाभ उठा सके। पिछड़ा जनपद होने के कारण सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि इस क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण अस्पतालों मे चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ पूरा रहे ताकि लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को बनाया जा सके।

4. शिक्षण संस्थायें –

शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध होती है एक शिक्षित व्यक्ति के लिए संसार मे सभी अवसर विद्यमान रहते है चाहे स्त्री हो या पुरूष शिक्षा के बिना वह अधूरा है अर्थात् वह समाज मे अपने आपको स्थापित नही कर सकता। सब कुछ होते हुए भी उसको अपने आप मे कमी महसूस होती रहेगी इसके लिए आवश्यक है कि पहले तो लोगो को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए दूसरा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर व साधन होने आवश्यक है। सरकार को प्रत्येक गांव कस्बे व जिले मे शिक्षण संस्थाओ की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह वहां की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर प्राइमरी स्कूल, जूनियर व सीनियर स्कूल हाईस्कूल इण्टरमीडिएट व कालेजो आदि की संस्थाये जनसंख्या के हिसाब से खोलें जिससे वहां के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। शहरो मे तो इसकी पर्याप्त व्यवस्था हो जाती है परन्तु जहां पर इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है वहां पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए जैसे छोटे–छोटे गॉवों आदि। प्रस्तुत सारिणी मे वर्ष के अनुसार तथा विकास खण्डवार वहां की शिक्षण संस्थाओ की संख्या आदि को प्रस्तुत किया गया है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से अत्यन्त कम है जिसमे तत्काल सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी संख्या I

तालिका 2.9

वर्ष / विकासखण्ड	कक्षा 1 से 5 तक				कक्षा 6 से 8 तक			
	छात्र		छात्रायें		छात्र		छात्रायें	
	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000—01	73239	23794	53784	20025	11982	2685	5488	806
2001—02	73592	23125	53768	20072	12221	2699	5535	869
2002—03	72740	20665	50925	18264	15458	4462	9084	2217
2003—04	73643	20835	51146	18475	17184	5504	9336	2475
विकासखण्ड वार								
2003—04								
1 पनवाड़ी	13311	4104	901	3101	3026	1082	1326	497
2. जैतपुर	15121	3762	8997	3012	2890	963	1392	361
3. चरखारी	13763	3803	9413	4017	2961	670	903	281
4. कबरई	18546	5223	13919	4632	3840	1036	1278	332
योग ग्रामीण	60741	16892	41350	14762	12717	3751	4899	1471
योग नगरीय	12902	3943	9796	3713	4467	1753	4437	1004
योग जनपद	73643	20835	51146	18475	17184	5504	9336	2475

क्रमशः

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी संख्या II

तालिका 2.10

वर्ष / विकासखण्ड	कक्षा 9 से 12 तक				स्नातक कक्षा में			
	छात्र		छात्रायें		छात्र		छात्रायें	
	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा
1	10	11	12	13	14	15	16	17
2000—01	13419	1524	3346	371	1469	290	366	77
2001—02	13426	1527	3366	414	1580	205	874	69
2002—03	9205	1507	3582	402	1398	225	983	74
2003—04	10630	2418	6098	809,	1394	211	1092	99
विकासखण्ड वार								
2003—04								
1 पनवाड़ी	1623	420	873	121	0	0	0	0
2. जैतपुर	958	320	353	97	0	0	0	0
3. चरखारी	0	0	0	0	0	0	0	0
4. कबरई	1833	667	967	140	0	0	0	0
योग ग्रामीण	4414	1407	2193	358	0	0	0	0
योग नगरीय	6216	1011	3905	451	1394	211	1092	99
योग जनपद	10630	2418	6098	809	1394	211	1092	99

क्रमशः

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में स्तरवार विद्यार्थी संख्या III

तालिका 2.11

वर्ष / विकासखण्ड	स्नातकोत्तर कक्षा में				औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में			
	छात्र		छात्रायें		छात्र		छात्रायें	
	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा	कुल	अ.जा. / जन.जा
	18	19	20	21	22	23	24	25
2000–01	160	30	18	82	–	–	–	–
2001–02	147	15	118	10	0	0	0	0
2002–03	158	31	120	8	0	0	0	0
2003–04	173	21	113	13	173	28	13	3
विकासखण्ड वार								
2003–04								
1 पनवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
2. जैतपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
3. चरखारी	0	0	0	0	0	0	0	0
4. कबरई	0	0	0	0	0	0	0	0
योग ग्रामीण	0	0	0	0	0	0	0	0
योग नगरीय	173	21	113	13	173	28	13	3
योग जनपद	173	21	113	13	173	28	13	3

स्त्रोत :– सांख्यकीय पत्रिका

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या I

तालिका 2.12

वर्ष / विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय	
	कुल	भवनहीन	कुल	बालिका	कुल	बालिका
1	2	3	4	5	6	7
2000–01	661	0	152	36	37	8
2001–02	698	0	157	36	30	8
2002–03	715	0	182	36	37	8
2003–04	720	0	184	36	37	8
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	153	0	30	6	5	1
2. जैतपुर	150	0	28	5	3	1
3. चरखारी	106	0	29	9	0	0
4. कबरई	200	0	53	9	8	0
योग ग्रामीण	589	0	140	29	16	2
योग नगरीय	131	0	44	7	21	6
योग जनपद	720	0	184	36	37	8

क्रमशः

जनपद में विकासखण्डवार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या II

तालिका 2.13

वर्ष / विकासखण्ड	वैकल्पिक शिक्षाकेन्द्र	महाविद्यालय		स्नातकोत्तर विद्यालय		औद्योगिक प्रशिक्षणकेन्द्र	
		कुल	बालिका	कुल	बालिका	कुल	बालिका
	8	9	10	11	12	13	14
2000–01	0	1	0	1	0	2	0
2001–02	0	1	0	1	0	2	0
2002–03	0	2	0	1	0	2	0
2003–04	87	2	0	1	0	2	0
विकासखण्ड वार							
2003–04							
1 पनवाड़ी	12	0	0	0	0	0	0
2. जैतपुर	23	0	0	0	0	0	0
3. चरखारी	10	0	0	0	0	0	0
4. कबरई	7	0	0	0	0	0	0
योग ग्रामीण	52	1	0	0	0	0	0
योग नगरीय	35	1	0	1	0	2	0
योग जनपद	87	2	0	1	0	2	0

स्त्रोत – 1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा

2. जिला विद्यालय निरीक्षक, महोबा

जनपद में विकासखण्ड वार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक संख्या I

तालिका 2.14

वर्ष / विकासखण्ड	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय	
	कुल	स्त्रियां	कुल	स्त्रियां	कुल	स्त्रियां
1	2	3	4	5	6	7
2001–02	1660	392	556	153	352	72
2002–03	1658	452	562	154	301	68
2003–04	1782	464	580	168	387	97
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	366	61	86	16	47	2
2. जैतपुर	365	96	78	25	27	4
3. चरखारी	348	65	90	25	0	0
4. कबरई	371	110	125	29	73	13
योग ग्रामीण	1450	332	379	95	147	19
योग नगरीय	332	132	201	73	240	78
योग जनपद	1782	464	580	168	387	97

क्रमशः

जनपद में विकासखण्ड वार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक संख्या II

तालिका 2.15

वर्ष / विकासखण्ड	महाविद्यालय		स्नातकोत्तर महाविद्यालय		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
	कुल	स्त्रियां	कुल	स्त्रियां	कुल	स्त्रियां
	8	9	10	11	12	13
2000–01	31	4	4	2	0	0
2001–02	22	4	2	2	0	0
2002–03	24	5	2	0	15	0
2003–04	24	5	2	0	15	0
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	0	0	0	0	0	0
2. जैतपुर	0	0	0	0	0	0
3. चरखारी	0	0	0	0	0	0
4. कबरई	0	0	0	0	0	0
योग ग्रामीण	0	0	0	0	0	0
योग नगरीय	24	5	2	0	15	0
योग जनपद	24	5	2	0	15	0

तालिका नं0 2.16 III

नगर का नाम एवं वर्ग (नगर निगम / नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत / कैण्टोमेन्ट बोर्ड, सेन्सस टाउन)	सम्बंधित तहसील	प्राथमिक विद्यालय मिश्रित	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय बालक	माध्यमिक विद्यालय बालिका	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1. चरखारी एम बी	चरखारी	32	8	3	1	11	1
2. कुलपहाड टी ए	कुलपहाड	19	7	2	1	10	0
3. खरेला टी ए	महोबा	21	4	2	1	0	0
4. कबरई टी ए	महोबा	17	3	1	1	2	0
5. महोबा एम बी	महोबा	42	22	7	2	12	1
योग		131	44	15	6	35	2

स्त्रोतः– 1– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा ।

2– जिला विद्यालय निरीक्षक, महोबा

जनपद में व्यवसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत प्रशिक्षण तालिका 2.17

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थानो के नाम पता एवं टेलीफोन ई–मेल सहित	संस्थानो की प्रकृति निजी / सरकारी या कहां से सम्बंधित	प्रशिक्षण के व्यवसाय के नाम व विवरण	प्रशिक्षण व्य0 की अवधि	शैक्षिक योग्यता	प्रवेश की प्रक्रिया	स्वीकृत सीटों की संख्या	प्रवेश का माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजकीय बालिका इण्टर कालेज फोन 255197	सरकारी	1. परिधान रचना	एक वर्ष	हाईस्कूल	व्यवसायिक विषय हेतु व्यापक प्रचार	–	जुलाई
			2. रंगाई धुलाई	दो वर्ष	हाईस्कूल	व्यवसायिक विषय हेतु व्यापक प्रचार	–	जुलाई
			3. खाद्य संरक्षण	दो पर्ष	हाईस्कूल	व्यवसायिक विषय हेतु व्यापक प्रचार	–	जुलाई
2	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज महोबा	निजी मा0शि0प0इलाहाबाद	1. खाद्य संरक्षण	दो वर्ष	हाईस्कूल	मेरिट के आधार पर	40	जुलाई
			2. फोटोग्राफी	दो वर्ष	हाईस्कूल	मेरिट के आधार पर	40	
3	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी (महोबा)	सरकारी	बी0टी0सी0	दो वर्ष	स्नातक	प्रवेश परीक्षा	100	विज्ञापित होनेपर

स्त्रोत – जिला सेवायोजन कार्यालय, महोबा।

जनपद में कुल शैक्षिक संस्थायें
जनपद – महोबा
ग्राफ – 2.1
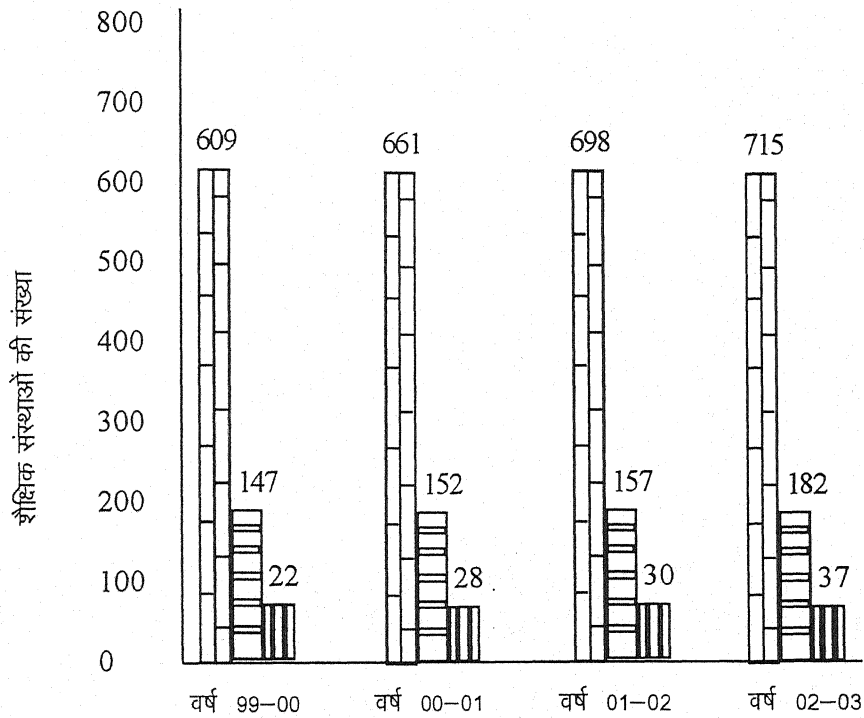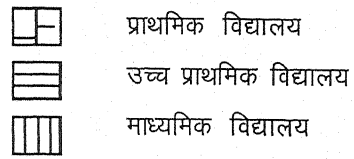
जनपद में कुल छात्रों की संख्या

जनपद – महोबा

ग्राफ – 2.2
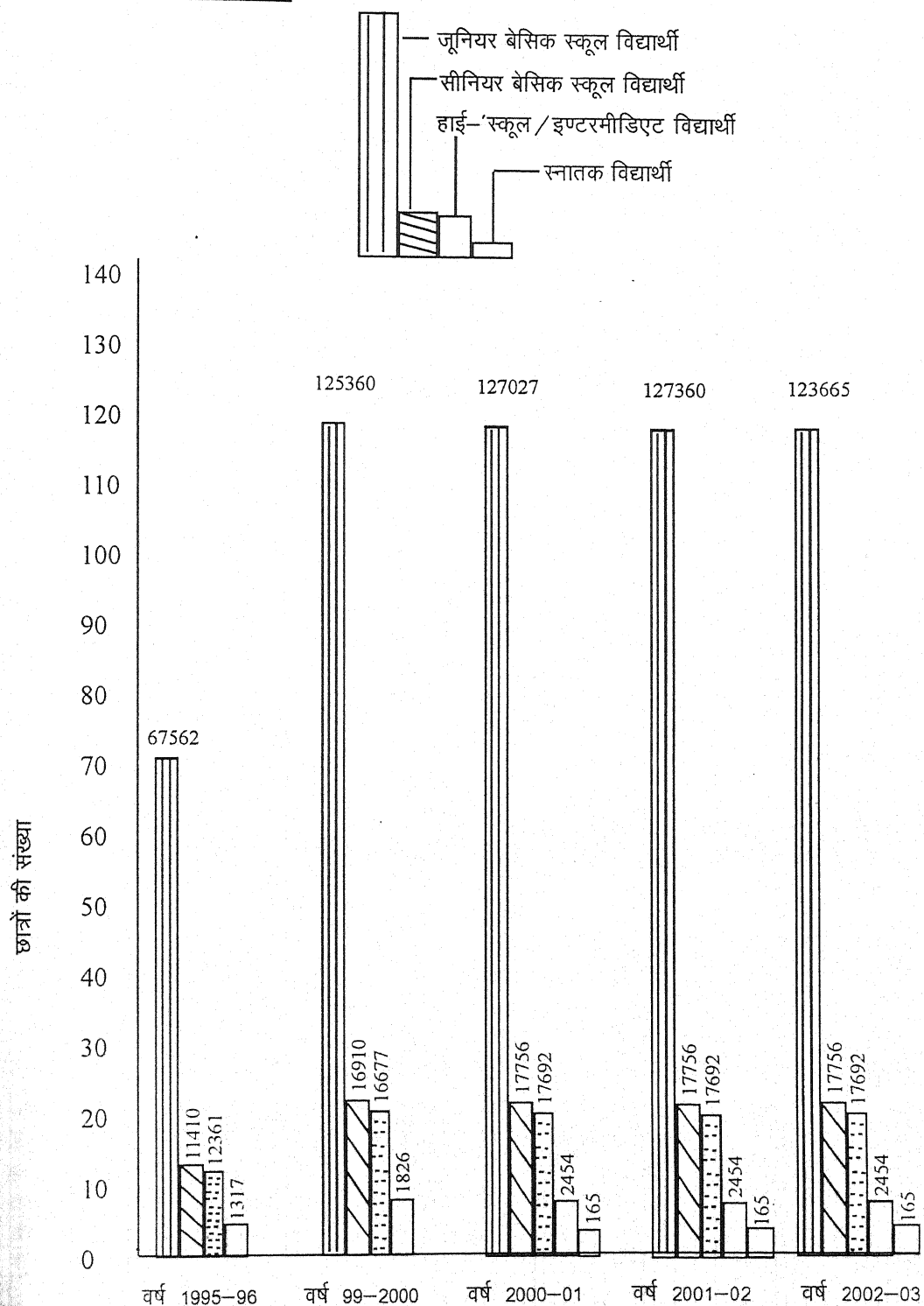
5. जल संसाधन –

जल ही जीवन है यह एक कहावत नही बल्कि सत्यार्थ है क्योंकि बिना जल के कोई भी व्यक्ति जीवित नही रह सकता है जल का उपयोग कई रूपों में होता है जैसे पीने में, बिजली मे, कृषि के लिए व सिंचाई आदि प्रत्येक के लिए जल आवश्यक है। जल को प्राप्त करने के कई साधन है। जैसे- तालाब, नदी, समुद्र, कुँआं, हैण्डपम्प, नल झरनें आदि परन्तु एक स्वच्छ जल ही स्वास्थ्य का आधार है इसके लिए हम केवल कुआं, हैण्डपम्प व नल आदि के जल को ही अपने घरेलू उपयोग मे लाते है इसके लिए आवश्यक है कि हैण्डपम्प नल आदि हमारे आस पास होने चाहिए। यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता है कि वह प्रत्येक जिले गांव कस्बे आदि मे पर्याप्त मात्रा मे हैण्डपम्प लगवाये जिससे कोई भी व्यक्ति इस सुविधा से अछूता न रहे। अतः पेयजल की आपूर्ति जगह जगह पर होनी चाहिए।

जनपद में विकासखण्ड वार ग्रामों में पेयजल सुविधा की स्थिति

तालिका 2.18

वर्ष / विकासखण्ड	नल/हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत ग्राम (संख्या)			सामान्यतया प्रयोग में लाये जा रहे स्त्रोतों के अनुसार ग्रामों की संख्या					
	पूर्णतः आच्छादित	आंशिक आच्छादित	लाभान्वित जनसंख्या	कुऑ	साधारण हैण्डपम्प	हैण्डपम्प इण्डिया मार्क–2	नल	अन्य	योग स्तम्भ 5 से 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000–01	415	0	464291	0	0	415	0	0	415
2001–02	435	0	507365	0	0	435	0	0	435
2002–03	435	0	507365	0	0	435	0	0	435
2003–04	435	0	507365	0	0	435	0	0	435
विकासखण्ड वार 2003–04									
1 पनवाड़ी	120	0	118536	0	0	120	0	0	120
2. जैतपुर	104	0	111222	0	0	104	0	0	104
3. चरखारी	85	0	89215	0	0	85	0	0	85
4. कबरई	126	0	188392	0	0	126	0	0	126
योग ग्रामीण	435	0	507365	0	0	435	0	0	435
योग नगरीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग जनपद	435	0	507365	0	0	435	0	0	435

जनपद में विकासखण्ड वार सिंचाई साधनों एवं स्त्रोतों की 31 मार्च की स्थिति

तालिका 2.19

वर्ष / विकासखण्ड	नहरों की लम्बाई कि0मी0	राजकीय नलकूप	पक्के कुए संख्या	रहट संख्या	भूस्तरीय पम्पसेट संख्या	बोरिंग पर लगे पम्पसेट संख्या	निजी नलकूप संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
2001—02	455	3	15280	0	756	775	30
2002—03	455	3	15360	0	1211	819	30
2003—04	455	3	15370	0	1889	887	36
विकासखण्ड वार							
2003—04							
1 पनवाड़ी	67	0	3120	0	347	134	12
2. जैतपुर	101	0	6501	0	614	0	0
3. चरखारी	104	2	2621	0	274	212	6
4. कबरई	183	1	3128	0	654	541	18
योग ग्रामीण	455	3	15370	0	1889	887	36
योग नगरीय	—	—	—	0	—	—	—
योग जनपद	455	3	15370	0	1889	887	36

स्त्रोत — 1. अधिअभि0 सिंचाई खण्ड, महोबा।
2. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता राजकीय लघु सिंचाई, महोबा।
4. अधि0अभि0 नलकूप खण्ड महोबा।

तालिका 2.20 I

नगर का नाम एवं वर्ग (नगर निगम/ नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत/ कैण्टोमेन्ट बोर्ड/ सेन्सस टाउन)	सम्बंधित तहसील	पब्लिक काल आफिस	टेलीफोन	सामान्यतः पेयजल की सुविधा (हां / नहीं)		
				नल पाइप द्वारा	हैण्डप्म्प इंडिया मार्क –2	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1. चरखारी एम बी	चरखारी	57	2468	हां	हां	हां
2. कुलपहाड टी ए	कुलपहाड	35	632	हां	हां	हां
3. खरेला टी ए	महोबा	24	350	हां	हां	हां
4. कबरई टी ए	महोबा	26	411	हां	हां	हां
5. महोबा एम बी	महोबा	83	2636	हां	हां	हां
योग		225	6497			

तालिका 2.21 II

क्रमांक	सकल सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 2002–03		शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्र.फल से प्रतिशत 2002–03		राजकीय नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित का कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 2002–03	
	विकासखण्ड	संकेतक	विकासखण्ड	संकेतक	विकासखण्ड	संकेतक
1	2	3	4	5	6	7
1	पनवारी	102.9	जैतपुर	61.0	पनवारी	30.9
2	जैतपुर	102.9	पनवारी	50.7	जैतपुर	27.6
3	चरखारी	101.1	कबरई	30.2	कबरई	22.5
4	कबरई	100.8	चरखारी	18.1	चरखारी	17.0

तालिका 2.22 III

क्रमांक	कुल नलकूपो द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल से प्रतिशत 2002–03		प्रति 100 आबादी ग्रामों पर बायो गैस संयत्रो की संख्या 2002–03		विद्युतीकृत कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत 2002–03	
	विकासखण्ड	संकेतक	विकासखण्ड	संकेतक	विकासखण्ड	संकेतक
1	2	3	4	5	6	7
1	कबरई	4.0	चरखारी	285.9	कबरई	73.0
2	पनवारी	0.5	पनवारी	206.7	चरखारी	64.7
3	जैतपुर	0.5	कबरई	186.5	जैतपुर	61.5
4	चरखारी	0.4	जैतपुर	184.6	पनवारी	55.0

पेयजल स्त्रोत - तालिका 2.23 IV

विकासखण्ड	ग्राम में	1 कि0मी0 से कम	1–3 कि0मी0	3–5 कि0मी0	5 कि0मी0 से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1. पनवारी	120	0	0	0	0	120
2. जैतपुर	104	0	0	0	0	104
3. चरखारी	85	0	0	0	0	85
4. कबरई	126	0	0	0	0	126
योग जनपद –	435	0	0	0	0	435

स्त्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका।

उपर्युक्त तालिका में नल या हैण्डपम्प इण्डिया मार्क –2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या पूर्णतः आच्छादित में 2001–02 मे 535 थी जिसमें लाभान्वित 507365 जनसंख्या हुयी यही संख्या 2002–03 में भी 535 रही और लाभान्वितों की जनसंख्या 507365 उतनी ही रही 2003–04 व 2004 में भी इसी अनुपात में है यह संख्या 2000–01 में कम थी जो कि 465 तथा लाभान्वितों की संख्या 464291 थी बाद मे इसमें 84 प्रतिशत की वृद्धि की गयी यदि विकास खण्डवार की तरफ से ध्यान केन्द्रित करे

तो हम पाते है कि चरखारी मे लाभान्वितों की जनसंख्या 89215 है जो कि 85 ग्रामो के अन्तर्गत उन्हे पेयजल सुविधा प्राप्त है विशेषकर गर्मी के मौसम में संपूर्ण जनपद में पानी का जबरदस्त संकट देखने को मिलता है अतः स्वयंसेवी संगठनों को सहकारी संस्थाओं व सरकार के साथ मिलकर वर्षा के पानी का पर्याप्त संग्रहण करने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि जल स्तर को बढाया जा सके । 5 वर्ष का जल का समुचित उपयोग किया जा सके साथ ही बनो के कटाव को रोकना व लोगों को अधिकाधिक वृक्ष लगाने की ओर उत्प्रेरित करना चाहिए।

6. दूरसंचार सेवायें –

आज के इस आधुनिक युग में साथ ही साथ रोजगार की तलाश में संयुक्त परिवार दूर दूर रह रहे है। ऐसे मे यदि उनके पास ऐसा कोई माध्यम हो जिससे वे आपस में बात-चीत कर सकें व्यवसायिक कार्यो मे तो प्रतिदिन लेनदेन होते है और यह आवश्यक नही है कि ये सभी आमने सामने ही हों। इसके लिए जो सेवाये सहयोगी सिद्ध हुयी है वे है दूरसंचार सेवायें। जिनके कई माध्यम हैं टेलीफोन, रेडियो, ईमेल, मोबाईल, फैक्स, डाकतार पीसीओ तारघर आदि ये सभी व्यक्तियों को आपस मे जोड़े हुए है क्योंकि व्यक्ति कमाई करने व अन्य कारणों से अपने घर से दूर रहता है जिसके लिए ये सभी सेवायें सहायक हुयी है। इसके लिए आवश्यक है कि गांव शहरों आदि मे सरकार को इसकी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। महोबा जनपद में इस समय बीएसएनएल, हच, एयरटेल, रिलायन्स, आदि के टावर हैं। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन आदि की सुविधा विद्यमान है। इसी प्रकार व्यापारिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गतिमान करने में दूरसंचार सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है यही कारण है कि 21वीं शताब्दी में दूरसंचार के क्षेत्र में अकल्पित क्रान्ति का वातावरण उत्पन्न हुआ है जिससे जन सामान्य, व्यापारिक औद्योगिक वर्ग ने विकास के नये कीर्तिमान स्थापित किये है तथा प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ है।

जनपद में विकासखण्डवार यातायात एवं संचार सेवायें संख्या

तालिका 2.24

वर्ष / विकासखण्ड	डाकघर	तारघर	पीसीओ	टेलीफोन	रेलवेस्टेशन / हाल्ट बस	बस स्टेशन / स्टाप
1	2	3	4	5	6	7
2000–01	85	4	250	5827	7	61
2001–02	92	4	312	5949	7	68
2002–03	92	4	406	7243	7	81
2003–04	92	4	411	7444	7	84
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	20		70	301	1	14
2. जैतपुर	15		47	260	2	17
3. चरखारी	14	0	37	175	1	8
4. कबरई	35	1	55	310	2	40
योग ग्रामीण	84	0	209	1046	6	79
योग नगरीय	8	0	202	6398	1	5
योग जनपद	92	1	411	7444	7	84

3

स्त्रोत – 1. अधीक्षक, डाक4 एवं तार महोबा।

2. सहायक अभियन्ता, टेलीफोन, महोबा।

7– प्रौद्योगिकी संस्थान

पॉलीटेक्निक परीक्षा के पाठ्यक्रमों के नाम

पाठ्यक्रम का नाम		अवधि
अ.	डिप्लोमा इंजीनियरिंग टैक्नालाजी पाठ्यक्रम	3 वर्षीय
ब.	एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग	3 वर्षीय
स.	फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेन्ट टैक्नालाजी	3 वर्षीय
1.	होम साइंस	
2.	टैक्सटाइल डिजाइन	
3.	टैक्सटाइन डिजाइनिंग प्रिंटिंग	
द.	मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटियल प्रैक्टिस	2 वर्षीय
य.	लाइब्रेरी एण्ड इनफारमेशन साइंस	2 वर्षीय
र	डिप्लोमा इन फार्मेसी	2 वर्षीय
ल	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नालाजी टिशू कल्चर	1 वर्षीय
व	पी जी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	2 वर्षीय
	1. पी जी डिप्लोमा इन मार्केटि।ग एण्ड सेल्स मैनेजमेन्ट	1 वर्षीय
	2. पी जी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेन्ट	1 वर्षीय
	3. पी जी डिप्लोमा इन टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेन्ट	1 वर्षीय
	4. पी जी डिप्लोमा इन ब्यूटी एण्ड हेल्थकेयर	1 वर्षीय
	5. पी जी डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एण्ड	

	पब्लिक रिलेशन	1 वर्षीय
स.	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टैक्नालाजी	3 वर्षीय
द	डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीरियरिंग	3 वर्षीय
य	पोस्ट डिप्लोमा इन इनफारमेशन टैक्नालॉजी	1 वर्षीय

सन् 2005 मे संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक) के पाठ्यक्रम इलेक्ट्रानिक्स इन्जीरियरिंग मे 30 सीटें थी तथा मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन मे भी 30 सीटें थी।

डिप्लोमा इंजीनियर टैक्नालॉजी पाठ्यक्रम

तालिका 2.25

सीटो की संख्या	30	30	30
वर्ष	यांत्रिक अभि0	विद्युत अभि0	इलेक्ट्रानिक्स अभि0
वास्तविक प्रवेश			
2002–03	41	31	43
2003–04	43	30	41
2004–05	34	32	29
2005–06	29	26	30

स्त्रोतः– जिला सेवायोजन पत्रिका

इसके बाद जनपद के विभिन्न तकनीकी संस्थानों को एक सारिणी के माध्यम से अग्रलिखित दर्शाया गया है ।

तालिका 2.26

जनपद के तकनीकी संस्थान

क्रम सं0	प्रशिक्षण संस्थानो के नाम पता एवं टेलीफोन ई–मेल सहित	संस्थानो की प्रकृति निजी /सरकारी या कहां से सम्बंधित	प्रशिक्षण के व्यवसाय का नाम व विवरण	प्रशिक्षण की अवधि	शैक्षिक योग्यता	प्रवेश की प्रकिया	स्वीकृत सीटों की संख्या	प्रवेश का माह
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजकीय पॉलीटेक्निक महोबा	राजकीय	1. इलेक्ट्रिकलइंजी.	त्रिवर्षीय	हाईस्कूल	संयुक्त प्रवेश परीक्षा	30	जुलाई
			2. मैकेनिकल इंजी	त्रिवर्षीय	हाईस्कूल		30	
			3. इलैक्ट्रानिक्स इंजी	त्रिवर्षीय	हाईस्कूल		30	
2	राज0औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पास महोबा दूरभाष 05281–254765	सरकारी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश श्रम विभाग	1. फिटर दो यूनिट	दो वर्षीय	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	32	जुलाई
			2. वायरमैन दो यूनिट एनसीबीटी	दो वर्ष	हाईस्कूल	प्रवेश परीक्षा	32	जुलाई
			3. मैके मो व्हीकल एक यूनिट	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता मेरिट	16	जुलाई
			4. आशुलिपि हिन्दी एक यूनिट	एक वर्ष	इण्टर सा0हिन्दी	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	जुलाई
			5. इलेक्ट्रानिक्स महिला एक यूनिट	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	जुलाई
			6. कटिंग टेलरिंग महिला एक यूनिट	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	जुलाई
			7. इम्बाइडी महिला एक यूनिट	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	मार्च
			8. हिन्दी टंकण	छह माह	इण्टर	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	24	सितम्बर
3	राज0 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरखारी, महोबा	सरकारी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश श्रम विभाग	एस सी वी टी					
			1. फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	32	अगस्त
			2. वायरमैन	दो वर्ष	हाईस्कूल	प्रवेश परीक्षा	16	अगस्त
			3. मैके0मो0व्हीकल	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता मेरिट	16	अगस्त
			4. इलैकिटशियन	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	अगस्त
			5. ड्राफ्टमैन सिविल	दो वर्ष	हाईस्कूल	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	अगस्त
			6. वेल्डर गेस एण्ड इलैक्ट्रिक	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	12	अगस्त
			7. कारपेन्टर	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	अगस्त
			8. मैकेनिक ट्रेक्टर	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	अगस्त
			9. कटिंग टेलरिंग पुरूष महिला	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	32	अगस्त
			एन सी वी टी					
			1. वायरमैन	दो वर्ष	हाईस्कूल	प्रवेश परीक्षा	16	अगस्त
			2. मैकेनिक ट्रेक्टर	एक वर्ष	आठ पास	शैक्षिक योग्यता (मेरिट)	16	अगस्त
4	हमीदिया मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पनवाड़ी, महोबा	निजी तंत्र द्वारा निर्देशक यू पी एम वी टी लखनऊ	1. कम्प्यूटर आपरेटर तथा प्रोग्रामिक असिस्टैन्ट	एक वर्ष	इण्टर	प्रवेश परीक्षा	16	अगस्त
			2. फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल	प्रवेश परीक्षा	16	अगस्त
			3. वेल्डर	एक वर्ष	आठ पास	साक्षात्कार	16	अगस्त

स्रोत – जिला सेवायोजन कार्यालय, महोबा

9. बैकिंग सुविधा –

बैकिंग कोई नया व्यवसाय नही है प्राचीन काल मे आज जैसे बैंक नही थे परन्तु बैकिंग का कार्य अनेक देशों में महाजन सुनार सर्राफ आदि किया करते थे। जिस प्रकार बैको का विकास धीरे धीरे हुआ है उनके कार्यो का विस्तार भी धीरे धीरे होता जा रहा है प्राचीन काल मे बैंकर आरम्भ मे केवल मुद्राओं का अदल बदल ही करते थे बाद मे वे लोगों से ब्याज पर ऋण भी स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे ऋण देना व साख पत्रो का विकास हुआ। ये बैंक जमा को स्वीकार करते थे जिसमें ये चालू खाता निश्चित कालीन जमा खाता, बचत खाता गृह बचत खाता व अनिश्चितकालीन जमा खाते खोलकर जनता को बचत के प्रति प्रोत्साहन व बचत को सुरक्षित रखने का कार्य करते है। इसके अलावा बैंक ऋण देना अग्रिम धन नकद साख अधिविकर्ष व विनिमय बिलों को भुगतान का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से बैंक बहुत उपयोगी है। आधुनिक रूप मे नौ प्रकार के बैंक है वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, कृषि बैंक, सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक, देशी बैंकर्स, बचत बैंक, केन्द्रीय बैंक आदि प्रमुख हैं जो लोगों को बैकिंग सम्बंधी अनेक सुविधाये प्रदान करते है। महोबा जिले मे जो बैकिंग संस्थान है जिनकी शाखाये निम्न है भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, छत्रसाल ग्रामीण बैंक, को–ऑपरेटिव बैंक जिला सहकारी बैंक, अरबन कोआपरेटिव बैंक की शाखा आदि है ।

जनपद के बैंकों की शाखाओं को अग्रलिखित सारिणी द्वारा दर्शाया गया है ।

जनपद में विकासखण्ड अनुसूचित व्यवसायिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या

तालिका 2.27

वर्ष / विकासखण्ड	राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखायें	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें
1	2	3	4
2001–02	17	18	0
2002–03	17	18	0
2003–04	17	18	0
विकासखण्ड वार			
2003–04			
1 पनवाड़ी	2	5	0
2. जैतपुर	2	2	0
3. चरखारी	2	2	0
4. कबरई	2	4	0
योग ग्रामीण	8	13	0
योग नगरीय	9	5	0
योग जनपद	17	18	0

जनपद में व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (,000 रूपये) तालिका 2.28I

क्रम सं0	मद	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1	जमा धनराशि	2229000	28264	26404
2	कुल ऋण वितरण	847100	10134	17330
3	जमा धनराशि मे ऋण वितरण का प्रतिशत	38	36	66
4	प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण			
4.1	कृषि तथा कृषि से सम्बंधित कार्य	602800	754817	13691
4.2	लघु उद्योग	22000	29538	394
4.3	अन्य	91500	103929	1361
	योग – 4.1 – 4.3	716300	888284	15446

स्त्रोत – लीड बैंक, अधिकारी महोबा।

जनपद में व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (,000 रूपये) तालिका 2.29 II

क्रम सं0	विकास खण्ड	प्रति व्यवसायिक बैंक शाखा पर जनसंख्या 1990–91	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1	पनवाड़ी	59268	16934	16934
2	जैतपुर	556	27806	27806
3	चरखारी	44607	22304	22304
4	कबरई	145318	24220	24220
	समस्त विकास खण्ड	249749	91264	91264

जनपद में व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (,000 रूपये) तालिका 2.30 III

नगर का नाम एवं वर्ग (नगर निगम/नगरपालिका परिषद/ नगर पंचायत/ कैण्टोमेंट बोर्ड/ सेन्सस टाउन)	सम्बंधित तहसील	ग्रामीण बैंक शाखायें	सहकारी बैंक शाखायें	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक शाखायें	डाकघर	तारघर
1	2	3	4	5	6	7
1	चरखारी	1	1	0	2	1
2	कुलपहाड	1	1	1	1	1
3	चरखारी	1	1	0	2	0
4	महोबा	1	1	0	1	0
5	महोबा	1	2	1	2	1
योग		5	6	2	8	3

जनपद में व्यवसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण (,000 रूपये) तालिका 2.31 IV

विकासखण्ड	ग्राम में	1 कि0मी0 से कम	1–3 कि0मी0	3–5 कि0मी0	5 कि0मी0 से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1. पनवाडी	6	0	11	37	66	120
2. जैतपुर	3	0	2	9	90	104
3. चरखारी	4	0	2	8	71	85
4. कबरई	6	0	2	18	100	126
योग जनपद	19	0	17	72	327	435

स्त्रोतः– लीड बैंक अधिकारी महोबा ।

जनपद में सहकारी बैंक तथा सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक

31 मार्च की स्थिति

तालिका 2.32

क्रम सं0	मद	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1	जिला सहकारी बैंक			
1.1	शाखायें	10	11	11
1.2	सदस्यता	111	111	111
1.3	हिस्सा पूंजी (000 रूपय)	10709	12631	18774
1.4	कार्यशील पूंजी (000' रूपय)	458268	930385	1095005
1.5	ऋण वितरण (000' रूपय)			
1.5.1	अल्पकालीन	86704	87793	98677
1.5.2	मध्यकालीन	874	222	1133
2.	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक			
2.1	शाखाये	2	2	2
2.2	सदस्यता	12644	13230	13749
2.3	हिस्सा पूजी (000' रूपय)	11332	15097	16597
2.4	कार्यशील पूंजी (000' रूपये)	173968	186274	188481
2.5	ऋण वितरण (000' रूपय)	42065	62611	39561

स्त्रोत – 1. प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, महोबा
2. प्रबन्धक, सह0कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, महोबा

9 डाक सम्बंधी सेवायें –

महोबा जनपद मे डाक सम्बंधी सभी सेवायें उपलब्ध है डाक घर में रजिस्ट्री स्पीडपोस्ट साधारण डाक, तार सेवा यू पी सी, फैक्स आदि सभी सेवायें उपलब्ध है इसके अलावा डाकघर एक बैंक का कार्य भी करता है इसके द्वारा बहुत सी बचत योजनायें चलायी जाती है। तथा खाते खोले जा सकते है। जैसे टाइम डिपाजिट स्कीम, रिकरिंग डिपाजिट खाता, किसान विकास पत्रों में मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम, बचत बैंक खाता एवं लोक भविष्य निधि जारी खाते खोले जा सकते हैं तारघर केवल महोबा मे एक है।

डाकघरों की संख्या –

शहरी क्षेत्र – 08

ग्रामीण क्षेत्र – 11

डाक घर की बचत योजनाओं मे पहली योजना टाइम डिपाजिट योजना है जो कि 5 वर्षीय है जिन लोगों ने 02.09.1993 से 31.12.1998 तक खाता खोला है या इसके पश्चात् खोला है तो उनके खातों पर देय वार्षिक ब्याज की दर निम्न सारिणी द्वारा प्रस्तुत है।

1. डाकघर टाइम डिपाजिट खातों पर देय वार्षिक ब्याज (प्रतिशत में)

खाता खोलने की तिथि	1 वर्षीय	2 वर्षीय	3 वर्षीय	5 वर्षीय
2.9.1993 से 31.12.98 तक	10.5	11	12	12.5
01.1.99 से 14.1.2000 तक	9	10	11	11.5
15.1.2000 से 28.2.2001तक	8	9	10	10.5
1.3.2001 से 28.2.2002 तक	7.5	8	9	9
1.3.2002 से 28.2.2003 तक	7.25	7.5	8.25	8.5
01.3.2003 से	6.25	6.5	7.25	7.5

ब्याज की गणना त्रैमासिक किन्तु ब्याज का भुगतान वार्षिक किया जाता है ।

2. 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता

2. 5 वर्षीय आवर्ती जमा खाता

(रिकरिंग डिपाजिट एकाउण्ट)

खाता खोलने की तिथि	100 रूपये के खाते का 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य	ब्याज दर
2.9.1993 से 31.12.98 तक	8334.00	12.50 %
01.1.99 से 14.1.2000 तक	8111.50	11.50 %
15.1.2000 से 28.2.2001तक	7896.00	10.50 %
1.3.2001 से 28.2.2002 तक	7585.30	9.00 %

1.3.2002 से 28.2.2003 तक	7484.90	8.50 प्रतिशत
01.3.2003 से	7289.00	7.50 प्रतिशत

इसमे भी ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है आवर्ती जमा खाते को परिपक्वता अवधि 5 वर्ष के पश्चात् समान रूप से किश्ते जमा कर या बिना किश्ते जमा किये चालू रखा जा सकता है।

3. किसान विकास पत्र –

किसान विकास पत्र धारक का खरीदने की तिथि उसकी परिपक्वता अवधि और उस पर मिलने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर को एक सारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

खरीदने की तिथि	परिपक्वता अवधि	वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर
2.9.1993 से 31.12.98 तक	5 1/2 वर्ष	13.43
01.1.1999 से 14.1.2000 तक	6 वर्ष	12.25
15.1.2000 से 28.2.2001तक	6 1/2 वर्ष	11.30
1.3.2001 से 28.2.2002 तक	7 1/4 वर्ष	10.03
1.3.2002 से 28.2.2003 तक	7 वर्ष 8 माह	9.46
01.3.2003 से	8 वर्ष 7 माह	8.40

4. 6 वर्षीय मासिक आय योजना खाता (एम आई एस एकाउण्ट)

खोले गये खाते की तिथि	वार्षिक ब्याज प्रतिशत में
2.9.1993 से 31.12.98 तक	13 प्रतिशत
01.1.1999 से 14.1.2000 तक	12 प्रतिशत
15.1.2000 से 28.2.2001तक	11 प्रतिशत
1.3.2001 से 28.2.2002 तक	9.5 प्रतिशत
1.3.2002 से 28.2.2003 तक	9 प्रतिशत
01.3.2003 से	8 प्रतिशत

5. 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम उनकी परिपक्वता मूल्य सारिणी

खोले गये खाते की तिथि	छमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत में
2.9.1993 से 31.12.98 तक	12 प्रतिशत
01.1.1999 से 14.1.2000 तक	11.5 प्रतिशत

15.1.2000 से 28.2.2001तक	11 प्रतिशत
1.3.2001 से 28.2.2002 तक	9.5 प्रतिशत
1.3.2002 से 28.2.2003 तक	9 प्रतिशत
01.3.2003 से	8 प्रतिशत

7. डाकघर में बचत खातो में देय ब्याज

खातों के प्रकार	1.3.2001 से वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में	अन्य विवरण
1. व्यक्तिगत खाते 2. ग्रुप एकाउण्ट 3. सिक्योरिटी डिपाजिट एकाउण्ट 4. ऑफिसियल कैपिसिटी एकाउण्ट	3.5 प्रतिशत 3.5 प्रतिशत 3.0 प्रतिशत 2.0 प्रतिशत	सिंगल खाते मे 1,00,000 रूपये तथा ज्वाइण्ट खाते मे 2,00,000 तक जमा रख सकते हैं।

8. 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता

वित्तीय वर्ष 1986–87 से 14.1.2000 तक ब्याज दर 12 प्रतिशत रही।

15.1.2000 से 28.2.2001 तक ब्याज की दर 11 प्रतिशत रही है।

01.3.2001 से 28.2.2002 तक ब्याज की दर 9.5 प्रतिशत रही है।

01.3.2002 से 28.2.2003 तक ब्याज की दर 9 प्रतिशत रही है।

01.3.2003 से ब्याज की दर 8 प्रतिशत रही है।

9. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की जमा योजना 1989

तिथि	ब्याज दर प्रतिशत में
01.01.99 से 28.2.2001	9 प्रतिशत
01.3.2001 से 28.2.2002	8.5 प्रतिशत
01.3.2002 से 28.2.2003	8 प्रतिशत
01.3.2003 से	7 प्रतिशत

9. बीमा सम्बंधी सेवायें –

महोबा जनपद मे बीमा की भी पूर्ण व्यवस्था की गयी है बीमा हमें न केवल बचत करने में प्रोत्साहित करता है बल्कि बचत करने के लिए भी बाध्य करता है। बीमा के अन्तर्गत जीवन बीमा के साथ साथ निम्नलिखित बीमा होते है जो किसी व्यक्ति के जीवन को तथा उसकी वस्तुओं मे होने वाली हानि को सुरक्षित करते हैं इन सभी का वर्णन निम्नलिखित है –

1. जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
2. ग्रामीण दुर्घटना बीमा
3. राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना
4. भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा
5. किसान पैकेज पॉलिसी
6. मेडीक्लेम इन्श्योरेन्स
7. जन आरोग्य बीमा पॉलिसी
8. गृहस्वामियों के लिए बीमा
9. दुकानदारों के लिए बीमा पॉलिसी
10. तकनीकी कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये अनूठी बीमा योजना
11. यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना

1. जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा –

यह पॉलिसी 10 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवसाय आय आदि को देखे बिना जारी की जा सकती है।

	सुविधायें	क्षतिपूर्ति की दर
अ.	दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	100 प्रतिशत
ब.	दुर्घटना के कारण दो अंगों/दोनों आंखों की दृष्टि/एक आंख एवं एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर	100 प्रतिशत

	सुविधायें	क्षतिपूर्ति की दर
स	दुर्घटना के कारण एक हाथ या पैर के उपयोग की / एक आख की दृष्टि की संपूर्ण एवं अपूरणीय वापिस न आ सकने योग्य क्षति होने पर	50 प्रतिशत
द	दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर	100 प्रतिशत

प्रीमियम की दर – न्यूनतम प्रीमियम 15 रूपये है।

इस बीमा के अन्तर्गत लम्बी अवधि के लिए पॉलिसी अधिकतम 5 वर्षो हेतु जारी की जा सकती है।

बीमा की राशि	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
25000	15	29	41	51	61
50,000	30	57	81	102	120
75,000	45	86	115	153	180
एक लाख	60	114	162	204	240
दो लाख	120	228	324	408	480
तीन लाख	180	342	486	612	720

स्त्रोत – दि ओरियण्टल कम्पनी लिमिटेड।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बीमा राशि की दर को बढ़ाया गया है उसी प्रकार से इन वर्षा की राशियों मे बढता हुआ परिवर्तन आया है।

इसमें ग्रुप पॉलिसियों पर निम्नलिखित प्रकार से छूट दी गयी है।	
व्यक्तियों की संख्या	छूट का प्रतिशत
101 से 1000 तक	5
1001 से 10,000 तक	7.5
10,001 से 50,000 तक	10
50,001 से एक लाख तक	12.5
एक लाख एक से दो लाख तक	15
दो लाख एक से पांच लाख तक	20
पॉच लाख एक से दस लाख तक	25
दस लाख से ऊपर	30

समूह ग्रुप पॉलिसियों के लिए किश्तों की सुविधा स्वीकार्य नही है।

इसमे किसी प्रकार की कोई अन्य छूट जैसे नो क्लेम अथवा नो क्लेम डिस्काउण्ट नही दिया जाता है ।

2. ग्रामीण दुर्घटना बीमा –

यह पॉलिसी 10 वर्ष से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले किसी भी व्यक्ति को उसके व्यवसाय आय आदि को देखे बिना जारी की जा सकती है।

3. राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना –

यह एक अनूठी बीमा योजना है जो कि महिलाओं के समुचित कल्याण को मद्देनजर रखते हुए बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बहुत ही अल्प प्रीमियम राशि देकर सभी वर्ग की महिलाओं को बीमा संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। बीमित महिला के पति की दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा बीमित महिला की स्थायी अपंगता हो जाने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाती है इसके अलावा अन्य ऐच्छिक जोखिमो के खिलाफ सरक्षण प्रदान करने का भी प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत 10 से 75 वर्ष की सभी वर्ग की महिलाओं को बीमा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना से कई लाभ है बाहरी एवं दृष्टिगत कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं जैसे डूबने, पहाड़ों पर से फिसल जाने, चट्टानों से खिसकने, जीव जन्तुओं तथा सांप इत्यादि के काटने से या प्राकृतिक आपदाओं से अथवा हत्या उपद्रव व आतंकवादी गतिविधियो से बीमित महिला की मौत या स्थायी अपंगता होने पर आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाती है।

इसके अलावा विभिन्न शल्य क्रियायें जैसे बंध्याकरण, सिजेरियन कैंसरग्रस्त बच्चेदानी व स्तनो को निकालने व बच्चे के जन्म के समय महिला की मृत्यु व स्थायी अपंगता होने पर भी आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्राविधान है बशर्ते असपताल या नर्सिंग होम में शल्यक्रिया के दौरान या उससे सात दिन के दौरान महिला की मृत्यु अस्पताल या नर्सिंग होम मे हो।

4. भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा –

बालिकाओं के कल्याण के लिए एक अनूठी बीमा योजना है। जिसके अन्तर्गत मात्र 15/– प्रतिवर्श की दर से बालिका के माता/पिता या दोनो की दुर्घटना से मृत्यु होने पर सरक्षण प्रदान करती है।

1. 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु पूरी करने तक बालिका के परवरिश हेतु उनके माता पिता या संरक्षक को रूपये 1200/– प्रतिवर्ष बालिका के भर पोषण हेतु।
2. 6 से 11 वर्ष की आयु पूरी करने तक बालिका की प्राथमिक शिक्षा हेतु उसके माता / पिता या संरक्षक को रूपये 1200/– प्रतिवर्ष।
3. 12 से 17 वर्ष की आयु पूरी करने तक बालिका के शिक्षण हेतु उसके माता पिता या सरक्षक को रूपये 2400/– प्रतिवर्ष।

5. किसान पैकेज पॉलिसी –

इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसान का मकान व उसके पास सामान्यतः वस्तुओं का बीमा किया जाता है। इस तरह एक ही पॉलिसी मे चीजों का बीमा हो जाने से किसान

की सुविधा होती है।

6. मेडीक्लेम इन्श्योरेन्स –

यह एक ऐसा कवर है जो निम्नलिखित स्थितियों मे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर किये गये चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति का आश्वासन देता है।

अचानक बीमार हो जाने पर, कोई दुर्घटना हो जाने पर कोर्ठ ऑपरेशन होने पर जो कि पॉलिसी की अवधि के दौरान उठने वाली किसी बीमारी के सम्बंध मे करना जरूरी है।

यह पॉलिसी 5 से 90 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति को कवर करती है यदि 70 वर्ष से ऊपर की उम्र वाला कोई व्यक्ति यह पॉलिसी लेना चाहे तो ऊपर की आयु के लिए प्रीमियम लोड किया जाता है । 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी तीन माह की आयु से कवर किये जा सकते है।

7– जन आरोग्य बीमा पॉलिसी

यह पॉलिसी जनता को ध्यान में रख कर बनाई गई है । गरीब लोग पैसे की कमी के कारण कई बार अपनी बीमारी का समुचित इलाह नही करवा पाते और पीड़ा सहते रहते हैं । इस योजना के अर्न्तगत रु0 5000/– तक इलाज/नर्सिंग होम/पैथॉलाजी की लागत की भरपाई की जाती है ।

8. गृहस्वामियों के लिए बीमा –

गृहस्वामियों के लिए बीमा पॉलिसी एक व्यापक कवर है जिसके अन्तर्गत घर एवं उसमें रखी गयी विविध वस्तुओं को अनेकों जोखिम के विरूद्ध संरक्षण दिया गया है यह ऐसी पॉलिसी है जो अनेक आकस्मिकताओं को कवर करती है।

9. दुकानदारों के लिए बीमा पॉलिसी –

यह एक व्यापक विशेष रूप से तैयार की गयी पॉलिसी है जो अनेक प्रकार की जोखिमों एवं आपदाओं के कारण होने वाली हानि को कवर करने का प्रयत्न करती है। यह दुकानदारों को अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त रखते हुए उसका ध्यान व्यवसाय को चलाने मे केन्द्रित रखने मे उसकी सहायता करता है। यह पॉलिसी 11 खण्डों मे विभाजित की गयी है।

10.तकनीकी कॉलेजों मे पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनूठी बीमा योजना

आज हम जिस तरह के वातावरण मे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें किसी भी समय कही भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। यद्यपि कोई भी दुर्घटना को टाल तो नही सकता पर उससे बचने के उपाय जरूर कर सकता है। सुरक्षा के

दूसरे उपायों के साथ एक महत्वपूर्ण उपाय है। बीमा जो कई प्रकार से लोगों का बचाव कर सकता है। दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान मे रखते हुए और उनसे बचने के उपायो के लिए ओरियण्टल कम्पनी द्वारा तकनीकी कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष सामूहिक नागरिक सुरक्षा पॉलिसी तैयार की है जो सिर्फ उन्ही छात्रो को दी जायेगी जो राज्य के तकनीकी कालेजो जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, आयुर्वेदिक पॉलिटेक्निक तथा विभिन्न मैनेजमेंट कालेज मे पढ़ाई कर रहे है। कुल मिलाकर लगभग एक लाख रूपये प्रतिवर्ष का भार एक बच्चे की पढ़ाई पर आता है।

बीमाकृत छात्र की पॉलिसी की अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु या अपंगता हो जाती है तो माता पिता को अपने बच्चे की मृत्यु या अपंगता का गम तो उठाना ही पड़ता है साथ ही फीस जो उन्होंने उसकी पढ़ाई पर खर्च की होती है उसका भी वित्तीय–भार उन्हें सहना पड़ता है।

11. यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना –

भारत में ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी ने एक आकर्षक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की है। और यह ध्यान रखा गया कि इसका लाभ गरीब लोग उठा सकें और केवल 1.00, 1.50 2.00 रूपये प्रतिदिन के प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ मिल सके ताकि किसी प्रकार की बीमारी होने की अवस्था मे बीमित व्यक्ति को पैसे के अभाव में इधर उधर नही भटकना पड़े और बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ लेकर अपनी चिकित्सा सुचारू रूप से करा सकें।

इसके मुख्य कुछ आकर्षण निम्नलिखित हैं –

1. बीमित व्यक्ति को बीमारी की अवस्था में उपचार के खर्चे की चिन्ता न करनी पड़े और इस योजना के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल के साथ बीमा कम्पनी की टीपीए के माध्यम से यह व्यवस्था होगी कि बीमित व्यक्ति सीधा अस्पताल मे जाकर इलाज करा सकता है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सा खर्च बीमित राशि तक नही वहन करना पड़ेगा। अस्पताल का बिल सीधा टीपीए के द्वारा भुगतान किया जाता है ।
2. बीमित व्यक्ति के परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जायेगा जो बीमित के पहचान के लिए कार्य करेगा।

3. इसकी आयु सीमा 3 माह से 65 वर्ष तक के लिए है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा गोल्ड (लाभ सहित योजना)–

यह मा0 प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह द्वारा सितम्बर 2005 को प्रारम्भ हुयी । एल0 आइ0 सी0 की स्वर्ण जयन्ती वर्ष मे प्रवेश पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह एक आकर्षक योजना है। इसमे मनी बैक, बीमा किरन, जनरक्षा आदि का सम्मिश्रण है। इसमे प्रत्येक चार वर्ष बाद धन वापसी होती है मृत्यु की दशा में पूरे बीमाधन का भुगतान बिना एस बी घटाये हुए होता है। परिपक्वता पर सभी अदा किये गये विद्यमानता लाभ को घटाते हुए प्रीमियमों की वापसी। इसमे पेड–अप वैल्यू कुल चुकाये गये प्रीमियमों के बराबर अर्थात् अधिक आयु वाले व्यक्तियो को आयु के कारण अधिक प्रीमियम देने का कोई नुकसान नही।

यह पॉलिसी 12, 16 एवं 20 वर्षो के लिए उपलब्ध है । इसमें तुलनात्मक रूप में काफी कम प्रीमियम है। 50 हजार से अधिक बीमाधन की पॉलिसी में आकर्षक एस ए रिबेट एक दो लाख एवं अधिक की पॉलिसी में 10 रूपये प्रतिहजार बीमाधन की आकर्षक छूट है। यह पॉलिसी 14 से 63 वर्ष तक के लिए व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। इसमें दुर्घटना हितलाभ तथा रायल्टी एडीशन की सुविधा है।

विद्यमानता हित लाभ – 12 साल की अवधि हेतु बीमाधन का 15 प्रतिशत प्रत्येक 4 साल एवं 8 साल के बाद।

16 साल की अवधि हेतु – बीमा धन का 15 प्रतिशत 4,8 साल एवं 12 साल के उपरांत 20 साल की अवधि।

बीमा धन का 10 प्रतिशत प्रत्येक 4,8,12 साल एवं 16 साल के उपरांत उच्च बीमा ध धन हेतु प्रीमियम में छूट।

रूपये 50,000 से कम	शून्य
रूपये 50,000 तथा एक लाख से कम	रूपये 2.5 प्रति हजार बीमित राशि
रूपये एक लाख तथा रूपये दो लाख से कम	रूपये 7.5 प्रति हजार बीमित राशि
रूपये एक लाख तथा इससे अधिक	रूपये 10 प्रति हजार बीमित राशि

भारतीय जीवन बीमा निगम की एकल प्रीमियम मनी बैक पालिसी एल0 आई0 सी0 बीमा बचत –

यह 14.11.2005 से प्रारम्भ है। इसमें प्रीमियम भुगतान सिर्फ एक बार है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद धन की वापसी है यह 9,12 व 15 वर्षो के लिए उपलब्ध है इसमे पॉलिसी ऋण की भी सुविधा है। यह 15 वर्ष से 66 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। पॉलिसी न्यूनतम बीमाधन मात्र 20,000/– अतः ग्रामीण एवं कम आय वर्ग के व्यक्तियों की पहुंच मे है।

9 वर्ष की अवधि हेतु	बीमा धन का 15 प्रतिशत 3 वर्ष एवं 6 वर्ष के उपरांत
12 वर्ष की अवधि हेतु	बीमा धन का 15 प्रतिशत 3,6,9 वर्ष के उपरांत
15 वर्ष की अवधि हेतु	बीमा धन का 15 प्रतिशत 3,6,9 वर्ष व 12 वर्ष के उपरांत

उच्च बीमाधन हेतु प्रीमियम की छूट –'

रूपये 50,000 से कम	शून्य
रूपये 50,000 तथा एक लाख से कम	5 प्रतिशत तालिका दर पर
रूपये एक लाख तथा रूपये दो लाख से कम	7 प्रतिशत तालिका दर पर
रूपये एक लाख तथा इससे अधिक	8 प्रतिशत तालिका दर पर

जीवन बीमा निगम

स्थापना –

भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा की गयी जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने 18 जून 1956 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम 1 जुलाई 1956 मे लागू किया गया और निगम ने एक सितम्बर 1956 से कार्य करना आरम्भ किया उसी दिन से निगम को जीवन बीमा व्यवसाय मे एकाधिकार प्राप्त है।

निगम एक स्वशासित संस्थान है तथा इसका कार्य व्यवहार एक व्यापारिक संस्था की भांति चलाया जाता है निगम के व्यापारिक ढंग पर कार्य करने की आवश्यकता को स्वयं जीवन

बीमा अधिनियम की एक धारा द्वारा स्वीकार किया गया है। निगम अपने उद्देश्य को पूरा करने मे संलग्न है। बीमे दारों के धन को पूरी सुरक्षा प्रदान करके बीमा दरों में कमी करके सेवा का स्तर ऊंचा उठाकर पॉलिसी शर्तो को अधिक अच्छा बनाकर खर्चा घटाकर तथा राष्ट्र निर्माण मे अधिक से अधिक योगदान देकर निगम जनता के विश्वास का पात्र बन चुका है।

निःसंदेह भारतीय जीवन बीमा निगम उस सौंपे गये दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है जो जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है कि जनता को अधिक से अधिक बचत करने को प्रोत्साहित किया जाये तथा राष्ट्र निर्माण की योजनाओं को सफल बनाने में इस बचत का अधिक से अधिक उपयोगी तरीके से विनियोग किया जाये।

निगम का केन्द्रीय कार्यालय मुम्बई में है इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय है जो क्रमशः मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद चेन्नई और भोपाल में हैं।

11. महोबा जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था
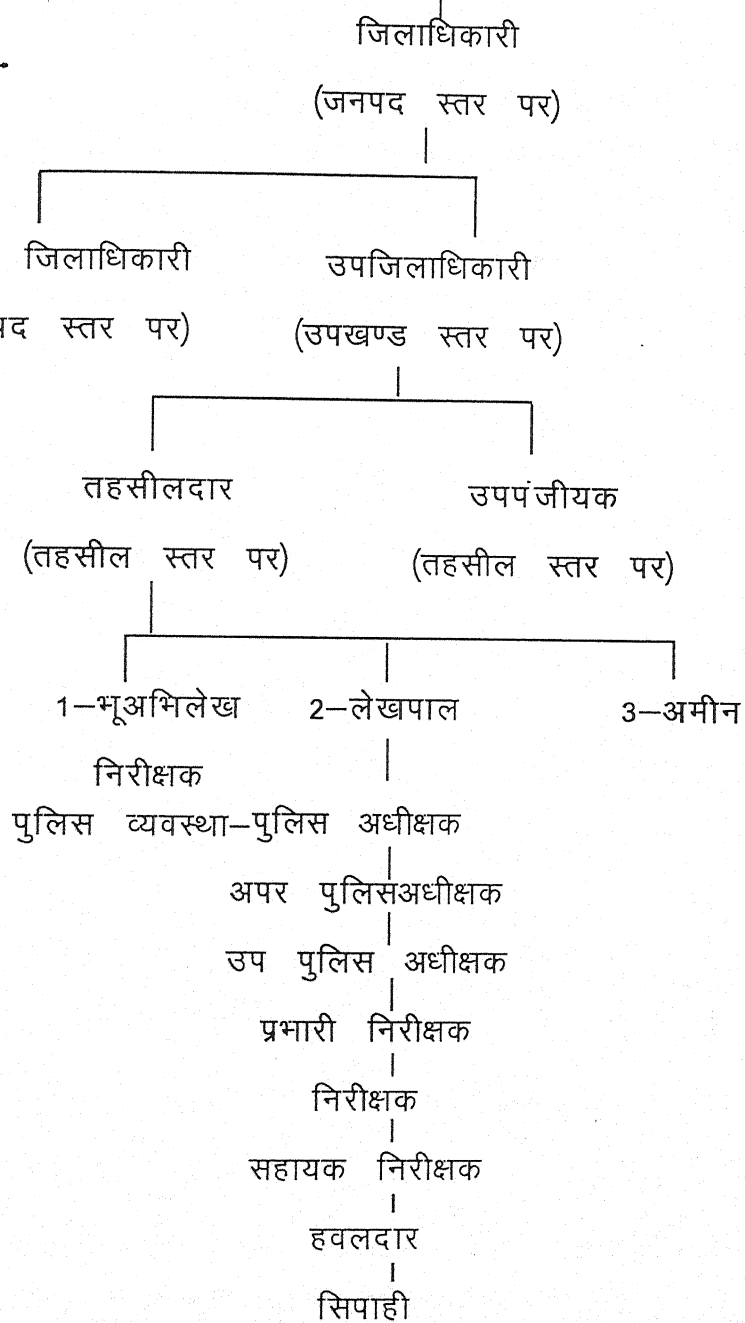
12–भण्डारगृह सुविधा –

महोबा जनपद मे भण्डारगृह की भी सुविधा है किसी भी देश, राज्य या जिले की जनसंख्या क्यों न हो उसके हिसाब से भण्डारण की सुविधा होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि जीने के लिए भोजन जरूरी है और उसके लिए गेहूँ, चावल, दाल व अनेक भोज्य पदार्थ आवश्यक है मानव प्रतिदिन इन वस्तुओं का उपभोग करता है इसलिए जिस देश में जितनी अधिक इन वस्तुओं की अधिकता होगी वहां के नागरिकों का उपभोग स्तर उतना ही अच्छा होगा। और जहां पर इसकी कमी है वहां के लोगों को जीवन कष्टमय होता है इन सबके अतिरिक्त सरकार को भण्डारण क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए तथा किसानों को उचित मूल्य पर इन सभी सुविधाओं को दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार द्वारा इन सभी के लिए अनेक योजनायें चलायी जा रही है जो निम्नवत् है –

1. मध्यान्ह भोजन योजना
2. अन्त्योदय योजना
3. सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना
4. अन्नपूर्णा योजना
5. गरीबी रेखा से ऊपर
6. गरीबी रेखा से नीचे

महोबा जनपद में गेहूँ और चावल के खाद्यान्न का स्टॉक रहता है।

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना –

केन्द्र सरकार की खाद्य नीति के 1962 के आधार पर एफ सी आई की स्थापना 1 जनवरी 1965को की गयी थी।

स्टाक रखने की क्षमता –

ढके पक्के बने शेडों गोदामों की भण्डारण क्षमता 10,000 एम टी एक लाख कुन्टल खुले मे रखने की भण्डारण क्षमता 2600 एम टी 26 हजार कुन्टल

कार्य –

1. भारतीय खाद्य निगम केन्द्र सरकार का उपक्रम है।

2. किसान को उचित मूल्य मिले इसके लिए यह कार्य करता है।

3. सभी जगह समान मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

4. खाद्यान्न उत्पादकता को उचित मूल्य दिलाना।

5. उपरोक्त स्कीमों के द्वारा आम जनता को गेहूँ व चावल उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

6. आवश्यकतानुसार गेहूँ चावल का परिचालन मूवमेन्ट के द्वारा प्रत्येक राज्य मे उपलब्ध कराना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपज वाले जिन्स उपलब्ध रहते है जो सीधे किसानो को बीज के लिए वितरण किया जाता है।

1. गेहूँ–यू0पी0–2338पी0सी0, गेहूँ–राज–3765, गेहूँ–डब्लू0एच0–147, गेहूँ–पी0बी0डब्लू0–343
2. चना–पूसा–256, चना–राधे, चना–अवरोधी, चना–बी0जी0–372
3. मटर रचना, मटर–शिक्षा
4. राई – वरूणा टाइप 59
5. मसूर बी पी एल 62, मसूर–के0–75,मसूर–बी0पी0एल0–15
6. जौ–के0–551

उपरोक्त बीज उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम जालौन, कानपुर, फैजाबाद, से आता है इनका आवंटन लखनऊ से होता है।

खनिज विभाग –

पट्टो की कुल संख्या 264

कुल पट्टों का क्षेत्रफल 383.336 हे0

पट्टो से	वार्षिक आय
2002–03	7,23,43314
2003–04	8,60,65,062
2004–05	10,91,00784

स्त्रोत – कृषि रक्षा सेवा केन्द्र महोबा।

जनपद में माहवार जिला केन्द्र से नगरीय फुटकर भाव वर्ष २००४/दिसम्बर 2005

तालिका–2.33

माह, वर्ष	गेहूं प्रति कि0	चना प्रति कि0	चावल प्रति कि0	अरहर प्रति कि0	मूंग प्रति कि0	उर्द प्रति कि0	प्याज प्रति कि0	आलू प्रति कि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जनवरी, 2004	7.20	15.0	10.00	30.00	30.00	24.00	10.00	3.00
फरवरी 2004	7.50	14.00	9.00	30.00	30.00	24.00	12.00	3.00
मार्च 2004	7.50	14.00	9.00	27.00	22.00	24.00	6.00	3.00
अप्रैल, 2004	6.50	13.00	10.00	28.00	24.00	26.00	6.00	4.00
मई 2004	6.00	14.00	10.00	29.00	24.00	22.00	4.00	5.00
जून 2004	6.00	14.00	10.00	28.00	27.00	22.00	4.00	6.00
जुलाई 2004	6.20	14.00	10.00	28.00	26.00	24.00	5.00	6.00
अगस्त 2004	6.50	15.00	11.00	30.00	26.00	24.00	5.00	6.00
सितम्बर 2004	7.00	15.00	12.00	30.00	26.00	22.00	7.00	7.00
अक्टूबर 2004	6.60	15.00	12.00	31.00	26.00	24.00	7.00	7.00
नवम्बर 2004	6.80	14.00	10.00	30.00	26.00	21.00	5.00	7.00
दिसम्बर 2004	6.90	15.00	10.00	30.00	26.00	20.00	6.09	3.00
वार्षिक औसत	6.72	14.33	10.25	29.25	26.08	23.08	6.42	5.00
दिसम्बर 2005	10.00	14.00	18.00	28.00	35.00	30.00	5.00	5.00

माह, वर्ष	सरसों तेल प्रति कि0	मांस प्रति कि0	मछली प्रति कि0	अण्डा प्रत्येक	गुड़ प्रति कि	चीनी प्रति कि0	लकड़ी प्रति कु0	दूध प्रति ली
1	10	11	12	13	14	15	16	18
जनवरी, 2004	56.00	90.00	60.00	2.00	10.00	15.00	160.00	15.00
फरवरी 2004	58.00	90.00	60.00	2.00	10.00	15.00	160.00	15.00
मार्च 2004	56.00	90.00	60.00	2.00	10.00	17.00	160.00	15.00
अप्रैल, 2004	50.00	90.00	60.00	2.00	10.00	16.00	150.00	15.00
मई 2004	46.00	90.00	60.00	2.00	10.00	17.00	150.00	15.00
जून 2004	48.00	90.00	60.00	2.00	14.00	17.00	150.00	15.00
जुलाई 2004	48.00	90.00	60.00	2.00	14.00	17.00	150.00	15.00
अगस्त 2004	52.00	90.00	60.00	2.00	15.00	18.00	150.00	15.00
सितम्बर 2004	50.00	100.00	50.00	2.00	17.00	17.00	150.00	15.00
अक्टूबर 2004	52.00	100.00	50.00	2.00	18.00	18.00	150.00	15.00
नवम्बर 2004	52.00	100.00	50.00	2.00	17.00	18.00	160.00	15.00
दिसम्बर 2004	52.00	100.00	50.00	2.00	14.00	18.00	160.00	15.00
वार्षिक औसत	51.67	93.33	56.67	2.00	13.25	16.92	154.17	15.00
दिसम्बर 2005	45.00	90.00	60.00	2.00	15.00	22.00	160.00	16.00

स्रोत– जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महोबा।

जनपद में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता

तालिका 2.34

क्रम सं0	मद	2001–2002 संख्या	2001–2002 क्षमता मी0टन	2002–2003 संख्या	2002–2003 क्षमता मी0टन	2001–2002 संख्या	2001–2002 क्षमता मी0टन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय खाद्य निगम	8	11250	8	11250	8	11250
2	केन्द्रीय भण्डार निगम	1	5000	1	5000	1	5000
3	राज्य भण्डारागार	1	1260	1	1260	1	1260
4	राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0
5	सहकारिता	29	7800	50	8000	50	8000
6	अन्य	5	750	5	750	5	750

भण्डार गृहों की संख्या व क्षमता में वर्ष 2002–03 के पश्चात् कोई वृद्धि नही हुई है ।

जनपद में विकास–खण्ड–वार कृषि से सम्बंधित कुछ मुख्य सुविधायें तालिका 2.35 I

वर्ष / विकासखण्ड	बीज विक्रय केन्द्र संख्या		अन्य	उर्वरक विक्रय केन्द्र संख्या		अन्य
	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग		सहकारिता विभाग	कृषि विभाग	
1	2	3	4	5	6	7
2001–02	8	5	0	39	0	10
2002–03	8	5	0	39	0	10
2003–04	8	5	0	39	0	10
विकासखण्ड वार 2003–04						
1 पनवाड़ी	2	1	0	8	0	0
2. जैतपुर	2	1	0	8	0	0
3. चरखारी	1	0	0	8	0	0
4. कबरई	1	0	0	15	0	0
योग ग्रामीण	6	2	0	39	0	0
योग नगरीय	2	3	0	0	0	10
योग जनपद	8	5	0	39	0	10

तालिका 2.36 II

वर्ष / विकासखण्ड	कीटनाशक विक्रय केन्द्र			कीटनाशक विक्रय केन्द्र		
	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग	अन्य	सहकारिता विभाग	कृषि विभाग	अन्य
1	8	9	10	11	12	12
2001–02	0	4	13	0	0	38
2002–03	0	4	13	0	0	38
2003–04	0	4	13	0	0	38
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	0	1	0	0	0	8
2. जैतपुर	0	1	0	0	0	8
3. चरखारी	0	0	0	0	0	8
4. कबरई	0	0	1	0	0	15
योग ग्रामीण	0	2	1	0	0	39
योग नगरीय	0	2	12	0	0	0
योग जनपद	0	4	13	0	0	39

जनपद में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता

तालिका 2.37 I

वर्ष / विकासखण्ड	शीत भण्डार		कृषि सेवाकेन्द्र		कृषि उत्पादन मण्डी समिति संख्या	बायो गैस संयत्र संख्या
	संख्या	क्षमता मी0टन	संख्या	क्षमता मी0टन		
1	2	3	4	5	6	7
2001–02	1	560	1	16	3	868
2002–03	0	0	1	16	3	893
2003–04	0	0	1	16	3	918
विकासखण्ड वार						
2003–04						
1 पनवाड़ी	0	0	0	2	1	248
2. जैतपुर	0	0	0	1	0	192
3. चरखारी	0	0	0	1	0	243
4. कबरई	0	0	0	1	0	235
योग ग्रामीण	0	0	0	5	1	918
योग नगरीय	0	0	1	14	2	0
योग जनपद	0	0	1	19	3	018

जनपद में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता

तालिका 2.38 II

वर्ष / विकासखण्ड	कुल ग्रामीण गोदाम की क्षमता मी0टन	कृषि रक्षा इकाई केन्द्र संख्या	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
2001–02	4900	4	1	9
2002–03	4900	4	1	9
2003–04	4900	4	1	9
विकासखण्ड वार				
2003–04				
1 पनवाड़ी	800	1	0	0
2. जैतपुर	800	1	0	0
3. चरखारी	1000	0	0	0
4. कबरई	2300	0	0	0
योग ग्रामीण	4900	2	0	0
योग नगरीय	0	2	1	9
योग जनपद	4900	4	1	9

शीत भण्डार– तालिका 2.39

विकासखण्ड	ग्राम में	1 कि0मी0 से कम	1–3 कि0मी0	3–5 कि0मी0	5 कि0मी0 से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1 पनवारी	0	0	0	0	120	120
2. जैतपुर	0	0	0	0	104	104
3. चरखारी	0	0	0	0	85	85
4. कबरई	0	0	0	0	126	126
योग जनपद	0	0	0	0	435	435

बीज विक्रय केन्द्र तालिका 2.40

विकासखण्ड	ग्राम में	1 कि0मी0 से कम	1–3 कि0मी0	3–5 कि0मी0	5 कि0मी0 से अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1 पनवारी	0	0	14	17	88	120
2. जैतपुर	0	0	1	6	96	104
3. चरखारी	0	0	0	4	79	85
4. कबरई	0	0	5	28	91	126
योग जनपद	0	0	20	55	354	435

स्त्रोतः– सांख्यकीय पत्रिका

अध्याय तृतीय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विकास

१. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - एक परिचय
२. प्रबन्ध प्रशासन एवं संगठन के आशय
३. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का विकास का उदय
४. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की विधिक स्थिति
५. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के उद्देश्य
६. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का महत्व
७. क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की पूंजी संरचना
८. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल का गठन
९. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की प्रबन्ध व्यवस्था
१०. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की अन्य वाणिज्यिक बैंको से भिन्नता
११. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे योगदान
१२. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथमिक एवं सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवायें प्रदान करना।
१३. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लेखा एवं अकेक्षण

अध्याय-तृतीय
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास

भारत का संपूर्ण आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र के कुशल क्रियान्वयन एवं प्रगति पर निर्भर करता है और कृषि क्षेत्र का विकास कृषको एवं ग्रामीण जनता को मिलने वाली साख सुविधाओं पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था क्योकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी के अभाव से ग्रस्त है। उत्तम किस्म के बीज रासायनिक खाद्य अच्छे औजार तथा कृषि उत्पादो के लिए विपणन सुविधायें कृषि उद्योग की प्रमुख आवश्यकतायें है। इन सभी आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा मे पूंजी की आवश्यकता होती है। जिसका भारतीय कृषकों में सर्वथा अभाव है। उचित समय और पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाओं को उपलब्ध होने पर कृषक उक्त साधनों को एकत्र करने तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने मे सफल हो सकते है इस प्रकार प्रादेशिक ग्रामीण बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित एक प्रकार का व्यवसायिक बैंक है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो की आवश्यकताओ को पूरा करना तथा उन्हें रियायती दरों पर साख प्रदान करना है।

भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों मे किसानो की ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नयी योजना प्रारम्भ की इस योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक ग्रामीणों की स्थापना की गयी। जून 1987 के अन्त तक भारत के विभिन्न राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे भारत सरकार ने ये बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के उपबन्धो के अनुसार स्थापित किये है एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि सशक्त उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रावाला प्रथम निगमत कर होते हुए भी उस वाणिज्य बैंक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है जो उसकी स्थापना के प्रस्ताव का प्रायोजक होता है। वाणिज्य बैंक के आवेदन करने पर

जब केन्द्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन सीमाओं का भी उल्लेख करती है जिनके भीतर उस ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है। ऐसे अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ही किसी भी स्थान पर वह ग्रामीण बैंक अपनी शाखायें या एजेन्सियों को खोल सकता है। ग्रामीण बैंको की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गयी क्योंकि सहकारी बैंको तथा वाणिज्य बैंकों जैसी ऋण एजेन्सियो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने मे कई पहलुओं में अक्षम थी उनकी ये अक्षमतायें संक्षेप में निम्नलिखित है।

1. जहां तक प्रबन्ध प्रतिभा ऋणोपरांत पर्यवेक्षण और ऋण वसूली का सम्बंध है इन मामलों में सहकारी ऋण व्यवस्था कमजोर है ये संस्थायें पर्याप्त साधन नही जुटा पाती है और इस तरह पुर्नवित्त सुविधा के लिए अधिकाधिक खर्च रिजर्व बैंक पर ही निर्भर करता है।

2. वाणिज्य बैंक मूलतः नगर उन्मुखी हैं ग्रामीण क्षेत्र में बैकिंग का कामकाज चलाने की दिशा मे इन बैको की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभायी है पहले तोउन्हे अपनी पद्धतियो प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण की ग्रामीण वातावण के अनुरूप ढालना पड़ेगा। परन्तु वह काम सहज जल्दी नही हो सकता इसके अतिरिक्त वाणिज्य बैकों मे उच्च वेतन ढांचा कर्मचारी व्यवस्था क्रम तथा लागत जो है इसके कारण इनके कामकाज का खर्च बहुत अधिक बैठता है और इस तरह वे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गो के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध नही करा सकते। अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की गयी जो कि इन दोनो 'संस्थाओं ' की अच्छाइयों से युक्त हो, बुराइयों से नही। इस तरह से ग्रामीण बैंक की एक ऐसी संस्था के रूप मे परिकल्पना की गयी जिसमें एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्र का पुट तथा स्थानीय भावना का तालमेल हो ग्रामीण समस्याओं से सुपरिचय हो और जिस तरह सहकारी संस्थायें अपने रूख मे बहुत हद तक ग्राम अर्थव्यवस्था से जुड़ी रहती है उसी तरह ग्रामीण बैंक भी उससे जुड़ा रहे लेकिन

इसके साथ ही उसका आधुनिक व्यापारिक संगठन हो इसमे वाणिज्यक अनुशासन हो संसाधन जुटा सकने की क्षमता हो वाणिज्य बैको की तरह उसकी भी केन्द्रीय मुद्रा बाजार मे पहुँच सके । संक्षेप मे हम कह सकते है कि ग्रामीण बैकों की संस्था को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गयी हो जो स्थानीय रूप से आधारित हो ग्राम उन्मुखी हो तथा वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर संगठित हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबन्ध प्रशासन एवं संगठन

प्रबन्ध प्रशासन एवं संगठन से आशय –

''प्रशासन उद्योग की महत्वपूर्ण शक्ति है जो उन उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसकी पूर्ति हेतु संगठन एवं प्रबन्ध प्रयत्न करते है तथा जिनके अनुकूल आचरण होता है।''

''प्रबन्ध उद्योग की वह शक्ति है जो कि पूर्व निश्चित उद्योगों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन का मार्ग दर्शन एवं नियन्त्रण करती है।

''संगठन से आशय माल, मशीन एवं औद्योगिक शक्ति आदि के संयोग से है जो कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किये जाते हैं''

''संकुचित अर्थ में प्रबन्ध से आशय दूसरे से कार्य करवाने की युक्ति से लिया जाता है वास्तव में यह व्यवसाय का मस्तिष्क होता है जिस प्रकार मानवीय शरीर मस्तिष्क के अभाव मे एक हाड़ मांस का पुतला रह जाता है उसी प्रकार प्रबन्ध के बिना एक व्यवसायी संस्थान श्रम एवं पूंजी आदि का एक निश्चित समूह मात्र रह जाता है। वह व्यक्ति जो व्यक्तियों से कार्य करवाता है प्रबन्ध कहलाता है।

''व्यापक अर्थ में प्रबन्ध एक कला है जिसमें नीति निर्धारण समन्वय, क्रियान्वयन संगठन तथा व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्यो को मिलाने की प्रक्रिया इत्यादि कार्य आते है। आज मानवीय क्रिया का किसी अन्य क्षेत्र मे इतना महत्व नही है जितना कि

प्रबन्ध में है। व्यापार हो या खेत, खलिहान कारखाना हो या कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम हो या निजी गैर आर्थिक संस्था, दान पुण्यवाली हो या बैंकिंग संस्था, सभी में किसी न किसी रूप मे प्रबन्धन प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रबन्ध विशेषज्ञ पीटर एफ0 ड्रकर के शब्दों में "प्रबन्ध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवन दायक तत्व होता है । उसके नेतृत्व के अभाव मे उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते है। कभी उत्पादक नही बन पाते मनुष्य का मस्तिष्क जितना अधिक विवेकशील होता है वह उतना ही चमत्कारिक कार्य करता है ठीक उसी प्रकार प्रशासन प्रबन्ध जितना अधिक चतुर क्रियाशील एवं योग्य होता है, व्यवसाय का उत्पादन एवं संगठन उतना ही श्रेष्ठ होता है। सरल शब्दों में प्रबन्ध का उद्देश्य योग्यता एवं कुशलता के साथ कार्य आवंटन कर न्यूनतम लागत पर उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।

प्रबन्ध का मुख्य कार्य विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित तथा नियंत्रित करना है। यह सभी कार्य जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभापति, सचिव/ महाप्रबन्धक, संचालक मण्डल, वरिष्ठ, शाखा प्रबन्ध तथा अधिकारी करते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्ध के स्तर –

आज के विशिष्टीकरण के युग में विशिष्ट कार्यो का आवंटन कर दिया जाता है ताकि प्रबन्ध तथा प्रशासन की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सके। उपक्रम में भिन्न भिन्न पदों को प्रबन्ध के स्तर के नाम से जाना जाता है।

शीर्ष प्रबन्ध –

प्रबन्ध के इस स्तर के अन्तर्गत सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को संस्था के लक्ष्यों, योजनाओ एवं नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण का कार्य करना होता है शीर्ष प्रबन्धन मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभापति, संचालक मण्डल एवं महाप्रबन्धक आते हैं, इनको

बैंक के प्रशासक भी कह सकते हैं।

मध्य स्तरीय प्रबन्ध –

इसके अन्तर्गत उन अधिकारियों को शामिल किया जाता है कि जो उच्च प्रबन्धन द्वारा निर्धारित नीतियों को उपक्रम के प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयत्न करते हैं। मध्यम प्रबन्धन के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबन्धक, लेखा, प्रशासन, संग्रह, एवं निरीक्षण एवं वरिष्ठ प्रबन्धक विकास को शामिल किया जाता है।

निम्न स्तरीय प्रबन्ध –

प्रबन्ध के इस स्तर के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबन्धकों एवं शाखा प्रबन्धकों को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शाखाओं मे कार्य करने वाले कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है। इन कर्मचारियों द्वारा कुशलतापूर्वक कार्य करने से ही लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विकास व उदय–

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है देश के आर्थिक विकास की योजनाओं मे यदि कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता नही दी गयी तो अतिशयोक्ति होगी। कृषि का कार्य अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है परन्तु कृषि के लिए ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा मे वित्तीय सुविधा चाहिए जिसकी कमी है। कृषि के पिछड़ेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण किसान के निजी साधन बहुत कम है इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति मे सुधार करने के लिए किसानो द्वारा साख की मांग निरन्तर बनी रहती है साख की आवश्यकता वाला किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। ठीक समय में और उचित मात्रा में साज उपलब्ध न होने पर किसान के लिए कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है इन्हें वित्त या साख की उचित प्रकार की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास किया गया।

ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों एवं सहकारी साख संस्थाओं के प्रयासों की पूरक संस्था के रूप मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की आवश्यकता एक लम्बे अरसे से महसूस की जा रही थी, क्योकि ग्रामीण क्षेत्रों मे वित्तीय साख की संस्थागत संस्थायें या तो नगण्य थी या उनकी संख्या अपर्याप्त थी। कृषकों को परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने की दृष्टि से सरकार द्वारा वर्ष 1972 मे आर॰बी॰सरैया की अध्यक्षता मे एक बैकिंग आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने व्यापारिक बैंकों की शाखाओं के विस्तार के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का सुझाव दिया ताकि लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण कारीगरों एवं फुटकर व्यापारियों आदि की ऋण समस्याओं का अच्छी तरह समाधान किया जा सके। आयोग की सहमति थी कि व्यापारिक बैकों को ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों के विस्तार पर अधिक व्यय आता है।
2. व्यापारिक बैंकों के पास ग्रामीण किसानों की वित्तीय समस्याओं को समझने एवं उनके अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक मशीनरी का अभाव है।

इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करके एम0 नरसिम्हम की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक स्थापित किये जाने को उचित बताया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का उदय –

26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी कर देश भर में क्षेत्रीय ग्राम बैंक स्थापित करने की घोषणा की।''

आरम्भ में 2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय बैंक स्थापित किये गये । उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर मे हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर और पश्चिम बंगाल मे माल्डा के स्थान पर । यह बैंक क्रमशः सिण्डीकेट बैंक, स्टेट बैंक इण्डिया, पंजाब

नेशनल बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा चालू किये गये।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विधिक स्थिति –

ये बैंक अनुसूचित बैंक है परन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैकों की अपेक्षा इन बैंको को रिजर्व बैंक से अधिक सुविधायें प्राप्त होती है। इन्हें राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्य) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थरीकरण) कोष से सहायता प्राप्त हो सकती है इन कोषों की व्यवस्था पहले रिजर्व बैंक द्वारा की जाती थी, परन्तु अब नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिये गये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुछ अन्य सुविधायें भी प्राप्त हैं। सन् 1990–00 तक 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्राम बैंक स्थापित किये गये जिनकी 14508 शाखायें थीं। इस प्रकार 1999–00 के अन्त तक इन बैंकों ने देहातों मे रहने वाले निर्बल वर्गों को 12660 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों का 95 प्रतिशत कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इन बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एवं रियायतें देता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्गो, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों, दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को समयानुसार उचित मात्रा मे ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास मे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन बैंकों की अधिकांश शाखायें पिछड़े क्षेत्रों मे खोली गयी हैं जहां पहले बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नही थीं।

जुलाई 1982 मे नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली सुविधा नाबार्ड, से मिलने लगी है। नाबार्ड अब इन बैंकों की पुर्नवित्त योजनाओ के प्रशासन उनके कार्य निष्पादन की देख रेख एवं शाखा विस्तार तथा निरीक्षण के लिए रिजर्व बैंक के साथ एक कड़ी के रूप मे कार्य करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अप्रतन आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय

कार्य निष्पादन की दृष्टि से लाभार्जन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मे समग्र रूप से गिरावट आई है । कुल 195 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से वर्ष 2001–02 मे 29 बैंक हानि मे चल रहे थे। हानि उठाने वाले बैंकों की संख्या 2002–03 मे बढ़कर 40 हो गयी ।

इन सब के बावजूद जून 2003 के अन्त तक 23 राज्यों मे स्थापित 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 145078 शाखायें देश के 500 जिलो मे कार्य कर रही है। इन बैंको की 12003, (83.07 प्रतिशत) शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों मे थी। इस तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने 83 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण एवं बैंक रहित क्षेत्रों मे खोलकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण एवं बैकिंग सुविधायें उपलब्ध कराकर एवं ग्रामीण क्षेत्र की बचतों को एकत्र करके सराहनीय कार्य किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रगति एवं शाखा विस्तार को निम्न सारिणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका नं0 3

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शाखा विस्तार

वर्ष	कुल शाखाओं की संख्या	ग्रामीण शाखाओं की संख्या	ग्रामीण शाखाओं का भाग प्रतिशत में
1976	112	94	83.9
1877	780	688	88.2
1980	2678	2473	92.3
1985	12138	11206	92.3
1995	14406	12475	85.9
1997	14405	12244	84.9
1998	14420	12307	85.3
1999	14406	12260	85.1
2000	14425	12158	84.3
2001	14467	12086	83.6
2002	14486	12049	83.2
2003	14508	12003	82.7

स्त्रोत – आर्थिक समीक्षा 2003–04

तालिका नं0 3.1

Expansion of RRB System 1975-1999

Period ending	Banks	Loans in Rs.Million	Deposits	C.D.Ratio
Dec. 1975	6	1-0	2.6	50
Dec 1980	85	2433-8	1998.3	122
Dec 1985	188	14076.7	12868.2	109
Dec 1990	196	35540.4	41505.2	86
Dec 1995	196	62909.7	111500.1	56
Dec 1997	196	78526.6	154234.2	51
Dec 1998	196	84866.2	193256.5	44
Dec 1999	196	93672.1	235976.1	40

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीब तथा छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकतायें पूरी करना है।

ग्रामीण बैंकों की संस्था को ऐसा रूप देने की परिकल्पना की गयी है जो स्थानीय रूप से आधारित हो, ग्रामोन्मुखी हो तथा वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर संगठित हो ये बैंक सामान्य बैकिंग कारोबार करते है तथा इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीब तथा छोटे देहातों मे कृषि तथा अन्य उत्पादन मे वृद्धि के लिए साख सुविधाओ मे वृद्धि करना है। इन बैंको का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानो, कृषि मजदूरों, देहाती कारीगरो तथा छोटे किसानों की ओर ध्यान देना है। इन बैंको को अलग अलग राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है।

इन बैंको के उद्देश्य निम्नवत् हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्र के विकास मे सक्रिय सहयोग प्रदान करना।
2. ग्रामीण बैकों मे साख की कमी को दूर करना।
3. इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों

स्त्रोतः– रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन

उद्यमियों तथा क्षेत्र के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को समयानुसार सहजतापूर्वक उचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराना है।

4. ग्रामीण बचतों को प्रोत्साहित करना।

5. ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करना।

6. ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आकलन के उपरान्त साख की व्यवस्था करना इन बैंकों का उद्देश्य है।

7. उन पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों में बैंक की शाखायें खोलना जहां वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार कम है।

8. जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों मे उत्पादक कार्यो के लिए उपयोग मे लाना।

9. शहरी मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों मे पुर्नवित्त के माध्यम से ऋण के प्रवाह को अनुपूरक चैनल तैयार करना।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्तमान शाखा जाल (Network) को युक्तिसंगत बनाने तथा उनमें परिचालनात्मक दक्षता लाने के उद्देश्य से दिसम्बर 1993 मे रिजर्व बैंक ने नाबार्ड तथा भारत सरकार के परामर्श से एकमुश्त उपायों की घोषणा की जिसमे निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं।

1. जिन 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संवितरण राशि 1992–93 के दौरान 2 करोड़ रूपये से कम थी उन्हें सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्त करना।

2. वर्ष 1992–93 मे पूर्व अनुमत नये उधार के 40 प्रतिशत के उनके गैर लक्ष्य समूह वित्त पोषण को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैको कों नुकसान पहुँचाने वाली मौजूदा शाखाओं का स्थान बदलकर उन्हें विकास खण्ड / जिला मुख्यालय पर मण्डियों / कृषि उत्पादन केन्द्रों जैसी नयी जगहों पर स्थापित करना।

4. उन्हें विस्तार काउण्टर खोलने की छूट देना।

5. उनके कार्यकलापों मे वृद्धि तथा गहनता लाना ताकि गैर निधिक व्यवसाय जैसे प्रेषण और बट्टे पर भुलाने की सुविधा शामिल हो सके।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्थापित करने का मूल उद्देश्य ग्राम क्षेत्रों मे कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है।

7. क्षेत्रीय ग्राम बैंकों ने लक्षित समूहों को उधार सुविधायें देकर लोगों के मन मे यह धारणा कायम की है कि छोटे व्यक्तियों के बैंक है। इनमे छोटे तथा सीमान्त किसान कृषि मजदूर, दस्तकार और उत्पादक उद्यमों मे कार्य कर रहे छोटे उद्यम शामिल किये जाते है।

8. जहां पर बैकिंग सुविधायें नही थी वहां पर ही अधिकांश शाखायें पिछड़े क्षेत्रों मे खोलना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का महत्व –

जब तक हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक हम उस वस्तु के महत्व को नही जान सकते है। क्योंकि आवश्यकता से ही उस वस्तु के महत्व का पता चलता है और जब तक हमे किसी वस्तु की आवश्यकता का पता नही चलेगा उसके महत्व की विवेचना नही की जा सकती। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय कृषकों की आवश्यकताओं और उसके महत्व का वर्णन निम्नलिखित है ।

1. कृषकों को खेती बाड़ी, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 मास से भी कम समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है जैसे उसे बीज उर्वरक और चारा आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस वर्ष फसल अच्छी न हुयी हो उस वर्ष अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए भी उसे धन की आवश्यकता हो सकती है ये ऋण अल्पावधि ऋण होते है जो साधारणतया फसल काटने पर चका दिये जाते है इस प्रकार ये सभी बैंक के महत्व को दर्शाते हैं।

2. कृषक को अपनी भूमि मे सुधार करने पशु खरीदने और कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए 15 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के मध्यावधि ऋणों की भी आवश्यकता होती

है अल्पावधि ऋणो की तुलना में ये ऋण अधिक होते हैं और उन्हे अपेक्षाकृत अधिक समय के बाद ही चकाया जा सकता है इस प्रकार ग्रामीण बैंक इन ऋणों को प्रदान करने मे सहायक होता है।

3. कृषक को अतिरिक्त भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने, ऋण अदा करने और मंहगे कृषि यन्त्र खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है । ये ऋण 5 वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए लिये जाते हैं। कृषक इन ऋणों को अनेक वर्षो मे थोड़ा थोड़ा करके चुका पाता है । इन्हें दीर्घकालीन ऋण कहते हैं और इन ऋणों की पूर्ति इस बैंक द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त किसानों को दो प्रकार के ऋणों की भी आवश्यकता होती है ये हैं उत्पादक और अनुत्पादक ऋण । उत्पादक ऋणों मे ऐसे उधार शामिल किये जाते हैं जो किसानों को कृषि क्रियाओं में सहायता देते हैं या भूमि उन्नत करने मे सहायता देते हैं जैसे बीज, खाद, औजार आदि क्रय करने के लिए ऋण, सरकार को कर का भुगतान करने के लिए ऋण, और भूमि पर स्थायी उन्नतियां करने जैसे कुँओं को खोदने एवं गहरा करने, बाढ़ लगाने आदि के लिए ऋण। इसके अतिरिक्त भारतीय किसान प्रायः अनुत्पादक कार्यो के लिए भी उधार लेता है जैसे विवाह, जन्म, मृत्यु, मुकदमेबाजी के लिए ऋण। यदि अनुत्पादक ऋण ब्याज की अत्यधिक दर पर लिये जायें तो वह बहुत अनुचित और अविवेकपूर्ण बात है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी संरचना –

प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये चुकता पूंजी 25 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। साझा पूंजी 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का 15 प्रतिशत सम्बंधित राज्य सरकार का तथा शेष 35 प्रतिशत प्रायोजित करने वाले वाणिज्य बैंक का होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजक बैंको नाबार्ड भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सिडनी और अन्य संस्थाओं से ऋण लिये जाते है जिनमे नाबार्ड का अंश सर्वाधिक रहता है।

मार्च 1990 तक भारत सरकार की मंजूरी से 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित

कार्यदल की सिफारिश के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निर्गमित शेयर पूंजी को चरणबद्ध रूप मे बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दिया गया। जून 1996 के अन्त में 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों मे से प्रत्येक की चुकता पूंजी 75 करोड़ लाख रुपये से अधिक किन्तु एक करोड़ रूपये से कम थी। 107 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों मे प्रत्येक की चुकता पूंजी 75 लाख रूपये तथा शेष 30 की 75 लाख रूपये से कम थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रूपये है । ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल उस निगर्मित पूंजी को रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंक से परामर्श कर तथा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन की धारा 6 अभिदत्त की जाती है । ग्रामीण बैंकों के अंशों को भारतीय न्याय अधिनियम 1982 में सम्मिलित हुआ समझा जाता है और यह भी समझा जाता है कि वे बैकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रायोजनों के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के 1976 के प्राविधानों के अनुसार सामान्य निरीक्षण, निर्देशन एवं समस्त व्यवस्थाओं के प्रबन्ध का कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित होता है जो समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समस्त कार्य सम्पन्न कराते हैं। अपने कार्यों का निर्वहन करते समय निदेशक मण्डल व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर सार्वजनिक हित में समस्त कार्य करते हैं।

निदेशक मण्डल का गठन –

निदेशक मण्डल मे अधिनियम की उपधारा 1 की धारा 11 के अनुसार एक अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया जाता है तथा अन्य सदस्य निम्नवत् होते हैं।

अ. 2 निदेशकों का मनोनयन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ऐसे व्यक्ति किसी भी केन्द्र सरकार राज्य सरकार रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक प्रवर्तक बैंक या अन्य किसी बैंक का अधिकारी नही होना चाहिए।

ब. एक निदेशक का मनोनयन उस बैंक द्वारा किया जायेगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक मे कोई अधिकारी हो।

1. Subs. by Act 1 of 1988 Sec.7

स. राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी को एक निदेशक के रूप उस बैंक द्वारा नामांकित किया जायेगा।

द. प्रवर्तक बैंक के अधिकारियों मे से दो निदेशकों की नियुक्ति उस बैंक द्वारा की जायेगी एवं 2 निदेशकों का मनोनयन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या मे वृद्धि कर सकती है लेकिन यह 15 से अधिक नही हो सकती बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष पहले की जाती है कोई भी सदस्य पुनः नामित किया जा सकता है तथा वह अपने पद पर तब तक कार्य करता है जब तक कि उसका कोई प्रस्थानी न आ जाये।

निदेशक मण्डलीय बैठकें –

वर्तमान मे निदेशक मण्डल की 7 बैठकें आयोजित की गयी। बैंक निदेशक मण्डल के महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य दिशा निर्देशों एवं प्रगति मापदण्डों के समय समय पर किये गये पुनरावलोकनों से लाभान्वित हुआ। निदेशक मण्डल द्वारा किये गये सहयोग एवं निर्देशन के कारण ही बैंक द्वारा व्यवसाय की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सका।

अध्यक्ष – (चेयरमैन)

प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष के लिए अधिनियम उपधारा 4 के अनुसार करने के लिए अधिकृत है। प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष को उसकी अवधि ा से पूर्व अधिनियम 1 की विहित प्रक्रिया के अनुसार हटा सकता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष अपने पद से निर्धारित अवधि से पूर्व त्यागपत्र दे सकता है लेकिन उसे इसकी सूचना प्रवर्तक बैंक को 3 महीने पूर्व लिखित मे देना होगा।

ग्रामीण बैंक की परिचालन लागत का पूरा पूरा नियंत्रण रखा जाता है केन्द्र सरकार इन बैंको के कर्मचारियो के वेतनमान नियत करती है और ऐसा करते समय यह ध्यान मे रखती है कि अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के समान स्तर तथा हैसियत के कर्मचारियों का वेतन ढांचा क्या है।

---

2. Subs. by Act Ist. of 1988 Sec.8

अयोग्यतायें –

एक व्यक्ति निदेशक के रूप मे नियुक्त होने के अयोग्य है यदि वह दिवालिया हो, अस्वस्थ्य मस्तिष्क का हो तथा ऐसा किसी सक्षम न्यायालय ने घोषित किया हो या केन्द्रीय सरकार की नजरों में अपराध किया हो।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्टाफ –

एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए आवश्यकता और पर्याप्त मात्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधि0 1976 के प्राविधानों के अनुसार की जाती है तथा प्रर्वतक बैंक से मांग करने पर ऐसे व्यक्तियों को प्रर्वतक बैंक द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उन्हे संचालक मण्डल द्वारा समय समय पर सौंपी जायेंगी।

31 मार्च 2005 को उपलब्ध जनशक्ति

तालिका 3.2

विवरण	एमएमजी–5	एमएमजी–4	एमएमजी–2	जेएमजी–1	योग	लिपिक	संदेशवाहक	योग
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ	–	–	30	126	156	88	87	331
प्रर्वतक बैंक स्टाफ	1	1	–	–	–	–	–	2

प्रायोजक बैंक की जिम्मेदारियां –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा क्षेत्रीय बैंकों के संचालन में प्रायोजक बैंकों की जिम्मेदारियां काफी बढ़ा दी गयी हैं। प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी प्रदान करने के अतिरिक्त उनके कर्मचारियों की उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे तथा प्रथम 5 वर्षो मे उन्हें प्रबन्धकीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रगति पर भी प्रायोजक बैंक देखभाल रखेंगे उनका निरीक्षण करेंगे तथा आंतरिक आडिट भी करेंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक की गारण्टी के आधार पर रिजर्व बैंक से अग्रिम धनराशियां लेने की सुविधा दी गयी है इन बैंकों मे रहने वाली जमाराशियो का बीमा तथा ऋण गारण्टी निगम द्वारा किया जाता है।

आन्तरिक निरीक्षण एवं अंकेक्षण –

वर्ष 2004–05 मे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 55 शाखाओं का आन्तरिक निरीक्षण किया गया। परिलक्षित अनियमितताओ के सुधार हेतु निरीक्षण आख्याओं को उपलब्ध कराई गयी तथा उनकी समय निराकरण हेतु सघन अनुश्रवण किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रबन्ध व्यवस्था –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यक्षेत्र किसी एक राज्य में एक अथवा एक से अधिक जिलों के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है। अपने कार्यक्षेत्र में ये बैंक विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसानों जिनके पास भूमि 2 हे0 से अधिक नही है, भूमिहीन मजदूरों कारीगरो, तथा अन्य उत्पादकों जिनकी वार्षिक आय 2400 से अधिक नही है को ऋण एवं अग्रिम धन देते हैं। इन बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की ग्रामीण सहकारी समितियों को भी ऋण दिये जा सकते हैं।

इन बैंकों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। ऐसा करते समय राज्य के कर्मचारियों तथा उस क्षेत्र में उसी स्तर के कर्मचारियों के वेतन स्तर को ध्यान में रखा जाता था परन्तु अब इन कर्मचारियों के वेतन वाणिज्य बैंकों के कर्मचारियों के वेतन के समान कर दिये जाने की मांग की जा रही है।

इन बैंकों की ब्याज दरें उस राज्य में सहकारी साख समितियों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नही होती हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 9 सदस्यों का संचालक बोर्ड भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार कार्य करती है।

ग्रामीण बैंकों के लिए यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि 15 लाख रूपये की जमाराशि प्राप्त होने पर ये 2 करोड़ रूपये के ऋण दे सकती हैं। शेष राशि प्रर्वतक बैंकों रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारों से प्राप्त की जा सकती है। अक्टूबर 1976 में चालू की गयी

योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक इन्हें पुर्नवित्त की सुविधा देता रहा है नाबार्ड की स्थापना हो जाने पर अब रिजर्व बैंक की इन बैंकों के प्रति जिम्मेदारियां यह संस्था निभा रही है।

2 अक्टूबर 1975 को प्रथम 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 1976 तक 50 बैंक स्थापित किये जायेंगे। मार्च 1981 के अन्त तक 163 जिलों में 100 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जायेंगे। छठी योजना के 1984–85 तक 270 जिलों में 170 क्षेत्रीय बैंक स्थापित करने का लक्ष्य था। अप्रैल 1985 मे इनकी संख्या 183 थी। इन बैंकों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 196 हो गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबंध एवं संचालन एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। संचालक मण्डल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा 1987 में एक्ट मे किये गये संशोधन के अनुसार अब यह संख्या कम होकर 2 रह गयी। 2 निदेशक राज्य सरकार द्वारा तथा 3 निर्देशक प्रवर्तक बैंक द्वारा मनोनीत होते हैं। बैंक का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है जो पूर्ण कालिक होता है।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने नियत क्षेत्र में कार्य करता है ये बैंक कार्य की आवश्यकतानुसार क्षेत्र में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकते हैं। प्रारम्भ में इन बैंकों में कार्य हेतु कर्मचारियों का चयन क्षेत्र के ही लोगों का किया जाता था ताकि उन्हें भाषा सम्बंधी एवं अन्य क्षेत्रीय कठिनाइयों को समझने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रवर्तक बैंक होता है जिसकी देख रेख में उसे कार्य करना होता है प्रवर्तक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अनेक प्रकार के कार्यो मे सहयोग करता है जैसे शेयर पूंजी क्रय करना एवं उसकी स्थापना में सहयोग देना इसके कर्मचारियों का चयन करना तथा उनके प्रशिक्षण में सहयोग करना, प्रबन्धकीय एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करना आदि।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अन्य वाणिज्यिक बैंकों से भिन्नता –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मूल रूप मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही है किन्तु वे कुछ पहलुओं में इनसे भिन्न हैं।

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलों के निर्धारित इलाके तक सीमित कर दिया जाता है। इसके विपरीत, वाणिज्यिक बैंक का कार्य क्षेत्र देश के अनेक राज्यों में फैला हुआ है और उनकी देश के बाहर भी शाखायें है जैसे भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें विदेशों में भी हैं।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों, देहाती कारीगरों, कृषि मजदूरों और अन्य कम सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण तथा अग्रिम देते हैं। वाणिज्यिक बैंक का कार्यक्षेत्र उनकी तुलना में बहुत व्यापक है। वे प्रधानतः व्यापारियों को नकद साख की सुविधा प्रदान करते हैं।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधार दरें किसी विशेष राज्य में सहकारी समितियो की उधारो दरों की तुलनीय हैं।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया गया है जिसमें यह ध्यान में रखा गया है कि सम्बंधित राज्य की सरकार के कर्मचारियों तथा उस राज्य के स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं उन्हें ध्यान मे रखते हुए ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान तथा सेवा सम्बंधी शर्ते आदि निर्धारित की गयी हैं इसके विपरीत, वाणिज्यिक बैंकों का वेतन ढांचा उनके प्रधान कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित होता है।

सहकारी क्षेत्र के बैंको और अन्य वाणिज्यिक बैंको की शाखाओं का विस्तार

तालिका 3.3

बैंक समूह	30 जून की स्थिति के अनुसार कार्यालयो की संख्या							30.6.03 और 20.6.03 के बीच वृद्धि	30.6.03 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखायें	30.6.03 स्थिति के अनुसार ग्रामीण शाखाओ की प्रतिशत कॉलम 10 से कालम 8
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	2462	13262	13375	13431	13473	13504	13533	11071	5475	40.5
ख. राष्ट्रीयकृत बैंक	4553	32397	32645	32561	32678	32947	33211	28558	13609	41.0
		14406	14426	14451	14464	14505	14507	14507	11978	82.6
ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंको का जोड़ क+ख+ग	7051	6065	60446	60443	60615	60956	61251	54236	31062	50.7
घ. अन्य भारतीय अनु0वाणिज्य बैंक	900	4902	5157	5206	5334	5447	5794	4894	1112	19.2
ड. विदेशी बैंक	130	178	226	236	251	214	218	88	–	–
सभी अनुसूचित बैंक	8045	85145	65929	65885	66200	66617	67263	59218	32174	47.8
च.गैर अनुसूचित बैंक	217	8	2	11	18	21	20	197	4	20.0
सभी वाणिज्य बैंक	8262	65153	65931	65896	66218	66638	67283	59021	32178	47.8

टिप्पणी –

1. आंकड़े वाणिज्यिक बैंक की मास्टर कार्यालय फाइल मे नवीनतम अद्यतन विवरण पर आधारित है।
2. वर्ष 2000 और 2001 के आंकड़ो मे संशोधन किया गया है वर्ष 2002 के आंकड़े अनन्तिम हैं।
3. जनसंख्या समूह वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है।
4. बैंको की शाखाओ मे प्रशासनिक कार्यालय शामिल नही है।

सिक्किम बैंक लिमिटेड का यूनियन बैंक आफ इण्डिया मे 22.12.1999 को विलय 1969 के आंकड़े वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण से लिये गये हैं।

स्त्रोत – भारतीय रिजर्व बैंक ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने स्थापना काल से ही कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के ऋण प्रवाह में सराहनीय कार्य किया है। इन बैंकों ने कृषि क्षेत्र के जो अल्पकालीन मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया है। उसे निम्नलिखित सारिणी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

(करोड़ रूपये में)

तालिका 3.4

वर्ष	अल्पावधि ऋण	मध्यम एवं दीर्घावधि ऋण	योग
1990—91	125	210	335
1995—96	849	532	1381
1996—97	1121	563	1684
1997—98	1396	644	2040
1998—99	1710	750	2460
1999—2000	2423	749	3172
2000—2001	3239	980	4219
2001—2002	3777	1077	4854
2002—2003	4156	1311	5467
2003—2004	4680	1400	6080

स्त्रोत — आर्थिक समीक्षा 2003—04

तालिका से प्रकट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1990–91 मे कृषि क्षेत्र को कुल 335 करोड़ रूपये का उधार दिया जो क्रमशः बढ़ते हुए वर्ष 2003–04 लक्ष्य में 6,080 करोड़ रूपये पहुंच गया।

किसान क्रेडिट कार्ड –

वर्ष 1998–99 मे प्रारम्भ की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के अल्पावधि ऋण प्राप्त करने को सुगम बनाने की अभिनव योजना है। 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा जारी किये गये कार्डो की संख्या और स्वीकृति राशि इस योजना के प्रारम्भ मे क्रमिक रूप से बढ़ती रही है। जिसमे सितम्बर 2002 तक 21.20 हजार कार्ड जारी किये गये है और इसकी स्वीकृति राशि, 5,211 करोड़ रूपये है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में योगदान –

1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आरम्भिक अवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना ध्यान बड़े किसानों और ऐसे किसानों पर केन्द्रित किया जो अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ानें मे व्यस्त थे। इन्हे पम्पिंग सेट, ट्रेक्टर, अन्य कृषि मशीनरी कुंए तथा ट्यूबवेल लगाने के लिए सीधे ऋण दिये गये इसी प्रकार फल तथा बागवानी फसलो, भूमि को हमवार तथा विकसित करने, दुधारू पशु खरीदने, मुर्गी पालन आदि के लिए भी ऋण दिये गये।

इसके अतिरिक्त छोटे किसानों की दशा सुधारने व कृषि विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निम्नलिखित योजनायें आरम्भ की हैं –

1. छोटे किसानों को विकास एजेन्सियां कायम की गयी हैं ताकि छोटे तथा भविष्य में सक्षम बनने योग्य किसानों की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उन्हें उनके जिलों मे ही कृषि योगदान सेवायें और उधार मुहइया कराये जा सकें।
2. सहकारी समितियों के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक योजना बनाई जिसके अधीन वाणिज्यि बैंक प्राथमिक कृषि उधार समितियों को वित्त उपलब्ध कराते हैं जो फिर किसानों के लिए वित्त प्रबन्ध करती हैं। यह योजना 13 राज्यों

के 142 जिलों में लागू की गयी और इससे लगभग 2.970 प्राथमिक समितियां सहायता प्राप्त कर रही हैं।

ग्राम ऋण के स्त्रोत –

किसान अपनी अल्पावधि और मध्यावधि वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों, सरकारी ऋण समितियां और सरकार से उधार लेता है। दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह साहूकारों, भूमि विकास बैंकों और सरकार से रूपया उधार लेता है।

(A) गैर संस्थानात्मक स्त्रोत–(Non Institutional Sources)

साहूकार – (Moneylanders)

गांवों में दो प्रकार के साहूकार है। एक वे साहूकार हैं जो खेती और साहूकारी दोनों ही कार्य करते है इन्हें कृषक साहूकार कहते है। ये मूलतः खूटी करते है किन्तु सहायक व्यवसाय के रूप में रूपया उधार देने का भी काम करते हैं। गांव का दुकानदार भी साहूकारी कर लेता है इसके अलावा एक दूसरे प्रकार के साहूकार होते है जिनका व्यवसाय रूपया उधार देना होता है। किसान को नकद रूपये की आवश्यकता के लिए साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है पिछले वर्षो से किसानों को नकद धन देने वाले साधन के रूप में साहूकार का महत्व तेजी से कम होता जा रहा है उदाहरणतया अखिल भारतीय ग्राम ऋण सर्वेक्षण 1954 की जांच के अनुसार संपूर्ण ग्राम ऋण मे साहूकारों द्वारा दिये गये ऋण का भाग लगभग 70 प्रतिशत था किन्तु 1991 मे किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार ऋण का अंश केवल 18 प्रतिशत था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि संस्थानात्मक अभिकरणों के मुकाबले साहूकार पिछड़ते जा रहे हैं किन्तु फिर भी गावों में साहूकारों की प्रधानता के अनेक कारण हैं –

1. साहूकार उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के लिए तथा अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के लिए किसान को खुले रूप मे ऋण देता है।
2. साहूकार के पास किसान आसानी से जा सकता है क्योंकि साहूकार का कृषक के परिवार से कई पीढ़ियो से पारिवारिक सम्बंध होता है।

3. उसके लेन देन के तरीके सरल और लचीले होते हैं।

4. स्थानीय स्थिति से परिचित रहने के कारण वह जमीन और प्रोनोट दोनो के ही बदले ऋण दे सकता है ऋण का रूपया वापिस लेने की कला वह भली भांति जानता है।

साहूकारों के दोषपूर्ण व्यवहार –

ग्रामीण साहूकार अपने अनेक दोषपूर्ण व्यवहारों के कारण बदनाम है वे किसान से बन्धक पत्र और प्रोनोट ले लेते हैं जिनमें वे ऋण की राशि बढ़ाकर लिखते है किसानों से भारी किश्त वसूल करते है वे किसानों को रुपया अदा करने के बदले में रसीद नहीं देते और कई बार रुपया वसूल कर चुकने पर भी मुकर जाते हैं। वे ऋण पर बहुत भारी ब्याज लेते हैं यहां तक 24 प्रतिशत और उससे भी अधिक इसके अलावा वे अनेक प्रकार के छल कपट करते हैं। भारतीय कृषि की बहुत सी बुराइयों की जिम्मेदारी साहूकारों पर ही है क्योंकि उनका एक मात्र उद्देश्य किसान का शोषण करना और उनकी भूमि हथियाना होता है जब तक दोषपूर्ण क्रियाओं पर रोक नही लगायी जाती तब तक किसान की दशा सुधारना कठिन होगा।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट –

(Traders and Commission Agents)

व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट किसानों को फसल के पकने से पूर्व उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते है। भूमिहीन श्रमिकों को बन्धुआ श्रम बनने के लिए मजबूर किया जाता है इससे भी बुरी बात यह है कि वित्त का यह स्त्रोत अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है यह 1951–52 मे 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 1961–62 मे 14.5 प्रतिशत वित्त जुटाने लगा परन्तु 1991 मे इसका भाग कम होकर 4.0 प्रतिशत रह गया।

कृषि वित्त के गैर सरकारी स्त्रोत के मुख्य दोष है अनुत्पादक उपभोग कार्यो के लिए ऋण का प्रयोग ब्याज की ऊंची दरें और इस प्रकार किसानो द्वारा मूलधन एवं ब्याज लौटाने की असमर्थता छोटे किसानों द्वारा ऋण प्राप्त करने की कठिनाई आदि।

B. ऋण के संस्थानात्मक स्त्रोत – (Institutional Sources of Credit)

संस्थानात्मक ऋण मे ऐसी राशियां शामिल की जाती है जो सहकारी समितियों वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्राम बैंको द्वारा उपलब्ध करायी जाती है राज्य सरकारें राज्य सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त तक्काणी ऋण भी उपलब्ध कराती है। सहकारिता के क्षेत्र मे प्राथमिक कृषि उधार समितियां अल्पकालीन एवं मध्य कालीन ऋण उपलब्ध कराती है और भूमि विकास बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋणो का प्रबन्ध करते है। वाणिज्य बैंक जिनके क्षेत्रीय ग्राम बैंक भी शामिल है कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाओं के लिए अल्पकालीन एवं सावधि ऋण दोनों ही उपलब्ध कराते है। कृषि तथा ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय स्तर पर या कृषि उधार के लिए शिखर संस्थान है। और ऊपर वर्णित सभी एजेन्सियों की पुर्नवित्त सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में ग्राम उधार के लिए व्यापक निर्देश और राष्ट्रीय बैंक को इसके कार्यो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संस्थानात्मक ऋण की आवश्यकता गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराये गये उधार अपर्याप्तता और इनके दोषों के कारण उत्पन्न होती है। वे किसानो को मजबूर करते है कि वे फसल को कम कीमतो पर बेचे और अपने लिए भारी कमीशन वसूल करते है। वित्त यह स्त्रोत नगद फसलों अर्थात् रुई, मूंगफली, तम्बाकू आदि या फलों के बगीचों आमो आदि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है व्यापारी एवं कमीशन एजेण्टों का कृषि वित्त में भाग जो 1951–52 मे 5.5 प्रतिशत था बढ़कर 1961–62 मे 8.7 प्रतिशत हो गया परन्तु 1991 मे कम होकर 2.5 प्रतिशत हो गया। व्यापारी एवं कमीशन एजेण्टों को भी महाजनों जैसा कि समझा जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा किसानों को दिये गये उधार की दरें अत्यधिक होती है और इनके अन्य अवांछनीय प्रभाव भी होते हैं।

1. सम्बंधी : (Relatives)

किसान अपने सम्बंधियों से नकद या वस्तुओं के रूप मे उधार प्राप्त करते है ताकि वे अस्थाई कठिनाइयों को दूर कर सके ये ऋण सामान्यतः अनौपचारिक रूप से दिये

जाते है इन पर ब्याज या तो लिया ही नही जाता या ब्याज की दर बहुत नीची होती है और ये ऋण फसल कटने के फौरन बाद लौटा दिये जाते है परन्तु वित्त का यह स्त्रोत अनिश्चित है और आधुनिक कृषि की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं के कारण किसान इस स्त्रोत पर अधिक निर्भर नही रह सकता वास्तव में ग्राम ऋण के इस स्त्रोत का महत्व कम होता जा रहा है। 1951–52 मे सम्बंधियों से उधार कुल ग्राम ऋण का 14.2 प्रतिशत था परन्तु 1991 मे यह कम होकर केवल 5.5 प्रतिशत रह गया।

2. भू स्वामी एवं अन्य : **(Landlords and others)**

किसान विशेषकर छोटे किसान एवं काश्तकार भू स्वामियों एवं अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं वित्त के इस स्त्रोत मे वे सभी दोष विद्यमान है जो महाजनों व्यापारियों या कमीशन एजेण्टों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त में पाये जाते है प्रायः इस वित्त से छोटे किसानों से उनकी भूमि हल द्वारा हर ली जाती है।

3. सहकारी ऋण समितियां :**(Co-operative Credit Societies)**

सहकारी वित्त प्रबन्ध ग्राम ऋण का सबसे सस्ता और बढ़िया स्त्रोत है इसमे किसान के शोषण का भय नही रहता। ब्याज की दर भी कम है। 1992–93 मे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से सहायता प्राप्त होने के कारण 88000 प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों द्वारा 5080 करोड़ रूपये के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराये गये है। 1994–95 मे ये बढ़कर 6600 करोड़ रूपये तक हो गया सक्रिय प्राथमिक उधार समितियां 86 प्रतिशत ग्रामो तक फैली हुयी है और इनमें 86 प्रतिशत ग्राम जनसंख्या को लाभ होता है सहकारी समितियों द्वारा 1981 में कृषि के लिए कुल उधार जिसमे सहकारी ऋण समितियों एवं भूमि विकास बैंक भी शामिल है की आवश्यकता का 33 प्रतिशत जुटाया गया जबकि 1951–52 मे यह अनुपात केवल 3 प्रतिशत था।

फिर भी किसानों को महाजनों के चंगुल से पूर्णतया छुड़ाया नही जा सका किसानों की सभी ऋण सम्बंधी आवश्यकतायें सहकारी समितियों द्वारा पूरी नही की गयी है। इसके अतिरिक्त छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं सहकारी समितियों से भी पूरी करने मे कठिनाई अनुभव करते है साथ ही पश्चिमी बंगाल, बिहार उड़ीसा और राजस्थान जैसे विशाल

क्षेत्र है जहां यह आंदोलन या तो फैल नही सका या इसकी जड़े गहरी नही हुयी है और परिणामतः किसान सहकारी समितियो के लाभों से वंचित रहे है। बहुत सी जगहो पर सहकारी समितियों का कार्य सिद्धान्तहीन और बेईमान किसानो द्वारा बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और इस प्रकार जरूरतमन्दों को सहकारिता के लाभ उपलब्ध नही हो पाये है।

4. भूमि बन्धक बैंक या भूमि विकास बैंक :

(Land Development Banks)

दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता भूमि बन्धक बैंको जिन्हें आजकल भूमि विकास बैंक कहा जाता है से पूरी हो रही है इन बैंको का उद्देश्य किसान को उसकी भूमि बन्धक रखकर दीर्घकाल ऋण प्रदान करना है भूमि विकास बैंको से मिलने वाला ऋण काफी सस्ता है और उसकी अदायगी काफी लम्बे समय में करनी होती है अतः यदि पिछले ऋणो की अदायगी करनी हो या नई जमीन खरीदनी हो या भूमि पर ट्यूबवेल आदि के रूप मे कोई सुधार करना हो तो इन बैंकों से उधार लेना सुविधापूर्ण होता है ऋण साधरणतयाः 15 से 20 वर्ष तक की लम्बी अवधि के लिए दिये जाते है यद्यपि भारत वर्ष मे पिछले कुछ वर्षो में भूमि विकास बैंको ने काफी प्रगति की है किन्तु फिर भी किसान की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति मे उनका योगदान अधिक नही रहा है बहुत से ऋणों के लिए किसानो को इन बैंको के बारे मे जानकारी उपलब्ध नही है और न ही वे इनकी लाभदायकता से परिचित है दूसरे इन बैंको की व्यवस्था करना कठिन है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों की संख्या 1950–51 मे 5 से बढ़कर 1983–84 मे 19 हो गयी जबकि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या इसी काल के दौरान 286 से बढ़कर 1170 हो गयी परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 70 प्रतिशत भूमि विकास बैंक दक्षिण भारत के तीन राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, और कनार्टक में स्थित है जबकि 1950–51 मे इन बैंकों द्वारा केवल 3 करोड़ का उधार उपलब्ध कराया गया इसकी मात्रा 1997–98 मे बढ़कर 3640 करोड़ रूपये हो गयी। भूमि विकास बैंक भूमि की प्रतिभूति के विरूद्ध ऋण देते है और बड़े भू–स्वामियों ने इसका लाभ उठाया है और मोटे तौर

पर छोटे किसानो को इनसे लाभ प्राप्त नही हुआ।

5. वाणिज्य बैंक और ग्राम वित्त :

(Commercial Banks and Rural Finances

चिर काल से भारत वाणिज्य बैंकों ने अपनी क्रियायें शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखी है वे शहरी जनता से जमा स्वीकार करते और शहरी क्षेत्रों मे व्यापार और उद्योग के लिए वित्त जुटाये इनके खिलाफ बहुत समय से यह शिकायत की जा रही थी कि वे कृषि क्षेत्र को उधार उपलब्ध नही कराते 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन्हे कृषि क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बाध्य किया गया जून 1969 मे अनुसूचित वाणिज्य बैंको द्वारा 44 करोड़ रूपये का वित्त उपलब्ध कराया गया। 1996–97 मे वाणिज्य बैंको ने क्षेत्रीय ग्राम बैंको के साथ कृषि क्षेत्र को 34300 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराये।

6. क्षेत्रीय ग्राम बैंक : (Regional Rural Bank)

ये बैंक 1975 से स्थापित किये गये और इनका विशेष उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानो कृषि मजदूरों देहाती दस्तकारों आदि को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना है । ये ऋण उत्पादन कार्यो के लिए दिये जाते हैं। 1997–98 तथा 196 क्षेत्रीय ग्राम बैंक कायम हो चुके थे और वे ग्रामीण जनता को लगभग 7500 करोड़ रूपये वार्षिक उधार के रूप मे उपलब्ध कराते रहे है इन बैंकों के ऋणों का 90 प्रतिशत ग्राम क्षेत्रों के कमजोर वर्गो को दिया जाता है।

7. सरकार और ग्रामीण उधार –**(Government & Rural Debt)**

सरकार ग्राम वित्त का अल्पकाल एवं मध्यकाल के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत रही है सरकार द्वारा किसानो को दिये गये ऋण आपात काल या संकट के समय जैसे अकाल, बाढ़ आदि के सामान्यतः दिये जाते है। इन पर ब्याज की दर नीची होती है । 6 प्रतिशत के करीब और इसकी वापसी का ढंग बहुत आसान होता है ये ऋण किसान किश्तो मे भू कर के साथ लौटाये जाते है ये ऋण ब्याज की दर नीची होने के कारण भी लोकप्रिय नही है और ये कभी भी महत्वपूर्ण नही बन पाये। 1951–52 मे कुल ग्राम ऋणों मे इनका

भाग केवल 3.3 प्रतिशत था जो 1991 मे थोड़ा बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया । राज्य सरकारों ने कृषि के अल्पकालीन ऋणों के लिए 350 करोड़ रूपये के अग्रिम दिये इस असंतोषजनक स्थिति के कई कारण है किसान टक्कावी ऋणों को प्राप्त करने मे बहुत कठिनाई महसूस करते है इसकी प्राप्ति मे बहुत सी परिस्थितियों मे अफसरों से ऋण स्वीकृत कराने के लिए कुछ रिश्वत भी देनी पड़ती है इसीलिए टक्कावी ऋण लोकप्रिय नही बन पाये।

निष्कर्ष –

1950 में ग्राम भारत मे महाजन का सबसे अधिक महत्व था और संस्थानात्मक स्त्रोंतो द्वारा कृषि उधार की कुल आवश्यकताओं का 3 प्रतिशत से अधिक नही जुटाया जाता था चाहे महाजन अभी भी महत्वपूर्ण है परन्तु उनका एकाधिकार बीते हुए युग की बात हो गयी है विभिन्न योजनाओं के अधीन कृषि उधार के अधिकाधिक संस्थानीकरण के कारण अल्पकालीन एवं मध्यकालीन उत्पादक उधार का लगभग 30 प्रतिशत इन स्त्रोतो से उपलब्ध कराया गया है सहकारी उधार पर आगामी वर्षो मे और भी बल दिया जायेगा जब वाणिज्य बैंक प्रत्यक्ष उधार देने की अपेक्षा अल्पकालीन उत्पादक उधार के लिए ग्रामीण प्रणाली का अधिकाधिक प्रयोग करने लगेगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्राथमिक एवं सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना –

वाणिज्यिक बैंक संस्थागत साख के एक मात्र सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप मे सामने आये है बैंकों द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इतनी विविध है कि इन्हें वित्तीय सेवाओं के विभागीय भण्डार कहा जा सकता है जिस प्रकार से व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों के 2 कार्य होते है इसी प्रकार इसके भी कार्य होते है इसके मुख्य या प्राथमिक कार्यो के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया जाता है।

1. जमाराशियां स्वीकार करना –

वाणिज्य बैंक का प्रथम प्रमुख कार्य व्यक्तियों से जमा स्वीकार करना है यद्यपि एक बैंक गैर चेक संख्या जमा भी स्वीकार करता है लेकिन इसे व्यक्तियों से चेक साध्य जमा अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार निम्नलिखित खातों में रूपया जमा कर सकते हैं।

2. चालू खाता –

चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गयी रकम जब चाहे निकाली जा सकती है इस खाते मे आवश्यकतानुसार कई बार रूपया निकालने की सुविधा रहती है बैंक ऐसे खातो पर या तो ब्याज बिलकुल नही देता या बहुत मामूली देता है।

3. स्थायी निक्षेप –

स्थायी निक्षेप वह है जिसे एक निश्चित अवधि जो 3 माह से 5 वर्ष तक हो सकती है के लिए बैंक लेता है स्थायी खाता कहते है। इन खातों पर ब्याज की दर ऊंची रहती है क्योंकि इन खातों की रकम का प्रयोग करने के लिए बैंक पूर्णतः स्वतंत्र होते है और उचित विनियोग वे पर्याप्त लाभ कमाते है।

4. बचत खाता

यह खाता प्रायः मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा खोला जाता है जिसमें वे अपनी छोटी-छोटी बचतों के भविष्य के लिए जमा करते है। परन्तु जमाकर्ता इस खाते मे से एक निश्चित रकम सप्ताह मे केवल एक या दो बार ही निकाल सकता है।

5. गृह बचत खाता –

इस खाते के अनुसार बैंक जमा करने वाले के घर गुल्लक रख देता है इन गुल्लकों मे अपनी सुविधानुसार घर का स्वामी या अन्य व्यक्ति पैसे जमा करते है महीने के अन्त मे या तीन महीने बाद इस गुलक को बैंक मे ले जाया जाता है । ऐसी जमा पर ब्याज बहुत कम दिया जाता है।

6. ऋण प्रदान करना –

इनका दूसरा महत्व पूर्ण कार्य ऋण प्रदान करना है वास्तव में जमा लेना या ऋण देना ये दो स्तम्भ है जिन पर आज कल के बैंको का ढांचा खड़ा रहता है ऋण प्रायः उत्पादक कार्यो के लिए दिये जाते है और इन पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर उससे अधिक होती है जो कि बैंक जमा कराने वाले व्यक्तियों को देता है इन दोनो मे ब्याज की दर का अन्तर ही बैंक का लाभ होता है। बैंक निम्न तरीको से ऋण देता है।

(क). नकद साख –

इसके अन्तर्गत ऋणी को निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है इस सीमा के अन्दर ही ऋणी आवश्यकतानुसार रूपया निकलवाता रहता है और जमा भी करता है इस अवस्था मे बैंक केवल वास्तव मे निकलवायी गयी राशि पर ब्याज लेता है।

(ख). अधिविकर्ष –

बैंक मे चालू जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकलवाने की अनुमति ले लेते है निकाली गयी रकम को ओवरड्राफ्ट कहते हैं।

(ग). ऋण तथा अग्रिम –

ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप मे दिये जाते है। बैंक ऋणदाता के खाते मे ऋण की रकम इकट्ठा जमा कर देता है ऋणदाता उसे कभी भी निकाल सकता है इन ऋणो की स्वीकृति के तुरन्त बाद ही ब्याज आरम्भ हो जाता है चाहे ऋणी बैंक द्वारा उस खाते मे से कुल ऋण का केवल एक ही भाग निकाले।

गौण कार्य			
प्राथमिक या मुख्य कार्य	**एजेन्सी सेवाएं**	**सामान्य उपयोगिता के कार्य**	**सामाजिक कार्य या आर्थिक कार्य**
1. जमा स्वीकार करना क. चालू खाता ख स्थायी निक्षेप ग बचत खाता घ गृह बचत खाता 2. ऋण प्रदान करना क. नकद साख ख अधिविकर्ष या ओवर ड्राफ्ट 3. ऋण तथा अग्रिम 4. सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 5. विनिमय पत्रो की कटौती करना 6. साख निर्माण	1. साख पत्रों के भुगतान का संग्रह 2. ग्राहकों की ओर से भुगतान 3. भुगतान संग्रह करना 4. धन का स्थानान्तरण 5. ट्रस्ट आदि का कार्य	1. बहुमूल्य धातुओं की रक्षा 2. साख प्रमाण पत्रो को प्रदान करना 3. वस्तुओ के वाहन मे सहायता 4. व्यापारिक सूचंना व आंकड़े एकत्रित करना 5. ऋण का अभिगोपन करना 6. विदेशी विनिमय का लेन देन करना 7. आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना	1. पूंजी की उत्पादकता मे वृद्धि 2. कोषों के हस्तान्तरण की सुविधा 3. विनियोग एवं अर्थ प्रबन्ध 4. पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन 5. विभिन्न क्षेत्रों मे कोषो का वितरण 6. रोजगार मे वृद्धि 7. भुगतान करने मे सुविधा 8. मुद्रा प्रणाली मे लोच 9. अन्य सामाजिक कार्य

घ. सरकारी प्रतिभूतियों मे विनियोग –

बैंको द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी सरकार को उधार देने का एक तरीका है बहुत से बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना पसन्द करते है क्योंकि यह सबसे सुरक्षित उधार माना जाता है।

ड. विनिमय पत्रों की कटौती करना –

इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर रूपया उधार देता है भुगतान के बाकी समय की ब्याज को कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है।

च साख निर्माण –

आजकल बैंको का कार्य साख निर्माण करना है बैंक अपनी प्रारम्भिक जमा से अधिक रूपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं।

गौण या सहायक कार्य –

जिस प्रकार से व्यापारिक व वाणिज्यिक बैंक के गौण व सहायक कार्य हैं उसी प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक के भी कुछ सहायक कार्य है। उन सहायक कार्यो में एजेण्ट रूपी व सामान्य उपयोगिता सम्बंधी कार्य भी आते हैं।

1. एजेन्सी सम्बंधी सेवायें –

इसके अन्तर्गत वे कार्य आते है जो बैंक अपने ग्राहकों को आदेशानुसार उसकी ओर से करता है और इन कार्यो के लिए वह कमीशन लेता है जो उसकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है इसके अन्तर्गत कुछ अन्य निम्नलिखित कार्य आते हैं।

2. बैंक अपने ग्राहकों से प्राप्त विनिमय बिलों, चेकों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि पर मिलने वाले धन की वसूली करके अपना कमीशन काटकर शेष राशि उनके खातो मे जमा कर देता है।

3. ग्राहकों के सभी प्रकार के भुगतान सम्बंधी आदेशों को भी बैंक पूरा किया करते है जैसे उनकी ओर से ऋणो की किश्ते ब्याज, चंदे, बीमा की किश्त कर आदि का भुगतान

करना। इस कार्य के लिए ये बैंक ग्राहक से साधारण सा कमीशन लेते हैं।

4. बैंक अपने ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, कमीशन, आदि की भी वसूली करते है ये कार्य भी बैंक कमीशन के आधार पर करते हैं।

5. ये बैंक अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से सम्बंधित उचित परामर्श देते रहते है तथा उनके आदेशानुसार क्रय विक्रय करते रहते हैं।

6. छत्रसाल ग्रामीण बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को धन शीघ्र से शीघ्र और कम व्यय पर भेजने की व्यवस्था करता है।

7. बैंक ग्राहक, के लिए ट्रस्ट, अटार्नी, एक्सक्यूटर्स तथा सलाहकार का कार्य भी करता है।

सामाजिक कार्य या आर्थिक विकास के कार्य –

(Social Function & Functions of Economic Development)

बैंक के विविध कार्यो के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि बैंको के हमारे आधुनिक सामाजिक व आर्थिक जीवन मे बहुत महत्व है क्योकिं आज की व्यापारिक प्रणाली और हमारा आर्थिक जीवन एक सुन्दर और सुदृढ़ बैकिंग व्यवस्था के अभाव मे सुचारू रूप से नही चल सकता बैंक ही व्यापार वाणिज्य और व्यवसाय का धमनी केन्द्र है।

बैंक समाज के उन व्यक्तियो तथा वर्गो का धन जमा करते है जिनके लिए वह अनावश्यक अथवा कम उपयोगी होता है और फिर इसी पूंजी को बैंक उद्योग धंधे और व्यापार आदि मे लगाते है जिससे उत्पादन व राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है।

बैंक एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराते है जिससे पूंजी में गतिशीलता आ जाती है और व्यापार का क्षेत्र बढ़ जाता है।

बैंक लोगों के निष्क्रिय कोषो एवं बचतों को संगठित करते हैं और उनको उत्पादक कार्यो के लिए उपलब्ध कराते है बचत के अलावा बैंक किफायत की भावना का विकास करते है जिससे पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है।

बैकिंग विकास से न केवल बैकिंग क्षेत्र मे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते

है बल्कि बैंको द्वारा पूंजी विनियोग अर्थ प्रबन्ध आदि से व्यापार उद्योग एवं सभी क्षेत्रों मे विकास से रोजगार मे वृद्धि होती है।

बैंकों द्वारा भुगतान करने मे सुविधा होती है व हस्तान्तरण करने मे सरलता होती है इसके अतिरिक्त बैंक देश में व्यापार की मांग के अनुसार साख का प्रसार या संकुचन करते रहते है इससे मुद्रा व्यवस्था निरन्तर लोंचपूर्ण बनी रहती है।

सामान्य उपयोगिता सम्बंधी कार्य –

(Function of General)

छत्रसाल ग्रामीण बैंक उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य बहुत से सुविधाएं अपने ग्राहकों तथा सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराता है।

1. बैंक अपने यहां ग्राहकों के गहने, आभूषण, मूल्यवान कागज आदि को सुरक्षित रूप से रखने के लिए लाकर की व्यवस्था रखते हैं।
2. बैंक अपने ग्राहकों को साख प्रमाणपत्र तथा यात्रियों को चेक जारी करते हैं।
3. बड़े बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों को माल भेजकर उसकी बिल्टी बैंक से भेज देते है खरीदार बैंक मे रूपये जमा करवाकर उस बिल्टी को छुड़वा लेते है और माल ले लेते हैं।
4. बैंक उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सम्बंधी विविध प्रकार के आंकड़ें और सूचनायें एकत्र करते है तथा प्रकाशित करते है अथवा मांगने पर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।
5. छत्रसाल ग्रामीण बैंक प्रतिभूतियों का अभियोजन भी करते है अर्थात् बैंक अपने ग्राहकों द्वारा खरीदे गये अंश अथवा अन्य प्रतिभूतियों को बेचने का दायित्व ले लेते है। इस कार्य के बदले ग्राहक से वे अभियोजन शुल्क या कमीशन लेते हैं।
6. बैंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की साख के सम्बंध मे सही तथा विश्वसनीय सूचना भी देते हैं।
7. बैंक अपने ग्राहकों को एक दूसरे की साख के सम्बंध मे सही तथा विश्वसनीय सूचना भी देते है।

ये जनता के बहुमूल्य सामानो को सुरक्षित रखते हैं। तथा ये सरकारी अर्थ

प्रबन्ध मे भी सहायक होता है क्योंकि सरकारी ऋणों का निर्गमन बैंको के माध्यम से ही किया जाता है। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक सहायता करके तथा उनके पक्ष मे विवरण देकर उनकी साख बढ़ाता है।

ये बैंक अधिकतर ग्रामीणों की सहायता की दृष्टि से बनाये गये है। ये उन्हे कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लेखा एवं अंकेक्षण –

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को केन्द्रीय सरकार के गजट के अनुसार घोषित तिथि को या 31 दिसम्बर को अपनी पुस्तके तथा आर्थिक चिट्ठे को बन्द करना होगा तथा केन्द्रीय सरकार से ऐसे लेखों का अंकेक्षण कराने के लिए किसी चाटर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति कर केन्द्र सरकार से उसका अनुमोदन करना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रत्येक अंकेक्षक कम्पनी अधिनियम की 1956 की धारा 226 के अनुसार योग्य होना चाहिए ऐसे अंकेक्षक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अनुमोदन के पश्चात् प्राप्त करने का अधिकार होगा।

प्रत्येक अंकेक्षक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ-हानि खाते की एक एक प्रति दी जायेगी तथा साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों की सूची प्रत्येक अंकेक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी इस सम्बंध मे अंकेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह चिट्ठे की प्रत्येक मद को सम्बंधित प्रमाणकों की सहायता से जांच करेगा ऐसी जांच वह तार्किक समयानुसार स्वयं कर सकता है ऐसे लेखो की जांच के लिए वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खर्चे पर लेखाकर या अन्य किसी व्यक्ति को जांच कार्यालय सहयोग हेतु नियुक्त कर सकता है वह क्षेत्रीय ग्रामीण के खर्चे पर लेखाकार या अन्य किसी व्यक्ति को जांच कार्यालय सहयोग हेतु नियुक्त कर सकता है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से खातों के सम्बंध मे आवश्यक पूछताछ कर सकता है प्रत्येक अंकेक्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के चिट्ठे एवं लेखों के आधार पर एक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमे वह निम्नलिखित तथ्यो का समावेश करेगा।

1. कि क्या उसके दृष्टिकोण मे बैंक का आर्थिक चिट्ठा पूर्ण और उचित है। क्या

उसमें सभी आवश्यक विवरण दर्शाये गये है अर्थात् वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करता है अथवा नही क्या उसने कोई स्पष्टीकरण या सूचनाये मांगी। और क्या ये संतोषजनक थे इसका अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन मे करता है।

2. कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय या शाखाओं से उसे पर्याप्त सूचना या रिटर्न जो कि अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक थी उसे प्राप्त हुयी अथवा नही।

3. कि क्या छत्रसाल ग्रामीण बैंक का सम्बंधित अवधि का लाभ हानि खाता उस अवधि का सही लाभ या हानि प्रकट करता है अथवा नहीं।

4. अन्य कोई भी सूचना जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्बंध मे उसके विचारार्थ प्राप्त हुयी हो जिसका कि रिपोर्ट मे उल्लेख करना आवश्यक हो।

वार्षिक प्रतिवेदन को अंशधारियों को भेजना –

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने खाते बन्द करने के तीन माह के अन्दर दो आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते तथा अंकेक्षक प्रतिवेदन की एक एक प्रति अधिकारियों को अवश्य भेजेगा। इस अवधि को रिजर्व बैंक की अनुमति से तीन माह और बढ़ाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को प्राप्त होने के पश्चात् उसका यह दायित्व है कि वह उसे संसद के पटल पर रखे।

अध्याय चतुर्थ

महोबा जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विकास

१. छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा की संरचना
२. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था
3. छत्रसाल ग्रामीण बैंक के उद्देश्य एवं कार्य
४. छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली बैकिंग सेवाओं का स्वरूप
५. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की पूंजी संरचना
६. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की सेवाओं का मूल्यांकन

अध्याय–चतुर्थ

महोबा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विकास

30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा जनपद की प्रगति करते हुए उसके सर्वागीण विकास की ओर अग्रसर है। महोबा जनपद के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक अपनी विभिन्न योजनाओ के तहत उपभोक्ताओं और ग्रामीण जनो के लिए वरदान साबित हुआ है यदि हम बैंक के पिछले लाभों व कार्यो की तरफ ध्यान दें तो पाते है कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने उन्नति ही की है। क्योंकि जब छत्रसाल ग्रामीण बैंक की स्थापना हुए 20 वर्ष पूर्ण हुए तब वहां के अध्यक्ष के प्रतिवेदन के अनुसार बैंक अपनी 85 शाखाओं एवं तीन रिटेल बैकिंग बुटिक्स एवं उसमे कार्यरत 334 कर्मचारियों के नेटवर्क के साथ झांसी एवं जनपद चित्रकूट धाम मण्डलों के जालौन हमीरपुर एवं महोबा जनपद मे सुदूर ग्रामीण अंचलों मे ग्रामीण बैकिंग के प्रचार प्रसार में खरा उतरा है। बैंक ने एक ओर जहां ग्रामीण जमा का संचय कर ठोस वित्तीय आधार तैयार किया वही कमजोर वर्ग एवं कृषकों को ऋण के माध्यम से वित्त सुलभ कराकर देश के आर्थिक आधार कृषि एवं उससे सम्बंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया। फलत ग्रामीण महाजनी शोषण प्रथा पर बहुत हद तक अंकुश लगा और बैंक ने अपेक्षित लाभोत्पादकता की दिशा मे भी अच्छी सफलता पायी। विगत वर्षो मे बैंक द्वारा बढ़ी हुयी प्रबंधन लागत के बावजूद अपने शुद्ध लाभ मे उत्तरोत्तर वृद्धि की है।

वर्तमान मे बैकिंग प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिसे ध्यान में रखते हुए शाखाओ का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया शाखा कार्यालयो को सुविधानुरूप स्वच्छ एवं बेहतर सेवा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से होडिंग्स, सूचना पट, पम्पलेट के माध्यम से अपने जमा एवं ऋण उत्पादों, उन पर प्रदान एवं प्राप्त होने वाले प्रभारो एवं ब्याज को प्रदर्शित करते है ताकि वह अपने लिए सुविधाजनक बैकिंग प्लेटफार्म चयनित कर सकें।

बैंक द्वारा सन् 2001–2002 मे 261772.36 लाभ के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया, जिसमें ऋण व जमा अंश क्रमशः रूपये 8,141.72 लाख व रूपये 18,630.64 लाख रहे तथा ऋण जमा अनुपात 43.70 प्रतिशत रहा। व्यवसाय के इस स्तर पर बैंक नें रूपये

281.73 लाख पर सीमित किया। अनुत्पादक आस्तियों का कुल स्तर 23.58 प्रतिशत एवं शुद्ध स्तर 12.47 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2002–03 मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने सभी संचयी हानियों को समाप्त कर शुद्ध लाभ की सम्मानजनक स्थिति मे पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया था तथा 2003–04 मे शुद्ध लाभ रूपये 33287 हजार अर्जित करते हुए कुल लाभ रूपये 34454 हजार प्राप्त किया।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की विभिन्न जमा योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूह जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की मदद से इन्होंने ग्रामीणों में बचत की आदतों का विकास किया है और यही प्रयास इनके ठोस वित्तीय आधार के कारण बने है। समाज के हर वर्ग की हर प्रकार की बैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनके पास विभिन्न प्रकार के ऋण तथा जमा योजनाये हैं, जिन्हें पर्याप्त जनसमर्थन प्राप्त हुआ है और इसी के चलते इनके ग्राहको की संख्या मे आशातीत वृद्धि हुयी है। महिला सशक्तीकरण वर्ष मे स्वयं सहायता समूहो से जुड़ी महिलाओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन ऋण योजना लागू करना समाज के इस विशिष्ट वर्ग के आर्थिक उत्थान के प्रति छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वचनबद्धता का प्रतीक है। एन पी ए स्तर मे उल्लेखनीय कमी तथा प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी व्यवसाय मे पर्याप्त वृद्धि छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने वर्तमान प्रतिस्पर्धा वातावरण मे आने वाली सभी चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया है।

आगामी वर्ष 2004–05 बैंक के लिए चुनौतियों से भरा था क्योंकि प्रगति के जिस स्तर को इस वर्ष इस बैंक ने प्राप्त किया है आने वाले वर्ष व समय में प्रतिस्पर्धा पूर्ण वातावरण में उसे बनाये रखना था अतः इस बैंक ने निर्णय लिया था इस वर्ष कम से कम रूपये 310 करोड़ की जमा राशियां और रू0 205 करोड़ की ऋण राशियों के साथ रू0 515 करोड़ के व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जमा समिश्र में 65 प्रतिशत का सी0डी रेशियो बैंक को एक स्थिर जीव्यता प्रदान करने मे मील का पत्थर लाना भी इन्होने निश्चित किया । इस वर्ष इस बैंक ने अपने स्तर को प्राप्त किया और आने वाले प्रत्येक वर्षो मे इसका लक्ष्य बढ़ता गया।

वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र के तीन जनपदों तथा तीन रिटेल बैकिंग बुटीक सहित 84 शाखाओ के माध्यम से जो पहचान बनायी गयी है इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष मे शुद्ध लाभ रूपये 24135 हजार अर्जित करते हुए कुल लाभ रू0 58589 हजार प्राप्त किया है इसके अलावा बैंक रू0 2810301 हजार के जमा तथा रूपये 1835524 हजार के ऋणों के साथ कुल रूपये 4645825 हजार के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया है इसके साथ साथ 2532 स्वयं सहायता समूहो का गठन एवं 1080 समूहो का वित्त पोषण करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाने की दिशा मे बैंक ने अभीष्ठ योगदान दिया है। विभिन्न शाखाओं ने 58 किसान क्लबों का गठन कर बैंक के सर्वांगीण विकास के साथ साथ क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

यह बैंक अपने इस विकास का श्रेय अपने उत्साही अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के साथ जिला प्रशासन, राष्ट्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तक बैंक संस्थागत वित्त निदेशालय तथा निदेशक के सदस्यो को देता है तथा उक्त सभी के समन्वित प्रयासों तथा सहयोग उनके सराहनीय योगदान अमूल्य दिशा निर्देश सुझावों आदि से छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने सफलता के नये आयाम स्थापित किये है तथा भविष्य मे भी यह बैंक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहेगा।

उपर्युक्त स्थिति छत्रसाल ग्रामीण बैंक की थी परन्तु अग्रलिखित तालिका में महोबा जनपद के छत्रसाल ग्रामीण बैंक की उपलब्धि को दर्शाया गया है जो उसके विकास की ओर इंगित करता है। निम्नलिखित शासकीय योजनाओं के आधार पर यह बैंक कार्य कर रहा है ।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की शासकीय योजनाओं मे वित्त पोषण की स्थिति – जिला महोबा

तालिका नं0 4

विवरण	31.3.2001				31.3.2002				31.3.2003				31.3.2004				31.3.2005				प्रतिशत
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
शासकीय योजनायें																					
1.एस जी एस वाई	781	14100	238	3790	51	2672	52	1300	41	8200	66	1314	40	1000	16	3000	39	9950	32	8000	82 %
	–	–	–	–	171	3088	74	1713	207	4140	177	3540	33	825	33	825	00	00	139	4170	–
2. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	250	4132	182	2525	288	1760	114	1140	190	3800	161	3220	180	3600	102	2040	360	10800	44	1300	12
3. सघन मिनी डेरी	35	770	05	05	74	14800	03	585	70	14000	05	750	10	20	07	1363	85	17000	24	5040	29
4. के वी आई सी ब्याज उपादान	1	100	–	–	12	1200	–	–	15	1125	01	75	2	4	–	–	2	200	0	00	–
5. के वी आई सी मार्जिन मनी	100	1050	–	–	10	1550	–	–	12	2400	02	24	1	3	3	9	0	00	0	00	–
6. किसान क्रेडिट कार्ड	2790		1039	–	4230	169200	1354	33846	3215	64300	1279	69427	3300	–	1770	48002	4624	11560	3353	98493	85

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक रिपोर्ट।

उपर्युक्त सारिणी 4 मे महोबा के छत्रसाल ग्रामीण बैंक के विकास मे शासकीय योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान परिलक्षित हो रहा है सरकार द्वारा चलायी जा रही एस जी एस वाई योजना है यानि समूह ऋण योजना इस योजना के अन्तर्गत ऋण समूह मे वितरित किये जाने का लक्ष्य है जिसके लक्ष्यों मे वर्ष 2005 मे 39 खातो पर 9750 की राशि और उपलब्धि मे 32 खातों पर 8000 रूपये की राशि प्राप्त हुयी है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों जनजातियों व हरिजनों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसका प्रतिशत शून्य है। के0वी0आई0सी0 यानि खादी ग्राम उद्योग योजना शहरी क्षेत्र के लिए समस्त प्रकार के ऋण प्रदान करती है। के0वी0 आई0सी0 मार्जिन मनी योजना मे इण्डस्ट्रीज आदि के लिए ऋण प्रदान किये जाते है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना महोबा जनपद मे सफलतापूर्वक चल रही है जिसका विकास व वसूली दर की स्थिति काफी अच्छी है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा की संरचना–

इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रवर्तित छत्रसाल ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा – 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत दिनांक 30 मार्च 1982 को स्थापित किया गया।

इसके कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डलों के अधीन तीन जनपद तथा जालौन, हमीरपुर व महोबा आते है बैंक का प्रधान कार्यालय राठ रोड उरई जनपद जालौन के मुख्यालय बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप मे सम्मिलित है। प्रत्येक जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग अलग नामो से जाना जाता है। जैसे बांदा मे तुलसी ग्रामीण बैंक आदि।

शाखा संजाल –

बैंक की कुल 84 शाखाओं, तीन रिटेल बैकिंग बुटीक्स सहित तीन क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है। इनमें से 78 ग्रामीण शाखाएं तथा 06 अर्द्धनगरीय क्षेत्र है। वर्तमान मे वित्तीय वर्ष में जनपद जालौन की कालपी तहसील मे स्थित मगरौल मुस्तफी शाखा का स्थानान्तरण

ग्राम मोतीनगर मे किया गया ।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की संरचना के अन्तर्गत वहां पर कार्य करने वाले शीर्ष प्रबन्धक के पद या व्यक्ति या शहर आते है फिर उसके द्वारा संचालित पद या व्यक्ति, शहर आदि आते है यानि किसी भी संगठन संरचना के आशय वहां के शीर्ष प्रबंधन से लेकर निम्नस्तर तक के कार्यालयो को इसमे सम्मिलित किया जाता है जैसे झांसी व चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत तीन जनपद आते हैं महोबा, हमीरपुर, जालौन फिर इनके अन्तर्गत इनकी शाखायें आती है और इन्ही शाखाओं को ग्रामीण, शहरी, अर्द्धशहरी मे बांट दिया जाता है इसी क्रम को इसकी संरचना कहते हैं जो अग्रलिखित सारिणी द्वारा स्पष्ट है।

बैंक परिचालन क्षेत्र एवं शाखा संजाल

तालिका 4.1

प्रधान कार्यालय – उरई

	विवरण				योग
A	मण्डल (Division)	झांसी	चित्रकूट धाम		02
B	जनपद (District)	जालौन	हमीरपुर	महोबा	03
	अंचल कार्यालय				
C	शाखा संचाल (Bank Network)	37	30	37	84
	ग्रामीण शाखायें (Rural Branches)	34	29	15	78
	अर्द्ध शहरी शाखाये (Semi urban Branches)	03	01	02	06
	शहरी शाखायें (Urban Branches)	–	–	–	–
D	क्षेत्रीय कार्यालय (Area Ofice)	01	01	01	03
E	रिटेल बैकिंग बुटीक (Retail Banking Boutique)	01	01	01	03
f	सेवाक्षेत्र मे आवंटित ग्राम (Allocaped village in service Area)	545	328	291	1164

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

उपर्युक्त सारिणी मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना को प्रस्तुत किया गया है चूंकि हमारी अध्ययन वस्तु महोबा है अतः महोबा जनपद की 17 शाखायें निम्नवत् हैं।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की महोबा जनपद की शाखाओं की संरचना

जनपद / ब्लाक	शाखाओं के नाम
महोबा / जैतपुर	1. अजनर
	2. बछेछर
	3. कुलपहाड़
महोबा / चरखारी	4. रिवई
	5. चरखारी
	6. खरेला
महोबा / पनवाड़ी	7. महोबकण्ठ
	8. भरवारा
	9. बैंदो
	10. पनवाड़ी
	11 सौरा
महोबा / कबरई	12. फतेहपुर
	13. ननौरा
	14. गहरा
	15. सिजहरी
	16. महोबा
	17. कबरई

उपर्युक्त तालिका के अनुसार 17 शाखायें महोबा जिले मे है महोबा जिले के अन्तर्गत तीन तहसीलें आती है।

1. महोबा 2. चरखारी 3. कुलपहाड़

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की प्रबंध – व्यवस्था

किसी भी संगठन के निर्माण हेतु सर्वप्रथम उद्देश्यानुसार कर्मचारियों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है ताकि अमुक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कार्यो की पूर्ति हेतु उचित अधिकार भी दिये जाते है ताकि कार्य समन्वित तरीके से होते रहे कर्मचारियो को उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता कुशलता एवं दक्षतानुसार ही कार्य आवंटित किये जाते हैं।

जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते है तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य बांटने की आवश्यकता होती है इसका नाम संगठन है विभिन्न विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को भी वाणिज्यिक भाषा मे संगठन कहते है। इसी क्रम में प्रबन्ध आता है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा के प्रबंधन को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

शीर्ष प्रबंधन –

प्रबंध के इस स्तर के अन्तर्गत सर्वोच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को संख्या के लक्ष्यों, योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण का कार्य करना होता है। शीर्ष प्रबंधन मे महोबा जनपद के अंचल प्रबंधक आदि आते है इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय मे अध्यक्ष, महाप्रबंधक, आदि आते है। इनको बैंक के प्रशासक भी कह सकते है मध्यस्तरीय प्रबंध के अन्तर्गत जो अधिकारी शामिल किये जाते है वह उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों को उपक्रम मे प्रभावी तरीके से लागू करने का प्रयत्न करते है। मध्यम प्रबंधन के अन्तर्गत बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक (लेखा), व अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासक), वरिष्ठ प्रबंधक संग्रह एवं निरीक्षण एवं प्रबंधक विकास को सम्मिलित किया जा सकता है।

निम्नस्तरीय प्रबंध –

प्रबंध के इस स्तर के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबंधकों एवं शाखा प्रबंधकों लिपिक आदि को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शाखाओ मे कार्य करने वाले कर्मचारियों से कार्य लिया जाता है। इन कर्मचारियों द्वारा कुशलतापूर्वक

कार्य करने से ही लक्ष्यो की प्राप्ति होती है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का प्रशासनिक ढांचा (प्रबंध - व्यवस्था)

अध्यक्ष, महाप्रबंधक व निदेशकगण

1. अध्यक्ष – छत्रसाल ग्रामीण बैंक
2. महाप्रबंधक – छत्रसाल ग्रामीण बैंक
3. सहायक प्रबन्धक – भारतीय रिजर्व बैंक
4. सहायक निदेशक – संस्थागत वित्त
5. सहयक महाप्रबंधक – इलाहाबाद बैंक
6. सहायक महाप्रबंधक – इलाहाबाद बैंक
7. सहायक महाप्रबंधक – नाबार्ड
8. मुख्य विकास अधिकारी– जालौन
9. जन निदेशक – भारत सरकार द्वारा गठित

विभागाध्यक्ष

1. वरिष्ठ प्रबन्धक लेखा एवं विनियोजन
2. वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण
3. वरिष्ठ प्रबंधक सतर्कता
4. वरिष्ठ प्रबंधक विकास एवं नियोजन
5. प्रभारी प्रशासन
6. प्रभारी अग्रिम
7. प्रभारी अध्यक्षीय सचिवालय
8. प्रभारी स्वयं सहायता समूह
9. प्रभारी क्रेडिट कार्ड
10. प्रभारी वसूली

अंचल प्रबंधक

1. अंचल प्रबंधक जालौन
2. अंचल प्रबंधक हमीरपुर
3. अंचल प्रबंधक महोबा

वरिष्ठ प्रबंधक

1. वरिष्ठ प्रबंधक उरई मुख्य शाखा
2. वरिष्ठ प्रबंधक महोबा मुख्य शाखा
3. वरिष्ठ प्रबंधक निरीक्षण विभाग
4. वरिष्ठ प्रबंधक मौदहा मुख्य शाखा
5. वरिष्ठ प्रबंधक राठ मुख्य शाखा
6. वरिष्ठ प्रबंधक कोंच शाखा

प्रधान कार्यालय का प्रशासनिक ढांचा (प्रबन्ध–व्यवस्था)

प्रधान कार्यालय (उरई)
|
अध्यक्ष
|
महाप्रबंधक
|
विभागाध्यक्ष
|
↓

1. वरिष्ठ प्रबंधक – अग्रिम
2. वरिष्ठ प्रबंधक – निरीक्षण
3. वरिष्ठ प्रबंधक– प्रशासन
4. वरिष्ठ प्रबंधक – सतर्कता
5. वरिष्ठ प्रबंधक – विकास एवं नियोजन
6. वरिष्ठ प्रबंधक – सचिवालय एवं आई.टी.
7. वरिष्ठ प्रबंधक – लेखा एवं नियोजन
8. प्रभारी (स्वयं सहायता समूह)
9. प्रभारी (क्रेडिट कार्ड)
10. प्रभारी (वसूली)

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा का प्रधान कार्यालय उरई में है। वहां पर अध्यक्ष इसकी प्रबंध व्यवस्था को संभालता है । इसलिए शीर्ष प्रबंध पर अध्यक्ष व मध्य प्रबंध के अन्तर्गत महाप्रबंधक आते हैं और इसके बाद विभागाध्यक्ष आते हैं जो कि कई विभागों मे अलग अलग बंटे हुए हैं यह व्यवस्था प्रत्येक प्रधान कार्यालय में होती है। अध्यक्ष, महाप्रबन्धक व विभागाध्यक्ष केवल एक होते है वही तीन जनपद महोबा हमीरपुर व जालौन के प्रधान होते हैं परन्तु जनपद स्तर की प्रबंध व्यवस्था में अन्तर होता है क्योंकि वहां पर शीर्ष स्तर पर अंचल प्रबंधक आते है इसी प्रकार जनपद को तहसील ग्रामीण व शहरी के अन्तर्गत बांटा जाता है जहां पर छत्रसाल ग्रामीण बैंक की अनेक शाखाएं खुली हुयी है। इस प्रकार से हमीरपुर जनपद में 30 तथा जालौन मे 37 शाखायें खुली हुयी है परन्तु सभी की प्रबंध व्यवस्था में अन्तर होता है। जनपद स्तर की प्रबंध व्यवस्था को अग्रलिखित सारिणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

कुल 17 शाखायें हैं।
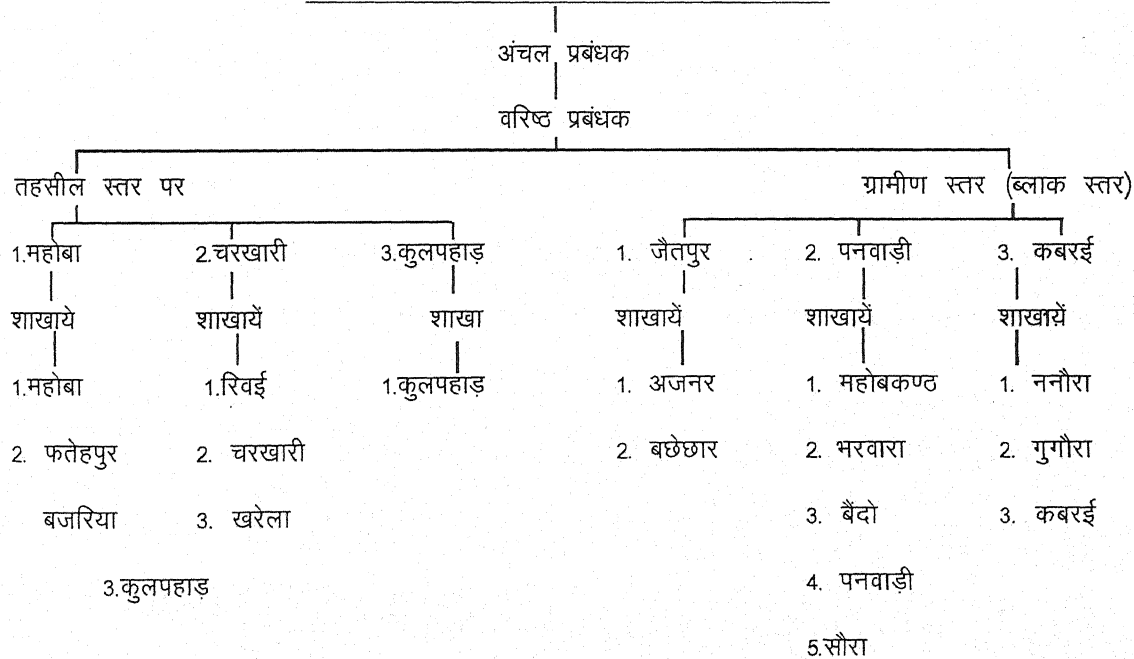
उपर्युक्त सारिणी मे जनपदवार छत्रसाल ग्रामीण बैंक की प्रबंध व्यवस्था को दर्शाया गया है । जिसमें शीर्ष स्तर पर अंचल प्रबंधक होते है अंचल प्रबंधक प्रत्येक जिले मे एक होता है । इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक होता है जो कि प्रत्येक जिले में एक होता है परन्तु इसके बाद तहसील स्तर की व्यवस्था आती है इनके कार्य भिन्न भिन्न होते है जो कि निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट होते हैं।
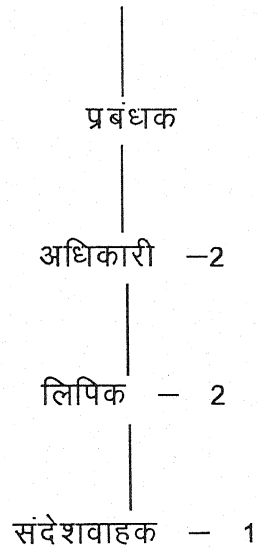
<u>प्रबन्धक –</u>

तहसील स्तर की प्रबंध व्यवस्था अलग होती है वहां पर शीर्ष प्रबंध पर शीर्ष प्रबंध का कार्य प्रबंधक देखता है और मध्य स्तर पर दो अधिकारी तथा दो लिपिक आते हैं और निम्न स्तर पर संदेशवाहक आते है जो कि एक होता हैं यह व्यवस्था महोबा, चरखारी कुलपहाड़ की एक सी है क्योकि उक्त तीन तहसील के अन्तर्गत आती है इसलिए तीनों की प्रबंध व्यवस्था भी समान है इनके कार्य भी इनके पद के हिसाब से भिन्न–भिन्न होते हैं जो कि निम्न हैं।

<u>प्रबंधक के कार्य –</u>

प्रबंधक के कार्यो के अन्तर्गत प्रत्येक छत्रसाल ग्रामीण बैंक के प्रबंधक का मुख्य कार्य ऋण का वितरण करना होता है तथा अन्य चीजों के लिए स्वीकृतियों को पास करता है।

अधिकारी –

प्रत्येक तहसील की शाखाओं मे दो अधिकारी होते हैं जिनका कर्तव्य या कार्य उस क्षेत्र का भ्रमण करना, ऋण का मूल्यांकन करना तथा अन्य अनेक कार्य होते हैं।

लिपिक –

प्रत्येक तहसील की शाखाओं मे दो लिपिक होते है जिसमे एक लिपिक खजान्ची का कार्य करता है जिसमे कैश का लेन देन आता है तथा दूसरा लिपिक काउण्टर मे बैठकर अन्य लिपिकीय कार्य करता है।

सन्देशवाहक –

यह प्रत्येक शाखा में एक होता है जो चपरासी के अन्तर्गत आने वाले अन्य कार्य व सहयोग से सम्बंधित कार्य करता है।

ग्रामीण स्तर की प्रबंध व्यवस्था
|
प्रबन्धक
|
लिपिक
|
संदेशवाहक
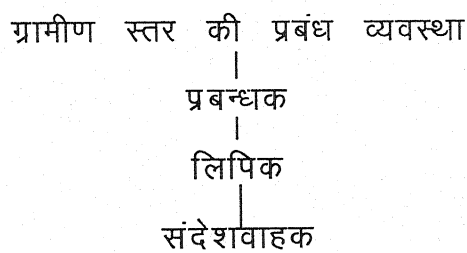
ग्रामीण स्तर के अन्तर्गत कई ग्राम आते हैं जैसे जैतपुर, पनवाड़ी व कबरई ब्लाकों के अन्तर्गत कई शाखाये है जैसे– जैतपुर के अर्न्तगत अजनर व बछेछर, पनवाड़ी के अर्न्तगत महोबकण्ठ, भरवारा बैदो पनवाड़ी व सौरा और कबरई के अन्तर्गत ननोरा गुगौरा व कबरई ग्राम मे एक शाखा है इनकी प्रबंध व्यवस्था मे भी थोड़ा अन्तर पाया जाता है इसमे एक प्रबन्धक एक लिपिक व संदेशवाहक आते हैं। जिनके कार्य निम्नलिखित हैं :–

प्रबंधक का कार्य ऋण वितरण करना व अन्य स्वीकृतियों को प्रदान करना आदि है । इसके तहसील स्तर के प्रबंधक की भांति ही कार्य होते हैं।

इसमे मध्यस्तर पर लिपिक होता है जो कि कैश के लेन देन का कार्य तथा काउण्टर पर बैठकर होने वाले दोनों कार्यो को करता है।

तीसरे नम्बर पर निम्न स्तर मे संदेशवाहक आते हैं जो चपरासी से सम्बंधित कार्य करते है और अन्य प्रकार के सहयोगात्मक कार्यो को करते हैं।

उपर्युक्त ग्रामीण–स्तर की प्रबंध व्यवस्था थी।

रिटेल बैंकिंग बुटीक –

रिटेल बैकिंग बुटीक प्रत्येक जिले मे एक होता है और यह प्रमुख रूप से सरकारी कर्मचारियों को ऋण प्रदान करती है इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है यह कई प्रकार के ऋण प्रदान करती है जैसे वैयक्तिक ऋण, भवन ऋण, शिक्षा के लिए ऋण व कार आदि के लिए अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के उद्देश्य एवं कार्य

छत्रसाल ग्रामीण बैंक भी अन्य की भांति जनता को वह सारी सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो अन्य बैंक कराते हैं जैसे बचत को बढ़ावा देना, ऋण प्रदान करना, जमाओं को स्वीकृत करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना परन्तु यदि छत्रसाल बैंक अन्य बैंको से अलग है तो इसका कारण यह है कि बैंक ग्रामीणो को तथा पिछड़े वर्गो के लिए ऋण की व्यवस्था करता है छत्रसाल ग्रामीण बैंक के उद्देश्य व कार्य निम्नलिखित हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े हुए वर्गो को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। पिछड़े वर्ग में छोटे एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, खेतिहर मजदूर खुदरा व्यापारी स्वरोजगार मे संलग्न व्यक्ति आदि शामिल किये जाते हैं।
2. महोबा जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों मे साख सुविधाओं की कमी को दूर करने का प्रयत्न करना।
3. छत्रसाल ग्रामीण बैंक क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओ के आंकलन के पश्चात् साख की व्यवस्था करना है।
4. सहकारी समितियों, विपणन समितियों, कृषि सम्बंधी परिष्करण समितियों सहकारी कृषि समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अथवा कृषि उद्देश्यों के लिए किसानो की सेवा समितियां बनाना।
5. महोबा जनपद के ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयत्न करना।

6. जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को जुटाना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों मे उत्पादक कार्यो के लिए उपयोग मे लाना।

7. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरों का सृजन करता है। ताकि ग्रामीणो के जीविकोपार्जन का इन्तजाम हो सकें।

8. अनुत्पादक आस्तियों में कमी लाये जाने हेतु प्रतिफल जनित प्रयास करना।

9. सेवा क्षेत्र के प्रत्येक कृषक को कार्ड सुविधा से आच्छादित किये जाने एवं लघु व सीमान्त कृषको को प्राथमिकता देना।

10. चयनित आदर्श ग्राम में किसान क्लब स्थापित कर अपना बैकिंग सेटेलाइट लान्च करना।

11. किसान क्लब के माध्यम से एस0 एच0 जी0 गठित करना, ताकि व्यक्ति ऋणों की संभावनाये उत्पन्न हो साथ ही गुणवत्तापूर्ण नये ऋण प्रस्तावो की प्राप्ति एवं वसूली प्रक्रिया को लागू किये जाने हेतु नेटवर्क स्थापित करना।

12. शासकीय योजनाओं मे कृषि आधारित पृष्ठभूमि एवं सुनिश्चित विपणन व्यवस्था रखने वाले गुणवत्तापूर्ण अग्रिमो को प्राथमिकता प्रदान करना।

13. जमा संग्रहण में सरकारी जमाओं पर निर्भरता कम कर पब्लिक जमा बढ़ाने पर जोर ताकि औसत जमा व्यवस्थित रहे।

14. निधि प्रबंधन, स्टाफ सामंजस्य, ग्राहकों एवं सरकारी एजेन्सियों के प्रति सद्‌भाव एवं सेवा भाव मे गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास।

15. महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक उत्थान हेतु कारगर प्रयास।

16. बैंक के कुछ प्राथमिक या मुख्य कार्य है जिनमे जमा स्वीकार करना, चालू निक्षेप स्थायी निक्षेप, बचत खाता, गृह बचत खाता, ऋण प्रदान करना के अन्तर्गत नकद साख अधिविकर्ष या ओरवड्राफ्ट । ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना, सरकारी प्रतिभूतियों मे विनियोग, विनिमय पत्रो की कटौती करना, साख निर्माण का कार्य करना आदि है।

17. इसके अतिरिक्त प्रबंध के कुछ गौण कार्य है जिसमे एजेंसी सेवाओं के अन्तर्गत साख पत्रों के भुगतान का संग्रह, ग्राहकों की ओर से भुगतान, भुगतान संग्रह करना,

धन का स्थानानतरण और ट्रस्ट आदि के कार्य है। इसमें वह कुछ सामान्य उपयोगिता सम्बंधी कार्य भी करता है। जिनमें बहुमूल्य धातुओं की रक्षा, साख प्रमाण पत्रों को प्रदान करना, वस्तुओं के वाहन मे विदेशी विनिमय का लेनदेन करना, आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना आदि है।

18. इसके अतिरिक्त बैंक कुछ सामाजिक विकास व आर्थिक विकास सम्बंधी कार्य करता है । जिसमें पूंजी की उत्पादकता मे वृद्धि करना, कोषों के हस्तान्तरण की सुविधा, विनियोग एवं अर्थ प्रबन्धन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, विभिन्न क्षेत्रों में कोषों मुद्रा प्रणाली मे लोच व अन्य सामाजिक कार्य करता है जिनका विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

इस प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक के अनेक कार्य व उद्देश्य हैं जिन्हें वह पूरा करता है और कुछ को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। छत्रसाल ग्रामीण बैंक जिन कार्यो को कर चुका है वह निम्नलिखित है।

प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक की प्रगति पूर्णतया इस बात पर निर्भर करती है कि वह बदली हुयी उपभोक्ताओं के अनुरूप अपने कदम कितने मिला पा रहे है इसी दृष्टिकोण से अपने को (New Generation) बैंक के रूप मे अपने ग्राहकों के समान प्रस्तुत करने का इसका लक्ष्य है व संकल्प है और इसकी प्राप्ति के लिए बैंक की प्रत्येक योजना का मूलबिन्दु सम्मानित ग्राहक एवं उनको प्राप्त होने वाली सुविधाये होगी। बैंक अपने सेवा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को उनकी आवश्यकतानुसार किसी न किसी रूप मे अपनी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रसिद्ध है। इनका उद्देश्य है कि हानि वाले वर्ष मे कुल संचयी हानि को समाप्त करते हुए शुद्ध लाभ की स्थिति मे पहुंचकर एक दीर्घकालीन व्यवहार्यता के साथ आगे बढ़ेगें। इसके अतिरिक्त बैंक का उद्देश्य आने वाले समय मे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए सेवा क्षेत्र के प्रत्येक गांव का प्रत्येक परिवार किसी न किसी रूप मे इस बैंक से अवश्य ही जुड़े इनका उद्देश्य बैकिंग सेवाओं को जमा निकासी एवं ऋण सम्बंधो का वाहक बनाना है आर्थिक विपन्न तथा पिछड़े वर्गो में बैकिंग व्यवसाय करना इनकी उन्नति में बाधक नही है अपितु उक्त कार्य बैंक को एक नयी चुनौती प्रदान करता है निर्धन एवं जरूरतमन्द वर्गो की संवेदनाओ को आत्मसात

करते हुए इस बैंक को अपने प्रति अपनेपन का भाव जाग्रत करना है नई चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक उन्नयन की ओर विशेष ध्यान दे रहे है इसके लिए जनशक्ति एवं संसाधनो दोनो के संतुलित विकास पर ध्यान किया जा रहा है इसी दिशा मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक की 40 शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदत्त की जाने वाली बैकिंग सेवाओं का स्वरूप

साधारण शब्दों में बैंक के दो अनिवार्य कृत्य होते हैं –

1. लोगों से जमा राशियां स्वीकार करना और अपनी निधियां उधार तथा विनियोजित करना। ये दोनो कृत्य ही बैंक व्यापार कहलाते है लेकिन आधुनिक बैंकर इन कृत्यो के अलावा अनेक अनुषंगिक सेवायें भी करता है।

सरकार द्वारा जब किसी बैंक की स्थापना की जाती है तो उसे स्थापित करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित करने का भी कुछ उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी है जिसकी कई शाखाये देश भर मे फैली हुयी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा जो महोबा जनपद मे खुली है उसका नाम है छत्रसाल ग्रामीण बैंक और इस अध्याय के अन्तर्गत हम छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन करेंगे।

इसके अन्तर्गत कुछ नई प्रमुख योजनायें लागू की गयी है –

1. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना
2. छत्रसाल मोबाइल ऋण योजना
3. किसान समृद्धि योजना
4. काश्तकारों एवं मौखिक पट्टेदारों को वित्तपोषण की योजना
5. छत्रसाल ग्रामीण बैंक गृहसज्जा वित्त योजना

वर्ष 2004–05 मे उक्त योजनायें चलायी गयी है उनकी स्थिति निम्न प्रकार है–

1. छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड –

कृषि क्षेत्र में अग्रिमों को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हेतु विशेष बल दिया

गया और बैंक द्वारा रूपये 515868 हजार की धनराशि के 16427 किसान क्रेडिट कार्ड वर्तमान वर्ष मे वितरित किये गये बैंक द्वारा 31 मार्च 2005 तक कुल 40470 किसान कार्ड राशि रूपये 1224107 हजार के निर्गत किये गये। प्रत्येक कार्डधारक बैंक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित है।

2. छत्रसाल किसान समृद्धि योजना –

वर्ष के दौरान 1975 कृषकों को रूपये 131500 हजार के ऋण वितरित किये गये जो कृषि ऋण के प्रवाह को दोगुना करने मे सहायक हुए।

3. रिटैल बैकिंग बुटीक –

बैंक ने अपनी रिटेल बैकिंग बुटीक के माध्यम से वेतनभोगी कर्मचारियों स्वनियोजित एवं व्यवसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को वृहद स्तर पर साख सुविधा उपलब्ध कराई जिन पर बैंक को अच्छी आय प्राप्त हुयी। तीनों बुटीक्स द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय ऋणों का ब्योरा तालिका द्वारा अंकित है।

जनपद महोबा की योजनायें

तालिका 4.2

योजना	महोबा / खाता	रूपये हजार में राशि
1. सम्पत्ति सृजन योजना	–	–
2. वैयक्तिक खाता	131	9828
3. बचत खातों पर ओ डी सुविधा	37	198
4. कार / जीप ऋण	10	2570
5. गृह ऋण	04	675
6. शिक्षा ऋण	03	81
7. अन्य	33	1900
योग	218	15252

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक रिपोर्ट

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि कुल 218 खाते खोले गये तथा उनसे प्राप्त हुयी राशि 15,252 हजार रूपये है इसमे सबसे अधिक वैयक्तिक खाते खोले गये है और सम्पत्ति सृजन योजना के अन्तर्गत एक भी खाता नही खोला गया है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही हैं वे निम्नलिखित हैं जिनमे कुछ की प्रगति का वर्णन पीछे किया जा चुका है परन्तु निम्नलिखित का वर्णन आगे है ।

1. छत्रसाल सरल ऋण योजना
2. छत्रसाल ग्रामीण बैंक आवास योजना
3. छत्रसाल ग्रामीण बैंक शिक्षा ऋण योजना
4. छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना
5. छत्रसाल किसान समृद्धि योजना
6. छत्रसाल लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
7. मर्चेण्ट क्रेडिट योजना आदि।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनायें भी है जो छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा चलायी जाती है स्कीम फोरट्रेप वीह फॉरमर्स, एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स ट्रेक्टर, लैण्ड परचेज स्कीम फार फारमर्स, एलीड एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चर टर्म लोन, रूल हावर्स कम सब स्कीम, स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान, ग्रुप एण्ड अदर लोन अण्डर एस जी एस वाई, ग्रुप लोन अण्डर जनरल स्कीम, छत्रसाल स्वरोजगारी क्रेडिट कार्ड छत्रसाल मुबीक लोन स्कीम, लोन अगेन्स्ट हाउस रेन्ट टू हावर, वर्किंग केपिटल एण्ड टर्म लोन, रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटर फार वन वीट, लोन अगेन्स्ट एन0 एस0 सी0/के0 वी0 पी0, लोन अगेन्स्ट एन0 एस0 सी0/क0 वी0 पी0 स्टाफ टर्म लोन, एस0 बी0 ओ0/डी0 पर्सनल लोन स्कीम, छत्रसाल एजुकेशन लोन, छत्रसाल कम्प्यूटर लोन स्कीम, क्लीन ओवरड्राफ्ट टू बैंक स्टाफ, लोन टू परचेज कार एण्ड जीप, पब्लिक हाउसिंग लोन स्कीम आदि है। उपर्युक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

छत्रसाल सरल ऋण योजना –

1. आच्छादित वर्ग वैतनिक व्यक्तियों पेशेवर स्वनियोजित एवं कृषक
2. प्रायोजन – कोई भी उद्देश्य
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 10.00 लाख रूपये तक
4. मार्जिन – वैल्यूवेशन रिपोर्ट में सम्पत्ति की दर्शित वैल्यू का 50 प्रतिशत
5. पुनर्भुगतान की अवधि – 60 मासिक किश्तों में

छत्रसाल ग्रामीण बैंक आवास ऋण योजना–

1. आच्छादित वर्ग – वेतनभोगी कर्मचारी / व्यवसायी / स्वनियोजित व्यक्ति
2. प्रयोजन – भवन निर्माण, नवीनीकरण, विस्तार हेतु
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 10.00 लाख
4. मार्जिन – वेतन भोगी कर्मचारियो हेतु 15 प्रतिशत व्यवसायी / स्वनियोजित व्यक्ति हेतु 25 प्रतिशत
5. पुनर्भुगतान अवधि – 20 वर्ष

छत्रसाल ग्रामीण बैंक शाखा ऋण योजना–

1. आच्छादित वर्ग – भारतीय नागरिक जिसका प्रवेश परीक्षा / चयनित पद्धति से पेशेवर तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु हुआ हो।
2. ऋण की सीमा – भारत मे अध्ययन हेतु अधिकतम रूपये 7.50 लाख एवं विदेश हेतु रूपये 15.00 लाख
3. पुर्नभुगतान की अवधि – 7 वर्ष
4. स्थगन अवधि – पाठ्यक्रम अवधि के बाद 01 वर्ष या 06 माह नौकरी मिलने की स्थिति में जो पहले हो।

छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड –

1. आच्छादित वर्ग – सभी कृषक सिंचित / असिंचित भूमि के मालिक
2. प्रयोजन – अल्पकालिक कृषि ऋण
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 2.00 लाख तक

4. विशेष सुविधा – रूपये 15/– प्रीमियम पर रूपये 50,000/– का दुर्घटना बीमा एवं राष्ट्रीय फसल बीमा सुविधा।

<u>छत्रसाल किसान समृद्धि योजना –</u>

1. आच्छादित वर्ग – सभी प्रकार की सिंचित / असिंचित भूमि के संक्रमरणीय भूमिधर कृषक
2. उद्देश्य – मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण आवश्यकतायें तथा व्यक्तिगत आवश्यकताये।
3. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 5.00 लाख भूमि के सरकारी मूल्य का 50 प्रतिशत
4. चुकौती अवधि – 5 से 7 वर्ष

<u>छत्रसाल लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना–</u>

1. आच्छादित वर्ग – उद्योग सेवा व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यवसायी
2. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 2.00 लाख
3. वैधता की अवधि – 3 वर्ष
4. मार्जिन – 25 प्रतिशत

<u>मर्चेण्ट क्रेडिट योजना –</u>

1. आच्छादित वर्ग – सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग।
2. ऋण की सीमा – अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक किन्तु वार्षिक बिक्री का 20 प्रतिशत से अधिक नही हो।
3. मार्जिन – स्टाक वही ऋण की स्थिति पर 20 प्रतिशत
4. प्रायोजन – कैश / क्रेडिट कार्ड की सुविधा

इसके अतिरिक्त छत्रसाल ग्रामीण बैंक में जो योजनायें चलायी जा रही हैं उसके स्वरूप को सारिणी क्रमांक 4.3 के माध्यम से दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3

वार्षिक कार्य योजना में वित्त–पोषण की स्थिति

छत्रसाल ग्रामीण बैंक जिला (महोबा)

(राशि हजार में)

विवरण	31–3–01		31–3–02		31–3–03		31–3–04		31–3–05		योग		
वार्षिक कार्ययोजना	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1– अल्पाधिकृषि	14881	31929	30000	33766	33200	69427	43150	221810	64173	132500	185404	489432	263
2– सावधिकृषि	18357	8971	5595	6345	6200	5328	15340	69642	15283	30700	60769	120986	199
3– सहा0 कृषि	3418	4180	7405	1736	8200	706	7488	46428	9054	4500	35568	57550	161
4– उद्योग	2030	363	2400	135	2650	45	3445	14945	4300	950	14825	15638	105
5– सेवा एवं व्यवसाय	3930	1955	5500	675	6150	1634	7995	54395	10000	4200	33575	62859	187
6– प्राथमिक क्षेत्र	36331	47398	50900	42657	56400	77140	73320	407220	102813	172050	319764	746465	233
7– गैर प्राथमिक क्षेत्र	6770	9652	10300	12927	11330	15085	22680	92780	40000	14931	91080	145375	159
महायोग	43101	57050	61200	55584	67730	92225	96000	92780	142813	186981	410844	484570	1179

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

उर्पयुक्त सारणी में महोबा जनपद के विकास की ओर घ्यान दें तो इस बैंक के अन्तर्गत जो योजनाएं चलायी जा रही है वे इसके विकास की ओर इंगित कर रहें हो इस बैंक के अन्तर्गत जो अल्पावधि कषषि योजना है उसमें फसली ऋण व लघु सिंचाई के अर्न्तगत ऋण लिया जाता है जिसमें 2005 में 64173 का लक्ष्य रखा गया जिसमें 132500 रुपये उपलब्धि हुई इसकी वृद्धि दर 2004 की अपेक्षा 67% है। सावधि के अन्तर्गत कुँआ पम्पसेट व बैलजोड़ी आदि के लिए ऋण दिया जाता है जिसका कुल लक्ष्य वर्ष 2005 में 15283 हजार था। और जिसकी उपलब्धि 30700 हजार रुपये हुई। सहायक कषषि के अर्न्तगत गैस लकड़ी , डेरी , मत्स्य पालन, सुअर पालन आादि के लिए ऋण दिया जाता है। सेवा एवं व्यवसाय में सर्विस , कढ़ाई , बुनाई , सिलाई आादि आते है। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2005 में अन्य सेवाओं का लक्ष्य जितना रखा गया उपलब्धि उसकी तुलना में कम हुई है। यदि हम इसका कुल योग करें तो वर्ष 2001 में लक्ष्य की अपेक्षा उपलब्धि अधिक थी। वर्ष 2002 में उपलब्धि कम, वर्ष 2003 उपलब्धि अधिक व 2004 में उपलब्धि अधिक तथा 2005 में लक्ष्य की अपेक्षा उपलब्धि कम रही। गैर–प्राथमिक क्षेत्र के अर्न्तगत स्वय की जमाओं के आधार पर ऋण मिलता है जिसमें वर्ष 2005 में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि अधिक रही।

छत्रसाल ग्रामीण, बैंक की पूंजी संरचना –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की पूंजी संरचना के अन्तर्गत निम्न को शामिल करेंगे।

अंश पूंजी सन् 1998–99 / 1999–2000

बैंक की पूंजी भारत सरकार प्रवर्तक बैंक व प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50:35:15 प्रतिशत की दर से कुल 10,000 हजार रूपये प्रदत्त की गयी है। पुर्नगठन के द्वितीय चरण मे चयनित बैंक को तुलनपत्र शोधन व तरल सहायता के रूप मे प्रदत्त रूपये 1,39695 हजार को अंश पूंजी जमा खाता मे प्रवर्तक बैंक मे रखा गया है।

तरल सहायता के रूप मे रूपये 28.450 हजार मे भारत सरकार एवं प्रवर्तक बैंक के अंश प्राप्त है किन्तु राज्य सरकार का अंश रूपये 4.267 हजार अभी भी प्राप्त होना शेष है।

जमा – बैंक की लाभप्रदता व वित्तीय सुदृढता मे जमा राशियों का विशेष महत्व है विपरीत परिस्थितियों व प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के उपरान्त भी बैंक कार्यक्षेत्र की जनता से जमाराशियो हेतु संपर्क करके उन्हे उसकी ओर प्रेरित किया गया है।

अंश पूंजी 2000–2001 / 2001–02

बैंक की अधिकृत अंश पूंजी रूपये 50,000 है जिसमें चुकता अंश पूंजी रूपये 10,000 है जो 50 : 35 : 15 के अनुपातिक भाग मे क्रमशः केन्द्र सरकार प्रवर्तक बैंक व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है।

अतिरिक्त इक्विटी के रूप मे चिट्ठा में शोधन हेतु रूपये 143962 हजार की राशि स्वीकृति थी जिसमे निम्नवत् राशि प्राप्त है।

अंशधारक	चुकता पूंजी	अंशपूंजी जमा
केन्द्र सरकार	5000	71981
प्रवर्तक बैंक	3500	50387
राज्य सरकार	1500	17326
	10,000	139694

अंश पूंजी 2002–03 / 2003–04

बैंक की अंशपूंजी भारत सरकार प्रवर्तक बैंक व प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 50. 35 व 15 के अनुपात में प्रदत्त है बैंक की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 5 करोड है जिसमे चुकता पूंजी अंशपूजी रूपये एक करोड़ है।

तुलनपत्र शोधन एवं तरलता सहायता हेतु बैंक को इसके अंशदाताओं द्वारा रूपये 143962000/– की स्वीकृति के सापेक्ष रूपये 13964000 की अतिरिक्त अंशपूंजी भी उपर्युक्त अनुपात मे प्राप्त हो चुकी है प्राप्त धनराशि को अंशपूंजी जमा खाते मे रखा गया है । शेष राशि रूपये 426800/– जो कि राज्य सरकार का अंश है अभी तक अप्राप्त है। परन्तु यह वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो गया।

अंश पूंजी 2004–05

बैंक की प्राधिकृत पूंजी रूपये 500 लाख के सापेक्ष चुकता पूंजी रूपये 100 लाख है जिसमे भारत सरकार प्रवर्तक बैंक व उत्तर प्रदेश सरकार का अंशदान क्रमशः 50 : 35 : 15 के अनुपात में है।

तुलनपत्र शोधन एवं तरलता सहायता हेतु बैंक को इसके अंशदाताओं द्वारा स्वीकृत रूपये 143962500/– की अतिरिक्त अंशपूंजी भी उपयुक्त अनुपात मे प्राप्त हो चुकी है प्राप्त धनराशि की अंशपूंजी को जमा खाते मे रखा गया है पिछले वर्षो मे सन् 1998 से 2005 तक की जमा वृद्धि तथा लागत को एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नलिखित है।

तालिका 4.4

छत्रसाल ग्रामीण बैंक

जमा वर्गीकरण, वृद्धि एवं लागत

विवरण	1997-98	1998-99	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1. कुल जमा							
अ. खाता	309141	101548	201979	211720	221263	235629	225501
ब. राशि	986147	1358978	1654998	1863065	2136045	2487263	2810301
2. जमा वृद्धि	18.31 प्रतिशत	14.59 प्रतिशत	21.78 प्रतिशत	12.57 प्रतिशत	14.65प्रतिशत	16.44प्रतिशत	12.99प्रतिशत
3. जमा वर्गीकरण							
अ. चालू	52013	80258	105490	122614	138029	157118	223738
ब. बचत बैंक	540272	738615	888605	992325	1230305	146003	1739734
स. मियादी	393862	540105	660903	748126	767711	870112	846829
4. मांग जमा का	–	60.26 प्रतिशत	60.07 प्रतिशत	59.84प्रतिशत	64.06प्रतिशत	65.02प्रतिशत	69.87प्रतिशत
5. जमा लागत	6.49 प्रतिशत	6.48 प्रतिशत	6.28 प्रतिशत	6.03प्रतिशत	5.54प्रतिशत	4.69प्रतिशत	4.30प्रतिशत
6. जमा प्रति							
अ. शाखा	12026	16373	19471	21918	25130	29610	33456
ब. कर्मचारी	2961	4081	4955	5578	8683	10194	8490

उपर्युक्त सारिणी में सन् 1997–98 मे कुल जमा 986147 लाख रूपये थी सन् 1998–99 में कुल जमा 118549 लाख रही बैंक के कार्यक्षेत्र मे इस वर्ष जमा राशियों मे 199802 लाख की बढ़ोत्तरी हुयी तथा जमा राशियों पर यह वृद्धि दर 18.31 प्रतिशत से बढ़कर 1998–99 मे 20.26 प्रतिशत अर्थात् 1.95 प्रतिशत अधिक रही बैंक की कुल जमा राशियों में न्यून लागत वाली राशियों का प्रतिशत 6.51 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष 6.49 प्रतिशत के स्तर मे .02 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमा राशियां बढ़कर रूपये 14463 एवं रूपये 3551 हजार पहुंच गयी।

इसी प्रकार जब हम 1999–2000 तथा 2000–01 के वर्षो का अवलोकन करते है तब हम पाते है कि 1999–2000 में कुल जमा 201548 लाख रूपये थी जो कि सन् 2000–01 मे बढ़कर 201975 लाख रूपये हो गयी जो कि 431 लाख रूपेय की वृद्धि को दर्ज कराता है तथा जमा राशियों पर यह वृद्धि दर 21.78 प्रतिशत तथा 12.57 प्रतिशत है जो कि 9.21 प्रतिशत की कमी दर्शाता है बैंक का मांग जमा राशियों का यह प्रतिशत 2001–02 मे 59.84 प्रतिशत तथा 2000–01 में 60.7 प्रतिशत जो कि .23 प्रतिशत कमी

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक रिपोर्ट।

को दर्शाता है वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां बढ़कर क्रमशः 21918 एवं 5578 हजार पहुंच गयी जो कि क्रमशः 2447 व 623 की वृद्धि दर को दर्शाती है।

जब हम वर्ष 2001–02 की वित्तीय वर्ष 2002–03 से तुलना करते है तब देखते है कि बैंक के कार्यक्षेत्र मे अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान जमाराशियों मे रूपये 272980 हजार की वृद्धि की गयी है। विगत वर्षो की जमाराशियों पर वृद्धि दर 14.65 प्रतिशत प्राप्त करते हुए सहमति ज्ञापन पत्र मे जमाराशियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रूपये 2250000 हजार के सापेक्ष रूपये 2136045 हजार का जमा राशि स्तर प्राप्त किया गया। बैंक की कुल जमाराशियों मे निम्नलिखित वाली जमाओं का प्रतिशत 64.06 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष के 59.85 प्रतिशत के स्तर मे 4.21 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करता है । परिणामतः जमा राशियों की लागत 6.03 प्रतिशत से घटकर 5.54 प्रतिशत हो गयी। वर्ष के दौरान प्रति शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां बढकर क्रमशः रूपये 25130 एवं रूपये 8683 हजार पहुंच गयी।

अब हमारी अवलोकन वर्ष 2002–03 से 2003–04 है जिसकी स्थिति के अन्तर्गत बैंक की लाभप्रदता एवं ऋणराशियों के विस्तार हेतु जमाराशियों का विशिष्ट स्थान है । जमाराशियो के संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किया गया है जिसमे ग्रामीणो के मध्य बचत करने की प्रवृत्ति पैदा करके उन्हे जमा हेतु प्रेरित करना ताकि कम मूल्य की जमाराशियां संग्रहित कर बैंक की आय मे अधिकाधिक वृद्धि की जाये। इस वर्ष जमा वृद्धि हेतु उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया। बैंक के कार्यक्षेत्र में अत्यन्त कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद बैंक के द्वारा वर्ष के दौरान जमाराशियों में रूपये 351218 हजार की वृद्धि की गयी। विगत वर्ष की जमा राशियों पर वृद्धि दर 16.44 प्रतिशत प्राप्त करते हुए सहमति ज्ञापन पत्र मे जमाराशियों हेतु निर्धारित लक्ष्य रूपये 2500000 हजार के सापेक्ष रूपये 2487263 हजार का जमा राशि स्तर प्राप्त किया गया। बैंक की कुल जमा राशियों मे निम्न लागत वाली जमाओं का प्रतिशत 65.02 प्रतिशत रहा जो कि गत वर्ष के 64.06 प्रतात के स्तर मे 0.96 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित करता है। परिणामतः जमा राशियो की लागत 5.54 प्रतिशत से घटकर 4.69 प्रतिशत हो गयी। वर्ष के दौरान प्रति

शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां बढ़कर क्रमशः रूपये 29610 एवं रूपये 10194 हजार पहुंच गयी।

वर्ष 2003–04 का 2004–05 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि 31 मार्च 2005 को बैंक की जमाराशियां रूपये 28103.01 लाख रही। बैंक के कार्यक्षेत्र मे बैंक ने अपनी मेहनत व कुशलता द्वारा जमाराशियों मे रूपये 3230.38 लख की वृद्धि प्राप्त की गयी। पिछले वर्ष की जमा राशियों पर वृद्धि दर 12.99 प्रतिशत रही बैंक की कुल जमाराशियों मे न्यून लागत वाली राशियों का प्रतिफल 69.87 प्रतिशत रहा।जो कि पिछले वर्ष 65.02 प्रतिशत के स्तर मे 4.65 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करता है परिणामतः जमा राशियो की लागत 4.69 प्रतिशत से घटकर 4.30 हो गयी पिछले वर्षो की भांति इसकी भी शाखा एवं प्रति कर्मचारी जमाराशियां बढ़कर क्रमशः रूपये 33456 एवं रूपये 08490 हजार पहुंच गयी बैंक की जमाओं का श्रेणीवार विवरण सारिणी मे प्रदर्शित किया गया है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की सेवाओं के योगदान का मूल्यांकन –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक 30 मार्च 1982 से स्थापित है तब से लेकर आज तक इस बैंक ने अपने कार्यो में निरन्तर प्रगति की है यदि किसी वर्ष यह हानि में गया है तो अगले ही वर्ष इस बैंक ने अपने आपको पुर्नस्थापित कर लिया है। इस अध्याय के अन्तर्गत बैंक द्वारा उपलब्ध उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे।

वर्ष 2001 व 2002 मे बैंक द्वारा रूपये 261772.36 लाख के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया जिसमे ऋण जमा अंश क्रमशः रूपये 8141.72 लाख व रूपये 18630. 64 लाख रहे तथा ऋण जमा अनुपात 43.70 प्रतिशत है वर्ष 2000–2001 में जहां 25 शाखाये हानि मे चल रही थी वे अब घटकर 15 रह गयी। समूह अभिधारणा पर पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के फलस्वरूप आज बैंक 1005 एस एच जी एवं 10 किसान क्लबों के साथ कार्यरत है जिनकी कुल जमा पूँजी रूपये 20.10 लाख के सापेक्ष रूपये 48.10 लाख का वित्त पोषण किया गया था समूह के गठन एवं सशक्तीकरण में एन जी ओ एवं बैंक स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस जागरूकता के लिए राष्ट्रीय बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है बैंक द्वारा 10 किसान क्लबों का गठन किया जा चुका

है। और आगामी वर्षो में इन्हें 50 तक पहुंचाकर समूहों से जुड़ाव हेतु सेतु तैयार किये गये है।

इसी क्रम में वर्ष 2002–03 मे बैंक द्वारा रूपये 21360 लाख के जमा तथा रूपये 10278 लाख के ऋणों के साथ कुल रूपये 3638 लाख के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया है। अनुत्पादक आस्तियों के स्तर मे कमी करके इसे 16.73 प्रतिशत तक लाया गया है जबकि ऋण जमा अनुपात में बढ़ोत्तरी के साथ 48.12 प्रतिशत के सम्मानजनक स्तर को प्राप्त किया गया है। बैंक ने रूपये 5396 लाख के लाभ को अर्जित किया है जिससे बैंक की रूपये 442.29 लाख की संचयी हानियों के समायोजन के पश्चात् रूपये 11.67 लाख के शुद्ध लाभ की सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुयी है। उत्कृष्ट वित्तीय परिणामो तथा बहुप्रतीक्षित प्रोन्नति प्रक्रिया के सपफलतापूर्वक पूर्व होने से बैंक कर्मियो मे नवीन स्फूर्ति का संचरण हुआ जिससे भविष्य मे और अधिक अच्छे परिणाम सामने आये। 1600 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं 600 समूहों का वित्तपोषण इस तथ्य का द्योतक है कि राष्ट्रीय महत्व के उक्त कार्यक्रम को जन आन्दोलन बनाने की दिशा मे बैंक ने विशिष्ट प्रयास किया है। विभिन्न शाखाओं में 50 किसान क्लबों का गठन करने का बैंको का प्रयास रहा है कि बैंक निर्णयो के प्रत्येक स्तर पर उचित पारदर्शिता आये एवं अधिकाधिक जन सहभागिता प्राप्त कर क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाये।

इसी प्रकार वर्ष 2003–04 मे बैंक के द्वारा रूपये 24873 लाख के जमा तथा रूपये 13453 लाख के ऋणों के साथ कुल रूपये 38326 लाख के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया गया है। गत वर्ष के ऋण जमा अनुपात 48.12 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष मे 54 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया। 2127 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं 975 समूहों का वित्तपोषण इस तथ्य को बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में जन आन्दोलन बनाने की दिशा में बैंक ने विशिष्ट प्रयास किया है विभिन्न शाखाओ में 53 किसान क्लबों का गठन कर छत्रसाल ग्रामीण बैंक का यह प्रयास रहा है कि बैंक निर्णयो के प्रत्येक स्तर पर उचित पारदर्शिता आय एवं अधिक से अधिक जन सहभागिता कर बैंक के आर्थिक विकास को बढ़ाया जाये।

वर्ष 2004–05 की स्थिति दर्शाता है कि कृषि प्रवाह को दोगुना करने के शासन के दिशा निर्देशो का अनुपालन करते हुए विगत वर्ष के रूपये 894975 हजार के सापेक्ष रूपये 1406473 हजार की उपलब्धि हासिल की गयी जो कि 57.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है बैंक ने रूपये 02810301 हजार के जमा तथा रूपये 1835524 हजार के ऋणो के साथ कुल रूपये 4645825 हजार के व्यवसाय स्तर को प्राप्त किया है। अनुत्पादक आस्तियो के स्तर में कमी करके इसे 8.77 प्रतिशत पर लाया गया है। गत वर्ष के जमा अनुपात 54.09 के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष मे 65.31 प्रतिशत के स्तर को प्राप्त किया गया है। बैंक ने जमा योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूह जैसे कार्यक्रमों की मदद से ग्रामीणों में बचत की आदत का विकास किया। समाज के प्रत्येक वर्ग की बैकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण तथा जमा योजनायें बैंक के पास है तथा इन्हें जनसामान्य का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे ग्राहकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है।

इस प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक इस बैंक की सफलता के लिए नये-नये आयाम स्थापित कर रहा है जिससे भविष्य में भी यह बैंक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता रहे ।

अग्रलिखित सारिणयों में महोबा जनपद की सेवाओं के योगदान का शाखावार मूल्यांकन किया गया है जिसमें बैंक की जमाराशि, ऋणराशि तथा लाभ–हानि को दर्शाया गया है ।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक जनपद महोबा (राशि हजार में) तालिका–4.5

विकासखण्ड	शाखा का नाम	शुभारम्भ की तिथि	2003 जमा राशि	2003 ऋण धनराशि	2004 जमाराशि	2004 ऋण धनराशि	2005 जमा राशि	2005 ऋण धनराशि
महोबा / जैतपुर								
1.	अजनर	10.12.1982	24085	14485	23731	18705	27485	26705
2.	बछेछर लमौरा	28.3.84	7641	18022	9054	19373	10661	22062
3.	कुलपहाड़	27.3.85	30457	9971	26696	10523	35686	15818
योग			62183	42478	59481	48601	73832	64585
महोबा / चरखारी								
1.	रिवई	20.6.83	8861	11877	9332	15090	20278	358
2.	बम्हौरी कलां	28.3.85	1967	3769	–	–	–	–
3.	चरखारी	27.3.85	74069	11884	75801	12982	17075	1688
4.	खरेला	30.12.87	7411	2905	8113	6492	16224	198
योग			25708	30435	93286	34564	53577	2244
महोबा / पनवाडी								
1	महोबगंठ	10.12.82	9349	19296	10459	20744	28284	552
2	भरवारा	24.6.83	10252	14306	12332	16496	24650	752
3	बैदो	24.6.83	12661	8130	12945	9779	16082	677
4	पनवाडी	28.3.85	27968	10027	27018	11008	19669	647
5	सौरा	26.11.87	2596	9487	2669	11044	18676	173
योग			62826	61246	65423	69071	107361	2801
महोबा / कबरई								
1	फतेहपुर बजरिया	20.6.83	39163	9286	43578	11377	63766	27302
2	ननोरा	20.6.83	7443	8556	8027	12588	10248	15816
3	गहरा	28.3.84	3328	6432	5641	11572	5516	14615
4	सिजहरी	15.6.84	12976	7745	28673	11461	34255	19400
5	महोबा	27.8.85	132714	22614	167151	47113	218886	43505
6	कबरई	29.8.2000	40258	6554	56548	10244	59678	17505
योग			235882	61187	309618	104355	392349	138142

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

उपर्युक्त सारिणी में हमने महोबा जनपद की शाखावार जमाराशियों व ऋणधनराशि को दर्शाया है यदि इस सारिणी का अवलोकन करे तो हम पाते है कि महोबा जनपद के जैतपुर ब्लाक मे बछेछर लमोरा मे सबसे कम जमा धनराशि आयी है 2003 में जमा धनराशि के सापेक्ष ऋण धनराशि 17381 हजार का अन्तर दर्शाती है। यह अन्तर 2005 तक 11401 हजार बना रहा। बाकी शाखाओं में जमा धनराशि की अपेक्षा ऋण धनराशि का प्रतिशत कम है।

महोबा जनपद के चरखारी ब्लाक का अवलोकन करने पर पता चलता है कि यहां की बम्हौरीकला शाखा मे जमा धनराशि 1967 हजार रूपये है जबकि ऋण राशि 3769 है 2004 व 2005 में कोई राशि नही है यह शाखा न ही जमाराशि प्राप्त कर पायी है और न ही इसने ऋण वितरित किये है इसलिए इस शाखा को 2004 मे समाप्त कर दिया गया।

पनवाड़ी ब्लाक की शाखाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने पर पता चलता है कि बैंदो की शाखाओं में जमा धनराशि की स्थिति तो अच्छी है परन्तु ऋण वितरण कम हुए है वर्ष 2005 मे महोबकंठ में सबसे अधिक जमाराशि है और पांचवे स्थान पर बैंदो है जिसमें ऋण वितरण की स्थिति सबसे अधिक भरवारा में है तथा सबसे कम सौरा में है।

कबरई ब्लाक के अन्तर्गत वर्ष 2005 मे महोबा में सबसे अधिक धनराशि जमा हुयी है इसके बाद दूसरा स्थान फतेहपुर बजरिया की शाखा का है परन्तु छटवां स्थान गहरा का है जमा राशि के साथ साथ ऋण राशि भी महोबा जनपद की सबसे अधिक है अन्य शाखाओ की अपेक्षा महोबा की स्थिति सन्तोषप्रद है।

तालिका 4.6

छत्रसाल ग्रामीण बैंक जनपद-महोबा

(राशि हज़ारों में)

विकास खण्ड	शाखा का नाम	शुभारम्भ की तिथि	2002		2003		2004		2005	
			लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
महोबा/जैतपुर										
1.	अजनर	10–12–1982	591	—	755	—	431	—	993	—
2.	बछेछर लमौरा	28–03–1984	216	—	140	—	49	—	454	—
3.	कुलपहाड़	27–03–1985	621	—	590	—	468	—	616	—
महोबा/चरखारी										
1.	रिवई	20–06–1983	—	128	137	—	14	—	358	—
2.	बम्हौरी कलां	28–03–1985	—	242	—	—	—	—	—	—
3.	चरखारी	27–03–1985	2048	—	2859	—	2005	—	1688	—
4.	खरेला	30–12–1987	—	98	84	—	4	—	198	—
महोबा/पनवाड़ी										
1.	महोबकंठ	10–12–1982	48	—	144	—	174	—	552	—
2.	भरवारा	24–06–1983	501	—	462	—	422	—	752	—
3.	बैंदों	24–06–1983	32	—	366	—	103	—	677	—
4.	पनवाड़ी	28–03–1985	1017	—	1056	—	452	—	647	—
5.	सैारा	26–11–1987	15	—	145	—	28	—	173	—
महोबा/कबरई										
1.	फतेहपुर बजरिया	26–06–1983	889	—	1112	—	748	—	1321	—
2.	ननौरा	20–06–1983	50	—	137	—	108	—	198	—
3.	गहरा	28–03–1984	—	60	05	—	—	384	3	—
4.	सिजहरी	15–06–1984	579	—	603	—	406	—	765	—
5.	महोबा	27–08–1985	5821	—	7202	—	5290	—	6643	—
6.	कबरई	29–08–2000	253	—	1206	—	1346	—	1423	—

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

महोबा जनपद के छत्रसाल ग्रामीण बैंक की लाभ और हानियों का शाखावार अवलोकन करने पर हम पाते है कि एक वर्ष 2003 में जैतपुर ब्लाक की तीनो शाखाओ ने लाभ अर्जित किये हैं वर्ष 2004 व 2005 में भी इसकी सभी शाखायें लाभ पर चल रही है परन्तु इन तीनों शाखाओ में पहले स्थान पर अजनर है।

चरखारी ब्लाक के अन्तर्गत बम्हौरी कलां नामक शाखा में वर्ष 2003 मे हानि हुयी है यह शाखा सफल न हो सकने के कारण 2004 में बन्द कर दी गयी है 2003 तक 18 शाखायें महोबा जनपद में थी परन्तु अब 17 कर दी गयी है। वैसे वर्ष 2002 मे ाि बम्हौरीकलां, रिवई व खरेला की बैंकें हानि में चल रही थी परन्तु बम्हौरीकलां अधिक हानि में होने के कारण बन्द कर दी गयी।

पनवाड़ी की शाखाओं का अवलोकन करने पर पता चलता है कि वर्ष 2003 व 2004 व 2005 में इनकी सभी शाखाओ में लाभ हुआ है परन्तु वर्ष 2003 व 2004 में पनवाडी ने सबसे अधिक लाभ अर्जित किये है और वर्ष 2005 में भरवारा की सबसे अच्छी स्थिति है।

कबरई ब्लाक के अन्तर्गत वर्ष 2002 में गहरा 60 हजार की हानि पर रहा और 2004 में यह 384 हजार की हानि पर रहा जो कि 2005 तक अपनी स्थिति मे काबू पाने में सफल हुआ। वर्ष 2005 मे सबसे अधिक लाभ महोबा ने अर्जित किये है।

अतः निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त चारों ब्लाकों की शाखाओं में जैतपुर मे वर्ष 2005 में अजनर, चरखारी में चरखारी की शाखा पनवाड़ी में भरवारा व माहोबा में महोबा की शाखा ने सबसे अधिक लाभ अर्जित करके अपनी सफलता दर्शायी है।

अध्याय पंचम

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का वित्तीय विश्लेषण

१. छत्रसाल ग्रामीण बैंक के गत आठ वर्षो के चिट्ठों के आधार पर विश्लेषण
२. वित्तीय विश्लेषण की विधियां
३. अनुपात विश्लेषण
४. प्रवृत्ति विश्लेषण
५. कार्यशील पूँजी प्रबन्ध विश्लेषण

अध्याय–पंचम

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का वित्तीय विवरण

किसी व्यवसाय के संचालन एवं नियन्त्रण हेतु वित्तीय लेखे उसी प्रकार महत्वपूर्ण औजार होते हैं जैसे एक सफल यान चालन के लिए वायु मापक यन्त्र दिशा सूचक यन्त्र और चार्ट्स होते हैं।

वित्तीय ढांचे से अभिप्राय किसी भी मौलिक ढांचे से हो सकता है जो किसी व्यवसाय या उद्योग के सम्बंध मे आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को प्रदर्शित करता हो, अर्थात् यह महत्वपूर्ण अवधि मे हुए व्यवसायों का सारांश होता है वित्तीय विवरण प्रायः वार्षिक आधार पर बनाये जाते हैं और इनके आधार पर ही बैकिंग संस्था की उन्नति विकास एवं भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है।

विज्ञान के विकास के साथ साथ व्यापार एवं उद्योग में उन्नति होती जा रही है व्यवसाय उद्योगों आदि के विकास पर ही राष्ट्र का विकास एवं समृद्धि निर्भर करती है। व्यवसाय उद्योगों के लिए वित्तीय विवरणों के अभाव मे प्रबन्धक न तो कोई योजना बना सकता है और न ही संचालन एवं नियन्त्रण का कार्य सरलतापूर्वक कर सकता है वित्तीय विवरण निश्चित अवधि में हुए लाभ या हानि और एक निश्चित तिथि को मौजूद वित्तीय स्थिति को दर्शाते है। इसके अतिरिक्त इन वित्तीय लेखों से विवरणात्मक रूप में उन कारणो का भी ज्ञान हो जाता है जो व्यवसायिक स्थिति के परिणाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। बैकिंग कम्पनी के लिए भी वित्तीय लेखों का बहुत अधिक महत्व है। वित्तीय लेखे बैंक को बैकों की साख सम्बंधी विश्लेषण में सहायक होते हैं बैंक ऋण देते समय अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति विशेषतः साख शोधन क्षमता एवं लाभार्जन आदि के सम्बंध में विश्लेषणात्मक सूचना प्राप्त करना चाहता है और ये सूचनायें वित्तीय लेखों से प्राप्त की जा सकती है।

वित्तीय ढांचे की व्यूह रचना –

वर्तमान में वित्तीय ढांचे के अन्तर्गत दो विवरणों को तैयार किया जाता है जिन्हें लेखपाल किसी निश्चित अवधि के अन्त में तैयार करता है ये विवरण दो प्रकार के होते हैं।

1. स्थिति विवरण जिसे आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं

2. लाभ/हानि या आय विवरण

हाल ही में व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा एक तीसरा विवरण भी तैयार किया जाता है जिसे आधिक्य विवरण या बचत लाभ विवरण के नाम से जानते हैं।

1. स्थिति विवरण (Balance Sheet) -

स्थिति विवरण को आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति का विवरण, सम्पत्ति एवं दायित्वों का विवरण, साधनों एवं दायित्वों का विवरण, सम्पत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी का विवरण इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह विवरण यह बताता है कि एक निश्चित समय बिन्दु पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है ? फ्रांसिस आर स्टीड के अनुसार, "स्थिति विवरण किसी निश्चित समय पर चालू बैकिंग की वित्तीय स्थिति का एक चित्र है।"[1] हावर्ड तथा अपटन के मतानुसार, " "स्थिति विवरण का विवरण पत्र है जो कि उपक्रम के स्वामित्वयुक्त सम्पत्ति मूल्यों, और इन सम्पत्तियों के विरूद्ध ऋणदाताओं तथा स्वामियों के दावों को सूचित करता है।"[2] गुथमैन के अनुसार, "स्थिति विवरण को किसी उपक्रम के दोहरे वित्तीय चित्र के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जो कि एक ओर तो इसके प्रयोग में आने वाली सम्पत्तियों तथा दूसरी ओर उन सम्पत्तियों के स्त्रोतों को दर्शाता है।"[3]

जान एन मायर के अनुसार, "इस प्रकार की स्थिति विवरण मूलाधार या संरचना समीकरण का विस्तृत प्रारूप है यह किसी उद्यम की वित्तीय संरचना के सामने रखता है यह प्रत्येक प्रकार की सम्पत्तियों की प्रत्येक दायित्वों की तथा स्वामी या स्वामियों के स्वामिगत स्वार्थ की प्रकृति एवं राशि को बताती है।"[4]

कापर के शब्दों मे "स्थिति विवरण लाभ हानि खाते मे सभी आगम मदों को बन्द करने के पश्चात् बचे खातों के शेष का वर्गीकृत सारांश है।"[5]

1- Balance sheet is screen picture of the financial position of a going banking at a coatiain moment. - Francis R.Stead.

2- The Balance sheet is a stetement which reports the values owned by the enterprise and the claims of the creditors and owners against these properties. - Howard and Upton.

3- The Balance sheet might be defined as the dual financial picture of an enterprise Depicting on the one hand the properties that it utilizes and on the other hand the sources of those properties. - H.G.Guthman.

4- The balances sheet is thus a detailed from of the fundamental or structural equation it sets forth the financial structure of an enterprise it states the nature and amount of each of the various assets of each of liabilities and of the proprietory interest of the Owners. - John N Myer.

5- A balance sheet is a classified summary of the ledger balance remaining after closing all revenue items into profit and loss account. - L.C.Cropper.

साधारणतया आर्थिक चिट्ठे को सन्तुलन पत्र भी कहते हैं जिसे एक निश्चित तिथि को प्रायः वर्ष के अन्तिम दिन सम्पत्ति पक्ष मे सम्पत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यो को तथा दायित्व पक्ष में स्वामित्व फण्ड ऋण एवं दायित्वों के मूल्यो को प्रदर्शित करके सन्तुलन लाया जाता है मूल्यों की रकम वही होती है जो प्रत्येक मद के व्यक्तिगत खातों के खतौनी और बाकी निकालने के बाद शेष बचती है दोहरा लेखा प्रणाली मे जमा एवं नाम की प्रविष्ट समान धनराशि होने के फलस्वरूप आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग भी समान होता है चिट्ठे में सम्पत्ति की तरफ उस प्रारूप को दर्शाया जाता है जिसमे व्यवसाय के फण्ड का प्रयोग किया जाता है और दायित्व पक्ष से यह पता लगता है कि उस फण्ड को प्राप्त करने के लिए किन–किन विधियों का प्रयोग किया गया है। वैसे आर्थिक चिट्ठे को कई और नामों से भी जानते है जैसे –

1. सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण
2. साधनों एवं दायित्वों का विवरण
3. आर्थिक चिट्ठा या सामान्य आर्थिक चिट्ठा
4 वित्तीय स्थिति या दशा का विवरण
5. सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण एवं स्वामी फण्ड का विवरण आदि।

आर्थिक चिट्ठे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है बायी तरफ दायित्वों को तथा दायी तरफ सम्पत्तियों को दिखाया जाता है इस प्रारूप को खाता प्रारूप वाला चिट्ठा कहते है इस प्रारूप को ही भारत वर्ष मे कानूनी मान्यता प्राप्त है इसलिए इस प्रारूप को कम्पनी विधान में अपनाया गया है। भारत में बैकिंग व्यवसाय के लिए खाता प्रारूप में ही आर्थिक चिट्ठे को प्रस्तुत किया जाता है।

Balnance Sheet

1- Share Capital (Authorised, Issued and Subscribed called up & paid up)	1- Fixed assets (Goodwill land & building machine furniture vehicles etc.
2- Reserves and surplus (Gen Reserve Debenture Redemption reserve P&L Act)	2- Investment
3- Secured Loans (Debenture Bank loan)	3- Current Assets & loan advances closing stock loose tools working progress (b/R) prepaid exp. cash and Bank Balance
4- Unsecured loans Loans from public	4- Misc. Expenditure & looses (Not provided for prelininary Exp. share issue exp Discount on Issue of Share)
5- Current Liabilities & provision	5- Ps.A/c If there is no general reserve fund which this loss can be deducted.
A- Current Liabilities	
B- Provisions (Income tax res proposed dividend unclaimed divident advance receipts	
6- Contigent liabilities not provided for	

स्थिति विवरण की विभिन्न मदों का संक्षिप्त वर्णन–

स्थिति विवरण को प्रमुख रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम दायित्व पक्ष (Liabilities Side) तथा द्वितीय (Assets Sides) सम्पत्ति पक्ष मे मुख्यतः निम्न पांच शीर्षक होते हैं।

1. अंश पूंजी (Share Capital)
2. संचय एवं आधिक्य (Reserve and Surplus)
3. सुरक्षित ऋण (secured Loan)
4. असुरक्षित ऋण (Unsecured Loan)
5. चालू दायित्व और आयोजन (Current liabilities and provisions)

सम्पत्ति पक्ष में मुख्यतः निम्न पांच शीर्षक होते हैं।

1. स्थायी सम्पत्तियां (Fixed Assets)
2. विनियोग (Investments)
3. चालू सम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम (Current Assets loans and advances)
4. विविध खर्च (Miscellianeous Expenditure)
5. लाभ हानि खाता नाम शेष (Debit Balance of profit and loss account)

दायित्व पक्ष की मदों का विवरण

(Description of Items of Liabilities)

1. अंश पूंजी (Share Capital)

स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में प्रथम मद अंश पूंजी होती है इसे अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी तथा अभिदत्त एवं चुकता पूंजी के रूप मे अलग-अलग दिखाया जाता है इन सभी रूपों में प्रदर्शित अंश पूंजी में विभिन्न प्रकार के अंशो सामान्य एवं पूर्वाधिकार अंश शोधन की शर्ते शोधनीय अशोधनीय परिवर्तनशील आदि। प्रतिफल हरण किये गये अंशो की राशि सहायक कम्पनियों में अंश तथा अग्रिम मांग के सम्बंध में अलग-अलग विवरण दिया जाता है।

2. संचय एवं आधिक्य –

स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष मे दूसरी मद संचय एवं आधिक्य की होती है इसके अन्तर्गत मुख्यतः संचय अंश प्रीमियम एवं आधिक्य की राशि दिखायी जाती है। संचय की राशि को दिखाते समय इनको संचयों के विभिन्न प्रकारों के अनुसार अलग अलग वर्गीकृत दिखाया जाता है।

3. सुरक्षित ऋण –

सुरक्षित ऋणों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा निर्गमित ऐसे ऋण पत्र बैंक से लिये गये ऋण एवं अग्रिम आते हैं जिनकी राशि कम्पनी की किसी सम्पत्ति की प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित होती है।

4. असुरक्षित ऋण –

सुरक्षित ऋणों के अलावा अन्य सभी प्रकार के ऋण एवं निक्षेप असुरक्षित ऋणों

में सम्मिलित किये जाते है इसे बैंकों के लिए अल्पकालीन ऋण जनता से प्राप्त धनराशि निक्षेप तथा प्रबंधको से लिये गये ऋणो को सम्मिलित किया जाता है।

5. चालू दायित्व एवं आयोजन –

चालू दायित्वों मे विविध लेनदार देय बिल न भुगतान किया गया लाभांश, ऋणों पर देय ब्याज एवं बकाया व्ययों को सम्मिलित किया जाता है आयोजन मे कर के लिए आयोजन प्रस्तावित लाभांश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है संदिग्ध दायित्व को स्थिति विवरण मे केवल टिप्पणी के रूप मे दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति पक्ष की मदों का विवरण–

1. स्थायी सम्पत्ति –

स्थायी सम्पत्तियों के अन्तर्गत भवन, भूमि संयत्र मशीनरी, फर्नीचर आदि को सम्मिलित किया जाता है स्थायी सम्पत्तियां स्थिति विवरण मे अपलिखित लागत पर दर्शायी जाती है।

2. विनियोग –

विनियोगों मे मुख्यतया कम्पनी द्वारा अन्य संस्था के अंशों, बाण्डों एवं ऋण पत्रों सरकारी प्रतिभूतियों व अन्य अचल सम्पत्तियों मे किया गया विनियोग सम्मिलित किया जाता है इन्हें स्थिति विवरण मे लागत मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. चालू सम्पत्तियां ऋण अग्रिम एवं जमा –

चालू सम्पत्ति मे मुख्यतयाः स्टाक, स्कन्ध देनदार प्राप्य बिल एवं नकद व बैंक शेष को सम्मिलित किया जाता है। ऋण अग्रिमों एवं जमाओं मे कम्पनी द्वारा दिये गये ऋण एवं पूर्तिकर्ताओं को तथा समझौतों के अन्तर्गत दी गयी अग्रिम राशियों एवं अन्य पक्षो को जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है।

4. विविध खर्चे –

विविध खर्चो के अन्तर्गत प्रारम्भिक खर्चे अंशों एवं ऋणपत्रों के अभिगोपन तथा दलाली सम्बंधित खर्चे, अंशो एवं ऋणों पर दिया गया बट्टा निर्माण के दौरान पूंजी में दिया गया ब्याज विकास सम्बंधी खर्चे इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

2—लाभ हानि खाता या आय विवरण

(Profit Loss Account or Income Statement)

लाभ हानि खाते को आय विवरण अर्जित आधिक्य का विवरण, अर्जनों का विवरण आय लाभ एवं हानि का विवरण तथा आय एवं खर्चो का विवरण आदि नामो से जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित नाम आय विवरण है। आय विवरण एक अमेरिकी शब्द है। अमेरिकी संस्थाओं मे लाभ-हानि का हिसाब एक विवरण के रूप में तैयार किया जाता है। अतः वहां उसे आय विवरण के नाम से जाना जाता है जबकि भारत में लाभ हानि के हिसाब को एक खाते के रूप में तैयार किया जाता है अतः यहां इसे लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है।

लाभ हानि खाता एक निश्चित अवधि के व्यवहारों का परिणाम दर्शाता है। यह एक प्रावैगिक प्रलेख है क्योंकि यह एक निश्चित अवधि की सभी घटनाओं का निदर्शन करता है । हावर्ड तथा अपटन के मतानुसार, ''किसी अवधि की क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामियों के दावे या समता के परिवर्तनो का समुचित विन्यासित सारांश लाभ हानि विवरण कहा जाता है।''[1]

राबर्ट एन एन्थानी के शब्दो में ''किसी लेखांकन अवधि के आगम मदों व्यय मदों एवं उनके मध्य अन्तर शुद्ध आय को संक्षिप्त करने वाला लेखांकन प्रतिवेदन आय विवरण अथवा लाभ हानि विवरण अर्जनो का विवरण या क्रियाकलापों का विवरण कहलाता है।''[2]

पैटन तथा पैटन के शब्दों में, ''किसी व्यवसायिक उपक्रम की किसी दी हुयी अवधि के आगमो व्ययों एवं अन्य कटौतियों तथा शुद्ध आय की क्रमबद्ध श्रृंखला आय विवरण अथवा लाभ हानि खाता कहा जा सकता है।''[3]

1- The summary of changes in the owner;s claim or equity relsulting from operations of a period of time properly arranged is called the profit ad loss statement. - Howard and Upton.

2- The accounting report which summarizes the revenue item the expense items and the different between them Net income for an accounting period is called the income statement or the profit and loss statement of earnings or statement of operation. - Robert N.Anthony

3- The Income statement sometimes refessed to as the profit and loss statement ma be defi ed as any systematic array of the sevenunes expenses and other deductions and net income of a business for a stated period. - Paton and Paton.

राय ए0 फालके के अनुसार, "आय विवरण वह विवरण है जो व्यवसाय के एक निश्चित अवधि के आय एवं व्यय को प्रदर्शित करता है एवं तदुपरान्त लेखा अवधि के लाभ एवं हानि की अन्तिम राशि को प्रदर्शित करता है।"[4]

हैरी जी गुथमन्न के अनुसार, "लाभ तथा हानि की विवरण ऐसे आय एवं खर्चो का वर्गीकृत व संक्षिप्त अभिलेख है जो एक निश्चित अवधि के लिए स्वामी हित मे परिवर्तन के कारण होते हैं।"[5]

फोसटर के मतानुसार, "यह लाभ हानि खाता अभी व्यतीत हुयी वित्तीय अवधि के क्रियाकलापों की कहानी बताता है।"[6] लाभ हानि विवरण के सम्बंध मे मत व्यक्त करते हुए विनियमपैटन ने लिखा है कि यह लाभ हानि विवरण एक निश्चित अवधि के लिए आय के आंकड़ों, आय मे कटौतियों मे विनियोग कर्ताओं में विवरण को एक सुव्यवस्थित रूप मे प्रस्तुत करता है।

लाभ हानि खाता एक निश्चित लेखा अवधि मे व्यवसाय संचालन के परिणाम का प्रतिवेदन होता है। लाभ और हानि का विवरण उन समस्त आयों तथा व्ययों का वर्गीकृत एवं संक्षिप्त अभिलेख होता है जो एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत स्वामी हित में परिवर्तन के कारण होते हैं । हैरी जी गुथमन्न के अनुसार "आर्थिक चिट्ठे से केवल यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है परन्तु प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन का शीघ्र और प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक चिट्ठे की मदों पर पड़ता है और परिवर्तन हो जाता है। परन्तु इस परिवर्तन को तत्काल मापना अथवा ज्ञात करना सम्भव नहीं होता है। क्योंकि आर्थिक चिट्ठा एक विशेष तिथि को ही तैयार किया जाता है।

4- The Income statement is the schedule that shows the income and expenditure of a business enterprise over a prriod of time and then given the final fugure sepresening the amount of profit or loss for the accounting period. - Roy. A Foulke

5- The statement of profit and loss is the condensed and classified record of the gains and losses causing changes in the owner's interest in the business for a period of time - Harry. G.Guthmann

6- It tells the story of operations over the fisical period just passed. - Lousis O Foster.

छत्रसाल ग्रामीण बैंको के वित्तीय विश्लेषणों का विवरण

वित्तीय विवरण एक संस्था के किसी ऐसे प्रलेख को कहा जा सकता है कि जिसमे संस्था से सम्बंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया गया हो। हावर्ड तथा अपटन के अनुसार, " यद्यपि ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों मे व्यक्त किया गया हो वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है लेकिन अधिकतर लेखांकन एवं व्यवसायिक लेखक इसका उपयोग केवल स्थिति विवरण तथा लाभ हानि विवराण के अर्थ मे ही करते हैं।"[1]

बैकिंग व्यवसाय में वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में बनाये जाते है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक चलता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वित्तीय विवरणों मे तुलन पत्र या चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता प्रमुख होते है इन विवरणो मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा कुछ अनुसूचियों का प्रयोग भी किया जाता है जो इन विवरणों मे दिये गये आंकड़ों एवं सूचनाओ के सहायक के रूप मे कार्य करती है विश्लेषण एवं निर्वाचन करते समय इन अनुसूचियों को वित्तीय विवरणों का ही एक भाग माना जाता है। कुछ सूचनाये ऐसी होती है जो तुलन पत्र द्वारा प्रकट नही होती अतएव व्यवहार मे एक कोष प्रवाह विवरण भी तैयार किया जाता है जो कि वित्तीय विवरणों का ही एक भाग होता है वित्तीय विवरणों में किन विवरणों को शामिल किया जाये इस विचार पर विभिन्न विद्वान एक मत नही है।

उन प्रमुख विचारकों के मत इस सम्बंध में निम्नलिखित हैं।

1. गुथमैन के अनुसार, "स्थिति विवरण एवं लाभ हानि खाता ही वित्तीय विवरणों मे शामिल किया जाना चाहिए।"[2]

1- Although any formal statements expressed in money value might be thought of as financial statements the term has come to be limited by most accounting and business writers to mean the balance sheet and the profit and loss statement. - Howard and upton

2- There are two financial statements The balance sheet and the profit & loss. - Hanr. G.Guthman

3. जे0 एन0 मायर के अनुसार, "शब्द वित्तीय विवरण जैसा कि आधुनिक व्यवसाय मे प्रयुक्त होता है, दो विवरण जिनको कि लेखपाल व्यवसायिक संस्था के लिए एक निश्चितसमयावधि के पश्चात् तैयार करता है, के लिए प्रयुक्त होता है ये विवरण या वित्तीय स्थिति विवरण तथा आम विवरण या लाभ हानि विवरण है।"[3]

4. कैनेडी एवं मूलर के शब्दों मे, "वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों के समंकों की महत्ता एवं आशय निर्धारित किया जाता है, ताकि भावी अर्जनों देयतिथियों पर ऋणों (चालू व दीर्घकालीन दोनों) एवं ब्याज के भुगतान की योग्यता और एक सुदृढ लाभांश नीति का लाभदायकता की संभावनाओ का पूर्वानुमान लगाया जा सके।"[4]

वित्तीय अवधि (Financial Period)-

वित्तीय अवधि से आशय उस लेखा अवधि से है जिसके अन्त में वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है। भारतीय कम्पनी अधिनियम एवं आयकर अधिनियम के अनुसार साधारणतया: किसी संस्था का वित्तीय वर्ष 12 महीने से अधिक का नही होना चाहिए संस्था को अपना वित्तीय वर्ष कैलेण्डर वर्ष या अन्य किसी प्रचलित समयावधि के अनुसार समाप्त करना आवश्यक नही है। साधारणतया व्यवसायिक संस्थायें किसी ऐसी तिथि को अपना वित्तीय वर्ष समाप्त करती है जो उनके वार्षिक बैकिंग चक्र का प्राकृतिक समापन बिन्दु (Natural Ending point of the Banking Cycle) होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि "सम्पत्तियों दायित्वों एवं स्वामित्वों के विवरण को सामान्यत: स्थिति विवरण के रूप में माना जाता है"[5]

3- The term financial statements as used in moder business refers to the two statements which the accountant prepares at the end of a period of time for a business enterprise. They are the balance sheet or statement of Financial position and the income statement or profit & loss statement.
- Joh. N.Myer.

4- The analysis and interpretation of financial statements of the financial statement all an attempt to delemine the significance and meaning of the financial statement date so that the forcast may be made of the prospectets for picture earnings ablity to pay interest and debt maturities (both current & longterm) and profictability of a sound disidend policy. - Kannedy & Muller.

5- Statement of assets liabilities and proprietorship is usually referred to as a balance sheet.
- Maurice and lousis.]

वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन
(Analysis and Interpretation of Financial Statements)

वित्तीय विवरण अपने आप मे लक्ष्य न होकर साधन मात्र होते हैं अतः इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना आवश्यक है जिस प्रकार मानव शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिए डाक्टर शरीर की सामयिक परीक्षण की सलाह देता है ठीक उसी प्रकार व्यवसाय को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ एवं लाभप्रद बनाये रखने के लिए वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है वित्तीय विवरण जितने अधिक बड़े तथा भारी होते है उतने ही उच्च प्रबन्ध के लिए बेकार होते हैं।"[6] वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों के परिणामों को संक्षिप्त में प्रबन्ध के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे उन्हे तुरन्त निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके, वित्तीय विवरण संस्था से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को अंकात्मक रूप से प्रस्तुत करते है कि ये अंकात्मक तथ्य मूक होते है अपने आप किसी निष्कर्ष को नही बताते है इसके लिए आवश्यक होता है कि रचना की तरह किसी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके इन अंकात्मक तथ्यों से कहलाये जाये जब प्रयोगकर्ता ऐसा प्रयास करता है तो उस क्रिया को वित्तीय विवरण का निर्वचन करते हैं।

स्पाइसर एवं पैगलर का कथन है कि लेखों के निर्वचन को वित्तीय समंकों को इस प्रकार अनुवाद करने की कला एवं विज्ञान के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है ताकि जिससे व्यवसाय की आर्थिक शक्ति तथा कमजोरी संवारण प्रकट हो सके।"[7]

वित्तीय विवरणों का निर्वचन सचमुच एक कला है इसके अन्तर्गत उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण, अनुविन्यसन सम्बंध स्थापना व उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना आदि क्रियायें शामिल होती है निर्वचन का कार्य आधुनिक लेखपालक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक कार्य माना जाता है। निर्वचन के अन्तर्गत निम्नलिखित को भी शामिल करते हैं।

6- The Financial statements are frequently voluminous combersome and detailed to the point where they are almost useless to top management.

7- Interpretation of Accounts may be defined as the art and Science of translating the figuress therein in such a way as to several the financial strength and weekness of a business and the causes which have contributed there to - Spicer and pegier.

.1. विश्लेषण (Analysis) 2. तुलना (Comparison)

3. प्रवृत्ति का अध्ययन (Study of Trend) 4. निष्कर्ष निकालना (Drawing Conclusion)

1.विश्लेषण **(Analysis)**

वित्तीय विवरणों के अंक न केवल खातों की बाकियां होती है बल्कि कई खातों की बाकियों के समूह भी होते है फलस्वरूप उनमे एकरूपता नही होती है इस प्रकार न केवल उनका निर्वचन करना कठिन होता है बल्कि असंख्य लेन देनों का निर्वचन मे प्रयोग भी नही होता है वित्तीय विवरणों में प्रदत्त अंक व उनसे सम्बंधित लेखों का निर्वचन करने के पूर्व बीच की अनेक सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वित्तीय विवरण मे प्रदर्शित मदों के योग को कई भागों मे विभाजित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए वित्तीय विवरणों के आधार पर यह ज्ञात करना है कि व्यवसाय में एक विशेष तिथि को ऋण की सीमा क्या है ? यह सूचना कुल दायित्व की मदद से प्राप्त होती है परन्तु व्यवहार में दायित्व दो प्रकार का हो सकता है पहला जो अल्पकाल मे भुगतान योग्य हो दूसरा जो दीर्घकालीन के रूप में दिखाया जाता है। परन्तु केवल चालू दायित्व के सम्बंध में ही ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नही होता है यह भी ज्ञात करना आवश्यक होता है। कि तीस दिन साठ दिन या नब्बे दिन मे भुगतान योग्य दायित्व कितने है इस कार्य के लिए कुल दायित्व का उपभोग मे विभाजन करना होगा इस क्रिया को विश्लेषण कहते हैं।

किने एवं मिलर के शब्दो मे "वित्तीय विवरण विश्लेषण में कुछ निश्चित योजनाओ के आधार पर तथ्यों का विभाजन करना, निश्चित दशाओं के अनुसार उनकी वर्ग में रचना करना और सुविधाजनक एवं सरल पाठ्य एवं समझने योग्य रूप में उन्हें प्रस्तुत करना शामिल है।"

जान मियर के अनुसार "वित्तीय विश्लेषण व्यापक रूप से किसी व्यवसाय में विवरणों के एक अकेले समूह द्वारा प्रकट किये गये विभिन्न वित्तीय कारकों के बीच सम्बंधों और विवरणोंकी एक श्रृंखला में दर्शायी गयी इन कारकों की प्रवृत्तियो का अध्ययन है।"[1]

1- Financial statement analysis is laugely a study of relationship among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements and a study of the trends of these factors as shown in a series of statement. - John.Myer.

इसी प्रकार मोग्स, जॉनसन तथा केलर ने लिखा है कि " वित्तीय विशलेषण चयन सम्बन्ध तथा मूल्याकन की प्रकिया है"। प्रमुख रूप से विशलेषण प्रकिया के अन्तर्गत निम्न को शामिल कर सकते हैं।

अंको का सन्निकटता –

इसके अन्तर्गत वित्तीय विवरण मे प्रदर्शित मौलिक अंको को सन्निकटता के आधार पर पूर्णांक बना लिया जाता है साधारणतया सैकड़ा हजार या लाख मे पूर्णांक बनाते समय जिस सीमा तक अंकों को पूर्णांक बनाना हो उसके बाद की आधे से कम राशि को छोड़ दिया जाता है तथा उससे अधिक राशि को मानकर जोड़ लिया जाता है इसके साथ ही हजार या लाख मे बनाये गये पूर्णांकों को लिखते समय उनको बोध कराने वाले शून्यों को भी लोप किया जा सकता है। और केवल संख्याओं को ही लिखा जा सकता है। परन्तु ये संख्यायें हजार या लाख में है इसका संकेत किसी उपयुक्त स्थान पर देना आवश्यक होता है।

2. तुलना (Comparison)-

वित्तीय विवरणों की मदों का विभिन्न भागों मे उपभागों में वर्गीकरण करने के बाद उसकी सापेक्षित मात्रा को मापना आवश्यक होता है जैसे चालू दायित्वों की रकम ज्ञात करने के बाद उनकी चालू सम्पत्तियों से तुलना करने पर ही उचित निष्कर्ष निकल सकता है। यही नही चालू सम्पत्तियों के विभिन्न उपभागों की आपस मे तुलना करना भी आवश्यक होता है यदि चालू दायित्वों व चालू सम्पत्तियों की निरपेक्ष रकम के आधार पर संस्था की भुगतान क्षमता सुदृढ़ दिखायी दे परन्तु जब देय रकम और प्राप्त रकम की तिथिवार तुलना की जाये तो स्थिति कुछ और भी स्पष्ट हो सकती है अतः शुद्ध निर्वचन के लिए तुलना आवश्यक होती है।

3. प्रवृत्ति का अध्ययन (Study of Trend)-

निर्वचन के लिए वित्तीय विवरणों के योग को ही अलग करना जरूरी नहीं होता है बल्कि उनकी तुलना करना भी आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त गत कई वर्षो के अन्दर व्यवसाय से सम्बंधित विवरण मदों में जो भी परिवर्तन हुए है उनका अध्ययन भी इसके लिए

2- Financial Analysis is the process of selection relation and evalulation
- Moges Jonsun Kaier.

आवश्यक है गत वर्षो के वित्तीय विवरणों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण मदों की प्रवृत्ति की माप करना व उनका विश्लेषण करना आवश्यक है इसके लिए क्षैतिज विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। प्रवृत्ति अनुपात, प्रवृत्ति औसत का प्रयोग करके ही क्षैतिज विश्लेषण सम्पादित होता है।

4. निष्कर्ष निकालना (Drawing Conclusion)-

वित्तीय विवरणों के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य संस्था की वित्तीय दशा के सम्बंध में राय प्रकट करना होता है। यह राय केवल वित्तीय समंको के विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन के आधार पर कायम नही की जा सकती इन समंको के आधार पर उचित विचार व धारणा को आर्थिक तथ्यो पर आधारित करना पड़ता है।

वित्तीय विश्लेषण की विधियां –

पाश्चात्य देशों में इस पद्धति का प्रयोग साख विश्लेषण के लिए प्रारम्भ हुआ था। सन् 1914 तक साख प्रदान करने वाले केवल वित्तीय विवरणों की वस्तु स्थिति पर विश्वास करके साख प्रदान करते थे परन्तु धीरे धीरे इन विवरणों में प्रदत्त समंको का विश्लेषण महत्वपूर्ण माना जाने लगा और इनके लिए अनेक विधियों का विकास हुआ। वर्तमान मे वित्तीय विश्लेषण की निम्न विधियां हैं –

1. तुलनात्मक वित्तीय विवरण (Comparative Financial Statement)
2. वित्तीय अनुपात (Financial Ratios)
3. समानाकार वित्तीय विवरण (Common Size Financial Statements)
4. प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis)
5. कोष प्रवाह विवरण (Funds flows analysis)
6. नकद प्रवाह विवरण (Cash flows statements)
7. सम विच्छेद विश्लेषण (Break Even Analysis)

यह आवश्यक नही है कि एक वित्तीय विश्लेषण मे उपयुक्त सभी तकनीकी का प्रयोग किया जाये। वित्तीय विश्लेषण की तकनीकी का चुनाव विश्लेषण के उद्देश्य पर निर्भर करता है विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषणकर्ता को उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त

तकनीकी का चुनाव करना चाहिए। एक विश्लेषण के लिए जो तकनीकी उपयुक्त साबित होती है दूसरे के लिए बिलकुल अनुपयुक्त साबित हो सकती है। इस शोध का विश्लेषण वित्तीय अनुपात विधि के अन्तर्गत किया गया है।

वित्तीय विश्लेषण का महत्व
(Importance of Financial Analysis)

वित्तीय विश्लेषण का बैकिंग निर्णयो में सर्वोपरि महत्व है। वित्तीय विश्लेषण की पद्धतियां बैंक को उसके नियोजन तथा नियंत्रण दोनों ही कार्यो मे सहायक होती है। वित्तीय नियोजन के समय मैनेजर यह देख सकता है कि उसके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों का बैंक की आर्थिक स्थिति तथा लाभदायकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र मे इन पद्धतियों के माध्यम से मैनेजर अपने भूतकालीन निर्णयों की विवेकशीलता तथा उनमे रही कमियों का पता लगा सकता है जो भावी निर्णयों में उसका मार्गदर्शन करते है अतः वित्तीय विश्लेषण भी बैंकर्स के निर्णयो को विवेकपूर्ण बनाकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। इसके कुछ लाभ निम्न है –

1. सहज ज्ञान एवं बिना विश्लेषण के लिए गये निर्णय भ्रामक एवं हानिकारक हो सकते है। वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर लिये गये निर्णय तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक होते है अतः उनके त्रुटिपूर्ण होने की संभावना कम रहती है।
2. वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त परिणामो के आधार पर सहज बोध द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जा सकती है।
3. सहज बोध के आधार पर लिये गये निर्णयो का औचित्य निर्णयकर्ता के अतिरिक्त अन्य पक्षकारो के समझ में आना कठिन होता है वित्तीय विश्लेषण पर आधारित निर्णयो का स्वरूप एवं औचित्य अन्य व्यक्तियों के भी समझ मे आ सकता है अतः ये निर्णय विश्वसनीय एवं मूल्यवान समझे जाते हैं।

वित्तीय विश्लेषण का महत्व बैंक के आन्तरिक प्रबन्ध तक ही सीमित नही है बल्कि इनका प्रयोग अन्य पक्षों यथा विनियोजको ऋणदाताओ तथा जमादाताओं द्वारा भी किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण मुख्यतः निम्न पक्षों के लिए अधिक महत्व रखता है।

1. बैंक के लेनदार तथा अन्य पक्ष जो बैंक के साथ व्यवहार करते हैं।
2. ऋण पत्र धारक
3. ऋणदेय संस्थायें जैसे वित्तीय निगम तथा बैंक इत्यादि
4. वर्तमान व भावी विनियोजक
5. बैंक से सम्बंधित अंशधारक या विनियोजक जो बैंक के साथ कोई दीर्घकालीन समझौता करना चाहते हो।
6. संसद सदस्य सार्वजनिक लेखा समिति तथा सरकार द्वारा स्थापित अनुमान समिति।

उपर्युक्त में से महत्वपूर्ण पक्षों के लिए वित्तीय विश्लेषण के महत्व की विवेचना नीचे करेंगे।

1. ऋणदाताओं के लिए महत्व –

ऋणदाताओं को दो प्रमुख वर्ग अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन में विभक्त किया जा सकता है अल्पकालीन ऋणदाताओं का प्रमुख स्वार्थ बैंक की तरलता में निहित होता है अतः ये बैंक के कोष प्रवाह के माध्यम से यह जानना चाहते है कि उनका कर्ज चुकाने के लिए बैंक के पास समय पर नकद कोष होंगे या नही दीर्घकालीन ऋणदाताओं का स्वार्थ दीर्घकालीन होता है अतः ये बैंक की दीर्घकालीन लाभ अर्जन क्षमता के विश्लेषण से यह देखना चाहते है कि दीर्घकाल में क्या बैंक की अर्जन क्षमता उनके ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन संचित रखेगी या नही। अतः ये बैंक की लाभ अर्जन क्षमता पूंजी संरचना तथा भावी कोष प्रवाह का विश्लेषण करते हैं।

2. विनियोजकों के लिए महत्व –

विनियोजकों का मुख्य स्वार्थ विनियोजन का सुरक्षा तथा बैंक की लाभ अर्जन क्षमता में होता है। विनियोजक बैंक में विनियोग की सुदढ़ता के सम्बंध मे स्वयं अपनी धारणा बनाते हैं। विनियोजक इस आशय के लिए प्रति अंश लाभांश की गणना कर सकते है तथा इस लाभांश को अंश के बाजार मूल्य से तुलना कर प्रति अंश मूल्य लाभांश अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।

3. सरकार के लिए महत्व –

सरकार की वित्तीय नीतियों के संचालन मे वित्तीय विश्लेषण एक बैंक से दूसरे बैंक

तथा उद्योग से तुलना मे सहायक होते है। लाभार्जन अनुपात तथा आवर्त अनुपात सरकार के लिए विशेष महत्व के होते हैं।

4. प्रबन्ध के लिए महत्व –

प्रभावशाली नियोजन व नियंत्रण के लिए बैंक के प्रबन्ध की रूचि प्रत्येक वित्तीय पहलू मे होती है। प्रबन्ध को विभिन्न अंशधारको को संतुष्ट करना होता है तथा बाह्य पूंजी की प्राप्ति में अपनी विनिमय करने की शक्ति में वृद्धि करनी होती है। अतः वे अपने वित्तीय विश्लेषण में पूंजी संरचना तरलता स्थिति लाभार्जन शक्ति आदि सभी बातों का समावेश करते हैं। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से बैंकर्स अपनी नीतियों व निर्णयों की प्रभावशीलता माप सकते है नई नीतियों व पद्धतियों के धारण के औचित्य का निर्धारण कर सकते है ताकि स्वामियों को अपने वित्तीय प्रयत्नो का प्रमाण दे सकते हैं।

5. जमाकर्ताओं के लिए महत्व –

जमाकर्ताओं को वित्तीय विश्लेषण के द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति का पता चलता रहता है यदि उसकी दशा अच्छी है तो जमा के साथ साथ उस बैंक में विनियोग करना उचित समझते है जो कि बैंक की लाभार्जन क्षमता को बढ़ाती है।

वित्तीय विवरणों की प्रकृति

(Nature of Financial Statements)

वित्तीय विवरण लिपिबद्ध किये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किये जाते है ये लिपिबद्ध तथ्य ऐसे होते है जिन्हें मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति यह समझता है कि किसी संस्था के प्रकाशित वित्तीय विवरणों में सम्पत्तियों एवं दायित्वों को वास्तविक एवं निरपेक्ष मूल्य पर दिखाया जाता है परन्तु यह धारणा उचित नही है क्योंकि वित्तीय विवरणों में उल्लेखित समंक लिपिबद्ध तथ्य लेखांकन परम्पराओं स्वयं सिद्धियों तथा लेखपाल के व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक परिणाम होते हैं।

1. लिपिबद्ध तथ्य **(Recorded Facts)**

इनसे आशय लेखांकन अभिलेखों से लिये गये समंको से होता है। बैकिंग व्यवहारों का लेखा बैकिंग पुस्तकों में उसी तिथि को तथा उसी मूल्य पर किया जाता है जब ये

व्यवहार किये जाते है ये अभिलेख वास्तविक लागत आंकड़ों के आधार पर रखे जाते है विभिन्न लेन देनो के अभिलेखन के लिए मूल लागत या ऐतिहासिक लागत आधार होती है विभिन्न खातों जैसे-हतस्थ, रोकड़ बैंक में रोकड़ प्राप्त विपत्र, विविध देनदान स्थायी सम्पत्तियों इत्यादि के अंक वे ही होते है जो लेखांकन पुस्तकों मे लिपिबद्ध होते है अतः वित्तीय विवरण लिपिबद्ध तथ्यों पर आधारित होते हैं।

2. लेखांकन परम्परायें **(Accounting Concentions)**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने मे कुछ निश्चित लेखांकन परम्पराओं का अनुसरण किया जाता है वित्तीय विवरणों में दिखाये गये तथ्य वास्तविक एवं निरपेक्ष नही होते है। लेखांकन की सारता की प्रथा के अनुसार कम मूल्यों की वस्तुओं के क्रय जैसे– पैन, स्टेशनरी, बल्ब आदि को उस वर्ष के आगमन व्यय मे सम्मिलित कर लिया जाता है जबकि मंहगी वस्तुओं के क्रय को जैसे– मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि को सम्पत्ति में सम्मिलित किया जाता है।

3. स्वयंसिद्धियां **(Postulates)-**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय लेखपाल कुछ बातों की स्वयंसिद्धि मानकर चलता है चाहे उनकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों न हो उदाहरणार्थ लेखपाल देश की मुद्रा रूपये का मूल्य स्थिर मानकर चलता है तथा विभिन्न तिथियों को किये गये लेन-देनों मे कोई अन्तर नही करता। इसी प्रकार व्यवसाय की चालू स्थिति की मान्यता के आधार पर स्थायी सम्पत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है।

4. व्यक्तिगत निर्णय **(Personal Judgement)-**

वित्तीय विवरणों पर लेखपाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी प्रभाव पड़ता है लेखपाल के बहुत से ऐसे क्षेत्र होते है जहां पर लेखांकन की अनेक वैकल्पिक पद्धतियां अपनाई जाती है जैसे असंग्रहयोग ऋण का अनुमान लगाने की अनेक विधियों मे से किसी एक विधि को अपनाना।

वित्तीय विवरणों की सीमायें
(Limitations of Financial Statements)

1. अत्यधिक सूक्ष्मता का प्रभाव **(Lank of High Accuracy)**

वित्तीय विवरणों के तथ्यों में अधिक सूक्ष्मता नही होती है। क्योंकि इनकी विषय

सामग्री ऐसे मामलों में सम्बंधित है जिसे सूक्ष्मता से व्यक्त नही किया जा सकता है ये तत्व लेखांकन मान्यताओं व प्रथाओं पर आधारित होते हैं।

2. गैर-मौद्रिक तथ्यों का समावेश **(Do not Include Non monetary Items)**

वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते है क्योकि इनमे केवल मौद्रिक तथ्यों को ही सम्मिलित किया जाता है जबकि गैर-मौद्रिक तथ्य भी व्यवसाय को प्रभावित करते है उदाहरण के लिए व्यवसाय की साख कर्मचारियों का मनोबल, प्रबन्ध की कुशलता आदि। लेकिन इन तत्वों को वित्तीय विवरणों में नही दर्शाया जाता है।

3. ऐतिहासिक प्रलेख **(Historical Records)**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण नहीं करते हैं।

4. भूतकालीन घटनाओं पर आधारित **(Bases on Past Events)**

वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होते है भविष्य के बारे में जानकारी नही देते हैं।

5. ऊपरी दिखावे **(Window Dressing)-**

वित्तीय विवरणों मे ऊपरी दिखावे का सहारा लेकर संस्था की स्थिति को वास्तविक से अधिक अच्छा दिखाया जा सकता है।

6. अन्तरिम प्रतिवेदन **(Interim Reports)-**

वित्तीय विवरण अन्तरिम प्रतिवेदन होते है क्योंकि व्यववसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समापन होने के बाद ही जानी जा सकती है।

7. भूल परिवर्तन को न दर्शाना **(Do not reflect price level change)-**

वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नही दर्शाते अतः विभिन्न वर्षो को वित्तीय विवरणों में दिखाये गये तथ्य तुलनीय नही होते है। इनकी सीमाओं के पश्चात् बैंक स्वामित्व निधि जमा व उधार से सम्बन्धित तालिका को आगे दर्शाया गया है।

तालिका नं0–5

डी0ए0वी / एम0ओ0यू0 वर्षों की अपेक्षायें एवं उपलब्धियां (रुपये हज़ार में)

विवरण	2000–01		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05	
	अपेक्षायें	उपलब्धियां	अपेक्षायें	उपलब्धियां	अपेक्षायें	उपलब्धियां	अपेक्षायें	उपलब्धियां	अपेक्षायें	उपलब्धियां
1. निजी स्वामित्व निधि										
अ.अंश पूंजी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ब. प्रारक्षतियां	—	—	—	—	—	1167	511.67	344054	1094.52	585.89
स.अंश पूंजी जमा	143962	139694	143962	139694	143962	139694	1439.62	1439.62	1439.62	1439.62
2. जमा	1700000	1654998	2000000	1863064	2250000	2136045	25000.00	24872.63	34000.00	28103.
अ.मांग जमा	105000	994095	1200000	1115904	13500000	1368334	17000.00	16171.51	23000.00	19634.72
ब.वृद्धि प्रतिशत	28023	60.07	20.71	12.25	20.97	22.62	24.00	18.00	42.22	21.42
स.सावधि जमा	6500000	660903	80000	747160	900000	767711	8000.00	8701.72	11000.00	8468.29
वृद्धि प्रतिशत	20.35	39.93	21.05	13.05	20.46	2.75	4.00	13.00	26.42	2.68
3. उधार	128000	75874	216866	98987	218187	1181612	3257.12	2644.95	—	—
वृद्धि प्रतिशत	29.91	(–)22.99	185.82	30.46	120.42	83.47	79.34	45.64	70.25	24.93
अ.राष्ट्रीय बैंक	103000	69966	185224	91187	198187	172212	3163.12	2644.45	4502.95	1985.68
ब. प्रवर्तक बैंक	25000	5908	31700	7800	20000	9400	94.00	0.50	0.00	0.00

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन।

उपर्युक्त सारिणी तालिका नं0 5 के अन्तर्गत विकास कार्य योजना तैयार कर प्रवर्तक बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर बैंक द्वारा हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत विभिन्न मानदण्डों वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर सहमति प्रदान की गयी। एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष बैंक द्वारा की गयी प्राप्तियों का विवरण सारिणी में दिया गया है जिसके अनुसार 2000–01 मे 10,000 की अंश पूंजी से अपेक्षा की गयी जिसकी उपलब्धियों भी 10000 हुयी इन वर्षो में प्रारक्षितियां यानि रिजर्व नही थे और अंश पूंजी जमा 143992 लाख थी इस लक्ष्य मे 139694 लाख रूपये की उपलब्धि हुयी जो कि लक्ष्य के अनुसार 1268 थी यही स्थिति 2005 तक रही वर्ष 2003–04 में कुछ रिजर्व भी थे वर्ष 2004–05 मे 1094.52 लाख का रिजर्व का लक्ष्य रखा गया था जिसमें केवल 585.89 तक की उपलब्धियां हो पाईं।

यदि जमा की स्थितियों को देखा जाये तो वर्ष 2000 से 2002 तक कोई भी मांग जमा लक्ष्यों के अनुसार पूर्ति नही कर पा रही है परन्तु 2002–03 मे 1350000 लाख रूपये के लक्ष्यों पर उससे अधिक रूपये 1368334 लाख की पूर्ति की गयी जो कि अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। 2003–04 व वर्ष 2004–05 मे भी कमी की स्थिति रही।

राष्ट्रीय बैंक से जो उधार इस बैंक को मिला है वह उसका लक्ष्य सन् 2004–05 मे 4502.15 लाख रूपये का था जिसकी उपलब्धियों 1885.68 रही। और प्रवर्तक बैंको से मिला उधार शून्य की स्थिति दर्शा रहा है।

तालिका 5.1

निवेश एवं उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रूपये हजार में)

वर्ष	विवरण			
	कुल निवेश	औसत कुल निवेश	अर्जित ब्याज आय	निवेश पर अर्जन दर
1997–98	748999	693802	87706	12.64 प्रतिशत
1998–99	916085	870473	103164	11.85 प्रतिशत
1999–2000	979584	997293	113760	11.41 प्रतिशत
2000–01	1151584	1102468	118776	10.77 प्रतिशत
2001–02	1102556	1140481	120403	10.56 प्रतिशत
2002–03	1266443	1122046	108589	9.68 प्रतिशत
2003–04	1373605	1198787	100460	8.38 प्रतिशत
2004–05	1104349	1302800	96845	7.43 प्रतिशत

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन ।

तालिका 5.2
जमा राशि एवं उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रूपये हजार) में

वर्ष		विवरण		
	अंश पूंजी जमाराशि	औसत अंशपूंजी जमाराशि	अर्जित ब्याज आय	जमाराशि अर्जन दर
1997–98	115512	115512	13638	11.80 प्रतिशत
1998–99	136395	136395	15574	11.42 प्रतिशत
1999–2000	139694	139694	14491	10.38 प्रतिशत
2000–01	139694	139694	14416	10.32 प्रतिशत
2001–02	139694	139694	12493	8.94 प्रतिशत
2002–03	139694	139694	10342	7.40 प्रतिशत
2003–04	143963	143151	8683	6.06 प्रतिशत
2004–05	143963	143963	8404	5.84 प्रतिशत

तालिका 5.3
प्रतिभूतियों पर निवेश एवं उन पर अर्जित ब्याज का तुलनात्मक विवरण (रूपये हजार में)

वर्ष		विवरण		
	अनुमोदित प्रतिभूतियों मे निवेश	औसत अनुमोदित प्रतिभूतियों मे निवेश	अर्जित ब्याज आय	अनुमोदित प्रतिभूतियां पर अर्जन दर
1997–98	200390	200390	28641	14.29 प्रतिशत
1998–99	200390	200390	31159	15.55 प्रतिशत
1999–2000	262890	217682	32316	14.85 प्रतिशत
2000–01	326390	300807	40339	13.41 प्रतिशत
2001–02	366890	358598	46999	13.89 प्रतिशत
2002–03	300500	336449	44015	13.08 प्रतिशत
2003–04	340500	324750	39172	12.06 प्रतिशत
2004–05	233500	312667	37141	11.88 प्रतिशत

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन ।

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 में बैंक ने कुल रूपये 916085 हजार का निवेश करते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 22.31 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है। जिसकी अर्जन दर 1998 से 1999 तक घटकर .79 प्रतिशत का अन्तर प्रदर्शित कर रही है वर्ष 2000 से 979584 लाख का कुल निवेश था जो कि 2001 की तुलना मे 17.55 प्रतिशत रहा है अगर इसी प्रकार हम इसकी तुलना करें तब सन् 2003 मे कुल निवेश 1266443 लाख था जो 2002 के सापेक्ष 14.86 वृद्धि अर्जित कर रहा है 2003 में निवेश कर अर्जन दर 9.69 प्रतिशत हो गयी जो घटती जा रही है। वर्ष 2005 में बैंक का कुल निवेश रूपये 11043.49 लाख है यह कुल जमा राशियों का 39.30 प्रतिशत है जो कि गत वर्ष 55.23 प्रतिशत था।

इसी प्रकार यदि हम छत्रसाल ग्रामीण बैंक की अंशपूंजी जमाराशि को देखें तो यह 1998 में 115512 थी जो कि जिस पर अर्जित ब्याज आय 13638 हजार थी और जमाराशि पर अर्जन दर 11.80 प्रतिशत हुआ। यह पिछले वर्ष के सापेक्ष 189.07 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है वर्ष 2000 मे जमाराशि 139694 लाख है जो कि 2003 तक है फिर 2004 में अंश पूजी जमा राशि 143963 लाख रूपये हो गयी जो कि पिछले वर्षो के सापेक्ष 3.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। 143963 पर अर्जित ब्याज आय 84.04 हजार रूपये प्राप्त हुयी जो कि जमाराशि अर्जन दर 5.84 प्रतिशत थी। 2004–05 की जमाराशि समान होते हुए इसकी अर्जित ब्याज आय मे परिवर्तन होने के कारण इसकी अर्जन दर में परिवर्तन आ गया है।

यदि हम वर्षवार बैंक की अनुमोदित प्रतिभूतियों में किये गये निवेश को देखे तो यह 1998 व 1999 मे 200390 लाख रूपये हुआ जिसमें अर्जित की गयी ब्याज आय 28641 हजार व 31159 हजार रूपये आयी और इसकी अर्जन दर क्रमशः 14.29 प्रतिशत व 15.55 प्रतिशत थी। यदि हम 2003 की 2002 में तुलना करे तो प्रतिभूतियों में निवेश 22.09 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। परन्तु यह निवेश 2004 मे बढ़कर 340500 रह गयी जिस कारण इसकी अर्जित की गयी ब्याज आय मे भी परिवर्तन आ गया यह 2004 की अपेक्षा 2031 हजार रूपये का अन्तर दर्शाती है। जो कि 5.46 प्रतिशत है।

सारिणी नं0 5.1 मे कुल निवेश बढ़ता जा रहा है और उसकी अर्जन दर कम होती जा रही है इसका एक कारण तो यह है कि बैंक ने पहले जो निवेश किया उस वक्त ब्याज दर अधिक रखी और बाद में ब्याज दर कम कर दी जिसके कारण अर्जन दर घटती जा रही है और इसके घटने का दूसरा कारण यह है कि बैंक इस विनियोग को ऐसी जगह कर रहा है जो कि अच्छा लाभ नही दे रही है इसलिए प्रबन्धक को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि बैंक अपना निवेश ऐसी जगह करे जहां से उसकी अर्जन दर में बढ़ोत्तरी हो।

उपर्युक्त तीनों तालिकाओं की अर्जन दरों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

ग्राफ–3

जमाराशि अर्जनदर
निवेश पर अर्जनदर
प्रतिभूतियों पर अर्जन दर
अर्जन दर का प्रतिशत
14
12
10
8
6
4
2
0
11.80
12.64
14.29
11.42
11.85
11.55
10.38
11.41
14.85
10.32
10.77
13.41
8.94
10.56
13.89
7.40
9.68
13.89
6.06
8.38
12.06
5.84
7.43
11.88
1997-98
1998-99
99-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
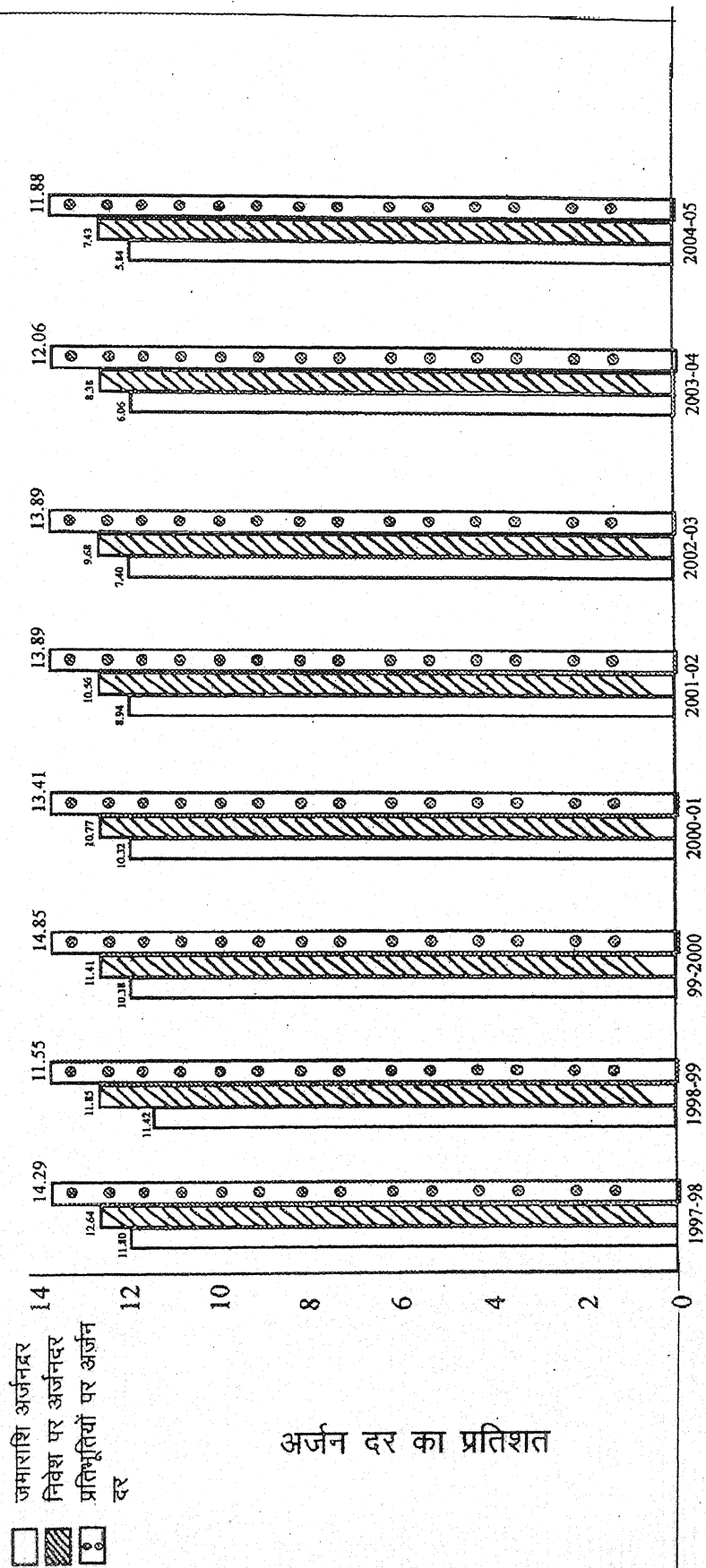
छत्रसाल ग्रामीण बैंक की जमायें

(रुपये हज़ार में)

तालिका 5.4

वर्ष	चालू खाते में जमा		बचत जमा	मियादी जमा		कुल योग
	बैंकों से	अन्य		बैंकों से	अन्य	
1997–98	–	52013	543072	–	393862	986147
1998–99	–	47849	675724	–	462376	1185949
1999–2000	–	80258	738615	–	540105	1358978
2000–2001	–	05490	888605	–	660903	1654998
2001–2002	–	122614	992325	–	748126	1863065
2002–2003	–	138029	1230305	–	767711	2136045
2003–2004	–	157118	1460033	110072	760040	2487263
2004–2005	–	223738	1739734	145374	701482	2810301
योग						14482746

उर्पयुक्त सारिणी में चालू खाते में जमा व बचत खाते जमा तथा मियादी जमा वर्ष–वार बढ़ता गया है जो कि अच्छी स्थिति का सूचक है ।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका नं0 5.5

अर्जित आय एवं ब्याज व्यय (रूपये हजार में)

विवरण / वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05
अ. आय स्त्रोत								
1. ऋणो एवं अग्रिमों पर ब्याज	24816	34356	34356	42471	73269	97954	108540	134007
2. निवेशों पर ब्याज	87706	32316	32316	40339	120403	108589	100461	96845
3. निवेशो पर अन्य आय	–	–	–	–	–	–	18768	1411
4. बैंक अवशेषों पर	–	83301	83301	79980	1938	3402	1964	1840
5. गैर निधि व्यवसाय से	4608	5160	5160	6770	9565	18346	12310	14046
6. विविध आय अपरलिखित खातों मे प्राप्त वसूली सहित	–	–	–	–	–	–	1294	3858
योग	117130	155137	155133	169560	205206	228291	243337	252007
ब. व्यय स्त्रोत								
1. जमा पर	56608	67993	77856	86662	98826	102896	100629	106258
2. उधार पर	6077	6703	8185	7097	6238	7599	12100	14575
3. कार्यगत पर	40355	44352	46787	48308	68751	72400	82700	89984
योग	103040	119048	132828	142067	173815	182895	195429	210817

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका नं. 5.5 मे विभिन्न आय स्त्रोतों व व्यय स्त्रोतों का वर्णन किया गया है यदि हम छत्रसाल ग्रामीण बैंक की आय के साधनो पर गौर करें तो ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज 1997–98 मे 24816 हजार था जो कि 1999–2000 मे बढ़कर 34356 हजार हो गया वह वृद्धि 38.4 प्रतिशत बढ़ी इसी प्रकार यह वृद्धि 2000–2001 में 42471 थी यदि इसकी तुलना 2004–05 से की जाये तो यह बढ़कर 215.5 प्रतिशत तक बढ़ी।

इसी प्रकार बैंक को निवेशों पर ब्याज बढ़ती हुयी दर से प्राप्त हुआ इसका कारण ब्याजदर का उच्च होना है और जिससे प्रदर्शित होता है कि बैंक ने निवेशों पर उपयोग सही जगह किया है परन्तु 2004–05 मे निवेशों पर ब्याज कम प्राप्त हुआ इसी प्रकार निवेशों पर अन्य प्रकार की आय वर्ष 2003–04 में 18768 हजार रूपये प्राप्त हुयी। और 2004–05 मे यह केवल 1411 हजार रूपये प्राप्त हुयी इसका कारण बैंक द्वारा इस वर्ष कम निवेश किये गये।

बैंक अवशेषों पर 1997–98 मे 1153 हजार रूपये प्राप्त हुआ जिसकी तुलना यदि हम 2001 से करें तो इसमे 68 प्रतिशत लगभग की वृद्धि अर्जित की गयी और यदि इसकी तुलना 2004–05 से की जाये तो यह 42 प्रतिशत की कमी दर्शाती है विविध आय अपलिखित खातों में वसूली 2003–04 में 1294 हजार थी जिसमें वर्ष 2004–05 में 139 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

इसी प्रकार उपर्युक्त सारिणी से यदि हम व्यय स्त्रोतों की गणना करे तो वर्ष 1997–98 मे 56608 हजार रूपये किये गये जिसकी वृद्धि दर 1998–99 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रही। बैंक द्वारा जमा पर किये गये व्यय वर्ष 1997–98 मे 6077 रूपये थे जो कि वर्ष 2004–05 की तुलना मे 139 प्रतिशत बढ़ गये इसी प्रकार कार्यगत पर किये गये व्यय वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक 123 प्रतिशत बढ़े।

इसी प्रकार यदि हम वर्ष 2004–05 के कुल आय स्त्रोतों की तुलना कुल व्यय स्त्रोतों से करे तो इनमें 41190 का अन्तर पाया जाता है जिसमे 19.5 प्रतिशत आय अधिक रही।

तालिका 5.6

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के आय–व्यय का विश्लेषण

(राशि हजार में)

वर्ष / विवरण	आय	व्यय	अन्तर
1998	118283	106915	11368
1999	135578	123331	12247
2000	155133	137194	17939
2001	169560	143894	25666
2002	205206	177033	28173
2003	228292	182895	45397
2004	243337	210050	33287
2005	252007	227872	24135

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1998 में रूपये 11368 हजार की आय का व्यय पर आधिक्य था। और 2000 में यह आधिक्य रूपये 17939 हजार हो गया जो कि 1998 की तुलना में 57.9 प्रतिशत बढ़ा। इसी प्रकार 2003 की 2004 से तुलना करने पर यह आधिक्य घट गया 36.3 प्रतिशत रहा यह आधिक्य वर्ष 2005 मे भी घटा जो कि 37.9 प्रतिशत रहा। इसका कारण यह है कि बैंक ने व्यय अधिक किये है उसकी आय स्त्रोतों पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे आय घट गयी।

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका 5.7

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के लाभ - हानि का विश्लेषण

(राशि हजारों मे)

वर्ष / विवरण	लाभ / हानि		
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / हानि	पीछे से लाया गया लाभ / हानि	योग
1998—1999	+ 11368	— 139622	— 128254
1999—2000	+ 12247	— 128254	— 116007
2000—2001	+ 17939	— 116007	— 98068
2001—2002	+ 25666	— 98068	— 72402
2002—2003	+ 28173	— 72402	— 44229
2003—2004	+ 45396	— 44229	+ 1167
2004—2005	+ 33287	— 934	+ 34221
2005—2006	+ 24135	— 12548	+ 36683

उपर्युक्त सारिणी में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की लाभ और हानि को प्रदर्शित किया गया है यदि हम 1998 की स्थिति को देखे तब छत्रसाल ग्रामीण बैंक को 128254 लाख की हानि हुयी और 1999 मे यह हानि घटकर 116007 हजार हो गयी वर्ष 2000 मे यह हानि घटकर 98068 हजार हो गयी वर्ष 2001 मे 72402 हजार हो गयी और वर्ष 2002 में घटकर 44229 हजार रूपये हो गयी यदि हम 1998 की तुलना 2002 से करे तो हम पाते है कि 84025 तक की हानि को कवर किया गया इससे सिद्ध होता है कि वर्ष 1998 मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी नही थी आगे के वर्षो मे बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार आता गया परन्तु फिर भी यह 2002 तक हानि में चलता रहा वर्ष 2003 में बैंक की आर्थिक स्थिति में एक नया मोड़ आया और बैंक ने 1167 हजार रूपये के लाभ अर्जित किये। वर्ष 2005 तक छत्रसाल ग्रामीण बैंक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा। वर्ष 2003 की तुलना मे 2005 में 30 प्रतिशत से अधिक का लाभ अर्जित किया इस प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक विकास की ओर अग्रसर है।

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वार्षिक प्रतिवेदन।

अनुपात विश्लेषण –(Ratio Analysis)

वित्तीय विश्लेषण के लिए आधुनिक समय में अनुपातों का सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है। अनुपात किन्ही दो संख्यात्मक तथ्यों के मध्य गणितीय सम्बंध स्थापित करता है इसके समर्थक एलेक्जेण्डर बॉल माने जाते है। इन्होनें सन् 1909 मे अनुपात विश्लेषण की विस्तृत पद्धति को प्रस्तुत किया था। इनके तथ्यों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नही होता जब तक कि इनके बीच कोई सम्बंध स्थापित न किया जाये। कैनेडी व मैकमुलन के अनुसार, "साधारण गणितीय स्वरूप में मदों के मध्य सम्बंध को अनुपात कहते है।"[1] रॉबर्ट एन एन्थोनी के अनुसार "अनुपात केवल मात्र एक संख्या को दूसरी के सम्बंध में अभिव्यक्ति है। यह एक संख्या आधार को 100 के बराबर लिया जाता है तथाउपलब्धि या भागफल को आधार के प्रति सौ के रूप मे व्यक्त किया जाता है।"[2] हंट विलियम व डोनाल्डसन के अनुसार, "अनुपात केवल मात्र वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के सम्बंध को अंकगणितीय रूप मे प्रदर्शित करने का साधन है।"[3] पद्धति के आधार पर सम्बंध स्थापना का परिणाम ही अनुपात कहलाता है। " साधारणतया गणितीय स्वरूप में मदों के मध्य सम्बंध को अनुपात कहते है।" इसके अतिरिक्त अनुपात एक संख्या की दूसरी संख्या के सम्बंध में केवल अभिव्यक्ति है यह एक संख्या का अन्य संख्या में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। अनुपात वित्तीय विवरणों की विभिन्न मदों के मध्य पारस्परिक संख्यात्मक सम्बंध को व्यक्त करता है।

1. अनुपात के रूप में 2:1, 4:1, 5:1 इत्यादि
2. दर के रूप में दो गुना, 4 गुना, 5 गुना आदि।
3. प्रतिशत के रूप में 20%, 30% इत्यादि।
4. सूक्ति या वाक्यांश के रूप में "Two for one."One and One half for One" etc.

1- The relationship of One item to another expresed in simple mathenatical from is knawn as a ration,. - Kennedy & Mc.Mullen

2- A ratio is simple one number expressed in terms of another. It is formed by dividing one number the base into the other as equalling 100 and the quotient is expressed as per hundred of th e base. - Anthony Robert.N.

3- Ratios are simply a means of high lighting in arithemetical terms the relationship between figures drawn from financial statements. - Hunt.William & Doneldron.

अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य :–

अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण का हृदय कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में हृदय की धड़कन के माध्यम से शरीर की स्वस्थता का पता लगाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के अनुपात विश्लेषण के माध्यम से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अनुपात विश्लेषण प्रबन्धकों की व्यवसाय की गतिविधियों का उचित ज्ञान कराता है। जिससे संख्या की कार्यकुशलता मे वृद्धि करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने में सहायता मिलती है।, जे0 बेटटी के शब्दो मे "लेखांकन अनुपात शब्द का प्रयोग चिट्ठे, लाभ हानि खाते, बजटरी नियंत्रण पद्धति में या लेखांकन संगठन के किसी भाग में दर्शायी गयी संख्याओं के मध्य सार्थक सम्बंध प्रदर्शित करने में किया जाता है।"[4] संख्या से सम्बंध रखने वाले विभिन्न बाहरी पक्ष यथा विनियोक्ताओं, ऋणदाता पूर्तिकर्ता, अंशधारी आदि भी संस्था के वित्तीय अनुपातों के माध्यम से व्यवसाय की गतिपिधियों का ज्ञान प्राप्त करके संस्था के साथ अपने सम्बंधो का समयोजन करने में समर्थ होते है। इसके उद्देश्यों के अन्तर्गत अनुपातों की सहायता से बड़े बड़े एवं जटिल अकं समूहों कों संक्षिप्त एवं सरल करना सम्भव हो जाता है। जिससे उनमें निहित अर्थों कों सरलतापूर्वक समझा जा सकता है इसके अलावा अनुपातों की सहायता से व्यवसायिक गतिविधियों का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना संभव होता है।

अनुपात विश्लेषण का महत्व एवं उपयोगिता –

इसके अध्ययन से विभिन्न संस्थाओं के मध्य तुलना की जा सकती है तथा उसकी कार्यक्षमता जानी जा सकती है।

वायरमैन के अनुसार, "वित्तीय अनुपात उपयोगी इसलिए है कि क्योंकि ये विस्तृत व कठिन गणना के परिणामों का संक्षिप्त सारांश देते है।"[5] अनुपात विश्लेषण तकनीकी मे केवल अनुपातो की गणना ही नही की जाती बल्कि वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों में

4- The term "accounting ratios is used to discribe significient reletionship which exist between figures shown on a Balance system or in any other past of the accountings organisation.
- J.Botty

5- "The financial ratios are useful because they summarize briefly the results of detailed and complicated computation." - Herealel Birman J.R and Allenare drabin

गणितीय सम्बंध का निर्वाचन भी किया जाता है हेलफेर्ट के अनुसार "अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक उच्च या निम्न कार्यक्षमता तथा किसी औसत या तुलनात्मक प्रभाव में महत्वपूर्ण विचलनों की प्रवृत्ति को मालूम करने के लिए संकेत व मार्गदर्शन का कार्य करता है।"[6]

यह संस्थाओं को बोलने की शक्ति प्रदान करते है मूल रूप में ये संख्यायें मौन रहती है, अतः अनुपात संख्याओं को बोलने की जो शक्ति प्रदान करता है वह बहुत लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त अनुपातों की सहायता से भविष्य की योजनाओं को भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है जिससे बजट एवं नियंत्रण प्रणाली को सलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलती है।

अनुपात विभिन्न अवधियों की वित्तीय गतिविधियों मे हुए परिवर्तनो को दर्शाने में सहायक होते है। इस प्रकार अनुपातों का प्रयोग भी प्रभावी सम्प्रेषण में सहायक होता है। अनुपातों के माध्यम से संस्था की सामान्य कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था की उचित गतिविधियों के मानक निर्धारित किये जा सकते है वास्तविक गतिविधियों को मानको अनुरूप बनाये रखने की चेष्टा करने से संस्था की गतिविधियों मे उत्तम समन्वय व सन्तुलन बनाये रखा जाता है।

अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्यकुशलता के मापदण्ड के रूप मे किया जाता है इनकी सहायता से विभिन्न कालों में हुए परिवर्तनो को या विभिन्न बैकिंग संस्थाओ में किसी लेखा अवधि में हुए परिवर्तनों को मापा जा सकता है तथा इस प्रकार उनकी तुलनात्मक कार्यकुशलता का अनुपात लगाया जा सकता है।

अनुपातों के सफल प्रयोग के लिए लेखांकन तथा विश्लेषण प्रक्रिया में एकरूपता बनाये रखना नितान्त आवश्यक है। लेखांकन सिद्धान्तों के प्रयोग में एकरूपता बनाये रखने का अभाव होने से अनुपातो के माध्यम से प्राप्त निष्कर्ष अशुद्ध एवं भ्रामक हो सकते है। अतः अनुपातों के प्रयोग के लिए लेखांकन प्रक्रिया मे एकरूपता होनी अनिवार्य है।

6- The ratio analysis prouide, guides and class expecially in spotting trends towards better on poor performance, and in binding out significient deviation from any average on relatively appliable of andaed. - Healfert Erich.A

अनुपात विश्लेषण के प्रकार :-

अनुपातों की गणना व निर्वाचन निम्न दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

काल श्रेणी विश्लेषण –

यदि अनुपातों की गणना प्रवृत्ति मालूम करने के लिए विभिन्न वर्षो के लिए की जाये तो ऐसे समय पर आधारित विश्लेषण को काल श्रेणी विश्लेषण कहते हैं।

प्रतिनिधिक समूह विश्लेषण –

यदि अनुपातों की गणना एक निश्चित समय में संपूर्ण बैंको की विभिन्न संस्थाओं के लिए की जाये तो ऐसे विश्लेषण को प्रतिनिधिक समूह विश्लेषण कहते हैं।

काल श्रेणी विश्लेषण व प्रतिनिधि समूह विश्लेषण दोनो एक साथ भी किये जा सकते है। साधारणतया सभी अनुपात सामान्य प्रवृत्ति नही बताते है। जब अनुपातों को समूह में रखा जाये तो उनसे विश्लेषण को प्रवृत्ति का बोध होना चाहिए तथा ये अनुपात उसी बैंकों की अन्य संस्थाओं से तुल्य होने चाहिए।

अनुपात विश्लेषण की मान्यतायें –

अनुपात विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है ।

1. जिन विवरणों के आधार पर वित्तीय अनुपातों की गणना की गयी है वे यथासम्भव पूर्व व विशिष्ट चित्र का प्रदर्शन करते हैं।
2. बैकिंग या संस्था जिसका विश्लेषण किया जा रहा है वे वित्तीय विवरणों में अंकित तथ्य अन्य संस्थाओं व संपूर्ण उद्योग के तथ्यो मे तुल्य है।
3. वित्तीय विवरण बैंक की बैकिंग स्थिति का वास्तविक प्रदर्शन करते है।

अतः उपर्युक्त मान्यतायें वास्तविक स्थिति में जितनी सही उतरती है उतने ही अनुपात विश्लेषण के निष्कर्ष सही होने की संभावना रहती है।

अनुपात विश्लेषण की सीमायें –

यद्यपि अनुपात विश्लेषण का प्रयोग वित्तीय विश्लेषण मे अत्यधिक लोकप्रिय है तथापि यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई अनुपात संपूर्ण चित्र प्रदर्शित नही करता लेकिन वे केवल संकेत मात्र देते है जो वित्तीय स्थिति एवं संस्था की प्रक्रियाओं की नियति के अत्यधि

अत्यधिक समुच्चयबोधक होते है। अनुपात स्वयं मे कोई निष्कर्ष नही होते बल्कि विश्लेषणकर्ता को अनुपात विश्लेषण व अपने चातुर्य के माध्यम से निष्कर्ष निकालने हेंतु होतें है। विश्लेषणकर्ताओ को विश्लेषण के मापदण्डो का उपयोग करना होता है जिनके आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। संक्षेप मे यह ध्यान रखा जाता है। कि अनुपात वित्तीय विश्लेषण में केवल मागदर्शन करते है तथा अपने आप में निर्णायक साध्य नही होते है।"[1] हैराल्ड वायरमैन के अनुसार, "अनुपात विश्लेषण सुदृढ़ निर्णय का स्थानापन्न नही है बल्कि यह अन्यथा जटिल स्थितियों मे निर्णय लेने में सहायक उपकरण होता है।"[2] यदि एक अनुपात महत्वपूर्ण है तो वह केवल मात्र सार्थक सम्बंध नही दर्शाता बल्कि विश्लेषणकर्ता को तुरन्त निर्णय लेने में सहायक होता है।"[3] अतः अनुपातों के उपयोगी व सार्थक होने के लिए यह आवश्यक है कि वे तुलना के लिए चुने गये सम्बंधित तथ्यों के मध्य या विभिन्न सम्बंधित वर्गो के लिए सार्थक सम्बंध दर्शाते हो तथा वे अवलोकित समस्या से संगति दर्शाते हो।

अनुपात विश्लेषण की निम्न प्रमुख सीमायें है –

1. केवल एक अनुपात किसी स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रदर्शित नही करता है अतः अवलोकित समस्या से सम्बंधित सभी अनुपातों पर विचार किये बिना एक ही अनुपात के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष स्थिति का भ्रामक चित्र प्रस्तुत करते है। इसलिए यह आवश्यक है कि निष्कर्ष निकालते समय सभी सम्बंधित अनुपातो पर विचार व टिप्पणी की जाये। कैनेडी व मैककिलन के अनुसार, "एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थहीन होता है। यह संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता।"[4]

अनुपात विश्लेषण अपने आप में साध्य नही है। यह केवल निर्वाचन के लिए साधन मात्र है। अतः यह उन पहलुओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करता है जिनकी अधिक छानबीन आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों मे कभी कभी कुछ झूठे दिखावे भी होते है जिनका प्रभाव वित्तीय अनुपातों पर पड़ता है क्योंकि वित्तीय अनुपात इन विवरणो में प्रदर्शित तथ्यों पर आधारित होते है। अतः

1- It should be remembered that ratios are only guides in analysis of financial statements and not concluseve ends in themselves. - Kron S.Klinton and Boyed.

2- Ratio analysis is not a substitute for round judgement rather it is a helpful tool to aid in applying judgement to otherwise complex situations. - Harold Bienman and Allem R.Dredin.

3- It a ratio is to be important it must not oly represet a true relatioship but must also aid the aalyst making his immediate decision. - Korn S.Winton and Boyd.thomas.

4- A Single ratio in itself is meaning less - it does not furnish a complete picture. -Kennedy & Memullen

विश्लेषक को निर्वाचन करते समय इन झूठे दिखावों पर ध्यान देना पड़ता है।

अनुपात विश्लेषण समस्या का केवल परिमाणात्मक विश्लेषण का यन्त्र है। इसमें समस्या के गुणात्मक कारकों से भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो।

अनुपातों की गणना लेखा अभिलेखों से की जाती है । अतः इनमे वे सभी कमियां एवं त्रुटियां रह जाती है जो इन अभिलेखों मे होती है लेखांकन कुछ मान्यताओं एवं सिद्धान्तों पर आधारित होता है। ये मान्यतायें अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता को सीमित कर देती है।

अनुपात विश्लेषण मे तुलना के लिए उसी प्रकार की अन्य संख्या या प्रमाप अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार की संख्याओं के लिए किसी एक अनुपात को प्रमाप अनुपात नही कहा जा सकता विभिन्न परिस्थितियों व संख्याओं के आकार के अनुरूप प्रमाप में संशोधन आवश्यक है। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण के आधार पर तुलना के लिए उचित प्रमापों का अभाव पाया जाता है।

विभिन्न अनुपातों की गणना भूतकालीन तथ्यों के आधार पर की जाती है। इन्हें वर्तमान या भविष्य के लिए प्रयोग करना सदैव ही वांछनीय नहीं होता है क्योंकि वर्तमान या भविष्य की घटनायें भूतकालीन प्रवृत्ति से भिन्न हो सकती है।

अनुपात विश्लेषण मे निर्वचन एवं निष्कर्ष विश्लेषक व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात से प्रभावित हो सकते है। अतः इनका प्रयोग बड़ी सावधानी तथा सतर्कता के साथ किया जाता है।

अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों में सन्निहित केवल कुछ सूचनाओं पर ही आधारित होता है उचित विश्लेषण एवं सुदृढ निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि इससे प्राप्त सूचनाओं को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के साथ प्रयोग किया जाये।

अनुपात केवल सापेक्षित स्थिति का प्रदर्शन करते है अतः अनुपातों को वास्तविक आंकड़ों का स्थानापन्न नही समझना चाहिए। वास्तविक आंकड़ों व अनुपातों मे पर्याप्त भिन्नता हो सकती है अतः विश्लेषक को निर्वचन करते समय वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।

अनुपातों का वर्गीकरण –

अनुपातों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा किया जाता है लेकिन यह आवश्यक नही है कि सभी व्यक्ति व संस्थाये एक सही समान अनुरूप अनुपातों की गणना करें। इन सभी को अपने उद्‌देश्य को मध्य नजर रखते हुए अपने उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ

विश्लेषकों के लिए भिन्न-भिन्न होते है जैसे कुछ अनुपातों का प्रयोग बैकिंग संस्थाओं के लिए कोई महत्व नही है।

चूंकि हम यहां केवल बैकिंग संस्थाओं का ही विश्लेषण कर रहे है और उनका ही वर्णन करेगें किन्तु संक्षेप में अनुपात अनेक प्रकार के हो सकते है जो कि निम्नलिखित है।

स्थिति विवरण के आधार पर वर्गीकरण –

1. विवरण के आधार पर
2. सापेक्षित महत्व के आधार पर
3. प्रकृति के आधार पर
4. लेखांकन के महत्व के आधार पर
5. प्रयोगकर्ता के आधार पर
6. उद्देश्य के अनुसार

लाभदायकता अनुपात

1. सकल लाभ अनुपात
2. शुद्ध लाभ अनुपात
3. परिचालन अनुपात
4. व्यय अनुपात

5 पूंजी निवेश पर प्रतिफल

A- अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय

B- समता अंश पूँजी पर प्रत्याय

C- विनियोजित पूँजी पर प्रत्याय

6. लाभांश अनुपात

7. विनियोगताओं की दृष्टि से लाभदायकता अनुपात

1. प्रति अंश आय
2. प्रति अंश लाभांश
3. मूल्य अर्जन अनुपात
4. लाभांश प्रतिफल अनुपात
5. भुगतान अनुपात

निष्पादन अनुपात

1. स्कन्ध आबर्त अनुपात

2. सम्पत्ति आबर्त अनुपात

A. स्थायी सम्पत्ति आबर्त अनुपात

B. चालू सम्पत्ति आबर्त अनुपात

3. प्राप्य आबर्त अनुपात
4. पूँजी आबर्त अनुपात
5. देय आबर्त अनुपात
6. आधार भूत रक्षक अन्तर
7. शोधन क्षमता अनुपात

वित्तीय स्थिति अनुपात

1. चालू अनुपात
2. तरल अनुपात
3. पूर्ण तरलता अनुपात
4. स्थायी सम्पत्ति अनुपात

ग्राफ–3.1

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका नं0–5.8
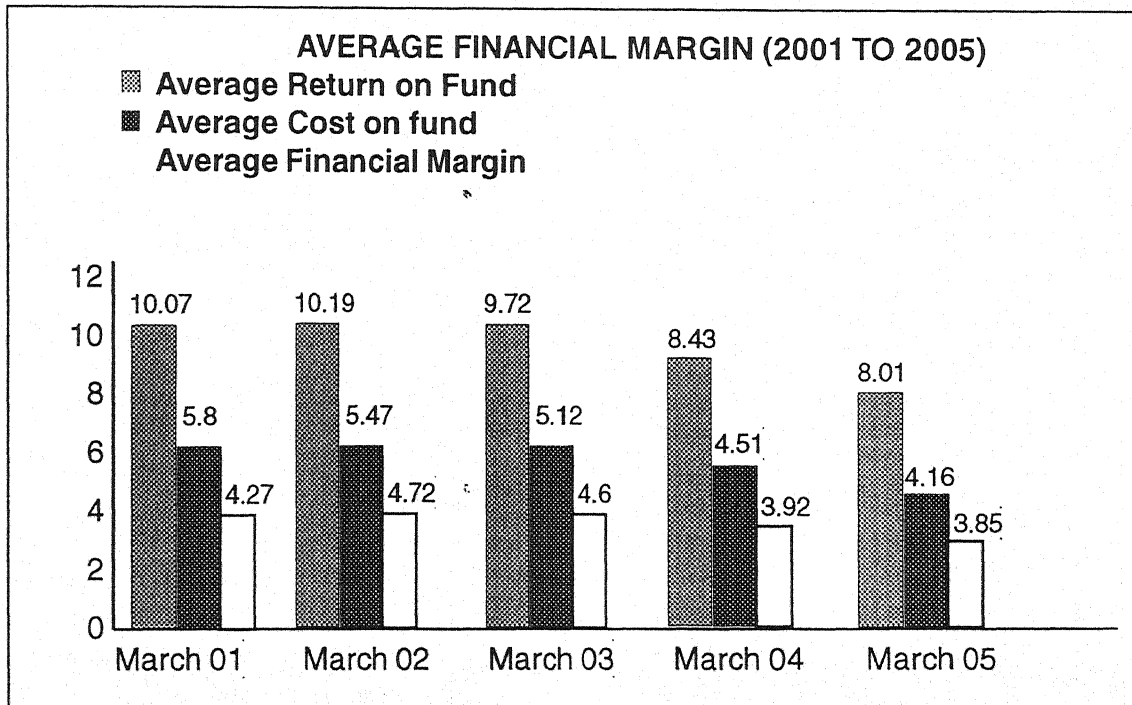
छत्रसाल ग्रामीण बैंक की चालू सम्पत्ति व चालू दायित्वों का तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

Capital&Liabilities/Years Current Liabilities	31-3-98	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. जमा राशियां (Deposits)	592285	723573	818873	994095	1114939	1368334	1617151	1963472
2. उधार (Borrowing)	105458	117494	98527	75874	98987	181611	264495	198568
3. अन्य देयतायें एवं प्राविधान (Other liabilities & provision)	149661	172807	166247	201316	150051	151925	138135	129794
TOTAL	847404	1013874	1083647	1271285	1363987	1701870	2019781	2291834
Current Assets								
नकद तथा अवशेष 1- (Cash & Balance) भारतीय रिज़र्व के पास	41980	48211	65680	75693	130450	169765	185917	228694
2. अन्य बैंकों में अवशेष एवं मांग तथा अल्प मचना पर जमा राशि Balance with Bank and money at call & short notice)	604848	784263	827478	966678	869740	693214	624320	396726
3. खरीदे एवं भुनाये गये बिल	800	12780	-	-	-	119	64641	11520
4. मांग पर देय कैश केडिट अधिविकर्ष एवं ऋण	59576	66210	79236	175536	352340	523190	727821	1078553
5. अग्रिम प्रदत्त कर/श्रोत से काटा गया कर	12	12	12	-	301	1655	3259	4675
6. उपार्जित आय(Intrust incurred)	33835	40724	51612	22412	25096	25600	25230	-
TOTAL	741051	952200	1024018	1240319	1378829	1413543	1631188	1743151

स्त्रोत– वार्षिक प्रतिवेदन छत्रसाल ग्रामीण बैंक

तालिका 5.9

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के विभिन्न तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

Ratio / Year	31-3-98	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1- Current Ratio चालू अनुपात	.87:1	.93:1	.94:1	.97:1	1.01:1	.83:1	.80:1	.76:1
2- Propritory Ratio स्वामित्व अनुपात	.09:1	.09:1	.084:1	.071:1	0.66:1	.057:1	.051:1	.63:1
3- Dept equity Ratio नक़द समता अनुपात	9.8:1	9.8:1	10.8:1	12.90:1	14.10:1	16.36:1	15.33:1	14.76:1
4- Return on Capital Employes पूंजीदर प्रत्यय अनुपात	9.05 %	8.18%	11.98%	17.14%	18.8%	30.3%	21.6%	15.67%
5- Ratio of Fixed assets to properties स्थायी सम्पत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात	1.34:1	1.09:1	.009:1	.016:1	.023:1	.042:1	.044:1	.054:1
6- Ratio of current assets to properties चालू सम्पत्तियों का स्वामियों के कोषो से अनुपात	5.90:1	6.36:1	6.84:1	8.285:1	9.21:1	9.369:1	8.65:1	8.2:1
7- Quick Ratio तरलता अनुपात या त्वारित अनुपात	.87:1	.93:1	.94:1	.97:1	1.1:2	.82:1	.80:1	.76:1

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन छत्रसाल ग्रामीण बैंक।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के विभिन्न तुलनात्मक वित्तीय अनुपात का विश्लेषण

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का स्वामित्व अनुपात बताता है कि व्यवसाय के कुल सम्पत्तियों के किस भाग के लिए अंशधारियों ने पूंजी दी है।यह अनुपात जितना अधिक होगा बैंक को कार्यशील पूंजी के लिए बाहरी स्त्रोत पर उतना ही कम निर्भर होना पड़ेगा तथा दूसरी तरफ ऋणदाताओं को उतना ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा संस्था को अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहेगी अतः यह अनुपात जितना अधिक होगा आर्थिक दृष्टि से संस्था उतनी ही सुदृढ़ मानी जायेगी परन्तु छत्रसाल ग्रामीण बैंक की उक्त सारिणी का अवलोकन करनें पर ज्ञात होता है कि बैंक का स्वामित्व अनुपात काफी कम है अध्ययन अवधि के दौरान बैंक के स्वामित्व अनुपात की गणना कुल सम्पत्ति को आधार मानकर की गयी है जबकि इसकी गणना कुल मूर्त सम्पत्तियों के आधार पर भी की जा सकती है बैंक का स्वामित्व अनुपात वित्तीय वर्ष 1997–98 मे ..09:1 था जो कि वित्तीय वर्ष 1999 मे समान रहा लेकिन वित्तीय वर्ष 2000 से वित्तीय वर्ष 2003 तक इसमें निरन्तर कमी परिलक्षित होती है जहां वित्तीय वर्ष 2003 में यह अनुपात .057:1 के अपने न्यूनतम स्तर पर था वही वर्ष 2004 में यह मामूली वृद्धि के साथ .061:1 के स्तर पर है यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंक की अर्जन क्षमता में स्थिरता है और यदि किसी औद्योगिक या वित्तीय संस्थान की अर्जन क्षमता मे स्थिरता होने पर तुलनात्मक रूप से नीचा स्वामित्व अनुपात साधारण अंशधारियों के लिए लाभदायक होता है कई वित्तीय विश्लेषक यह मानते है कि व्यवसाय की स्थायी सम्पत्तियों का अर्थ प्रबंधन जितना अंशधारियों के कोष से होगा व्यवसाय उतना ही आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ माना जायेगा यदि बैंक की स्थायी सम्पत्तियां अंशधारियों के कोष से अधिक है तो इसका आशय यह है स्थायी सम्पत्तियों का अर्थ प्रबंधा ऋण पूंजी से भी किया गया है ऐसी दशा मे यदि किसी भी दशा में ऋणदाता अपना ऋण वापिस मांग लेते है तो संस्था के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि संपूर्ण ऋण भुगतान के लिए कुछ स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय अवश्यम्भावी होगा यदि कुल दृश्य स्थायी सम्पत्तियों में स्वामित्व पूंजी का भाग देकर अनुपात ज्ञात किया जाये तो यह अनुपात जितना कम होगा संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता उतनी ही श्रेष्ठ होगी क्योंकि अंशधारियों के कोष कार्यशील पूंजी मे भी उपलब्ध होंगे इस अनुपात के सम्बंध में कोई सर्वमान्य प्रभाव निर्धारित

नही किया जा सकता संस्था की आर्थिक स्थिति लाभार्जन दर एवं वित्तीय संरचना को देखते हुए यह अलग-अलग हो सकता है। इस तथ्य को स्थायी सम्पत्ति अनुपात की गणना द्वारा भी विश्लेषित किया जा सकता है जिसमें कुल दृश्य स्थायी सम्पत्तियों में स्वामित्व पूंजी व दीर्घकालीन उधार का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है ऐसी दशा मे यह अनुपात 1:1 होने की स्थिति में सुदृढ वित्तीय स्थिति का परिचायक है क्योंकि 1:1 से अधिक का अनुपात यह बताता है कि स्थायी सम्पत्तियों कुल दीर्घकालीन कोषों से अधिक है तथा इससे निष्कर्ष निकाला जायेगा कि संस्था ने अल्पकालीन कोषों के प्रयोग के सम्बंध में दूरदर्शी सोच नहीं अपनाई है।

चालू अनुपात यह बताता है कि चालू दायित्व के प्रत्येक रूपये के लिए कितनी चालू सम्पत्ति की व्यवस्था है। चालू अनुपात अल्पकालीन ऋणदाताओं की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्योकि यह अनुपात अल्पकालीन ऋणों की शोधन क्षमता एवं सुरक्षा सीमा प्रकट करता है। यह अनुपात एक से जितना ही अधिक होगा संस्था की चालू दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी व अल्पकालीन ऋणदाताओं समय पर ऋणों की वापसी के प्रति उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे। परन्तु इस अनुपात का एक सीमा से अधिक होना ऋणदाताओं की दृष्टि से अवश्य अच्छा होता है पर वित्तीय प्रबंध की दृष्टि से अल्पकालीन वित्तीय साधनों की त्रुटिपूर्ण नियोजन का द्योतक होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यवसाय का अत्यधिक धन अनावश्यक रूप से अनुत्पादक रूप में बेकार पड़ा रहता है जिस पर कोई आय प्राप्त नही होती है दूसरी ओर निम्न चालू अनुपात व्यवसाय मे कार्यशील पूंजी की कमी को प्रदर्शित करता है। जिसमें व्यवसाय के सुचारू संचालन में बाधा आती है। इस सम्बंध में अधिकतर लेखकों का मत है कि औद्योगिक फर्मो मे 2:1 का चालू अनुपात आदर्श समझा जाता है क्योंकि यह मत इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि वर्तमान स्तर से मूल्यों में 50 प्रतिशत गिरावट भी हो जाये तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय पर भुगतान हो जायेगा। परन्तु यह केवल औद्योगिक फर्मो के लिए आदर्श माना जाता है चूंकि हमारी अध्ययन वस्तु बैकिंग संस्था है इसलिए यह अनुपात 2:1 से भी कम हो सकता है क्योंकि बैकिंग संस्थानों को औद्योगिक फर्मो की तरह उत्पादन प्रक्रिया को बनाये रखने हेतु इसी प्रकार व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का 2:1 का चालू अनुपात कोई प्रमाणित माप नही है क्योंकि पर्याप्त दीर्घकालीन कार्यशील

पूंजी की आवश्यकता नही होती इसका तात्पर्य यह नही है कि बैकिंग संस्थानों को कार्यशील पूंजी की कतई आवश्यकता होती है। जिसके लिए उनके पास पर्याप्त तरलकोष उपलब्ध होते हैं।

प्रत्येक व्यवसाय की निजी विशेषतायें होती है तथा उनकी कार्य करने की दशायें भी भिन्न-भिन्न होती है अतः व्यवसाय की प्रकृति व प्राप्त तथा दी गयी साख अवधियों को ध्यान मे रखते हुए इस अनुपात की आदर्श सीमा में परिवर्तन वांछनीय होगें।

इसी प्रकार त्वरित या तरलता अनुपात के अन्तर्गत सन् 1998 मे यह अनुपात .87:1 रहा। इसकी स्थिति वर्ष 2002 मे 101:1 रही जो कि 2005 में घटकर .76:1 हो गयी।

ऋण समता अनुपात के अन्तर्गत एक व्यवसायिक संस्था की कुल सम्पत्तियों का अर्थ प्रबंधन स्वामी समता या वाहन ऋणों द्वारा किया गया होता है कुल सम्पत्तियों के अधिग्रहण मे कितना फण्ड स्वामियों द्वारा प्रदान किया गया और कितना धन वाहन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है इसका गहरा प्रभाव संस्था की शोधनक्षमता (दीर्घकालीन) पर पड़ता है। अतः यह आवश्यक होता है कि कुल सम्पत्तियों, स्वामी समता और ऋणों के बीच कुल सम्पत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु अधिकांश रूप से स्वामी समता पर निर्भर करती है तो वापिस लेनदारों का हित सुरक्षित होता है और संस्था के समक्ष भी उनके भुगतान की कोई कमी नहीं होती है।

तालिका 5.10

चिट्ठे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

विवरण	1997—98	1998—99	1999—2000	2000—2001	2001—02	2002—03	2003—04	2004—05
1. लाभ/हानि प्रावधानों से पूर्व	+ 15243	+ 16530	+ 22304	+ 27493	+ 31391	+ 45396	+ 46907	+ 38843
2. लाभ / हानि प्रावधानों के पश्चात्	+ 11368	+ 12247	+ 17939	+ 25666	+ 28173	+ 45396	33287	24135
3. ऋणों एवं अग्रिमों पर आय	24816	26925	34356	42471	73269	97954	108540	134007
4. निवेश पर आय	88858	107719	113760	118776	120403	108589	100460	96845
5. कुल व्यय	106915	123331	137194	143894	177033	182895	210050	227872
6. वेतन पर व्यय	37230	40505	42364	43298	61789	64592	72210	75436
7. कुल व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत	34.82	32.84	30.88	30.09	34.90	35.32	34.38	33.10
8. कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का प्रतिशत	31.48	29.96	27.31	25.54	30.11	28.29	29.67	29.93
9. कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का प्रतिशत	37.74	35.96	34.10	33.57	38.84	39.46	39.37	40.52
10. औसत जमा लागत	6.64	6.51	6.50	6.28	6.03	5.51	4.84	4.30
11. अन्तशाखायी लेनदेन पर ब्याज दर	12.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	8.00

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन छत्रसाल ग्रामीण बैंक।

चिट्ठे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात का विश्लेषण

महोबा जनपद में कार्यरत छत्रसाल ग्रामीण बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत है को हम चिट्ठे पर आधारित कुछ वित्तीय अनुपातों का विश्लेषण कर रहे है यदि हम पिछले कुछ वर्षो का वर्तमान वर्षो से तुलनात्मक अध्ययन करे तो हमें वित्तीय विवरणो मे हुए उतार चढ़ावों का पता चलता है।

मेरे प्रथम अवलोकन के दौरान मुझे तालिका से पता चलता है कि बैंक का लाभ प्रावधानो से पूर्व वित्तीय वर्ष 1997–98 मे 15243 हजार थी जो कि 2003–04 मे 46907 हजार बढ़ गयी यह प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर बढती गयी है जो कि 1998–99 मे 8.440 प्रतिशत बढ़ी तथा 1999–2000 मे वर्ष 1997–98 की तुलना मे यह 46.32 प्रतिशत की गति से बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2001–02 मे 14.17 प्रतिशत बढ़ी और 2003–04 मे वर्ष 2002–04 की तुलना मे 3.30 प्रतिशत की वृद्धि बढी बैंक के लाभो मे वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि बैंक की वित्तीय स्थिति मे निरन्तर सुधार आया है जिसके कारण लाभ बढ़ते गये यदि हम 1997–98 की तुलना वित्तीय वर्ष 2003–04 से करें तो हमें पता चलता है कि इसने 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करायी है परन्तु यह वृद्धि प्रावधानों के पूर्व की है इसलिए इसे उच्चतम दर्जा देना पूर्ण रूप से सही नही है जबकि गत वर्ष की तुलना में 2004–05 की वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत हो गयी।

बैंक के लाभ / हानि प्रावधानों के पश्चात् का यदि हम अवलोकन करे तो हमें पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 1997'98 मे 11368 हजार थे जिनमे 1998–99 मे 897 यानि 8 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है इसी प्रकार 1999–2000 में भी थोड़ी बहुत वद्धि हुयी परन्तु 2000–01 मे यह वृद्धि 43 प्रतिशत तक बढ़ी है फिर वित्तीय वर्ष 2001–02 मे अधिक वृद्धि नही हुयी बल्कि 2002–03 में आशातीत से अधिक वृद्धि हुयी जो कि 2001–02 की तुलना मे 61 प्रतिशत है। बैंक ने 1997 से 2003 तक लाभ को बढ़ाया जो कि प्रावधानों को करने के पश्चात् हुए थे परन्तु वित्तीय वर्ष 2004–05 मे इसमें 38 प्रतिशत की कमी आ गयी जो कि बैंक के लिए हानिकारक है यदि हम वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2002–03 की स्थिति पर प्रकाश डालें तो यह वृद्धि निरन्तर रही है जो कि 30 प्रतिशत है। अतः बैंक के लिए यह अवश्यक है कि वह वर्तमान में अपने लाभो को बढ़ाने का प्रयास करें जिससे इसी कमी को पूरा किया जा सके।

अब यदि हम अपनी दृष्टि बैंक के ऋणों एवं अग्रिम की आयों पर डालें तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 से लेकर 2003–04 तक यह चरम आय उच्च सीमा में पहुंच गयी है। 1997–98 की तुलना में लेकर वित्तीय वर्ष 2000–01 तक यह वृद्धि 71.14 प्रतिशत रही है तथा वित्तीय वर्ष 2001–02 में 72.5 प्रतिशत 2002–03 मे 33.60 और 2003–04 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 23.4 प्रतिशत रही है यह वृद्धि 1997–98 से वित्तीय वर्ष 2004–05 तक 44 प्रतिशत रही जिससे ज्ञात होता है कि बैंक को ऋणों व अग्रिमों से ब्याज के अतिरिक्त आय अधिक हो रही है बैंक की स्थिति आगे की ओर अग्रसर है।

बैंक द्वारा निवेशों से प्राप्त आय पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें दृष्टिगोचर है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 मे निवेश पर आय 88,858 थी जो कि निरन्तर बढ़ती हुयी वित्तीय वर्ष 2000–01 में 33.6 प्रतिशत रही । बैंक की साख अच्छी होने के कारण अन्य पक्षो ने बैंक में अपने वित्त का विनियोग किया जिससे बैंक की आय मे वृद्धि हुयी और विनियोजकों का भी उत्साहवर्धन हुआ जिससे अधिक से अधिक इस बैंक मे निवेश किया गया इन निवेशों के अवलोकन द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक निवेशों से आय 33.6 प्रतिशत तक बढ़ी परन्तु कुछ कारणों से वित्तीय वर्ष 2002–03 व 2003–04 में यह आय घट गयी अतः बैंक को ऋणों की देन व अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए 2003–04 व 2004–05 मे 3.37 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है।

बैंक के कुल व्यय पर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 में यह व्यय 15.3 प्रतिशत रहा फिर 1998–99 मे बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया। बैंक का कुछ व्यय प्रतिवर्ष 2004–05 तक यह 8.48 प्रतिशत बढ़ा यदि हम वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2004–05 की तुलना करें तो पाते है कि इसमें कुल व्यय वृद्धि रही है जो कि चिन्ताजनक है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वेतनों पर किये गये व्ययों की अध्ययन अवधि के दौरान हमने पाया कि वेतनों पर व्यय प्रतिवर्ष बढ़ते चले गये है वित्तीय वर्ष 1997–98 में वित्तीय वर्ष 2000–01 तक यह 16.2 प्रतिशत बढे और यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2004–05 तक 102.6 प्रतिशत वृद्धि हुयी है वेतन पर व्यय में वृद्धि मंहगाई में निरन्तर वृद्धि होने के सापेक्ष है जिससे बैंक के वेतन व्यय पर अधिक भार पड़ा अतः वेतन पर व्यय में वृद्धि को बैंक की कार्यक्षमता या परिणाम

से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

वित्तीय अनुपात की अध्ययन अवधि के दौरान यदि हम कुल व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय का प्रतिशत ज्ञात करें तो वित्तीय वर्ष 1997–98 मे यह 34.82 प्रतिशत था जो कि 1998–99 में घटकर 6.02 प्रतिशत रह गया वित्तीय वर्ष 1999–2000 2000–2001 मे यह लगभग स्थिर रहा जबकि 2001–02 में यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.9 प्रतिशत बढ़ गया। 2002–2003 में इसमें मामूली सी वृद्धि हुयी परन्तु वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 2003–04 की अपेक्षा 3.8 प्रतिशत की कमी आ गयी।

बैंक के कुल आय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत का अवलोकन करने पर पता चलता है कि जहां एक ओर वित्तीय वर्ष 1997–98 से 1998–99 में 5 प्रतिशत की कमी दर्ज हुयी वही 1999–2000 मे भी लगातार 8 प्रतिशत की कमी हुयी है कुल आय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत में निरन्तर कमी व वृद्धि परिलक्षित हुयी है इससे स्पष्ट होता है कि बैंक ने एक तरफ जहां अपनी कुल आय में वृद्धि की है तो दूसरी तरफ आय के सापेक्ष वेतन पर भार में कमी हुयी है। जो कि बैंक के उच्च कार्यक्षमता एवं निरन्तर नवीन तकनीकी का प्रयोग करने से संभव हुआ है अन्य अनुसूचित बैंको अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह छत्रसाल ग्रामीण बैंक का भी कम्प्यूटरीकरण हुआ है जिससे बैंक में नियुक्त साख संसाधनों में कमी आयी है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कुल व्यय के सापेक्ष प्रबंधन लागत का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2003–04 तक विभिन्न उतार चढ़ाव लिये हुए है जिसमें 2000–2001 तक यह लागत कम हुयी है जो वित्तीय वर्ष 1997–98 मे 4.9 प्रतिशत थी तथा 2000–2001 मे 2001–02 की तुलना में 5.6 प्रतिशत हो गयी है इससे इसकी कार्यक्षमता बढ़ती है जिससे बैंक अपनी आय से निरन्तर वृद्धि कर सकता है और वित्तीय वर्ष 2001–02 मे यह बढ़ गयी है तथा 2004–05 में 2.92 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज कराती है।जिसके कारण बैंक की आय में कमी आ जाती है।

सारांशतः उपर्युक्त सारिणी के आधार पर कहा जा सकता है कि छत्रसाल ग्रामीण बैक के लाभों में निरन्तर प्रगति हुयी है ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष वेतन एवं प्रबन्धन लागत में कमी हुयी है। जिससे यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको से अपनी तुलना कर सकता है। अग्रलिखित सारणी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों को दर्शाया गया है।

तालिका 5.11
तुलनात्मक वित्तीय अनुपात

Particular / Year	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05
औसत कार्यशील निधि	1043611	1293735	1463228	1617049	1920349	2159160	2501382	2904484
1. वित्तीय आय	10.68	10.15	10.25	10.07	10.19	9.72	8.43	8.01
2. वित्तीय व्यय	5.89	5.77	5.88	5.80	5.47	5.12	4.51	4.16
3. वित्तीय मार्जिन	4.97	4.38	+ 4.37	+ 4.27	+ 4.72	+ 4.60	+ 3.92	+ 3.85
4. कार्यशील मार्जिन	3.79	3.43	3.20	2.99	3.58	3.35	3.31	3.18
5. विविध व्यय	0.43	0.33	0.35	0.42	0.50	0.85	1.29	0.67
6. कार्यशील लाभ	1.43	1.28	+ 1.52	+ 1.70	+ 1.64	+ 2.10	+ 1.90	+ 1.34
7. जोखिम लागत	0.43	0.33	0.30	0.11	0.17	एन ए	0.58	0.51
8. शुद्ध मार्जिन	+ 1.00	+ 0.95	+ 1.22	+ 1.59	+ 1.47	+ 2.10	+ 1.32	+ 0.83

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन छत्रसाल ग्रामीण बैंक ।

वित्तीय विवरणों के आधार पर छत्रसाल ग्रामीण बैंक का विश्लेषण –

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में महोबा जनपद मे कार्यरत छत्रसाल ग्रामीण बैंक की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम हम वित्तीय विवरणों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों को सारिणी से प्रदर्शित कर रहे है जिसमे विभिन्न वित्तीय अनुपातों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत इस बैंक के वित्तीय स्थिति का विश्लेषण हो सके तुलनात्मक वित्तीय अनुपातों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बैंक की औसत कार्यशील निधि मेरी अध्ययन अवधि के दौरान लगभग डेढ़ गुनी हो गयी है यह 150 प्रतिशत की वृद्धि यह प्रदर्शित करता है कि बैंक ने अपने क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य विस्तार किया है इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जहां वर्ष 1997–98 मे बैंक की औसत कार्यशील पूंजी 10.43 लाख रूपये है वही 1998–99 के दौरान इसमें 23.96 प्रतिशत की वृद्धि हुय पुनः 1999–2000, 2000–2001 2001–2002 2002–2003 में औसत कार्यशील निधि की बैंक ने अपने वित्तीय आय में कमी के अनुपात में वित्तीय व्ययों में कमी की है निश्चय ही बैंक का यह प्रयास उसकी आर्थिक सेहत के लिए लाभकारी है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का वित्तीय मार्जिन जहां 1997–98 में 4.79 था वही 1998–99 में घटकर 4.38 रह गया पुनः वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान यह 4.37 तथा वित्तीय 2000–2001 मे 4.27 रहा इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2000–2001 तक बैंक के वित्तीय मार्जिन में कमी दर्ज की गयी है जो कि चिन्ताजनक है लेकिन 21वीं शताब्दी में प्रवेश के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे बैंक का वित्तीय मार्जिन पुनः 4.72 के अंक पर पहुंचा जिसमें अगले दो वित्तीय वर्षो में पुनः गिरावट दर्ज की गयी और यह वित्तीय मार्जिन वित्तीय वर्ष 2003–04 मे 3.29 रह गया अर्थात् 1997–98 की तुलना मे वित्तीय मार्जिन में 18.16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी जो कि निश्चय ही वित्तीय आय के कम होने के कारण भी हो सकता है।

बैंक का कार्यशील मार्जिन वित्तीय वर्ष 2000–01 में मेरी अध्ययन अवधि के दौरान 2.99 के साथ साथ अपने न्यूनतम स्तर पर था वही वित्तीय वर्ष 1997–98 मे 3.79 के साथ

अपने उच्चतम बिन्दु पर में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है वित्तीय वर्ष 2003–04 में बैंक की औसत कार्यशील निधि 25.01 लाख रूपये तक पहुँच चुकी है जो निरन्तर कार्य प्रगति में वृद्धि का द्योतक है। जो कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 29.04 लाख हो गयी है।

बैंक की वित्तीय आय का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 से 1999–2000 तक बैंक की वित्तीय आय लगभग स्थिर रही है वित्तीय वर्ष 2000–2001 में इसमें मामूली कमी आयी है वही 2001–2002 में इसमें वृद्धि हुयी है लेकिन वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में इसमें कमी आयी है। वित्तीय वर्ष 1997–98 की तुलना मे वर्ष 2003–04 में यह कमी 21.07 प्रतिशत है जो वित्तीय वर्ष 2004–05 मे गत वर्ष की तुलना में 5.10 की कमी हुयी। जो कि निश्चय ही चिन्ताजनक है। क्योंकि वित्तीय आय में कमी होने से बैंक के उपलब्ध कोषों में कमी होती है जिसका प्रभाव वित्तीय मार्जिन पर भी पड़ता है इस सम्बंध में मेरी राय यह है कि उदारीकरण के बाद बैंको में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और इससे निश्चय ही कुछ बैंको की वित्तीय आय प्रभावित हुयी है।

बैंक की वित्तीय व्यय पर दृष्टिगत करने से ज्ञात होता है कि बैंक की वित्तीय व्यय वर्ष 1997–98 से लेकर वर्ष 2000–2001 तक लगभग 5.8 के लगभग रहे है जिसमे वित्तीय वर्ष 2001–2002 2002–2003 एवं 2003–2004 में लगातार कमी देखी गयी है वित्तीय व्यय की यह कमी 1997–98 की तुलना में दर्ज 2003–04 मे 23.42 प्रतिशत है वर्ष 2005 मे भी निरन्तर गिरावट की स्थिति रही है। इससे स्पष्ट है कि समष्टि रूप में कार्यशील मार्जिन में निरन्तर कमी दृष्टिगोचर होती है और यह कमी वित्तीय मार्जिन में कमी के समानान्तर है।

बैंक के कार्यशील लाभ जहां वित्तीय वर्ष 1997–98 मे 1.43 थी वही वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 2.10 हो गयी परन्तु वित्तीय वर्ष 2003–04 में गिरकर 1.90 थी।

बैंक की जोखिम लागत अध्ययन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2000–2001 मे 0. 11 अंक के साथ अपने न्यूनतम स्तर पर रही वित्तीय वर्ष 2003–04 मे 0.58 के साथ सर्वाधिक थी।

बैंक का शुद्ध मार्जिन वित्तीय वर्ष 1997–98 मे 1.00 था जो कि वर्ष 2002–03 मे अपने उच्चतम बिन्दु 2.1 पर पहुंचा किन्तु अगले वित्तीय वर्ष मे इसमे 37.14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।

सारांशतः उपर्युक्त सारिणी के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक की वित्तीय स्थिति मे अपेक्षाकृत सुधार हुआ है लेकिन अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करने एवं अपने आपको प्रतिस्थापित करने के लिए बैंक को अपनी जोखिम लागत विविध व्यय एवं वित्तीय व्ययो में निरन्तर कमी करनी होगी तथा वित्तीय आय वित्तीय मार्जिन तथा शुद्ध आय को उत्तरोत्तर वृद्धि करने के दायरे में लाना होगा।

प्रवृत्ति विश्लेषण
(Trend Analysis)

व्यवसाय एक गत्यात्मक (Dynamic) प्रक्रिया है जिसे अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों का सामना कर दीर्घकाल में अस्तित्व बनाये रखना होता है किसी वर्ष विशेष के लेखों का परीक्षण कर बैंक के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त नही की जा सकती अतः बैंक विशेष के सम्बंध में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्षो से सम्बंधित वित्तीय लेखों की श्रृंखला की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर बैंक मे विभिन्न मदों की दीर्घकालीन रूख या प्रवृत्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सके। सिम्पसन एवं काफका के शब्दो में, "प्रवृत्ति जिसे दीर्घकालिक या दीर्घकालीन प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है एवं श्रृंखला में वृद्धि या कमी का आधारभूत प्रवृत्ति को बताती है प्रवृत्ति की अवधारणा अल्पकालीन उच्चावचनों का सम्मिलित नही करती है बल्कि यह एक लम्बे समय में हुए परिवर्तनों को बताती है।"[1] हिरच ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा कि "प्रवृत्ति जिसे दीर्घकालिक प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है का अभिप्राय दीर्घकाल में एक श्रेणी में हुयी अनुक्रमिक वृद्धि या ह्रास को बताता है।"[2]

1- Trend also called secular or long term trend is the basic tendancy of a series to grow or decline over a period of time. The concept of trend does not include short range oscillations but rather steady movements over a long time.
- Simpson & Kafka

2- By trends some time also called seculer trend we mean the long run gradual growth or decline in a series.
- Hirsch

प्रवृत्ति विश्लेषण की विधियां : (Techniques of trend analysis)

अनुपात विश्लेषण व तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रवृत्ति विश्लेषण में तो सहायक होते है परन्तु इनके अतिरिक्त प्रवृत्ति विश्लेषण की कुछ निम्नलिखित विधियां हैं।

1. निरपेक्ष समंक चार्ट
2. निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन
3. श्रृंखला आधार निदेशांक व इन पर आधारित परिवर्तन दर
4. प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत

1. निरपेक्ष संपर्क चार्ट –

साधारणतण बैकिंग गृह अपने व्यवसाय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक प्रकाशित लेखा के साथ दस वर्षीय सांख्यकीय सारांश भी प्रकाशित करते है। इस सारांश में कार्यशील पूंजी, स्थिति विवरण व लाभ हानि खातो से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनायें दी हुयी होती है। वित्तीय विश्लेषक इन दस वर्षीय सांख्यकी सारांशों के आधार पर बैंक के सम्बंध में धारणा बना सकता है।

2. निरपेक्ष मूल्य परिवर्तन –

इस विधि के अन्तर्गत प्रवृत्ति अध्ययन के लिये किसी मद विशेष के मूल्यों की एक श्रृंखला प्राप्त की जाती है मद के निरपेक्ष मूल्य की बिल्कुल पिछली अवधि के मूल्य से तुलना की जाती है तथा अन्तर को धन अथवा ऋण चिन्हों के साथ दिखाया जाता है।

3. श्रृंखला आधार निर्देशांक एवं इन पर आधारित परिवर्तन दर –

उपर्युक्त विधि का प्रमुख दोष सापेक्षिता का अभाव है इस दोष को दूर करने के लिए श्रृंखला आधार निर्देशांक व इन पर आधारित परिवर्तन दर विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत परिवर्तनों को निरपेक्ष मूल्यों में न व्यक्त कर प्रतिशतों के रूप में व्यक्त किया जाता है।

साधारण निर्देशांक व उन पर आधारित परिवर्तन दर –

उपर्युक्त विधि में सबसे बड़ा दोष यह रह जाता है कि सूचकांक व परिवर्तन दर परिवर्तित आधार पर परिकलित किये जाते है। इनकी सहायता से तुलना पिछले वर्षो से की जा सकती

है अन्य वर्षो से नही अतः प्रवृत्ति अध्ययन में निरन्तरता का अभाव महसूस किया जाता है। इस विधि मे निर्देशांक व परिवर्तन दर एक ही आधार पर आधारित होती है अतः तथ्य अधिक तुल्य होते हैं।

5. प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत –

पूर्व वर्णित विधियों से किसी एक मद विशेष की प्रवृत्ति का अध्ययन तो किया जा सकता है परन्तु इस प्रवृत्ति का अन्य मदों से सापेक्ष अध्ययन नहीं किया जाता है प्रवृत्ति विश्लेषण में इस गुण का समावेश करने के लिए एक मद की प्रवृत्ति की तुलना किसी दूसरे मद से करना आवश्यक है। वस्तुतः इस प्रकार की विभिन्न मदों की प्रवृत्ति के तुलनात्मक विश्लेषण में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे प्रवृत्ति अनुपात या प्रवृत्ति प्रतिशत कहते हैं।

जॉन मायर के अनुसार, "विवरणो की एक श्रृंखला मे एक वित्तीय विवरण मद के परिणामो का आधार के रूप में चयनित विवरण में इसके परिणाम से अनुपात प्रवृत्ति अनुपात कहलाते हैं क्योंकि ये समय के व्यतीत होने पर मद की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं।"[3] प्रवृत्ति अनुपात विधि में विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस मद में प्रवृत्ति सन्तोषप्रद है तथा किस मद की प्रवृत्ति मे सापेक्षित परिवर्तन होना चाहिए।

प्रवृत्ति अनुपात के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय विश्लेषक को ध्यान रखने योग्य बातें –

1. किसी अकेले मद का प्रवृत्ति अनुपात अध्ययन अपने आप में बहुत सीमित महत्व रखता है। इसलिए विश्लेषक को सम्बंधित प्रवृत्ति अनुपातों की तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए।
2. मूल समंको पर ध्यान दिये बिना केवल प्रवृत्ति प्रतिशतो के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष भी तर्कहीन व असंगत हो सकते है अतः प्रवृत्ति अनुपातो के साथ साथ मूल समंको को भी ध्यान मे रखा जाता है।
3. लेखांकन के सिद्धान्तों व अवधारणाओं के परिपालन में एकरूपता व सत्यता का अभाव होने पर भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते है। इसी प्रकार मूल्य स्तरों में तेजी से परिवर्तन के

3- The ratio of the magnetades to a financial statement item in a series of statements to its magnitude in one of the statements selected as the base may be called trend ratios because they reveal trend of the item with the passage of time. - John. N.Myer.

कारण भी समंको की तुलनीयता संदिग्ध हो जाती है। अतः निकाले गये निष्कर्ष वस्तु स्थिति का प्रदर्शन नही करते है।

4. आधार वर्ष का चुनाव सही न होने पर आधार वर्ष प्रतिनिधि वर्ष न होने पर प्रवृत्ति अनुपात भ्रामात्मक परिणाम दे सकते है।

5. प्रवृत्ति विश्लेषण से प्रबन्ध की कार्यकुशलता या प्रभावशीलता नही मापी जा सकती है।

ग्राफ एवं चित्र –

मानव मस्तिष्क संख्याओं में व्यक्त तालिकाओं व आंकड़ों की अपेक्षा चित्रों या रेखाचित्रो का अधिक तेजी से अध्ययन कर जल्दी से समझ सकता है अतः प्रवृत्ति प्रदर्शन के लिए बैकिंग संस्थायें साधारणतया वार्षिक वित्तीय विवरणो मे रेखा चित्रों एवं दण्डचित्रों का प्रयोग करती है। कुछ संस्थाये केवल निरपेक्ष मूल्यों को ही रेखाचित्रों पर प्रदर्शित करती है। जबकि कुछ प्रवृत्ति अनुपातों को संस्था के हित मे रखने वाले व्यक्ति या प्रबन्ध वर्ग इन ग्राफों तथा दण्ड चित्रों से एक दृष्टि में ही जान सकते है कि बैंक उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है या अवनति की ओर ग्राफ एवं चित्र रंग-बिरंगें रंगों तथा आकर्षित प्रदर्शन के कारण आंखों को अच्छे लगते है क्योंकि इनमें आंकड़ों की सी नीरसता नही होती है।

ग्राफ–3.2
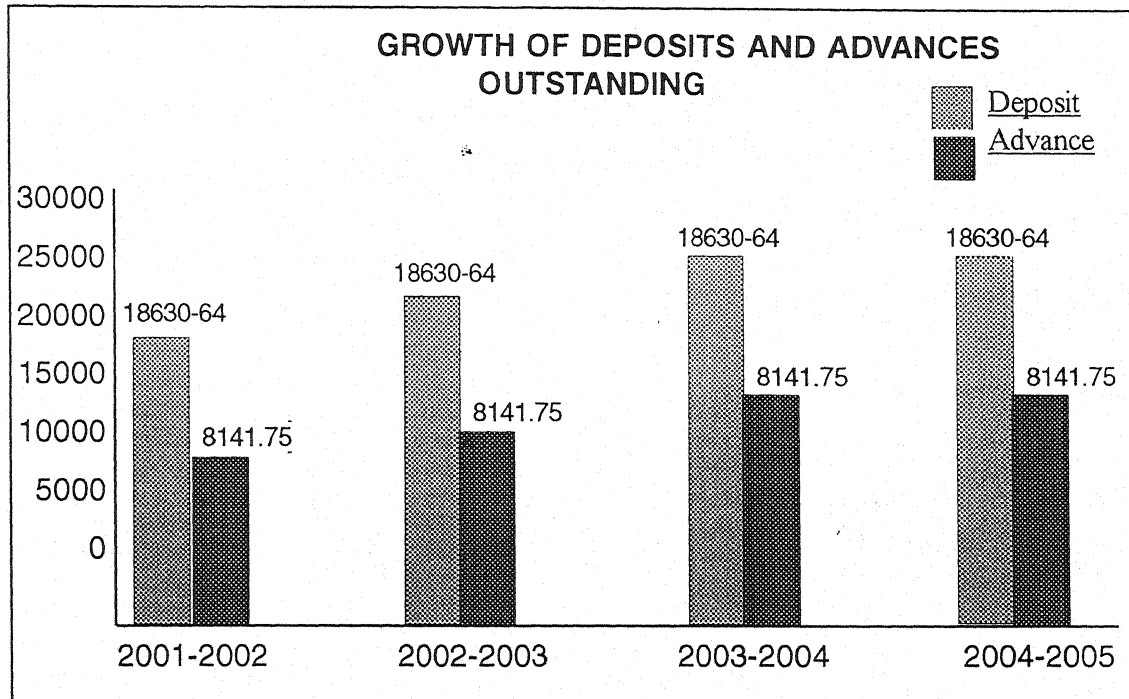
छत्रसाल ग्रामीण बैंक की जमाओं एंव अग्रिमों में हुयी वृद्धि का अवलोकन करने पर प्राप्त परिणाम काफी सन्तोषजनक है जहां जमायें वित्तीय वर्ष 2001–02 में 18630.64 लाख रूपये थी वहीं वित्तीय वर्ष 2002–03 में यह 14.65 प्रतिशत बढ़कर 2136.45 लाख रूपये हो गयी वही वित्तीय वर्ष 2003–04 में जमाओं की धनराशि गत वर्ष की तुलना में 16.44 प्रतिशत बढ़कर 24872.63 लाख रूपये हो गयी तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में जमाओं वर्ष 2001–02 की तुलना मे 50.84 प्रतिशत की दर से बढ़कर 28103.01 लाख रूपये हो गयी इससे यह सिद्ध होता है कि छत्रसाल ग्रामीण बैंक के प्रति आम जनता के विश्वास में लगातार वृद्धि हुयी है तथा वे लोग अपनी बचतों को सुरक्षित रखने के लिए इस बैंक की तरफ पर्याप्त मात्रा में आकर्षित हुए है। इसकी तरफ उक्त अवधि में बैंक द्वारा दिये गये अग्रिमों का अवलोकन करे तो पाते है कि जहां वित्तीय वर्ष 2001–02 में बैंक ने 8141.75 लाख रूपये के ऋण दिये है वही वित्तीय वर्ष 2004–05 मे अग्रिमों की धनराशि में वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना में 125.45 की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल 18355.24 लाख रूपये के अग्रिम स्वीकृत किये गये है।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ–3.3
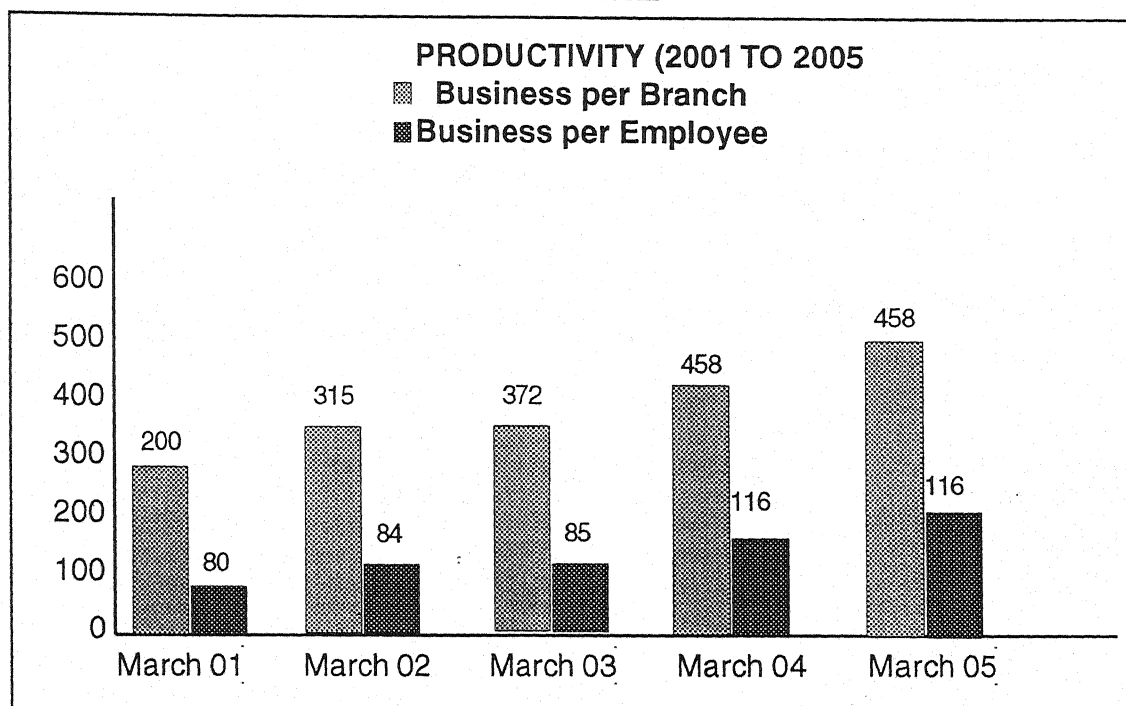
छत्रसाल ग्रामीण बैंक की उत्पादकता का अध्ययन दो आधारों पर किया गया है जिसमें पहला प्रतिशाखा व्यवसाय एवं दूसरा प्रति कर्मचारी व्यवसाय को ध्यान में रखा गया है जहां वर्ष 2001 में प्रतिशाखा व्यवसाय 266 लाख रूपये था जो 2002 में बढ़कर 315 लाख तथा 2003 में 372 लाख 2004 में 456 लाख एवं 2005 में 553 लाख रूपये हो गया इस प्रकार वर्ष 2005 में 2001 की तुलना में 107.9 प्रतिशत की दर से व्यवसाय में प्रति शाखा बढ़ोत्तरी हुयी है जो कि निश्चित रूप से बैंक की बढ़ती शाखाओं की सार्थकता को सिद्ध करता है तथा बैंक की उत्पादकता में दर्ज की गयी वृद्धि क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को कृषि एवं ग्रामीण कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुयी है यदि उत्पादकता का आंकलन प्रति कर्मचारी संख्या के आधार पर किया जाये तो यह उत्पादकता में वृद्धि को ही दर्शाता है। परन्तु इस आधार में हुयी वृद्धि की दर प्रति शाखा व्यवसाय में हुयी वृद्धि की दर की तुलना में कम है। जहां पर वर्ष 2001 में प्रति कर्मचारी व्यवसाय 80 लाख रूपये का था वही पर 2005 में 75 प्रतिशत बढ़कर 140 लाख रूपये हो गया। अतः उत्पादकता मापन के दोनों ही आधारों में उत्पादकता में वृद्धि बैंक की उच्च परिचालन क्षमता को प्रदर्शित करती है।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ–3.4
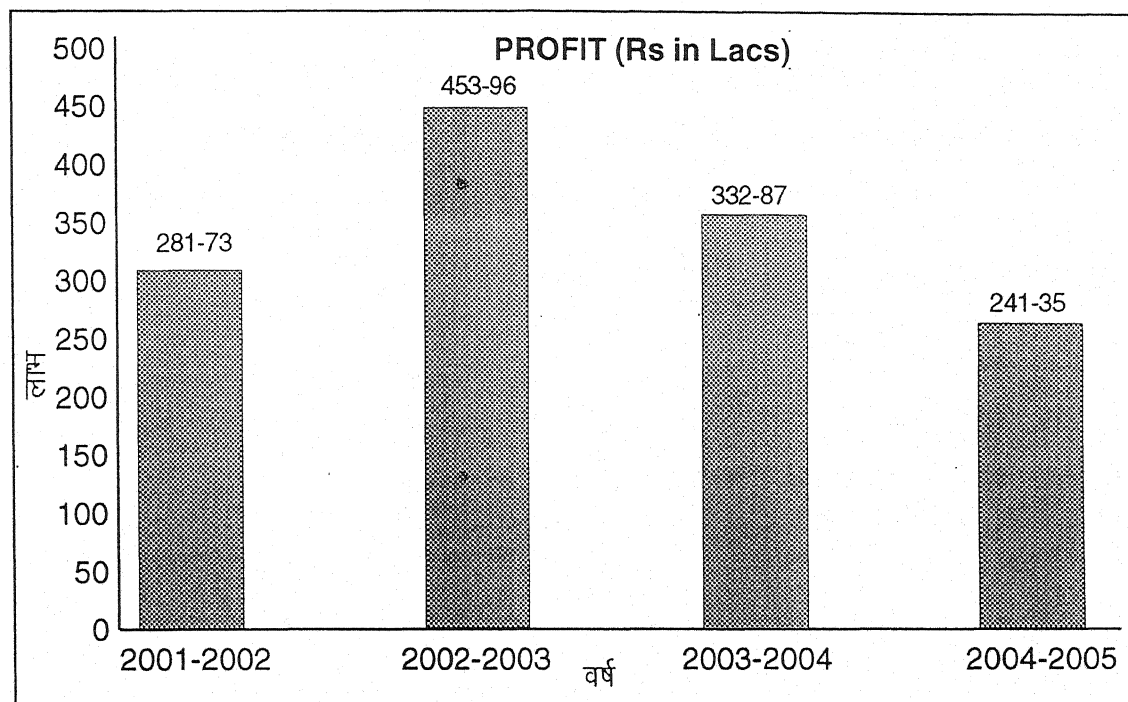
छत्रसाल ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न वित्तीय वर्षो में कमाये गये लाभों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2001–2002 में बैंक के लाभ समेकित रूप में 281.73 लाख रूपये थे जो वित्तीय वर्ष 2002–03 में बढ़कर 453.96 लाख रूपये हो गये इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में लाभों में 61.13 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। परन्तु वित्तीय वर्ष 2003–04 में वित्तीय वर्ष 2002–03 की तुलना में 26.67 प्रतिशत की कमी आयी तथा कुल लाभ 332.87 लाख रूपये रहा वित्तीय वर्ष 2004–05 में वित्तीय वर्ष 2003–04 की तुलना में लाभों की धनराशि में कुल 91.52 लाख रूपये की कमी हुयी है जो कि वित्तीय वर्ष 2003–04 की तुलना में 27.49 प्रतिशत है। इस प्रकार संपूर्ण अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2002–03 को छोड़कर बैंक के लाभों में निरन्तर गिरावट दर्ज की गयी है जो कि चिन्ताजनक है।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ–3.5
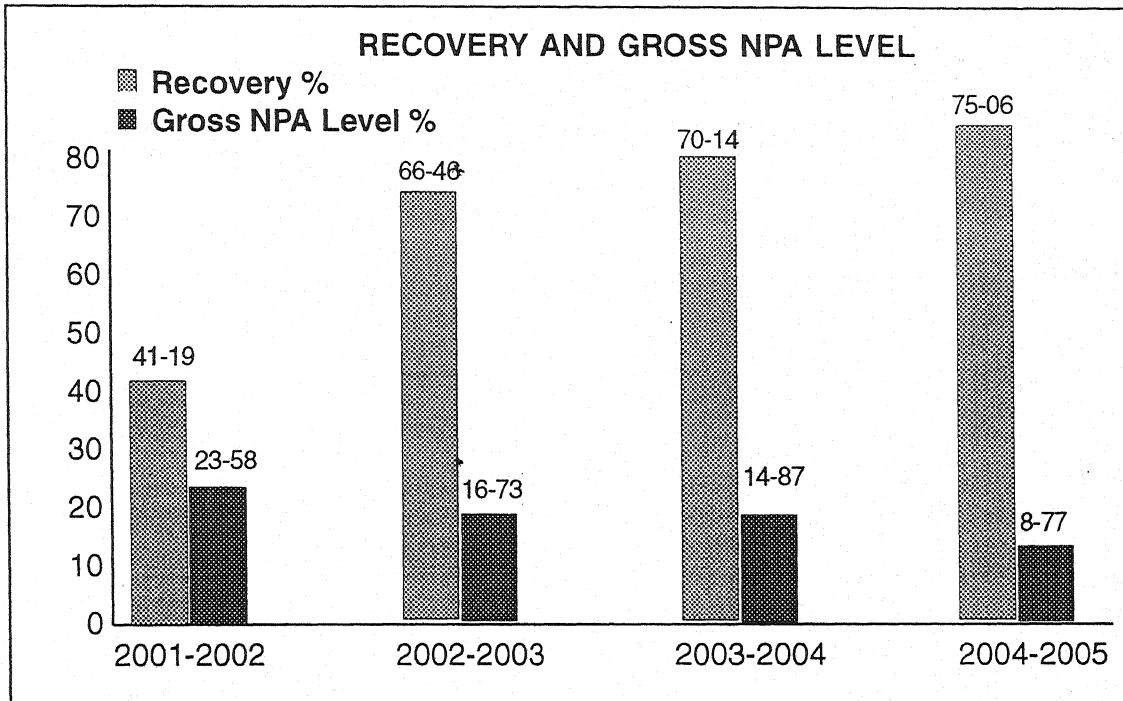
छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वसूली और सकल गैर-निष्पादक सम्पत्तियों के स्तर का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य प्रकाशित होते है। छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वसूली वित्तीय वर्ष 2001 से लेकर 2005 तक निरन्तर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हुयी है वित्तीय वर्ष 2001–02 में जहां यह वसूली 41.19 प्रतिशत थी वही वित्तीय वर्ष 2002–03 में 66.46 प्रतिशत 2003–04 में 70.14 तथा वर्ष 2004–05 में 75.06 प्रतिशत थी इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004–05 में वसूली का प्रतिशत 82.23 प्रतिशत की दर सें बढ़ा है वही सकल गैर–निष्पादक सम्पत्तियों के स्तर में निरन्तर कमी हुयी है। जो कि बैंक के लिए वित्तीय दृष्टि से अनुकूल है। जहां वित्तीय वर्ष 2001–02 में सकल गैर-निष्पादक सम्पत्तियों का स्तर 23.58 प्रतिशत था वही यहां वित्तीय वर्ष 2004–05 में 62.8 प्रतिशत गिरकर 8.77 प्रतिशत रह गया इस प्रकार गैर–निष्पादक सम्पत्तियों में निरन्तर कमी होना बैंक दक्ष परिचालन क्षमता की ओर इंगित करता है।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ–3.6
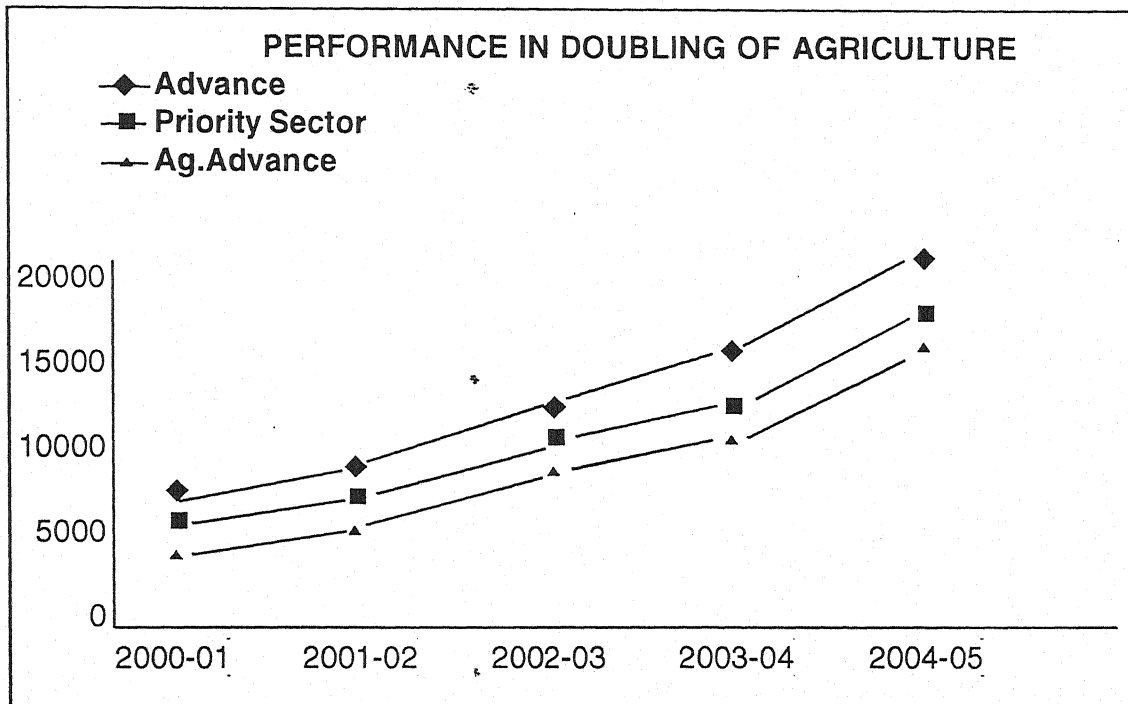
उपर्युक्त ग्राफ की स्थिति का अवलोकन यह दर्शाता है कि वर्ष 2000–01 से लेकर वर्ष 2004–05 तक कृषि स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है।

स्त्रोतः– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

कार्यशील पूंजी प्रबन्ध का विश्लेषण
(Analysis of working Capital Management)

जिस प्रकार वित्तीय प्रबन्ध में पूंजी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में किया जाता है उसी प्रकार व्यवसायिक जगत मे कार्यशील पूंजी का अर्थ भी विवादास्पद है। कई लोगो के बीच इसके सम्बंध में मतभेद है। कार्यशील पूंजी की उतनी व्याख्यायें है जितनी संख्या इस शब्द की व्याख्या करने वालों की है कुछ व्यक्ति कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्तियों का योग मानते है जबकि कुछ व्यक्ति चालू दायित्वो पर चालू सम्पत्तियों के अधिक्य को मानते है वैसे किसी भी बैंकिंग संस्था को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है।

1. स्थायी पूंजी – यानि स्थायी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।
2. अस्थायी पूंजी – यह सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समय उपलब्ध रहती है।

कार्यशील पूंजी के वास्तविक अभिप्राय को समझने के लिए इसकी अवधारणाओं का अध यन व विश्लेषण आवश्यक है।

1. परिमाणात्मक अवधारणा (Quantitative concept)
2. गुणात्मक अवधारणा (Qualitative concept)
3. अन्य अवधारणायें (Other concept)

कार्यशील पूंजी की परिमाणात्मक अवधारणा पूंजी के परिमाण या मात्रा पर अधिक बल देती है। तथा गुणात्मक पहलू पर कम। इसके अनुसार संपूर्ण चालू सम्पत्तियों का योग कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक मीड, मैलर, बेकर फील्ड, बोलबिले, जे एस मिल तथा एडम स्मिथ है। मीड, मैलर तथा फील्ड के अनुसार, "कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू सम्पत्तियों के योग से है।"[1]

1- Working capital means curret Assets. - Mead Melalt & field.

बोलबिले के अनुसार, "कोषों की कोई भी प्राप्ति जो चालू सम्पत्तियों में वृद्धि करती है वह कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि करती है क्योंकि ये दोनो एक ही है।"[2] अतः स्पष्ट है कि बोनबिले ने कार्यशील पूंजी तथा चालू सम्पत्तियों को एक ही अर्थ मे प्रयुक्त किया है। जे॰ एस॰ मिल के अनुसार, "चालू सम्पत्तियों का योग ही व्यवसाय की कार्यशील पूंजी होती है।"[3] कार्यशील पूंजी की इस अवधारणा के समर्थक अपने विचारों के समर्थन मे तर्क देते है। कि चालू सम्पत्तियों की व्यवस्था चाहे दीर्घकालीन आधार पर (अंशपूंजी या दीर्घकालीन ऋण से) की जाये अथवा चालू देनदारियों के द्वारा अल्पकालीन ऋण व लेनदारों से की जाये इससे उनकी उपयोगिता पर कोई प्रभाव नही पड़ता चूंकि वे समस्त चालू सम्पत्तियों बैंक में प्रयुक्त होती है तथा लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि करती है अतः समस्त चालू सम्पत्तियों को कार्यशील पूंजी माना जाता है।

गुणात्मक अवधारणा के अनुसार "चालू सम्पत्तियों के चालू दायित्व पर अधिक्य को कार्यशील पूंजी कहते है।"[4] गुणात्मक अवधारणा के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिए चालू सम्पत्तियो का चालू दायित्वों पर आधिक्य आवश्यक है। यदि दोनों ही समान राशि हो तो संस्था में कार्यशील पूंजी की अनुपस्थिति मानी जाती है इसके विपरीत यदि चालू दायित्व चालू सम्पत्तियों से अधिक है तो यह स्थिति कार्यशील पूंजी के घाटे का प्रतिनिधित्व करती है जो वित्तीय संकट का द्योतक है। इस अवधारणा के अनुसार यदि चालू देनदारियों अल्पकालीन ऋण इत्यादि मे वृद्धि होती है तो इससे कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि नही होगी क्योंकि उतनी ही मात्रा से चालू सम्पत्तियां भी बढ़ जायेगी। अतः चालू सम्पत्तियों व चालू दायित्वों मे अन्तर वही रहेगा जो पहले था। इस अवधारणा के अनुसार केवल निम्न दशाओं मे ही कार्यशील पूंजी मे वृद्धि सम्भव है

1. अतिरिक्त अंशपूंजी निर्गमित कर पूंजी में वृद्धि की जाये।
2. दीर्घकालीन ऋण निर्गमित कर पूंजी में वृद्धि की जाये।

2- Any acquisition of funds which increases the current assets increases working capital for they are one and the same.
- Bonneville.

3- The sum of the currnt assets is the working capital of a business. - J.S.Mil

अन्य अवधारणाओं के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी के सम्बंध में कुछ मतभेदों के कारण कुछ विद्वानों ने इसके लिए विभेदात्मक नामों का प्रयोग किया है। केनेडी तथा मैकमुलन के अनुसार, "चालू सम्पत्तियों के योग को हम सकल कार्यशील पूंजी तथा चालू सम्पत्तियों के चालू दायित्वो पर आधिक्य को शुद्ध कार्यशील पूंजी कह सकते है उनके अनुसार "यह मानते है कि चालू सम्पत्तियों के नकद में परिवर्तन करने पर कोई हानि या लाभ नही होगा। शुद्ध कार्यशील पूंजी सभी चालू दायित्वों के भुगतान के पश्चात् शेष रही चालू सम्पत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।"[5] एडम स्मिथ ने चालू सम्पत्तियों को चक्रीय पूंजी कहना अधिक उपयुक्त माना। उनके अनुसार "व्यवसायी का माल तब तक लाभ या धनराशि नही देता जब तक वह उसे मुद्रा के बदले बेच न दे तथा जब तक इस मुद्रा के बदले वापिस माल प्राप्त नही किया जाता तब तक यह मुद्रा उसे बहुत कम प्रत्यय या लाभ देगी। उसकी पूंजी लगातार एक रूप से उसके पास से जाती है तथा दूसरे रूप मे उसके पास आ जाती है तथा यह चक्र या निरन्तर आदान प्रदान ही उसे लाभ प्रदान करता है। अतः ऐसी पूंजी को यथार्थ मे चक्रीय पूंजी कहा जा सकता है।"[6] लिंकन स्टेवेन्स, सेलियर्स आदि विद्वान ऐसे है जो कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों के बीच अन्तर मानते हैं।

हागलैण्ड के मतानुसार, "कार्यशील पूंजी का अर्थ व्यापारिक लेखा पुस्तकों में चालू दायित्व एवं चालू सम्पत्ति के अन्तर से माना जाता है।" इस वर्ग के विद्वानों के मत को निम्न स्थिति विवरण की सहायता से जाना जा सकता है।

5- Net working capital sepresents the amount of the current assets which would remain if all of the current liabilities were paid assuming no less or gain in converting current assets into cash.
- Kennedy & Macmullen

6- The goods of the merchant yield him no revenueor profit till he sells them for money and the money yield him a little till it is again exchanged for goods. His capital is continuously going from him in one shape and returning to him in another and it is only by means of such circulation or successive exchange that it can yield him a profit such capital therefore may very properly be balled ciculating capital.
- Adom Smith.

Balance Sheet

Liabilities	Rs.	Assets.	Rs.
Share Capital	9000	Plants Machinery	4000
Debentures	5000	Building.	2000
		Cash	2000
Sundry Creditors	3000	Stock in trade	6000
Accruals	1000	Debtores	4000
	18000		18000

Current Liabilities

Sundry Creditors	3000
Accruals	1000
	4000

Current assets.

Stock in trade	6000
Debtores	4000
Cash	2000
	12000

Working Capital = Current Assets - Current Liabilities
W.C = 12000 - 4000
= 8000

इस वर्ग के विद्वान जो कार्यशील पूंजी को चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्व का अन्तर मानते हैं, अपने पक्ष में निम्न दलीले देते हैं –

1. यह सिद्वान्त काफी समय से उपयोग मे लाया जा रहा है अतः इसे प्रयोग करना ही उचित है।

2. यह मत अंशधारियों तथा ऋणपत्रधारियों में यह विश्वास उत्पन्न करता है कि उनका विनियोग सुरक्षित है क्योंकि कार्यशील पूंजी में वृद्धि केवल लाभ के पुनर्विनियोजन तथा स्थायी सम्पत्ति को कार्यशील सम्पत्ति मे बदलने के द्वारा ही हो सकती है एवं चालू दायित्व में वृद्धि कार्यशील पूंजी को प्रभावित नही करती।

3. चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य इस बात का प्रतीक है कि वह संस्था आकस्मिकताओं का दृढ़ता से सामना कर सकती है।

4. ऐसी संस्था जिसकी चालू सम्पत्ति चालू दायित्व से अधिक होती है, मंदीकाल का सामना अधिक दृढता से कर सकने मे सफल होती है।

5. यह विचारधारा किसी संस्था की वास्तविक वित्तीय स्थिति ज्ञात करने में अधिक उपयोगी है क्योंकि केवल चालू सम्पत्ति की मात्रा ही अच्छी वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नही करती वरन् वित्तीय स्थिति का अनुपात चालू सम्पत्ति तथा चालू दायित्व दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से किया जा सकता है।

कार्यशील पूंजी के स्त्रोत – (Sources of working Capital)

1. दीर्घकालीन स्त्रोत (Long term sources)
2. अल्पकालीन स्त्रोत (Short term sources)

1. दीर्घकालीन स्त्रोत **(Long term sources)**

दीर्घकालीन स्त्रोतों से साधारणतया कार्यशील पूंजी के केवल उसी भाग की पूर्ति की जाती हैं जिसके लिए यह विश्वास हो कि उस बैंक से लम्बे समय तक निरन्तर आवश्यकता होगी जो कार्यशील पूंजी बैंक में लम्बे समय तक निरन्तर रखी जाती है उसे दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी कहते हैं। अतः साधारणतया दीर्घकालीन पूंजी की पूर्ति ही दीर्घकालीन स्त्रोतों से करनी चाहिए।

कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन स्त्रोतों को मुख्यतः दो भागों 1. स्वामित्व स्त्रोत 2. ऋणगत स्त्रोत में विभक्त किया जा सकता है। विवरण निम्न है।

1. स्वामित्व स्त्रोत

इसके अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है।

अ. अंश निर्गमन **(Issue of Share)**

कार्यशील पूंजी के लिए कोष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन अंश निर्गमन है। अंश हमारे साधारण व पूर्वाधिकार दोनों ही प्रकार के हो सकते है अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी से व्यवसाय की आय पर कोई स्थायी भार उत्पन्न नही होता है, अतः साधारणतया स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए अंशों द्वारा कोष प्राप्त किये जाते है।

ब. प्रतिधारित अर्जनें **(Retained Earnings)**

बैंक द्वारा अर्जित लाभ कार्यशील पूंजी का एक नियमित एवं लागत रहित स्त्रोत होता है बैंक के विकास के साथ साथ कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता रहती है। जिसकी पूर्ति बैंक के लाभों का पुनर्विनियोजन करके की जा सकती है।

स. संचित कोष **(Reserves)**

प्रतिधारित अर्जनों की भांति ही संचित कोषों का प्रयोग भी बैंक की आय पर स्थायी भार उत्पन्न नहीं करता है।

द. चालू दायित्वों का पुस्तक मूल्य से कम पर भुगतान
(Retiring Current Liabilities below Bank Value)

चालू दायित्वों का भुगतान करते समय एक बैकिंग संस्था कुल छूट प्राप्त कर सकती है इसी प्रकार कर व विभिन्न खर्चो के लिए प्राविधान किये जाते है हो सकता है कि वास्तविक भुगतान इन प्राविधानो की राशि से कम हो। अतः चालू दायित्व का पुस्तक मूल्य से कम पर किया गया भुगतान कार्यशील पूंजी के लिए समावर्ती साधन है।

2. ऋणगत स्त्रोत : **(Borrowed Sources)**

इन स्त्रोतों के अन्तर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है।

अ. ऋण पत्र (Debentures)

अंशपूंजी की भांति एक कम्पनी ऋणपत्र निर्गमित करके कार्यशील पूंजी के लिए प्राप्त कर सकती है यहां यह आवश्यक होता है कि ऋणपत्र निर्गमन से कम्पनी की आय पर ब्याज का स्थायी भार उत्पन्न हो जाता है अतः इसका प्रयोग बैंक की प्रगति उसी आय मे स्थिरता जोखिम की मात्रा इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ब. दीर्घकालीन ऋण (Long term Debts)

ऋण पत्र निर्गमन के अतिरिक्त एक संस्था कार्यशील पूंजी के लिए कोष औद्योगिक निगमो, प्रन्यासों तथा विनियोग कम्पनियों आदि से भी प्राप्त कर सकती है।

स. अल्पकालीन स्त्रोत (Short term Sources)

अल्पकालीन स्त्रोतों को प्रमुखतः दो भागों (अ) आन्तरिक स्त्रोत, (ब) बाह्य स्त्रोत मे विभक्त किया जा सकता है।

अ. आन्तरिक स्त्रोत (Internal Sources)

1. ह्रास कोष (Deprecation Fund)

ह्रास कोष स्थायी सम्पत्तियों को पुनः खरीदने के उद्देश्य से प्रतिधारित लाभ होते है। अतः जब तक इन कोषों का प्रयोग स्थायी सम्पत्ति खरीदने में नही किया जाता तब तक यह संस्था को कार्यशील पूंजी प्रदान करते हैं।

2. अदत्त भुगतान (Outstanding payments)

बैंक में चिट्ठे की तिथि का कुछ भुगतान अदत्त रह जाते है इनमें प्रमुखता प्रदत्त वेतन, अदत्त किराया आदि सम्मिलित किये जाते है इन व्ययों का भुगतान स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात् किया जाता है। अतः मध्यान्तर समय में अदत्त भुगतान कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं।

3. करों के लिए प्रावधान (Provision for taxaction)

बैंक के करों के लिए किये गये प्रावधान की राशि का भुगतान कर चुकाने मे साधारणतया कुछ मध्यान्तर मे ही किया जाता है अतः मध्यान्तर की अवधि में प्रावधान की राशि को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

ब. बाह्य स्त्रोत (External Sources)

व्यापारिक ऋण प्रायः सभी बैकिंग संस्थायें इस साधन का प्रयोग कार्यशील पूंजी के रूप में करती हैं।

1. व्यवसायिक साख पत्र (Credit Papers)

इसके अन्तर्गत देय बिल प्रतिज्ञापत्र तथा अन्य विनिमय पत्र सम्मिलित किये जाते है ये सभी कार्यशील पूंजी के स्त्रोत होते हैं।

2. बैंको से साख (Bank Credit)

प्रायः सभी बैंक अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों को अधिविकर्ष, नकद साख बिलों की पुर्नकटौती व अल्पकालीन ऋणों की सुविधा देते हैं। इन सबसे संस्था को कार्यशील पूंजी प्राप्त होती है।

3. वित्त संस्थाये (Finance Companies)

विभिन्न वित्त संस्थायें जैसे विनियोग कम्पनियां, बीमा कम्पनियां, तथा औद्योगिक विकास निगम आदि उद्योगों को विभिन्न प्रकार के ऋण देते है जो कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

4. जन निक्षेप (Public Deposits)

बैकिंग संस्थायें जन निक्षेप के रूप में भी अल्पकालीन व मध्यकालीन कोष प्राप्त करती है कार्यशील पूंजी का यह स्त्रोत अधिक विश्वसनीय व नियमित नहीं है।

5. देशी साहूकार (Native Money lenders)

पुराने समय से ही देश मे साहूकार ऋण लेने व देने का कार्य करते आ रहे है एक उपक्रम इन साहूकारों से भी ऋण लेकर अपनी कार्यशील पूंजी की पूर्ति कर सकता है।

6. सहकारी साहूकार (Government Assistances)

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है ऐसे उद्योग जिनको सरकार प्राथमिकता देती है उन उद्योगो में यह सहायता की राशि कार्यशील पूंजी में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है।

7. प्रबन्धकों एवं संचालकों आदि से ऋण (Loans from EXecutives & Directors etc)

समय–समय पर अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की कुछ पूर्ति प्रबन्धक या संचालकगण कर देते हैं इस प्रकार एक उपक्रम कुछ सीमा तक अपनी कार्यशील पूंजी की पूर्ति इस ऋण के माध्यम से कर सकती है।

8. कर्मचारियों की प्रतिभूति **(Securities of Employees)**

कुछ उपक्रम अपने कर्मचारियों से प्रतिभूति के रूप मे एक निश्चित धनराशि अग्रिम जमा ले लेते है जो साधारणतया उनके पूरे सेवाकाल तक संस्था के पास जमा रहती है यह धनराशि संस्था कार्यशील पूंजी के लिए प्रयुक्त कर सकती है।

कार्यशील पूंजी का महत्व

बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में कार्यशील पूंजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उचित मात्रा में पूंजी का प्रबन्ध कर लेने मात्र से ही बैकिंग का संचालन नही किया जा सकता बल्कि इस पूंजी का पूर्ण उपयोग करके ही बैंक द्वारा लाभ कमाया जा सकता है बैंक की पूंजी का पूर्ण उपयोग कार्यशील पूंजी के उचित प्रबन्ध पर निर्भर करता है बैक की सामान्य कार्यवाही का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के लिए समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशो मे बदलने उनका निर्गमन करने तथा उनका आवंटन इत्यादि मे इसकी आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त प्रविवरण का निर्गमन करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। बैंक में कार्यशील पूंजी का महत्व मनुष्य शरीर मे रक्त प्रवाह की भांति है जिस प्रकार मनुष्य का स्वास्थ्य रक्त प्रवाह अधिक होने व कम होने पर बिगड़ जाता है ठीक उसी प्रकार कार्यशील पूंजी की व्यवस्था छिन्न भिन्न होने से बैंक का व्यवसाय भी अवनति की ओर जाने लगता है। कार्यशील पूंजी का प्रयोग विभिन्न व्ययों के तत्काल भुगतान के लिए किया जाता है।

कार्यशील पूंजी का विश्लेषण
(Analysis of working Capital)

किसी भी संस्था के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी न तो आवश्यकता से कम होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। यदि संस्था में प्रत्येक समय आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी बनी रहेगी, तो संस्था का संचालन भी सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकेगा और विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम बनाया जा सकेगा। अतः वित्तीय

प्रबन्ध और न ही आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। यदि संस्था में प्रत्येक समय आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी बनी रहेगी, तो संस्था का संचालन भी सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकेगा और विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम बनाया जा सकेगा। अतः वित्तीय प्रबन्ध का सदैव यही प्रयास होता है कि संस्था की आवश्यकता व कार्यशील पूंजी की मात्रा मे सन्तुलन बना रहे।

किसी भी बैकिंग व्यवसाय की कुल विनियोजित पूंजी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है । इसकी पर्याप्तता तथा कुशल प्रबन्ध पर ही संस्था का भविष्य निर्भर करता है अतः वित्तीय प्रबन्धक समय समय पर कार्यशील पूंजी का मापन तथा विश्लेषण करते रहते है कार्यशील पूंजी का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि संस्था में कार्यशील पूंजी का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया गया है या नही यदि प्रभावी ढंग से प्रयोग नही किया गया तो सुधार की कहां सम्भावना है तथा इस प्रकार कार्यशील पूंजी के अधिक कुशल प्रयोग से किस प्रकार संस्था लाभदायकता तथा वित्तीय सुदृढता मे वृद्धि कर सकती है। कार्यशील पूंजी के विश्लेषण की निम्न पद्धतियां है।

1. कार्यशील पूंजी की तालिका तैयार करके
2. अनुपात विश्लेषण करके
3. कोष प्रवाह विश्लेषण करके
4. रोकड़ प्रवाह विश्लेषण करके
5. कार्यशील पूंजी का बजट तैयार करके

1. कार्यशील पूंजी की तालिका तैयार करके
(By preparing Statement of working Capital)

कार्यशील पूंजी की तालिका से कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है इस तालिका मे विभिन्न चालू सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों को दर्शाया जाता है तथा चालू दायित्वों के विभिन्न मदों में परिवर्तन को मापा जाता है। कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण विश्लेषण में विशेष सहायक सिद्ध होता है कार्यशील पूंजी का विवरण मुख्यतः दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है।

1. कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण – केवल योग में परिवर्तन दर्शाते हुए
2. कार्यशील पूंजी का तुलनात्मक विवरण – व्यक्तिगत मदों में परिवर्तन दर्शाते हुए।

उपरोक्त के अतिरिक्त समानाकार कार्यशील पूंजी का विवरण एवं कार्यशील पूंजी का विश्लेषण किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हम इसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची भी कहते है इसे कभी कभी कार्यशील पूंजी स्थिति विवरण भी कहते है। इसके आधार पर हम यह ज्ञात होता है कि कार्यशील पूंजीकी प्रवृत्ति क्या रही है और साथ ही साथ इस प्रवृत्ति के लिए कार्यशील पूंजी के विभिन्न मदों में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन उत्तरदायी रहे है इनका नमूना निम्नलिखित है।

Schedule working Capital Changes
Between 1989 & 1991

	31st December			Changes between 1989 & 1990		Changes between 1990 & 1991	
	2004	2002	2000	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Current Assets Cash in hand Sundry Debtores Bills Receivables Closing Stock Investments							
Total							
Current Liabilities Sundry Creditors Bank overdraft							
Total							
Working Capital in Increase & Decrease.							

Statement of working Capital

	1989 - 1990	1990 - 1991
Increase in working Capital by	Nill	Nill
Increase in Cash in hand	"	"
Inc. in Sundry Debtones	"	"
Inc. in B/R	"	"
Inc in closing stock	"	"
Dec. in Sundry Creditory	"	"
Dec in Bank overdraft		
Total	"	"
Decrease in working Capital by	"	"
Dec in Cash in hand	"	"
Dec in Sundry Debtores	"	"
Dec in Investment	"	"
Inc. in Bank overdraft		
Total		
Net Increase (Change)		

2. अनुपात विश्लेषण –

अनुपात विश्लेषण के द्वारा संस्था की लाभदायकता, निष्पादन क्षमता व वित्तीय स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । कार्यशील पूंजी के विश्लेषण के लिए कार्यशील पूंजी पर आधारित विभिन्न अनुपातों का अध्ययन किया जाता है जिनमें चालू अनुपात, त्वरित अनुपात प्राप्यों की तरलता का अनुपात, औसत संग्रहण अवधि अनुपात, प्राप्त आवर्त अनुपात देय आवर्त अनुपात स्कन्ध आवर्त अनुपात, नकद स्थिति अनुपात दैनिक नकद भुगतान अनुपात, आधारभूत रक्षक अन्तर अनुपात तथा स्कन्ध कार्यशील पूंजी अनुपात प्रमुख हैं।

3. कोष प्रवाह विवरण (Fund flow statement)

कोष प्रवाह विवरण से ज्ञात हो जाता है कि कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्त्रोत क्या रहे है तथा इन स्त्रोतों का संस्था में कहां कहां उपयोग किया गया।

4. रोकड़ प्रवाह विवरण (Cash flow statement)

रोकड़ चालू सम्पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण मद होता है। रोकड़ स्थिति संस्था की कार्यक्षमता व सुदृढ़ता को प्रभावित करती है।

5. कार्यशील पूंजी का बजट तैयार करना –

कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान वित्तीय बजट का ही एक भाग होता है इसके तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का पहले से ही अनुमान करके उसके लिए आवश्यक कोष जुटाना होता है । ऐसा पूर्वानुमान तैयार करके कार्यशील पूंजी के विभिन्न तत्वों तथा नकद स्कन्ध देनदार तथा लेनदार आदि में सन्तुलन स्थापित किया जा सकता है।

कार्यशील पूंजी का परिचालन चक्र
(Operating Cycle of working Capital)

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए परिचालन चक्र की अवधि की गणना वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रयुक्त की जाती है। अमेरिकन इन्सटीट्यूट और सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स के अनुसार, "चल दायित्वों पर चल सम्पत्तियों के आधिक्य के रूप में उपस्थित कार्यशील पूंजी संपूर्ण उपक्रम की कुल पूंजी की वह तरल स्थिति है जो आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य परिचालन चक्र की अवधि में उपलब्ध होती है।

जब कोई बैंक अपना कार्य आरम्भ करता है तो उस समय उसकी कार्यशील पूंजी रोकड़ के रूप में होती है और यह रोकड़ ऋण व अग्रिम के रूप में होता है इसके बाद बैंक जनता को कुछ अन्य भुगतान भी प्रदान करता है। फिर तीसरे चरण में इन सभी भुगतानों की प्राप्ति होती है जो कि जमा के रूप मे बैंक के पास आ जाता है फिर इसी जमा से वह ऋण व अग्रिम देता है यही चक्र हमेशा बैंक में चलता रहता है बैंक के पास रोकड़ विनियोग से भी प्राप्त होती है।
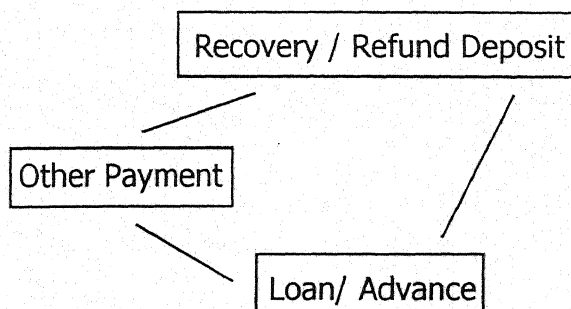
1- Working capital as represented by the excess of current assets on current liabilities and identifying the selahievely liquid position of the total enterprise capital which consitutes of may meeting obligation within the ordinary or operating cycle of the business.

- American Institute of certified Public account

अध्याय षष्ठम

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का जनपद की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे योगदान का मूल्यांकन

१. कृषि व सिंचाई के क्षेत्र मे योगदान

२. रोजगार व अन्य क्षेत्रो में योगदान

3. ग्रामीण क्षेत्र मे बैंक द्वारा चलाई जाने वाली विविध योजनाएं एवं उनकी प्रवाहकारिता का मूल्यांकन

४. वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शर्ते

५. जनपद में वित्तीय सुविधा प्रदान किये गये अग्रिमो की वसूली का विश्लेषण

६. वित्तीय सुविधा प्रदान करने में आने वाली समस्यायें एवं उनको दूर करने के लिए सुझाव

अध्याय–षष्ठम

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का जनपद की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यकृमों में योगदान का मूल्यांकन

राष्ट्रीय आय के उत्पादन की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कृषि उत्पादकता मे सुधार आवश्यक हो जाता है। कृषि द्वारा केवल जनसंख्या की भोजन सामग्री की ही आपूर्ति नही होती वरन् औद्योगिक विकास के लिए विविध प्रकार के कच्चे पदार्थो की आपूर्ति भी होती है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि सुदृढ आधार प्रदान करती है जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के तीव्रतर विकास के लिए पूंजी निवेश अत्यावश्यक होता है, परन्तु अपनी विशिष्टताओं के कारण कृषि क्षेत्र की पूंजी निवेश सम्बंधी आवश्यकतायें अन्य क्षेत्रों की पूंजी निवेश आवश्यकताओं से भिन्न होती है।

उद्योगों की तरह कृषि विकास के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि विकास को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि कृषको को उत्पादन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे उन्नत बीज, उर्वरक सिंचाई हेतु जल, आधुनिक कृषि औजार और विपणन हेतु वित्त की उपयुक्त व्यवस्था हो जब तक कृषकों को उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग नही कर सकते है इतना ही नही कृषकों को वित्तीय सुविधा कम ब्याज दर पर उपलब्ध होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये, भारतीय योजनाकारों ने प्रारम्भ में ही इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि आर्थिक उन्नति के लिए सुदृढ बैकिंग प्रणाली एवं ऋण व्यवस्था आधारभूत स्तम्भ होती है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की स्थापना करके सरकार ने प्रथम बार देश मे ग्रामीण साख व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया और इस हेतु सरकारी साख संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया गया वर्तमान समय में सहकारी साख समितियो एवं बैकों के अतिरिक्त ग्रामीण साख के क्षेत्र में वाणिज्य बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कार्य कर रहे है संस्थागत वित्तीय प्रणाली के विकास एवं सुदृढ़ीकरण से देश के सुदूरतम क्षेत्रो मे भी बैंकों की शाखायें स्थापित की गयी है और की

जा रही है। परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण क्षेत्र में अनेक वित्तीय संस्थायें कार्य कर रही है।

1. अल्पकालीन साख प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियां
2. मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख के लिए सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक
3. वाणिज्य बैंक
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इन संस्थाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साख प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है प्रत्यक्ष साख प्रदान करने वाली व्यापारिक बैंक तथा ग्रामीण बैंक आते है जो कृषकों को सीधे प्रत्यक्ष रूप में ऋण प्रदान करते है। परोक्ष रूप से साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंक को सम्मिलित किया जाता है।

ऋण के उद्‌देश्य एवं प्रकार –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा के ऋण व्यवसाय का प्रमुख उद्‌देश्य जनपद के जरूरतमंद कृषकों को कृषि विकास कार्यो के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। यद्यपि ऋणों के वितरण मे बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली ऋणों को प्राथमिकता दी जाती है, तथापि बैंक कृषकों को मध्यकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है। बैंक चूंकि ऋणों की सुरक्षा को महत्व देते हैं, इसलिए ऋण प्रायः उत्पादक कार्यो के लिए ही प्रदान किये जाते है कृषि विकास हेतु दिये जाने वाले समस्त ऋण इसी श्रेणी में आते है। परन्तु ग्रामीण कृषक के दृष्टिकोण से ऋणों पर विचार करे तो प्रतीत होता है कि कृषक को उत्पादक ऋणो के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के अनुत्पादक ऋणों की भी आवश्यकता होती है यदि ग्रामीण बैंक के द्वारा केवल उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान किये जाये तो अनुत्पादक कार्यो के लिए ऋणों की आपूर्ति हेतु ग्रामीण कृषकों को पुनः साहूकारो एवं महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है ऐसी स्थिति में संस्थागत कृषि वित्त विशेष रूप से ग्रामीण कृषि साख का उद्‌देश्य अधूरा रह जाता है इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय मे ग्रामीण बैंक कृषकों को अनुत्पादक ऋण भी उपलब्ध कराती है।

छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार के उद्‌देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार योजना तथा ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण बैंक महोबा द्वारा महत्वपूर्ण अभिकर्ता की भूमिका निभाई जा रही है।

जनपद महोबा के आर्थिक विकास को समुचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से ` यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं विकास हेतु तथा सेवा क्षेत्र में परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार विकास के लिए समय समय पर अग्रिम प्रदान करता है।

कृषि व सिंचाई के क्षेत्र में योगदान –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए जो वित्त उपलब्ध कराया जाता है वह दो श्रेणियों मे बांटा जा सकता है (1) प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था जो किसानों को (क) खेती करने / फसलें उगाने के लिए लघुकारिक उधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल ऋणो के रूप मे तथा (ख) कृषि भूमि मे धन लगाने के लिए मध्यम कालिक और दीर्घकालिक उधार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए विकास ऋणों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है और (2) अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था जो किसानों को विभिन्न रूपों में उपलब्ध कराई जाती है निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए बैकों द्वारा दिये जाने वाला ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम समझा जाता है।

अ. कृषि हेतु किसानों के लिए दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था –

फसलें उगाने के लिए लघुकालिक ऋण (फसल ऋण) किसानों को उनकी कृषि उपज गिरवी दृष्टिबन्धक रखकर 5000 रूपये तक के अग्रिम जिनकी अवधि 3 महीने से अधिक की नही हो सकती और उत्पादन तथा विकास की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए वित्त व्यवस्था हेतु मध्यम तथा दीर्घकालिक इस श्रेणी में आते है।

1. कृषि औजार तथा मशीनरी जिसमें परिवहन उपकरण भी शामिल है, की खरीद करना
2. सिंचाई क्षमता का विकास
3. भूमि का पुनरूद्धार तथा उसके विकास की योजनायें
4. कृषि फार्म भवन तथा ढांचे आदि का निर्माण

5. भण्डारण सुविधाओं का निर्माण तथा संचालन

6. संकर किस्मों के बीजों का उत्पादन तथा प्रसंस्करण

7. सिंचाई प्रभार आदि की भुगतान

8. किसानों को अन्य प्रकार से सीधे ही वित्त उपलब्ध कराना, उदाहरणार्थ-गैर परम्परागत बागानों बागवानी तथा दुग्ध उत्पादन मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन तथा शहद, मक्खी पालन आदि जैसी अन्य अनुसंगी गतिविधियों के लिए लघु कालिक ऋण उपलबध कराना।

ख. कृषि हेतु अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था –

1. उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, बीजों आदि के वितरण की वित्त व्यवस्था के लिए उधार।

2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, कृषक सेवा समितियो तथा बृहदाकार आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण

3. बिजली बोर्डो को ऋण ताकि वे उस खर्च की प्रतिपूर्ति कर सके जो उन्होनें अलग-अलग किसानों को कुँए चलाने के लिए कम टेन्शन वाले बिजली कनेक्शन देने पर किया है।

4. अन्य प्रकार से अप्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था।

सिंचाई –

किसानों के पास यदि भूमि हो, उपजाऊ संसाधन हो कार्य करने की क्षमता हो तब भी खेती नही कर सकता क्योकि जब तक उसके पास सिंचाई करने के साधन नही होगें खेती करना सम्भव नही होगा इसलिए इस बैंक के द्वारा सिंचाई करने के सम्बंध में ऋण लेने के लिए किसानों को सुविधा प्रदान की गयी है इसके तहत चलाई जाने वाली योजना निम्न है।

1. एलीड एग्रीकल्चर एण्ड एग्री टर्म लोन –

इस योजना के अन्तर्गत डीपी सेट पम्पिंग सेट व अन्य कार्यो के लिए ऋण लिया जा सकता है।

2. छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड–

छत्रसाल किसान कार्ड का प्रयोजन कृषक को कृषि क्रियाकलापों हेतु अल्पावधि कार्यशील पूंजी और इसकी घरेलू आवश्यकताओं हेतु वित्त प्रदान करना है न कि लाभ के व्यवसाय /

सट्टा क्रियाकलापों हेतु। इसके अन्तर्गत आच्छादित वर्ग में सभी कृषक सिंचित / असिंचित के भूमि मालिक आते है इसके प्रयोजन मे अल्पकालिक कृषि ऋण दिये जाते है और इसके ऋण की सीमा अधिकतम 2.00 लाख तक है इसकी विशेष सुविधाओं के अन्तर्गत रूपये 15 प्रीमियम पर रूपये 50,00.00 का दुर्घटना बीमा एवं राष्ट्रीय फसल बीमा सुविधा है।

इसमें प्रति आवेदन रूपये 150.00 प्रवेश शुल्क के रूप मे एक बार वसूल किया जाता है। छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली शाखा से ही किसी भी समय अपनी साख सीमा के अन्दर कितनी भी नकद राशि आहरण के लिए स्वतंत्र होगा। आहरित राशि को सीमा से घटा दिया जाता है।

जनपद में कुल 14727 के लक्ष्यों के सापेक्ष 31.1.2005 तक 14151 कार्ड जारी किये गये सभी पात्र कृषको को कार्ड जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. **छत्रसाल किसान समृद्धि योजना –**

इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के सिंचित / असिंचित भूमि के संक्रमरणीय भूमिधर कृषक आते है यह व्यक्तिगत आवश्यकताओ के लिए मध्यकालिक व दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

4. **एग्रीकल्चर इम्पलीमेंन्टस ट्रेक्टर योजना –**

ट्रेक्टर आदि खरीदने के लिए यह ऋण लिया जाता है जिनके पास कम से कम 5 एकड़ जमीन सिंचित हो उन्हे यह ऋण दिया जाता है इसके अतिरिक्त खेती करने व भाड़े से सम्बंधित कार्यो के लिए भी ऋण दिया जाता है।

5. **छत्रसाल मुबीक लोन स्कीम –**

यह स्कीम किसानों के लिए है जिनके पास 4 एकड़ जमीन सिंचित हो।

नौकरी पेशा आय वालो को जिनकी आय 6000 रूपया मासिक हो व वह आयकर देता हो।

6. **लैण्ड परचेज स्कीम फॉर फारमर्स –**

ऐसे किसान मजदूर जो भूमिहीन हैं उनके लिए कृषि योग्य भूमि क्रय करने के लिए यह ऋण दिया ज़ाता है।

7. कृषकों हेतु कृषि भूमि क्रय करने के लिए ऋण योजना –

राष्ट्रीय बैंक के दिनांक 2.8.2001 के पत्रांक एन बी डीपीडी–एफएस/एच–525/ सीएलपी (एफएम)/2001–02 के आधार पर निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 29.1.2002 की बैठक मे उपरोक्त योजना बैंक में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है योजना की प्रमुख विशेषतायें नियम एवं शर्ते आदि निम्नवत है –

1. परिचय –

वर्तमान मे बैंकों, कृषकों को कृषि विकास हेतु सावधि ऋण तथा उत्पादन के उद्‌देश्य से अल्पावधि ऋणो के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है। कृषको को भूमि के क्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी गतिविधियां बढ़ा सके और चल रही लघु और सीमान्त इकाइयों को आर्थिक रूप से जीव्य बना सके यह योजना, कृषकों को उनकी वर्तमान गतिविधियों और सहायक कार्यकलापों में समर्थ बनाने के लिए होती है।

2. उद्‌देश्य –

क. लघु एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत / जीव्य बनाने हेतु

ख. बंजर एवं परती भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु

ग. कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने हेतु

घ. साझेदार / बटाईदार कृषकों को भूमि क्रय हेतु वित्तपोषित हेतु ताकि वे अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो सके।

3. पात्रता मानदण्ड –

(क) योजनान्तर्गत क्रय की जाने वाली कृषि भूमि सहित, लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास स्वयं की अधिकतम 5.00 एकड़ असिंचित अथवा 2.5 एकड सिंचित भूमि होनी चाहिए।

4. प्रयोजन –

योजना का उद्‌देश्य किसानों को भूमि क्रय करने, बंजर परती भूमि का विकास करने तथा कृषि योग्य बनाने हेतु वित्तपोषण प्रदान करना है। बैंक दूसरे सहायक क्रियाकलापों को बढ़ावा अथवा स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद हेतु भी वित्तपोषण प्रदान करती है बैंक द्वारा भूमि क्रय हेतु वित्तपोषण पर विचार करने हेतु कृषक से परियोजना प्रस्ताव के समस्त विवरण

प्राप्त किये जाते हैं।

5. मार्जिन –

मार्जिन न्यूनतम 20 प्रतिशत होता है अथवा जैसा कि भा0रि0बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

6. प्रतिभूति –

बैंक ऋण से क्रय की गयी भूमि को बैंक के पक्ष में बन्धक किया जाता है।

7. ब्याजदर –

रूपये 25,000.00 तक	12 प्रतिशत
रूपये 25,000.00 से अधिक किन्तु रू0 2.00 लाख तक	13 प्रतिशत
रूपये 2.00 लाख से अधिक किन्तु रू0 5.00 लाख तक	14.5 प्रतिशत

8. ऋण की मात्रा –

ऋण की मात्रा क्रय किये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसके विकास पर आने वाले व्यय पर निर्भर होगी।

9. पुर्नभुगतान अवधि –

ऋण का पुर्नभुगतान 7–10 वर्षो में छमाही / वार्षिक किश्तों में किया जाता है जिसमें अधिकतम 24 माह की स्थगन अवधि भी शामिल होगी।

10. चुकौती क्षमता –

ऋण प्रदान करने वाले बैंक को स्वयं में संतुष्ट होना चाहिए कि क्रय की जाने वाली भूमि के उत्पादन क्रियाकलापों से उचित मात्रा में बचत प्राप्त हो और ऋणग्राही की अन्य आय को जोड़कर बैंक ऋण की ब्याज सहित निर्धारित समयावधि में अदायगी सुनिश्चित हो सके और तदनुसार ही पुर्नभुगतान अवधि का निर्धारण किया जायेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति 31.3.2005 में

तालिका 6

(राशि लाखों में)

संख्या	बैंक	खाता (लक्ष्य)	उपलब्धि		उपलब्धि
			खाता नं0	राशि	
1	इलाहाबाद बैंक	2744	3586	1439.97	130.68
2	एसबीआई	1088	1558	595.35	143.20
3	बीओबी	272	182	46.84	66.91
4	ओबीसी	272	278	109.66	102.20
5	सीजीबी	4624	3353	1325.00	72.52
6	डीसीबी	5727	5834	437.55	101.87
7	यूपीजीवीबी	0	0	0.00	0.00
	योग	14727	14791	3954.37	100.43

उपर्युक्त सारिणी में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति को अन्य बैंकों से तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है। इलाहाबाद बैंक का लक्ष्य 2744 क्रेडिट कार्ड खोलने का लक्ष्य रखा गया जिसमे 3586 खाते खुले और 143.97 रूपये की धनराशि की उपलब्धि हुयी यदि हम प्रतिशत मे इसकी वृद्धि को आंके तो यह 130.68 प्रतिशत रही इसकी तुलना में एस बी आई का लक्ष्य 1088 था जिसमें 1558 खातों के अन्तर्गत 595.35 की धनराशि उपलब्ध की गयी । यदि हम इन बैको की तुलना छत्रसाल ग्रामीण बैंक से करे तो इसमें 4624 क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य रखा गया जिसमें उपलब्धि दर्ज की गयी वह 72.51 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार यदि हम बैंकवार इनकी उपलब्धि की गणना करे सभी बैंको की उपलब्धि सन्तोषजनक है क्योंकि वर्ष 2004–05 में सभी बैंको की उन्नति 60 प्रतिशत से अधिक है क्योकि वर्ष 2004–05 में किसान क्रेडिटकार्ड की योजना सफल रही है परन्तु जहां जनपद की कृषि मानसून पर आधारित है तथा आम जनता की आजीविका 81 प्रतिशत भाग कृषक एवं कृषक मजदर के रूप मे अपनी आजीविका कमाता है वहां उनकी खराब

स्त्रोत–उपर्युक्त बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन।

वित्तीय स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ऐसे में कृषि हेतु उन्नत बीज खाद, सिंचाई सुविधाओं, तथा उच्च कृषि तकनीकी का प्रयोग करने हेतु ग्रामीण कृषक को वित्त की निरन्तर आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक कर रहे है परन्तु फिर भी ग्रामीण अंचलो में साहूकार एवं महाजनों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध कराया जाता है क्योंकि ग्रामीण कृषक की पहुँच बैंको की तुलना में साहूकार या महाजन तक आसान है साथ ही उसे किसी कागजी कार्यवाही की पूर्ति नही करनी पड़ती भले ही उसे ब्याज दर अधिक चुकानी पड़े वह अपनी कृषि वित्त सम्बंधी आवश्यकता की पूर्ति बड़े पैमाने पर आज भी साहूकार एवं महाजनों से कर रहा है तथा उनके आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है ऐसे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में छत्रसाल ग्रामीण बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंको का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह जनपद के प्रत्येक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा तक लाने का निरन्तर प्रयास करे ताकि कृषक उसका उचित सदुपयोग अपनी कृषि को उन्नत बनाने में कर सके तथा अपनी कृषक उत्पादकता मे वृद्धि करते हुए अपनी आय एवं जीवन स्तर को उन्नत कर सके तथा साथ वह साहूकारों और महाजनो के चंगुल से बचा जा सके। अतः आवश्यकता है कि समस्त बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में केडिटकार्ड के द्वारा धन उपलब्ध कराने की प्रकिया को सरल करते हुए ऋण प्रक्रिया मे लगने वाले अनावश्यक विलम्ब को अविलम्ब दूर करे ताकि कृषक इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठा सकें।

रोजगार व अन्य क्षेत्रों में योगदान

छत्रसाल ग्रामीण बैंक जिस प्रकार से कृषि के सम्बंध में किसानों को अनेक प्रकार के ऋण प्रदान करता है तथा कृषि से सम्बंधित अनेक प्रकार की योजनायें चलाकर महोबा जनपद के लोगो के कार्यो में सहयोग प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने रोजगार के क्षेत्र में भी यहां के निवासियों के लिए अनेक योजनाओं के द्वारा उनकी ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। जैसे व्यवसाय चलाने के लिए शिक्षा के लिए अनेक मशीनों को खरीदने आदि के लिए ऋण प्रदान करते है तथा कुछ योजनायें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलायी जा रही है जो रोजगार के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हुयी हैं।

रोजगार से सम्बंधित कुछ योजनायें निम्नलिखित है –

1. छत्रसाल स्वराजगिरि क्रेडिटकार्ड योजना –

यह योजना छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए है इसमे 25000/– तक का क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है।

2. मर्चेन्ट क्रेडिट स्कीम –

यह सभी प्रकार के व्यापारी वर्गो के लिए होती है इसके ऋण की सीमा 10.00 लाख तक है किन्तु बिक्री का 20 प्रतिशत से अधिक नही हो। इसमे कैश क्रेडिट की सुविधा है और इसका मार्जिन स्टाक वही ऋण की स्थिति पर 20 प्रतिशत है।

3. छत्रसाल मुबीक लोन स्कीम –

यह स्कीम किसानों के लिए है तथा नौकरी पेशा आय वालो के लिए भी है जिनकी आय 6000 रूपया मासिक हो व वह आयकरदाता हो।

4. रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटन फॉर वन व्हीकल–

यह एक सामान्य योजना है जिसमें ट्रक, बस जैसे ट्रान्सपोर्ट के लिए ऋण दिया जाता है।

5. छत्रसाल एजुकेशन लोन स्कीम –

यह लोन भारतीय नागरिक जिसका प्रवेश परीक्षा / चयन पद्धति से पेशेवर / तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु हुआ हो जैसे-एम बी ए, एमबीबीएस, आदि इस राशि में 4 लाख तक कोई जमानत नही है इसके ऋण की सीमा मे भारत मे अध्ययन हेतु अधिकतम 7.50 लाख एवं विदेश हेतु अधिकतम 15.00 लाख तक है इसके पुर्नभुगतान की अवधि 7 वर्ष है तथा स्थगन अवधि पाठ्यक्रम अवधि के बाद 01 वर्ष या 06 माह (नौकरी मिलने की स्थिति में) जो पहले होगी। यह राशि सीधे उस संस्था के नाम देय होती है जहां की फीस के लिए ऋण लिया गया हो।

6. छत्रसाल कम्प्यूटर लोन –

यह आयकरदाताओं और वैतनिक कर्मचारियों को दिया जाता है यह ऋण का 75 प्रतिशत या 50,000.00 या 50,000.00 से कम हो दिया जाता है।

7. वर्किंग कैपिटल एण्ड टर्मलोन –

यह खादी ग्रामोद्योग की योजना है इसमे 4 प्रतिशत ब्याज होता है। इसकी मार्जिन

मनी विभाग द्वारा दी जाती है और इसमे स्वयं द्वारा 5 प्रतिशत लगाया जाता है और इसकी अधिकतम सीमा तीन लाख रूपये तक है यह उद्योग आदि के लिए ऋण प्रदान करता है इसमें 20 के लक्ष्यों के सापेक्ष 20 केसों में ऋण वितरण किया गया । यह कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को समस्त प्रकार के ऋण उपलब्ध कराती है।

8. लघु उद्यमी क्रेडिट योजना –

अनुदेश परिपत्र सं0 797 दिनांक 24.10.03

1. आच्छादित वर्ग – उद्योग सेवा, व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारी
2. प्रयोजन – ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
3. ऋण की मात्रा – अधिकतम रूपये 2 लाख तक
4. निर्धारण अवधि –

(क) लघु व्यवसायियों, खुदरा व्यापारियों हेतु कर प्रयोजन के लिए घोषित टर्नओवर का 20 प्रतिशत अच्छा रिकार्ड रखने वाली पार्टियों के सम्बंध में जहां बिक्री का विवरण उपलब्ध नही है ऋण सीमा का निर्धारण पिछले दो वर्षो के दौरान खाते मे वार्षिक टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) पेशेवर एवं स्वनियोजित व्यक्तियों को आयकर विवरणी के अनुसार सकल वार्षिक आय का 50 प्रतिशत।

(ग) लघु उद्योग इकाइयों को बिक्री का 20 प्रतिशत

5. मार्जिन – 25 प्रतिशत
6. ब्याज दर – 11 प्रतिशत वार्षिक मासिक अवशेषों पर
7. प्रतिभूति – प्राथमिक स्टाक वही ऋणों एवं अन्य चल सम्पत्तियों पर दृष्टिबंधन प्रभार समपार्शिविक शत–प्रतिशत जो विपणन योग्य प्रापर्टी पर इक्विटेबल मार्गेज या तरल प्रतिभूतियो अथवा दोनों ।

खाते को लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड खाते में परिवर्तित करते समय वर्तमान प्रतिभूतियों को बनाये रखा जाये। प्रतिभूतियों को छोड़ने का प्रस्ताव तथा नये प्रकरणों पर यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय प्रधान कार्यालय स्तर पर ही किया जाता है।

8. प्रलेखन शुरू – रूपये 2 लाख तक रूपये 1000/–

9. स्वीकृतकर्ता अधिकारी – ग्रामीण स्केल रूपये 25000/– स्केल 11 रूपये 50,000/–
   जनपद स्केल रूपये 50,000 स्केल 11 रूपये 100,000

10. वैधता तिथि – 03 वर्ष

11. अन्य – ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा

अन्य क्षेत्रों में योगदान–

अब इसी प्रकार अन्य कार्यो के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक मे योजनाये चलायी गयी जिसका वर्णन निम्न है।

1. स्पेशन कम्पोनेंट प्लान –

यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है यह केवल अनुसूचित जाति के लिए है इसमें अधिकतम 10,000 तक का अनुदान दिया जा सकता है यह गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए है इसमे सभी मदों के लिए ऋण दिया जाता है।

2. ग्रुप एण्ड अदर लोन अण्डर एस0पी0एस0वाई0 या समूह ऋण योजना –

यह केन्द्र सरकार की योजना है इसमें 10 मद या 10 से अधिक लोगों के समूह को किसी विशेष मद के लिए ऋण दिया जाता है इसमें अनुदान की सीमा 1 लाख रूपये है यह ऋण भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को दिया जाता है।

3. ग्रुप लोन अण्डर जनरल स्कीम –

इस योजना मे नाबार्ड बैंक द्वारा सहयोग किया जाता है।

4. लोन अगेन्स्ट एन0एस0सी0 / के0वी0पी0 टर्म लोन –

इस योजना के अन्तर्गत किसान विकास पत्र एनएससी पर ऋण दिया जाता है इसमे सम मूल्य का 75 प्रतिशत ऋण दिया जाता है ऋण देने के पूर्व पोस्ट आफिस से बैंक के पक्ष में बंधक करना होता है।

5. हाउसिंग लोन फार स्टाफ –

यह केवल स्टाफ के लिए होता है इसमें अधिकारियों के लिए 7 लाख व कर्मचारियों

के लिए 4 लाख तक दिया जाता है।

6. एस0वी0ओ0 / डी0 –

यह वैतनिक कर्मचारियो के लिए है जो एक माह के वेतन के बराबर ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देता है व वेतन आने पर समायोजित कर ली जाती है।

7. पर्सनल लोन स्कीम –

यह वैतनिक कर्मचारियों के लिए है इसमे वेतन का 15 गुना ऋण दिया जाता है इसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रूपये है यह टर्म लोन है।

8. क्लीन ओवर ड्राफ्ट टू बैंक ड्राफ्ट –

यह भी बैंक कर्मचारियों की सुविधा वाली योजना है जिसकी सीमा रूपये 25000 है।

9. लोन टू परचेज कार एण्ड जीप –

यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी न्यूनतम आय 6000 मासिक हो। इसमें 25 प्रतिशत मार्जिन होता है।

10. पब्लिक हाउसिंग लोन –

यह योजना मकान निर्माण के लिए होती है यह पब्लिक व बैंक कर्मचारियों के लिए होती है इसके लिए उसे आयकर दाता होना चाहिए।

11. छत्रसाल सरल ऋण योजना –

यह योजना वैतनिक व्यक्तियों पेशेवर, स्वनियोजित एवं कृषक के लिए होता है किसी भी उद्देश्य के लिए है। इसके ऋण की अधिकतम सीमा 10.00 लाख रूपये तक है और इसका मार्जिन वैल्यूऐंशन रिपोर्ट मे सम्पत्ति की दर्शित वैल्यू का 50 प्रतिशत है। इसके पुनर्भुगतान की अवधि 60 मासिक किश्तों में है।

12. समूह सहेली रसोई गैस ऋण योजना –

नाबार्ड लखनऊ के पत्रांक एन बी एल के सी पी डी /179 दिनांक 10.1.2003 के अनुपालन में महिला स्वयं सहायता समूहों की समस्याओं के लिए रसोई गैस कनेक्शन तथा प्रेशर कुकर हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना लागू करने का निर्देश प्राप्त हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलायें खाना बनाने के लिए उपले, लकड़ी, कोयला के साथ साथ कृषि उत्पाद के अवशिष्ट का प्रयोग करती है। ईंधन के इन साधनों से धुँआ उत्पन्न होता है जो कि महिलाओं मे आँखों तथा श्वांस की बीमारियों का मुख्य कारण है इसके अतिरिक्त ईंधन के परम्परागत साधनों से खाना बनाने मे समय भी अधिक लगता है तथा ये सीमित है। यह सर्वविदित है कि रसोई गैस खाना बनाने का सबसे आसान साधन है तथा यह सस्ता भी है।

1. पात्रता – केवल स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के लिए ये है।
2. प्रयोजन – योजना लागत के अनुसार गैस कनेक्शन तथा प्रेशरकुकर
3. ऋण की राशि –

(अ) एक सिलेण्डर के साथ गैस कनेक्शन की योजना लागत 2300.00 रूपये है।
(ब) दो सिलेण्डर के साथ गैस कनेक्शन की योजना लागत 3250.00 रूपयें है।

4. अंशधन (मार्जिन मनी) : शून्य
5. सेवा शुल्क / प्रक्रियाधीन शुल्क : कोई प्रक्रियाधीन शुल्क आवश्यक नहीं
6. ऋण स्वीकृति अधिकारी : शाखा प्रबंधक की विवेकाधीन सीमा के अन्तर्गत
7. प्रतिभूति : ऋणराशि से सृजित सम्पत्ति का दृष्टिबंधक
8. सहअनुबंधी : कोई सहअनुबंधी आवश्यक नहीं है।
9. ऋण निस्तारण : सीधे ऋणों को होता है।
10. ब्याज दर : 10 प्रतिशत वार्षिक (अर्द्धवार्षिक देय)
11. पुनर्भुगतान : अधिकतम 36 समान मासिक किश्तों में

अ. योजना लागत 2300/– हेतु रूपये 080/–
ब. योजना लागत 3250/– हेतु रूपये 110/–

12. सुप्तावधि : प्रथम किश्त ऋण निस्तारण के एक माह पश्चात् देय होगी।
13. ऋण दस्तावेज : पी–1, एमसीआर –6 एवं ऋण अनुबंध पत्र

तालिका नं0–6.1
मार्च 2005 के अर्न्तगत तुलनात्मक सफलतायें

कम0 सं0	बैंक का नाम	कृषि उपलब्धि				लघु औद्योगिक इकाई उपलब्धि			रोज़गार व अन्य उपलब्धियां			कुल उपलब्धियां		
		मार्च–2004	मार्च–2005	विचलन	प्रतिशत	मार्च–04	मार्च–05	विचलन	मार्च–04	मार्च–05	विचलन	मार्च–04	मार्च–05	विचलन
1.	इलाहाबाद बैंक	2136	3501	+ 1365	63.9%	73	62	−11	248	130	−118	2457	3693	+1236
2.	स्टेट बैंक	1278	1886	+ 608	47.57%	43	4	−39	177	159	− 18	1498	2049	+ 551
3.	बैंक आफ बड़ौदा	46	95	+ 49	106.52%	1	1	0	136	86	− 50	183	182	− 1
4.	ओ0बी0सी0	84	116	+ 32	38.09%	0	3	+3	28	0	− 28	112	119	+ 7
5.	सी0जी0बी0	649	1677	+1028	158.39%	2	1	−1	40	42	+ 2	691	1721	+1030
6.	डी0सी0बी0	798	1149	+ 351	43.98%	0	0	0	33	28	−5	831	1176	+ 345
7.	यू0पी0जी0वी0बी0	368	384	+ 16	4.35%	2	35	+33	21	43	+ 22	391	492	+ 71
	योग	5359	8808	+3449		121	106	− 15	683	488	−195	6163	9402	+3239

स्त्रोतः–उर्पयुक्त बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन

विविध क्षेत्रों में सफलताओं का तुलनात्मक अध्ययन तालिकाओं से महोबा जनपद मे कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों, छत्रसाल ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंको की कृषि लघु उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों मे उपलब्धियों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 2003–04 की तुलना में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक उपलब्धि छत्रसाल ग्रामीण बैंक की रही है जो कि 63.9 प्रतिशत है जबकि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की इसी अवधि के दौरान उपलब्धि मात्र 47.5 प्रतिशत रही इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बडौदा, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स एवं जिला सहकारी बैंक की उक्त अवधि के दौरान उपलब्धि प्रतिशत क्रमश 63.9 प्रति, 106.5 प्रति0 38.1 प्रति तथा 43.9 प्रतिशत रहा है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कृषि के क्षेत्र में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की भूमिका निरन्तर बढ़ रही है तथा कृषि क्षेत्र के लिए आवेदन करने वालों का प्रतिशत गत दो वित्तीय वर्षो मे छत्रसाल ग्रामीण बैंको का सर्वाधिक रहा है लेकिन जहां तक एक निश्चित वर्ष में समग्र आवेदकों का सवाल है वहां जनपद में इलाहाबाद बैंक वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 3501 आवेदकों के साथ कृषि क्षेत्र मे प्रथम स्थान पर स्टेट बैंक 1886 आवेदकों के साथ द्वितीय स्थान पर तथा छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने इसी अवधि मे 1677 आवेदकों के साथ तृतीय स्थान पर है इस प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक जनपद मे स्थित 4 बैंकों से आगे है एवं 2 बैको से पीछे चल रहा है अतः जहां जनपद की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है वहां छत्रसाल ग्रामीण बैंक को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिए ताकि जनपद में कृषि का त्वरित गति से विकास हो सके।

इसी प्रकार हम लघु औद्योगिक इकाई की सफलताओं का तुलनात्मक अध्ययन करे तो राष्ट्रीकृत बैंको, क्षेत्रीय बैंको जिला सहकारी बैकों व लघु उद्योग सेवा क्षेत्रो मे वर्ष 2004–05 मे 2003–04 से तुलना करने पर पता चलता है कि यह उपलब्धि क्रमशः 17.4 प्रतिशत, 57.5 प्रतिशत, 1650 प्रतिशत थी।

इसके सम्बंध में किसी भी बैंक की स्थिति अच्छी नही रही है केवल ग्रामीण बैंको में इसकी उपलब्धि 165 प्रतिशत है। रोजगार व अन्य क्षेत्र की सफलताओं के विषय मे अध्ययन करने पर पता चलता है कि इलाहाबाद बैंक का 90 प्रतिशत भाग हानि में चल रहा है स्टेट बैंक का 11.1 प्रतिशत भाग व बैंक आफ बडौदा का 58 प्रतिशत व ओ बी सी सभी की

उपलब्धि हानि पर चल रही है। छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने रोजगार व अन्य सेवाओं के अन्तर्गत केवल 5 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की है इसके समकक्ष ग्रामीण विकास बैंक ने 104 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है रोजगार के क्षेत्र मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक का दूसरा स्थान है जबकि पहला स्थान ग्रामीण विकास बैंक का है छत्रसाल ग्रामीण बैंक को इस क्षेत्र में अभी और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

तालिका 6.2

महोबा जनपद की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत बैंकवार निष्पादन वर्ष 31–3–05

(राशि लाखों में)

क0 सं0	बैंक का नाम	कृषि उपलब्धि			उद्योग			रोज़गार			कुल		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	इलाहाबाद बैंक	1839.00	3501.44	190.40	74.00	62.18	84.03	159.00	129.52	81.46	2072.00	3693.14	178.24
2.	स्टेट बैंक	662.00	1886.41	284.95	35.00	3.55	10.14	87.00	159.30	183.10	784.00	2049.26	261.38
3.	बैंक आफबड़ौदा	155.00	94.80	61.16	12.50	1.00	8.00	58.50	86.30	147.52	226.00	182.10	80.57
4.	ओ0बी0सी0	84.00	116.08	138.19	2.40	3.05	127.08	6.60	0.45	6.82	93.00	119.58	128.58
5.	सी0जी0बी0	885.13	1677.00	189.46	43.00	1.50	3.49	100.00	42.00	42.00	1028.13	1720.50	167.34
6.	डी0सी0बी0	1749.00	1148.75	65.68	0.00	0.00	0.00	37.00	27.43	74.13	1786.00	1176.18	65.85
7.	यू0पी0बी0वी0बी0	607.00	383.41	63.16	88.00	88.00	40.00	35.00	42.93	122.66	730.00	461.54	63.22
	योग–	5981.13	8807.89	147.26	254.90	106.48	41.77	483.10	487.93	101.00	6719.13	9402.30	139.93

स्त्रोतः– उर्पयुक्त बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन

बैंक की वार्षिक कार्य योजना का मूल्यांकन करने पर तथा अन्य बैंको से तुलना करने पर यह परिलक्षित होता है कि छत्रसाल ग्रामीण बैंक. ने कृषि क्षेत्र में लक्ष्यों के सापेक्ष 179.46 प्रतिशत की वृद्धि की है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि 3.49 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र मे 42 प्रतिशत तथा समेकित रूप से 167.34 प्रतिशत है इस सन्दर्भ मे जनपद मे स्थित छत्रसाल बैंक की अन्य बैंको से तुलना करने पर यह प्रकट होता है कि भारतीय स्टेट बैंक की महोबा शाखा ने कृषि एवं सेवाक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है जो कि क्रमशः 284.95 प्रतिशत एवं 183.10 प्रतिशत है तथा समेकित रूप से यह वृद्धि 261.38 प्रतिशत है ओ0बी0सी0 बैंक ने वृद्धि अर्जित की है समग्र रूप से देखा जाये तो छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कार्यक्षमता अध्ययन अवधि के दौरान काफी प्रभावशाली रही है।

तालिका 6.3

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजनार्न्तगत समूहों की ऋण स्थिति यथा 31—3—05

(धनराशि लाखों में)

क0 सं0	बैंक का नाम	लक्ष्य	समूह गठित		खाता खुले		प्रथम ग्रेडिंग		सी0सी0एल0 स्वीकृति		द्वितीय ग्रेडिंग		ऋण स्वीकृति		वितरित	
			वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक	वर्ष में	कमिक
1.	इलाहाबाद बैंक	29	25	332	332	284	58	186	48	125	29	79	19	56	19	56
2.	भारतीय स्टेट बैंक	12	16	131	8	97	19	67	21	52	11	33	10	28	10	28
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2	0	19	0	19	4	6	4	6	0	1	0	1	0	1
4.	ओ0बी0सी0	1	8	465	5	42	8	15	8	11	8	10	1	2	1	2
5.	छत्रसाल ग्रामीण बैंक	39	18	556	22	469	75	215	65	150	17	47	15	32	15	32
6.	डिस्टिक्ट को—आपरेटिव बैंक	14	0	83	0	79	8	52	9	41	11	26	9	16	9	16
7.	उ0प्र0ग्रा0विकास बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योंग	100.	67	1166	57	990	172	541	155	385	76	196	54	135	54	135

स्त्रोतः— उर्पयुक्त बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूहों की ऋण स्थिति तालिका का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि महोबा जनपद मे समूह गठित करने के लक्ष्य सर्वाधिक छत्रसाल ग्रामीण बैंक जो कि जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में कार्यरत है के थे जिनकी संख्या 39 थी जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2004–05 मे 18 समूह गठित किये गये जिनके 22 खाते खोले गये तथा 65 समूहों को सी सी एल स्वीकृति जारी की गयी इसी वित्तीय वर्ष में 15 समूहों को ऋण स्वीकृत किया एवं वितरित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का यह कार्य जनपद मे स्थित अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको की तुलना मे काफी सफल रहा है इलाहाबाद बैंक को छोड़कर जो कि इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रवर्तक बैंक भी है अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक की तुलना मे अच्छा कार्य नही कर सका है जहां भारतीय स्टेट बैंक का लक्ष्य 12, बैंक ऑफ बड़ौदा का 2, ओ0 बी0सी0 का 4, जिला सहकारी बैंक का 14, इलाहाबाद बैंक का 29 था वही छत्रसाल ग्रामीण बैंक का लक्ष्य 39 था जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि छत्रसाल ग्रामीण बैंक जनपद के समग्र विकास में सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन कर रहा है लेकिन जनपद के क्षेत्रफल जनसंख्या एवं उसके पिछड़ेपन को देखते हुए यह लक्ष्य पर्याप्त नही है जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जनपद के ग्रामीण अंचल मे व्याप्त निर्धनता का उन्मूलन कर क्षेत्र का समग्र विकास किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र में बैंक द्वारा चलाई जाने वाली विविध योजनाओं एवं उनकी प्रवाहकारिता का मूल्यांकन

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा जनपद के समग्र विकास के लिए अनेकानेक योजनायें चलाई जा रही है जिससे कई योजनायें जनपद के सर्वांगीण विकास मे मील का पत्थर साबित हुयी है बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र गैर प्राथमिक क्षेत्र लक्ष्य समूह गैर लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष कम्पोनेंट प्लान के तहत अल्पसंख्यक को लघु कृषक एवं सीमान्त कृषकों एवं कृषि कार्य मे संलग्न श्रमिकों समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना एवं केन्द्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनेक योजनाओं की क्रियान्विती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा की जा रही है अतः उक्त समस्त योजनाओं की प्रवाहकारिता का मूल्यांकन किया जाना नितान्त

आवश्यक एवं वांछनीय है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उक्त योजनायें अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने मे कहां तक सफल सिद्ध हुयी है प्रस्तुत शोध कार्य मे उक्त समस्त योजनाओं की प्रवाहकारिता के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है जिससे समग्र रूप मे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैद्धान्तिक रूप से उक्त समस्त योजनाये काफी प्रभावशाली है बशर्ते कि उनकी क्रियान्विती पूर्ण निष्ठा ईमानदारी एवं समर्पण की भावना से की जाये।

किसान क्रेडिट कार्ड –

जनपद मे कुल 14727 के लक्ष्यों के सापेक्ष 31.1.2005 तक 14151 कार्ड जारी किये गये।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान –

यथा 31.1.05 तक बैंको द्वारा 830 स्वीकृति केसों में से 464 केसों में ऋण प्रदान किया गया।

खादी ग्राम उद्योग ब्याज उपादान योजना –

20 के लक्ष्यो कें सापेक्ष 20 केसों में ऋण वितरण किया गया।

के0बी0आई0सी0 मार्जिन मनी योजना –

07 के लक्ष्यों के सापेक्ष 5 केसों में स्वीकृति एवं वितरण किया गया।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (समूह)–

यथा 31.1.2005 तक जनपद में 52 समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया। चालूवर्ष 153 समूहों में प्रथम ग्रेडिंग, 160 समूहों में सी0सी0एल0 एवं 71 समूहों में द्वितीय ग्रेडिंग की गयी। कुल 398 व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया।

बैंक की योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दर		ब्याज दर
1.	छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना	
	50,000 रूपये तक के लिए	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 2,00,000 तक	12.00 प्रतिशत
2.	छत्रसाल किसान समृद्धि योजना	
	50,000 तक	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 2,00,000 तक	10.00 प्रतिशत
	2,00,000 से 5,00,000 तक	11.00 प्रतिशत
3.	स्कीम फोरट्रेप वीह0 फॉर फारमर्स किसानो के लिए चार पहिया वाहन ऋण योजना	
	25,000 तक	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000 तक	11.50 प्रतिशत
	2,00,001 से 5,00,000 तक	11.50 प्रतिशत
4.	एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स कृषि औजार	
	ट्रेक्टर 25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000 तक	11.50 प्रतिशत
	2,00,001 से 10,00,000 तक	11.50 प्रतिशत
5.	लैण्ड परचेज स्कीम फार फारमर्स	
	25,000	12.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000 तक	13.50 प्रतिशत
	200,001 से 5,00,000 तक	14.50 प्रतिशत
6.	एलीड एग्रीकल्चर एण्ड ऐजी0 टर्मलोन	
	25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000	11.50 प्रतिशत
	2,00,001 से 10,00,000	12.50 प्रतिशत
7.	रूल हावर्स कम स्व0 स्कीम	
	25,000 तक	12.50 प्रतिशत
	25,001 से 30,000 तक	13.00 प्रतिशत

8.	स्पेशन कम्पोनेंट प्लान	
	50,000 तक	11.50 प्रतिशत
9.	ग्रुप एण्ड अदर लोन अण्डर एस0जी0एस0वाई0	
	समूह एवं अन्य ऋण योजना	
	50,000	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 5,00,000	12.50 प्रतिशत
10.	ग्रुंप लोन अण्डर जनरल स्कीम	
	50,000	9.00 प्रतिशत
	50,001 से 5,00,000 तक	12.50 प्रतिशत
11.	समूह सहेली रसोई गैस योजना	9.00 प्रतिशत
12.	छत्रसाल स्वराजगिरी क्रेडिट कार्ड	9.00 प्रतिशत
	25,000	
13.	छत्रसाल सरल लोन स्कीम	11.50 प्रतिशत
14.	मर्चेन्ट क्रेडिट स्कीम	
	25,00	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000 तक	13.00 प्रतिशत
	2,00,001 से 5,00,000	15.50 प्रतिशत
	5,00,001 से 5,00,0000	16.00 प्रतिशत
15.	लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड	11.50 प्रतिशत
16.	छत्रसाल मुबीक लोन स्कीम	11.00 प्रतिशत
17.	लोन अगेन्सट रेन्ट किराये के सापेक्ष	14.00 प्रतिशत
18.	वर्किंग कैपिटल एण्ड टर्म लोन	
	कार्यशील पूंजी एवं अवधि ऋण	
	25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000	11.50 प्रतिशत
	2,00,001 से 5,00,000	12.50 प्रतिशत
	5,00,000 से अधिक 10,00,000	12.50 प्रतिशत
	10,00,000 से अधिक	13.00 प्रतिशत
19.	रोड ट्रान्सपोर्ट आपरेटर- फार वन व्हील	
	25,000	11.50 प्रतिशत
	25,001 से 2,00,000	11.50 प्रतिशत

	2,00,000 से अधिक	12.50 प्रतिशत
	1 से 10 लाख तक व 2 लाख से अधिक	13.50 प्रतिशत
20.	लोन अगेन्सट एन0एस0सी0 / क0वी0पी0	
	टर्मलोन	12.50 प्रतिशत
	ओ/डी लिमिट	12.50 प्रतिशत
21.	लोन अगेन्सट एन0एस0सी0 / के0वी0पी0	
	स्टाफ टर्मलोन	10.00 प्रतिशत
	ओ0/डी0 लिमिट	11.50 प्रतिशत
22.	हाउसिंग लोन फार स्टाफ	
	10,000	5.00 प्रतिशत
	5,00,000 तक	10.00 प्रतिशत
	6,00,000 तक	11.00 प्रतिशत
23.	एस0बी0आ0 / डी0	
	10,000	16.00 प्रतिशत
24.	पर्सनल लोन स्कीम	
	2,00,000	12.00 प्रतिशत
25.	छत्रसाल एजुकेशन लोन स्कीम	
	4,00,000	11.50 प्रतिशत
	4,00,000 से अधिक	12.50 प्रतिशत
26.	छत्रसाल कम्प्यूटर लोन स्कीम	15.00 प्रतिशत
27.	क्लीन ओवर ड्राफ्ट टू बैंक स्टाफ	10.50 प्रतिशत
28.	लोन टू परचेज कार	
	5,00,000	10.00 प्रतिशत
29.	पब्लिक हाउसिंग लोन स्कीम	
	10,00,000 से अधिक 5 सालों के लिए	8.25 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 5 से 10 सालों के लिए	8.75 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 10 से 15 सालों के लिए	8.75 प्रतिशत
	10 लाख से अधिक 15 से 20 सालों तक	9.25 प्रतिशत

तालिका 6.4

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान प्रगति यथा 31—5—05

(राशि लाखों में)

क0 सं0	बैंक का नाम		प्रेषित आवेदन पत्रा	स्वीकृत आवेदन—पत्र		वितरित आवेदन पत्र		लम्बित वास्ते		
		लक्ष्य		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि.	स्वीकृत	वितरण	निरस्त वापस
1.	इलाहाबाद बैंक	250	252	151	90.60	129	77.40	0	22	101
2.	भारतीय स्टेट बैंक	100	196	160	80.00	154	77.00	0	6	36
3.	बैंक आफ बड़ौदा	25	35	15	4.50	12	3.60	0	3	20
4.	ओ0बी0सी0	25	25	10	2.00	6	1.20	0	4	15
5.	सी0जी0बी0	360	300	75	15.00	51	10.20	0	24	225
6.	डि0को0बैंक	90	100	25	5.00	18	3.60	0	7	75
7.	उ0प्र0ग्रा0विकास बैंक	150	412	394	118.20	225	67.50	0	169	18
	योग	1000	1320	830	315.30	595	240.50	0	235	490

स्त्रोतः— उर्पयुक्त बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट

उपर्युक्त सारिणी के अनुसार स्पेशन कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक में 250 का लक्ष्य रखा गया जिसमे 252 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 151 स्वीकृति व 129 वितरित करने पर 101 आवेदन पत्र निरस्त किये गये। भारतीय स्टेट बैंक में 100 के लक्ष्य पर 196 आवेदित व 160 स्वीकृत हुए व 154 वितरित करने पर 77 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुयी व 36 निरस्त कर दिये गये।

उपर्युक्त बैंको में सबसे अधिक इस योजना के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक मे 360 का लक्ष्य रखा गया जिसमें अधिक संख्या में आवेदन भी हुए हैं परन्तु इनमें 75 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये और 51 वितरित करके 24 आवेदन पत्र लम्बित रह गये तथा 225 आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये यह योजना सबसे अधिक छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा चलायी जा रही है।

तालिका 6.5

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उपादान योजना यथा–31–3–05

(राशि लाखों में)

क0 सं0	बैंक का नाम	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्रा	स्वीकृत आवेदन–पत्र		वितरित आवेदन पत्र		लम्बित वास्ते		
				संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	स्वीकृत	वितरण	निरस्त वापस
1.	इलाहाबाद बैंक	10	20	10	15.15	10	15.15	0	0	10
2.	भारतीय स्टेट बैंक	6	8	7	11.35	6	7.35	0	1	1
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1	2	1	1.00	1	1.00	0	0	1
4.	ओ0बी0सी0	1	1	1	1.00	1	1.00	0	0	0
5.	सी0जी0बी0	2	2	0	0.00	0	0.00	2	0	0
6.	डि0को0बैंक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	उ0प्र0ग्रा0विकास बैंक	0	4	4	6.20	4	6.20	0	0	0
	योग	20	37	23	34.70	22	30.70	2	1	12

स्त्रोतः– उर्पयुक्त बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट

उपर्युक्त सारिणी में खादी ग्राम उद्योग योजना के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक का विभिन्न बैंको के साथ विश्लेषण किया गया है इलाहाबाद बैंक ने 10 का लक्ष्य रखा जिसमें 20 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 10 स्वीकृत होने पर रूपये 15.15 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी इसमे एक भी पेडिंग नहीं रहा भारतीय स्टेट बैंक मे 6 के लक्ष्य के सापेक्ष 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें 7 आवेदन स्वीकृत किये गये जिसमे 6 वितरित करने पर 7.35 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुयी यानि 1 आवेदन पत्र को निरस्त करना पड़ा यह स्थिति बैंक ऑफ बड़ौदा की भी रही जिसमें 1 आवेदन पत्र निरस्त करना पड़ा। ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स मे 1 के लक्ष्य पर 1 आवेदन आया छत्रसाल ग्रामीण बैंक मे 2 के सापेक्ष 2 आवेदन पत्र स्वीकृत नही किया गया और दोनों ही आवेदन पत्र पेन्डिंग पड़े रहे। डिस्ट्रिक को–आपरेटिव बैंक मे कोई लक्ष्य नहीं था व उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में भी एक भी लक्ष्य नही रखा गया।

तालिका 6.6

खादी ग्रामोद्योग मार्जिन मनी योजना यथा 31—3—05

क0 सं0	बैंक का नाम	लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्रा	स्वीकृत आवेदन—पत्र		वितरित आवेदन पत्र		लम्बित वास्ते		
				संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	स्वीकृत	वितरण	निरस्त वापस
1.	इलाहाबाद बैंक	3	7	2	2.80	2	2.80	0	0	5
2.	भारतीय स्टेट बैंक	3	3	3	4.75	3	4.75	0	0	0
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
4.	ओ0बी0सी0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
5.	सी0जी0बी0	0	5	2	2.50	2	2.50	0	0	3
6.	डि0को0बैंक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
7.	उ0प्र0ग्रा0विकास बैंक	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
	योग	7	15	7	10.05	7	10.05	0	0	8

स्त्रोतः— उर्पयुक्त बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट

खादी ग्रामोंद्योग की मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा मे क्रमशः 3,3,1 का लक्ष्य रखा गया जिसमें 3 पर 7 आवेदन आये और दूसरे में 3 के सापेक्ष 3 और बैंक आफ बड़ौदा में 1 पर कोई आवेदन पत्र नहीं आया। उपर्युक्त बैंकों की स्वीकृत धनराशि 2.80, 4.75 व शून्य थी। इलाहाबाद बैंक के 5 आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये और छत्रसाल ग्रामीण बैंक में शून्य लक्ष्य पर 5 आवेदन आये चूकि इस योजना ने छत्रसाल ग्रामीण बैंक में कोई भी लक्ष्य निर्धारित नही किया परन्तु इसके लिए 5 आवेदन पत्र प्रेषित किये गयें जिसमें दो आवेदन पत्रों को स्वीकृत करते हुए 3 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार यह योजना छत्रसाल ग्रामीण बैंक में नवीन रूप मे प्रारम्भ हुयी अतः भविष्य में बैंक को अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इस योजना को भी अपने लक्ष्य में शामिल करना चाहिए।

सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की प्रवाहकारिता का मूल्यांकन अग्रलिखित सारिणियों द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका 6.7
छत्रसाल ग्रामीण बैंक
मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2003

जनपद :– महोबा

(राशि लाखों में)

क0सं0	सेक्टर कोड	क्रियाकलाप	मांग अतिदेय		चालू मांग		योग		वसूली		अतिदेय		अतिदेय खाता वसूली प्रतिशत
			खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
1	ए	अल्प सिंचाई	806	32.99	1242	55.65	1584	88.64	931	43.76	879	44.88	49.37
2	सी	कृषि मशीनीकरण	58	11.26	85	22.54	94	33.80	60	18.10	52	15.70	53.55
3	ई	पशुपालन/दुग्ध विकास	478	22.62	460	14.44	653	37.06	276	9.84	484	27.22	26.55
4	एफ	पशुपालन/मुर्गीपालन	11	0.34	6	0.22	15	0.56	10	0.37	7	0.19	66.07
5	जी	पशुपालन/अन्य	458	21.94	465	19.00	658	40.94	308	12.09	476	28.85	29.53
6	एच	मत्स्य पालन	4	0.24	4	0.22	8	0.46	3	0.17	6	0.29	36.96
7	के	अन्य कृषि ऋण	190	8.80	173	6.16	257	14.96	130	5.56	162	9.40	37.17
8	एल	अकृषि क्षेत्र/लघु उद्योग	257	20.41	198	7.53	332	27.94	132	4.87	238	23.07	17.43
9	एम	अकृषि क्षेत्र/अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	560	28.91	469	18.07	717	46.98	321	13.62	504	33.36	28.99
10	एन	फसली ऋण	584	109.24	2605	749.53	2964	858.77	2324	672.10	773	186.67	78.26
		महायोग	**3406**	**256.75**	**5707**	**893.36**	**7282**	**1150.11**	**4495**	**780.48**	**3581**	369.63	67.86
1	2 से 6	संग्राविका/एसजीएसवाई	1747	79.41	1885	56.26	2488	135.67	1334	49.65	1559	86.02	36.60
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	487	20.61	584	21.42	780	42.03	343	15.16	517	26.87	36.07
3	13	एससी/एसटी	755	32.44	907	31.61	1333	64.05	587	22.74	910	41.31	35.50
4	14	महिलायें	171	7.99	171	7.68	255	15.67	176	7.03	214	8.64	44.86
5	16	अल्पसंख्यक	43	1.94	52	3.00	81	4.94	43	1.47	47	3.47	29.76
6		अल्प सिंचाई	555	23.37	885	35.68	1093	59.05	691	30.07	602	28.98	50.92
7		अकृषि/सीसी लिमिट	29	2.13	158	38.04	171	40.17	134	32.96	47	7.21	82.05
8		अन्य सामान्य कृषि ऋण	238	27.09	783	243.85	1079	270.94	706	194.82	408	76.12	71.91
		(ट्रैक्टर,अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खाते)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9		अकृषि ऋण सामान्य	3	8.62	2	0.15	4	8.77	3	0.21	1	8.56	2.39
10		ट्रैक्टर	24	9.30	42	19089	48	29.19	36	15.22	24	13.97	52.14
11		सड़क परिवहन सामान्य	3	1.48	3	0.29	5	1.77	2	0.28	3	1.49	15.82
		महायोग	4055	214.38	5472	457.87	7337	672.25	4055	369.61	4332	302.64	54.98

स्त्रोत – छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 6.8

छत्रसाल ग्रामीण बैंक

मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2004

जनपद :— महोबा

समस्त खाते (राशि लाखों में)

क0सं0	सेक्टर कोड	क्रियाकलाप	मांग अतिदेय खाता	मांग अतिदेय राशि	मांग चालू खाता	मांग चालू राशि	मांग योग खाता	मांग योग राशि	वसूली खाता	वसूली राशि	अतिदेय खाता	अतिदेय राशि	वसूली प्रतिशत
1	ए	अल्प सिंचाई	1015	44.81	1119	64.61	1615	109.42	1066	64.94	899	44.48	59.35
2	सी	कृषि मशीनीकरण	53	15.71	66	19.39	75	35.10	58	19.88	45	15.22	56.64
3	ई	पशुपालन/दुग्ध विकास	537	29.52	544	18.23	730	47.75	302	14.69	514	33.06	30.76
4	एफ	पशुपालन/मुर्गीपालन	13	0.43	12	0.39	20	0.82	4	0.29	12	0.53	35.37
5	जी	पशुपालन/अन्य	479	26.91	351	13.10	552	40.01	251	12.33	381	27.68	30.82
6	एच	मत्स्य पालन	5	0.23	5	0.34	12	0.57	3	0.18	5	0.39	31.58
7	के	अन्य कृषि ऋण	161	8.86	146	4.71	234	13.57	103	5.53	128	8.04	40.75
8	एल	अकृषि क्षेत्र/लघु उद्योग	244	22.99	164	5.10	324	28.09	129	11.16	210	16.93	39.73
9	एम	अकृषि क्षेत्र/अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	518	34.32	449	15.65	867	49.97	239	13.94	455	36.03	27.90
10	एन	फसली ऋण	982	195.87	4023	1040.14	3978	1236.01	3679	987.77	992	248.24	79.92
		महायोग	4007	379.65	6879	1181.66	8407	1561.31	5834		3641	430.60	72.42
1	2 से 6	संग्राविका/एसजीएसवाई	1499	90.13	1312	44.77	1934	134.90	986	54.26	1374	80.64	40.22
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	541	28.61	471	20.11	788	48.72	381	16.35	520	32.37	33.56
3	13	एससी/एसटी	1070	62.06	891	66.24	1519	128.30	829	65.48	964	62.82	51.04
4	14	महिलायें	372	21.86	373	17.65	563	39.51	288	18.71	364	20.80	47.36
5	16	अल्पसंख्यक	132	8.31	97	4.29	179	12.61	81	4.68	125	7.93	37.12
6		अल्प सिंचाई	803	34.43	987	51.54	1228	85.97	790	52.04	656	33.93	60.53
7		अकृषि/सीसी लिमिट	12	0.48	135	33.64	145	34.12	116	29.50	29	4.62	86.46
8		अन्य सामान्य कृषि ऋण	266	43.79	943	250.04	1068	293.83	845	229.87	322	63.96	78.23
		(ट्रैक्टर,अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खाते)	106	13.28	765	221.39	547	234.67	689	201.47	152	33.20	85.85
9		अकृषि ऋण सामान्य	1	8.56	0	1.00	1	9.56	1	5.65	1	3.91	59.10
10		ट्रैक्टर	18	11.44	31	14.44	31	25.88	27	14.72	18	11.16	56.88
11		सड़क परिवहन सामान्य	2	0.17	1	0.20	3	0.37	1	0.20	2	0.17	54.05
		महायोग	4822	323.13	6007	725.31	8006	1048.44	5034	692.93	4528	355.50	66.09

तालिका 6.9

छत्रसाल ग्रामीण बैंक

मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2005

जनपद :– महोबा समस्त

समस्त खाते (राशि लाखों में)

क0सं0	सेक्टर कोड	कियाकलाप	मांग	अतिदेय	चालू	मांग	योग		वसूली		अति देय		वसूली प्रतिशत
			खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	
1	ए	अल्प सिंचाई	871	47.51	1335	74.64	1537	122.15	1014	79.66	696	42.49	65.21
2	सी	कृषि मशीनीकरण	47	16.36	86	31.50	90	47.86	74	34.05	50	13.81	71.15
3	ई	पशुपालन/दुग्ध विकास	505	33.25	375	25.29	668	58.54	332	25.27	419	33.27	43.17
4	एफ	पशुपालन/मुर्गीपालन	6	0.17	4	0.08	6	0.25	3	0.14	3	0.11	56.00
5	जी	पशुपालन/अन्य	433	33.76	320	22.09	577	55.85	295	22.64	402	33.21	40.54
6	एच	मत्स्य पालन	7	0.50	60	4.06	64	4.56	51	3.48	19	1.08	76.32
7	के	अन्य कृषि ऋण	122	7.43	92	4.36	162	11.79	74	5.65	100	6.14	47.92
8	एल	अकृषि क्षेत्र/लघु उद्योग	221	17.83	95	6.49	245	24.32	126	12.98	149	11.34	53.37
9	एम	अकृषि क्षेत्र/अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	776	76.01	444	155.60	961	231.61	628	195.79	467	35.82	84.53
10	एन	फसली ऋण	998	243.43	5125	1367.56	5613	1610.99	4668	1312.86	1171	298.13	81.49
		महायोग	3986	476.25	7936	1691.67	9923	2167.92	7265	1692.52	3476	475.40	78.07
1	2 से 6	संग्राविका/एसजीएसवाई	1418	89.69	1000	55.26	1875	144.95	891	57.26	1202	87.69	39.50
2	12	स्पेशल कम्पोनेंट	445	27.45	346	15.09	589	42.54	315	16.62	376	25.92	39.07
3	13	एससी/एसटी	915	53.02	639	39.19	1222	92.21	622	35.71	867	56.50	38.73
4	14	महिलायें	296	17.32	305	23.32	477	40.64	260	21.71	295	18.93	53.42
5	16	अल्पसंख्यक	117	7.79	115	9.78	178	17.57	91	9.85	116	7.72	56.05
6		अल्प सिंचाई	515	27.27	878	48.75	1001	76.02	650	48.30	487	27.72	63.54
7		अकृषि/सीसी लिमिट	136	36.99	584	156.53	622	193.52	539	153.68	139	39.84	79.41
8		अन्य सामान्य कृषि ऋण	167	20.89	821	196.54	930	217.43	728	185.26	233	32.17	85.20
		(ट्रैक्टर,अल्प सिंचाई एवं सीसीएल खाते)	90	20.81	392	93.42	394	114.23	337	92.20	93	22.03	80.71
9		अकृषि ऋण सामान्य	11	2.68	385	110.33	393	113.01	329	107.45	22	5.56	95.08
10		ट्रैक्टर	18	11.11	45	24.05	47	35.16	39	22.93	19	12.23	65.22
11		सड़क परिवहन सामान्य	3	1.43	0	0.00	3	1.43	1	0.03	3	1.40	2.10
		महायोग	4131	316.45	5510	772.66	7731	1088.71	4802	751.03	3852	337.71	698.03

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

ग्राफ–4
वर्ष 2005 की वार्षिक कार्ययोजनाओं की
वसूली का प्रतिशत
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
वसूली प्रतिशत
65.21%
71.15%
43.17%
56.00%
40.54%
76.32%
47.92%
53.37%
84.53%
81.49%
A
C
E
F
G
H
K
L
M
N
वार्षिक कार्ययोजनाओं के सैक्टर कोड
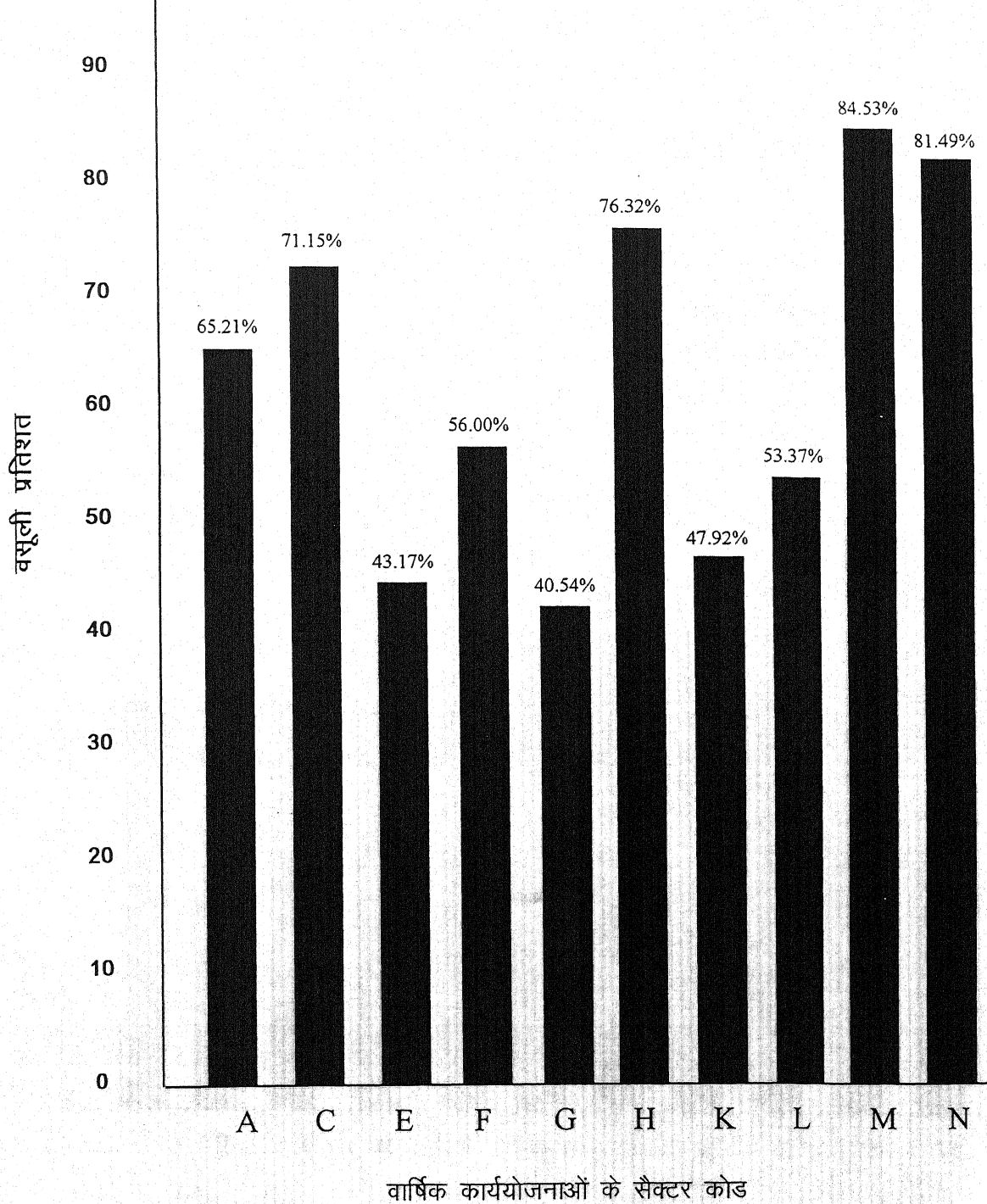
ग्राफ–4.1
वर्ष 2005 की शासकीय योजनाओं की
वसूली का प्रतिशत
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
वसूली प्रतिशत
39.50%
39.07%
38.73%
53.42%
56.05%
63.54%
79.41%
85.20%
80.71%
95.08%
65.22%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
कम – संख्या
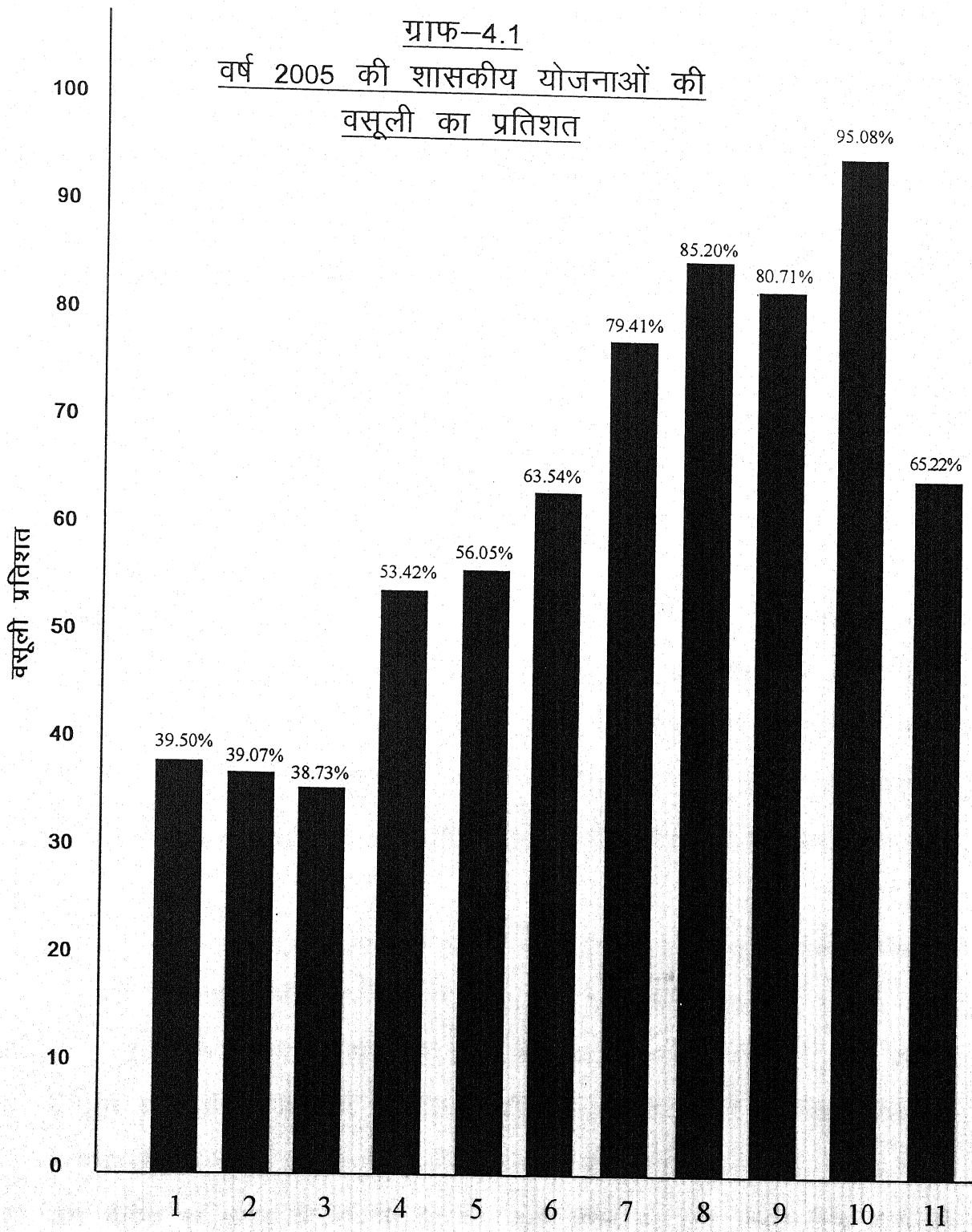
महोबा जनपद के छत्रसाल ग्रामीण बैंक मे विभिन्न प्रकार की योजनायें चलायी जा रही है जिनकी स्थिति विश्लेषण उपर्युक्त तीनों सारणियों में किया गया है ये सारणियां वर्ष 2003, 2004 व 2005 की स्थिति का विश्लेषण करती है वर्ष 2003 से 2005 मे इन्हे वार्षिक कार्य योजनाओं व शासकीय योजनाओं मे वर्गीकृत किया गया हैं इन योजनाओं को सेक्टर कोडों सहित दर्शाया गया है अल्प सिंचाई के अन्तर्गत 806 खातेऐसे थे जो पिछले बकाये थे जिनकी राशि 32.99 लाख रूपये थी चालू वर्ष में ये खाते 1,242 हो गये पिछले बकाये और चालू बकाये का योग करने पर 1584 खाते बकाया है जिनकी राशि 88.64 लाख रूपये है जिनमें 931 खाते वसूल हुए व 43.76 लाख की राशि वसूल की गयी है शेष बकाया खाते 879 और राशि 44.88 लाख रूपये शेष रह गयी है जो 49.37 प्रतिशत है इसी प्रकार से उपर्युक्त सारिणी में प्रत्येक योजनाओ की स्थितियों का वर्णन किया गया है।

उपर्युक्त सारिणी में बकाया वसूली प्रतिशत योजनावार दिया गया है जिनको दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2003 मे प्रथम स्थान पर फसली ऋण है जिनकी बकाया वसूली प्रतिशत 78.26 प्रतिशत है और शासकीय योजनाओं के तहत सबसे अधिक बकाया वसूली प्रतिशत अकृषि / सी सी लिमिट की है। और सबसे कम वसूली का प्रतिशत लघु उद्योगों का 17.43 प्रतिशत है व शासकीय योजनाओं में अकृषि ऋण सामान्य का 2.39 प्रतिशत है।

वर्ष 2004 मे प्रथम स्थान पर फसली ऋण की वसूली 79.92 है और सबसे कम मत्स्य पालन की है।

शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत सबसे अधिक वसूली प्रतिशत अकृषि/सी0सी0लिमिट का व सबसे कम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की वसूली का 33.56 प्रतिशत है।

वर्ष 2005 में सबसे अधिक वसूली अकृषि क्षेत्र/अन्य प्राथमिकता क्षेत्रो की 84.53 प्रतिशत है दूसरे स्थान पर फसली ऋण है। जिसका प्रतिशत 81.49 है। सबसे कम वसूली पशुपालन व अन्य कृषि की 40.54 प्रतिशत है शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत सबसे अधिक वसूली अकृषि ऋण समान्य की 95.08 प्रतिशत रही है। और दूसरे स्थान पर अन्य समान्य कृषि ऋणों की वसूली 85.20 प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर, अल्पसिचाई व सी0सी0एल0 आदि के लिए ऋण दिये जाते है। यदि हम सबसें कम वसूली की तरफ घ्यान दें तो इनमें सबसे कम वसूली

सड़क परिवहन सामान्य की है। जो कि 2.10 प्रतिशत है।

वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शर्ते

छत्रसाल ग्रामीण बैंक छोटे छोटे किसानों, ग्रामीणों व अन्य लोगों के लिए अनेक योजनाओं को चलाता है ताकि उपर्युक्त पिछड़े वर्ग के व अन्य श्रेणी मे आने वाले लोग इससे लाभान्वित हो सके आज के इस वर्तमान युग मे जहां कुछ लोगों ने इन सब चीजों का पूर्णतया अभाव है चूंकि छत्रसाल ग्रामीण बैंक का उद्देश्य पिछड़े व गरीब किसानों को उनके विकास हेतु सुविधायें दिलाना है लेकिन यदि उन्हें यह वित्तीय सुविधाये बिना किसी शर्त या प्रक्रिया के तहत दी जाये तो प्रत्येक कार्य में अव्यवस्था फैल जायेगी और यह सुविधा ईमानदार व सरल जीवन व्यतीत करने वाले नही उठा पायेगें क्योंकि इसके विपरीत लोगों का उन पर दबाव रहेगा। इसलिए हमारी सरकार ने इन सुविधाओ को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्ते रखी है यदि किसान उन शर्तो को पूरा करता है या उस पर खरा उतरता है तो यह सुविधा उसे प्रदान की जाती है और वह अपने संपूर्ण विकास के प्रति उन्मुख होता है।

समूह सहेली गैस योजना की शर्ते –

1. यह सुविधा सिर्फ उन्ही महिला समूहों के सदस्यों को प्राप्त होती है, जो कि प्रथम ग्रेडिंग मे उत्तीर्ण होकर सी सी एल प्राप्त कर चुके है तथा जिनके सी0सी0एल0 खाता नियमित चल रहे हो।

2. ऋण स्वीकृत करते समय शाखायें मुख्य कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

3. ऋण स्वीकृत करने से पूर्व शाखायें सुनिश्चित करें कि आवेदक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समस्त देयतायें नियमित चल रही है।

4. शाखायें ऋण राशि से प्राप्त किये गये गैस कनेक्शन प्रेशर कुकर तथा चूल्हे की रसीद की फोटो प्रति प्राप्त कर दस्तावेजों के साथ सुरक्षित रखें तथा ऋण राशि का सदुपयोग कराना सुनिश्चित करें।

5. गैस चूल्हा तथा कुकर आई0एस0आई0 मार्क का होना चाहिए।

6. गैस कनेक्शन तथा अन्य सहायक उपकरणों हेतु चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा

तथा कुकर खरीदने के लिए नकद भुगतान किया जाता है।

7. शाखा ऋण का नियमित फालोअप सुनिश्चित करना आदि।

छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नियम, छूट व शर्ते

छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत कुछ शर्ते व नियम है जो कि निम्नलिखित है –

1. कमजोर वर्ग के कृषकों कीं जोत सीमा 2.5 एकड़ सिंचित या 5.00 एकड़ असिंचित को सदस्यता शुल्क में पूरी सीमा तक छूट प्रदान की गयी है। अर्थात् इस श्रेणी के कृषक से मात्र प्रवेश शुल्क ही लिया जाता है तथा तीन वर्षो हेतु दी जाने वाली सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे।

2. अदा किया गया सदस्यता शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नही जाता है। कार्डधारक, कार्ड की वैधता समाप्ति के दो माह पूर्व इसके नवीनीकरण हेतु इसे उस शाखा को भेजेगा जहां उसका खाता है। यह नवीनीकरण भी तीन वर्षो की अवधि के लिए होता है।

3. प्रत्येक सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति और परिवार की कृषि, गैर कृषि और अन्य स्त्रोतों से आय से सम्बंधित आंकड़े बैंक को प्रस्तुत करेगा। यदि मांगे जाने पर डाटा प्रस्तुत नही किये जाते तो बैंक अपने विवेकानुसार कार्ड की नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकता है या कार्ड को रद्द कर सकता है।

कार्ड का प्रयोजन –

1. छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड बैंक की सम्पत्ति है और हस्तांतरणीय नही है। जारीकर्ता शाखा में इसे प्रस्तुत किये जाने पर सकारा जायेगा।

2. बैंक केवल अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताये आवेदन अस्वीकार कर सकता है।

3. आवेदक सेवा क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

4. कार्डधारक को चाहिए कि वह अपने पते में या पहले प्रस्तुत की गयी सूचना मे परिवर्तन होने की दशा में बैंक को लिखित रूप में अविलम्ब सूचना दे।

5. कार्ड के अन्तर्गत बैंक के प्रति समस्त बकाया तथा इससे सम्बंधित प्रासंगिक प्रभार कार्ड जारी कर्ता शाखा में कार्डधारक द्वारा रखे गये नकदी ऋण खाते को नाम लिखकर वसूल किये जाते है। वर्ष के 10 महीने में सीमा का आहरण अनुमत है। शेष दो महीनों के दौरान ब्याज सहित अवस्थित नामे अवशेषों को जमा करना होता है। कार्ड धारक इससे पहले भी चुकौती करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में उसकी सीमा की गयी चुकौती माह का निर्धारण स्थानीय फसल पद्धति को ध्यान मे रखकर किया जाता है। छत्रसाल किसान क्रेडिट कार्ड हेतु समस्त चुनौतियां जमा केवल कार्ड जारीकर्ता शाखा में की जायेगी।

6. नाम अवशेष पर ब्याज का परिकलन दैनिक उत्पाद आधार पर वार्षिक अंतरालों पर निम्नलिखित दर से परिपत्र दिया जाता है।

साख सीमा	वार्षिक ब्याज दर
रूपये 25,000/– तक	12.5 प्रतिशत
रूपये 25,001 से रूपये 1,00,000 तक	13 प्रतिशत

उक्त उल्लिखित ब्याज दरों में बैंक द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है और कार्डधारक इस प्रकार संशोधित ब्याज दर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा और हमेशा इसका अर्थ यह लगाया जायेगा कि कार्डधारक द्वारा भुगतान करने पर सहमति दी गयी और एतद् द्वारा प्रतिभूति है।

प्रतिभूति –

खाते में लेनदेन फसल / मवेशी / चारे, उर्वरक, कीटनाशक आदि के स्टाक कृषि मशीनरी एवं उपकरण / वर्तमान और भावी घरेलू सामान के दृष्टिबंधन एवं कृषि भूमि के द्वारा प्रतिभूति होगी।

कार्डधारक का बीमा –

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत सामान्य बीमा कं० की शाखा से प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक को रूपये 50,000 तक की राशि हेतु प्रत्येक कार्डधारक को बीमित कराया जाना अनिवार्य होता है। तीन वर्षो हेतु निर्धारत प्रीमियम राशि को 2:1 मे क्रमशः बैंक एवं कार्डधारक द्वारा वहन किया जाता है। प्रीमियम राशि में भविष्य में बीमा कम्पनी द्वारा

संशोधित किये जाने पर बैंक एवं कार्डधारक द्वारा 2:1 में वहन की जाती है। बीमा दावों का निस्तारण कार्ड धारक को उपलब्ध कराई गयी पॉलिसी के नियमों एवं शर्तो के अनुरूप होता है।

क्षेत्राधिकार –

सभी विवाद कार्ड जारी कर्ता शाखा के जिले के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

निबन्धनों और शर्तो में संशोधन –

बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से यदि आवश्यक समझे, तो बिना कोई कारण बताये इन नियमों से परिवर्तन संशोधन कर सकता है और ये परिवर्तन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे।

इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं से सम्बंधित शर्तो को उन योजनाओं के साथ किया गया है।

जनपद में वित्तीय सुविधा प्रदान किये गये अग्रिमों की वसूली का विश्लेषण

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा 1982 से लेकर सन् 2005 तक किसानों, पिछड़े वर्गो, व्यवसायियों, शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र/ छात्राओ महिला वर्गो अनुसूचित वर्गो आदि अन्य लोगों को अनेक वित्तीय सुविधाये प्रदान की गयी है अर्थात् अनेक प्रकार के ऋण व अग्रिम प्रदान किये गये है जो कि किन्ही शर्तो के तहत प्रदान किये गये है इन ऋणो एवं अग्रिमो की वसूली का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है।

कृषि व सरकारी योजनाओं के सम्बंध मे ऋण की वसूली –

ऋण की वसूली न आने पर सरकारी योजनाओं व कृषि में आर सी जारी की जाती है यह तहसील के माध्यम से अमीनो द्वारा वसूल की जाती है जिसमे जितनी राशि का वह कर्जदार होता है उतनी राशि के साथ वसूली का 10 प्रतिशत कलैक्शन चार्ज लिया जाता है जो तहसील के खाते में जमा होता है।

गैर सरकारी योजनाओं वाली राशियों की वसूली –

इनकी वसूली जमानतदारों से होती है यह कोर्ट के द्वारा उनकी सम्पत्तियों की नीलामी

करके की जाती है।

विभिन्न योजनाओं में वसूली की स्थिति –

1. किसान क्रेडिट कार्ड की वसूली की दर 80 प्रतिशत
2. स्पेशन कम्पोनेंट प्लान की वसूली की दर 30 से 40 प्रतिशत तक है।
3. ग्रुप लोनिंग में वसूली की दर 30 से 40 प्रतिशत है।
4. बाकी अन्य योजनाओं में वसूली की स्थिति 70 प्रतिशत तक है।

जिन योजनाओं की वसूली की स्थिति 50 प्रतिशत तक है।

वे योजनायें चल रही है उनकी स्थिति ठीक मानी जाती है और जिन योजनाओं के अन्तर्गत उनकी वसूली 30 से 40 प्रतिशत तक है वे योजनायें आगे कार्य नही कर पायेगी। इसका कारण है कि जिन योजनाओं के लिए ऋण लिया जा रहा है उसका उपयोग उन कार्यो के लिए नही किया जा रहा है जिससे उनकी वसूली स्थिति खराब है और जिन योजनाओं की वसूली 70 या 80 प्रतिशत चल रही है वे योजनायें सफल रही है और आगे भी ये अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करेगी।

तालिका 6.10

मांग, एकत्रीकरण, बकाया व वसूली खाता जून 2001

	मांग		योग एकत्रीकरण		बकाया		वसूली
MAHOBA	A/c	Amt.	A/c	Amt.	A/c	Amt.	Percentage
AJNAR	440	29.69	257	14.64	263	15.05	49.31%
B.LAMAURA	410	18.90	172	10.83	285	8.07	57.30%
B.KALA	463	26.35	254	13.77	209	12.58	52.26%
BENDO	585	45.67	205	25.55	460	20.12	55.94%
BHARWARA	307	24.32	214	16.29	187	8.03	66.98%
CHARKHARI	123	5.05	49	2.27	87	2.78	44.95%
F.BAZARIA	257	17.57	130	8.99	170	8.58	51.17%
GAHARA	302	15.48	119	5.28	255	10.20	34.11%
KHARELA	148	8.17	88	3.10	110	5.07	37.94%
KULPAHAR	351	16.40	213	10.68	228	5.72	65.12%
MAHOBA	318	16.53	165	7.00	216	9.53	42.35%
MAHOB KAN	596	37.23	184	18.63	453	18.60	50.04%
NANURA	417	16.24	150	6.84	292	9.40	42.12%
PANWARI	182	21.04	86	7.06	119	13.98	33.56%
RIWAI	393	25.44	100	5.78	329	19.66	22.72%
SAURA	506	34.65	188	17.01	388	17.64	49.09%
SIJAHRI	320	21.27	196	14.93	191	6.34	70.19%
KABRAI	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL	6118	380.00	2770	188.65	4242	191.35	49.64%

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 6.11

छत्रसाल ग्रामीण बैंक
मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति, यथा जून 2002
(केवल समस्त खाते)

जनपद महोबा

क0 सं0	शाखा	महायोग						वसूली प्रतिशत	अपलिखित राशि	शुद्ध वसूली प्रतिशत	अन्तर प्रतिशत
		मांग		वसूली		अतिदेय					
		खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि				
1.	अजनर	549	64.92	402	45.74	248	19.18	70.46	0.31	69.98	0.48
2.	बछेछर लमौरा	650	91.30	467	67.89	310	23.41	74.36	1.11	73.14	1.22
3.	बम्हौरी कलां	453	28.77	261	15.67	192	13.10	54.47	0.62	52.31	2.16
4.	बेंदों	646	70.48	395	45.89	329	24.59	65.11	0.95	63.76	1.35
5.	भरवारा	435	69.29	357	55.38	206	13.91	79.92	0.10	79.78	0.14
6.	चरखारी	161	24.48	112	14.16	101	10.32	57.84	0.30	56.62	1.23
7.	फतेहपुर बजरिया	289	40.05	181	33.58	134	6.47	83.85	0.21	83.32	0.52
8.	गहरा	395	46.08	304	37.06	149	9.02	80.43	0.77	78.75	1.67
9.	खरेला	148	12.09	113	7.14	84	4.95	59.06	0.23	57.15	1.90
10.	कुलपहाड़	449	47.38	363	40.56	169	6.82	85.61	0.76	84.00	1.60
11.	महोबा	379	41.67	305	33.75	160	7.92	80.99	0.32	80.23	0.77
12.	महोबकंठ	764	106.72	522	74.67	316	32.05	69.97	3.00	67.16	2.81
13.	ननोरा	452	43.73	317	33.71	214	10.02	77.09	2.09	72.31	4.78
14.	पनवाड़ी	360	66.21	197	35.27	201	30.94	53.27	0.32	52.79	0.48
15.	रिवई	423	61.13	281	33.56	280	27.57	54.90	1.18	52.97	1.93
16.	सैरा	588	59.60	399	40.70	273	18.90	68.29	2.64	63.86	4.45
17.	सिजहरी	390	40.74	331	36.74	109	4.00	90.18	1.13	87.41	2.77
18.	कबरई	64	18.26	62	17.92	9	0.34	98.14	0.00	98.14	0.00
	महायोग	7645	932.90	5369	669.39	3484	263.51	71.75	16.04	70.03	1.72

मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2002

	जालौन	26624	2450.96	18872	1685.30	12316	765.66	68.76	131.74	63.39	5.38
	हमीरपुर	16890	1675.99	10722	1008.17	8614	667.82	60.15	71.41	55.89	4.26
	महोबा	7645	932.90	5369	669.39	3484	263.51	71.75	16.04	70.03	1.72
	महायोग	51159	5059.85	34963	3362086	24414	1696.99	66.46	219.19	62.13	4.33

तालिका 6.12

छत्रसाल ग्रामीण बैंक
मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति, यथा जून 2003
(केवल समस्त खाते)

जनपद महोबा

क0 सं0	शाखा	महायोग						वसूली प्रतिशत 2003	वसूली पतिशत June 2002
		मांग		वसूली		अतिदेय			
		खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि		
1.	टजनर	612	75.54	434	53.01	263	22.53	70.17	70.46
2.	बछेछर लमौरा	643	103.50	222	41.67	435	61.83	40.26	74.36
3.	बम्हौरी कलां	335	24.18	167	8.18	267	16.00	33.83	54.47
4.	बेंदों	529	72.22	313	53.56	276	21.66	71.20	65.11
5.	भरवारा	538	90.80	422	65.54	223	25.26	72.18	79.92
6.	चरखारी	274	58.67	169	41.26	135	17.41	70.33	57.84
7.	फतेहपुर बजरिया	292	50.58	173	38.72	142	11.86	76.55	83.85
8.	गहरा	379	57.36	250	44.10	129	13.26	76.88	80.43
9.	खरेला	140	17.52	102	13.37	64	4.15	76.31	59.06
10.	कुलपहाड़	435	70.68	311	59.93	178	10.75	84.79	85.61
11.	महोबा	317	43.04	172	31.96	166	11.08	74.26	80.99
12.	महोबकंठ	649	131.75	343	83.39	306	48.36	63.29	69.97
13.	ननोरा	399	52.66	246	36.91	208	15.75	70.09	77.09
14.	पनवाड़ी	347	74.27	272	52.23	130	22.04	70.32	53.27
15.	रिवई	427	67.23	190	30.76	281	36.47	45.75	54.90
16.	सैारा	473	61.29	309	40.21	228	21.08	65.61	68.29
17.	सिजहरी	371	62.27	295	55.32	121	6.95	88.84	90.18
18.	कबरई	122	33.55	105	30.36	29	3.19	90.49	98.14
	महायोग	7282	1150.11	4495	780.48	3581	369.63	67.86	71.75
	मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति यथा जून 2003								वसूली प्रतिशत June 2002
	जालौन	20.096	3221.50	12190	2286.96	10190	934.54	70.99	68.76
	हमीरपुर	14.929	2433.72	8446	1618.27	8485	815.45	66.49	60.15
	महोबा	7.282	1150.11	4495	780.48	3581	369.63	67.86	71.75
	महायोग	42307	6805.33	25131	4685.71	22256	2119.62	68.85	66.46

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

उर्पयुक्त तीनों सारणियों में जनपद महोबा की शाखावार मांग, एकत्रीकरण का विश्लेषण वर्ष 2001 से वर्ष 2003 तक किया गया है इन सारणियों में शाखावार कुल वसूली का प्रतिशत दिया गया है। वर्ष 2001 में सबसे अच्छी वसूली सिजहरी शाखा की है जो 70.19 प्रतिशत है यह कबरई ब्लाक के अन्तर्गत आती है और सबसे कम वसूली प्राप्त करने वाली शाखा रिवई है वर्ष 2001 में 18 शाखायें है जिनकी कुल वसूली 49.64 प्रतिशत है।

वर्ष 2002 में शुद्ध वसूली की सबसे अच्छी स्थिति कबरई की 98.14 प्रतिशत है जिसका अन्तर शून्य है और सबसे कम वसूली प्रतिशत बम्हौरी कला की है जिसका अपलिखित राशि से मूल्यांकन करने पर 2.16 प्रतिशत का अन्तर है इसवर्ष की शुद्ध वसूली 70.03 प्रतिशत रही इसकी तुलना यदि हम जालौन, हमीरपुर से करे तो महोबा की स्थिति सबसे अच्छी है जो कि 70.03 प्रतिशत है और दूसरे नम्बर पर जालौन है जो कि 63.397 की वसूली प्रदर्शित करता है। हमीरपुर की वसूली का प्रतिशत 55.99 प्रतिशतहै।

अतः कुल छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वसूली का प्रतिशत वर्ष 2002 मे 62.13 प्रतिशत रहा।

अब हम वर्ष 2003 का अवलोकन करने पर पाते है कि सबसे अच्छी वसूली प्रतिशत इस वर्ष भी कबरई की रही है और सबसे कम पनवाड़ी की जो कि 53.27 प्रतिशत है। कुल प्रतिशत 71.75 प्रतिशत रहा।

2003 में यदि हम जालौन हमीरपुर व महोबा की स्थिति देखें तो यह प्रतिशत क्रमशः 68.76, 60.15 71.75 प्रतिशत रहा इस वर्ष भी महोबा जनपद की स्थिति काफी अच्छी है।

वर्ष 2003 में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वसूली का प्रतिशत 66.46 प्रतिशत रहा।

तालिका 6.13
वसूली प्रतिशत – शाखावार

जनपद महोबा

क0 सं0	शाखा	जून 1998 वसूली प्रतिशत	जून 1999 वसूली प्रतिशत	जून 2000 वसूली प्रतिशत	जून 2001 वसूली प्रतिशत	जून 2002 वसूली प्रतिशत	जून 2003 वसूली प्रतिशत
1.	अजनर	61.39	43.00	38.67	49.31	70.46	70.17
2.	बछेछर लमौरा	54.06	61.46	55.69	57.30	74.36	40.26
3.	बम्हौरी कलां	37.81	47.93	81.15	52.26	54.47	33.83
4.	बेंदों	48.37	28.70	52.24	55.94	65.11	71.20
5.	भरवारा	73.80	56.29	70.17	66.98	79.92	72.18
6.	चरखारी	81.32	81.66	59.20	44.95	57.84	70.33
7.	फतेहपुर बजरिया	69.34	57.78	61.58	51.17	83.85	76.55
8.	गहरा	36.32	43.26	46.83	34.11	80.43	76.88
9.	खरेला	49.15	50.77	52.77	37.94	59.06	76.31
10.	कुलपहाड़	65.42	31.81	62.46	65.12	85.81	84.79
11.	महोबा	52.62	36.25	40.01	42.35	80.99	74.26
12.	महोबकंठ	55.52	66.87	50.46	50.04	69.97	63.29
13.	ननोरा	33.33	47.33	51.21	42.12	77.09	70.09
14.	पनवाड़ी	38.75	46.50	42.22	33.56	53.27	70.32
15.	रिवई	54.80	46.96	53.59	22.72	54.90	45.75
16.	सैरा	41.96	32.36	30.13	49.09	68.29	65.61
17.	सिजहरी	67.89	64.29	58.07	70.19	90.18	88.84
18.	कबरई	–	–	#DIV/0!	–	98.14	9049
	महायोग	51.80	50.95	49.87	49.64	71.75	67.86
	ज्नपद–जालौन	30.79	31.80	37.18	0.00	68.76	70.99
	ज्नपद–हमीरपुर	32.89	33.46	34.07	33.04	60.15	66.49
	ज्नपद–महोबा	51.80	50.95	49.87	49.64	71.75	67.86
	महायोग			41.09	41.19	66.46	70.14

उर्पयुक्त सारिणी में जून 1998 से 2003 की वसूली का जो प्रतिशत दिया गया है उसके अन्र्तगत सबसे अच्छी स्थिति वर्ष 2002 की रही जिसमें 71.75 प्रतिशत तक की वसूली की गयी । जो कि महोबा की है।

विभिन्न योजनाओं की वसूली का प्रतिशत वर्ष 2005 तक पिछले खण्ड में दर्शाया जा चुका है ।

स्त्रोत–छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 6.14

DISTT.MAHOBA		31-03-04		31-03-05		FRESH NPA		NPA CASH RECOV.DURING 2004-05
SN	BRANCH	NPA-TOTAL	PROV.	NPA-TOTAL	PROV	A/C	AMT	
1.	AJNAR	2036647.25	526301	960631.60	434434	3	47735.00	1123750-65
2.	B.LAMAURA	5441926.00	955574	4742851.00	1047748	58	1443070.00	2084577.00
3.	BENDO	2290670.00	604000	1897398.00	938175	7	122725.00	515997.00
4.	BHARWARA	1912944.75	327438	1397018.00	307430	25	600879.00	1089966.00
5.	CHARKHARI	1075896.50	159630	906274.00	189013	31	388217.00	547959.00
6.	F.BAJARIA	772794.00	234919	443057.00	218320	18	138763.00	468500.00
7.	GAHARA	3862054.46	1186305	3492573.31	1618922	21	233218.00	501102.40
8.	KHARELA	443240.00	269551	159507.00	89202	1	12370.00	155604.00
9.	KULPAHAD	866511.00	216288	478327.00	149313	19	213747.00	515471.00
10.	MAHOVA	635248.00	360896	1153060.45	449572	35	686265.00	161380.55
11.	M.KANTH	4109435.00	701671	2895496.00	1093457	4	74930.00	1283645.00
12.	NANAURA	1813659.35	374963	1279157.80	443396	18	237181.00	693528.55
13.	PANWARI	1981413.00	607624	1199099.00	365207	13	167828.00	815001.00
14.	REWAI	4591263.00	871905	3449944.00	1048211	14	574551.00	1686022.00
15.	SAURA	1103106.00	425055	1110629.00	416472	30	313147.00	268879.00
16.	SIJAHRI	751604.55	181143	582708.55	193059	9	195193.00	340654.00
17.	KABRAI	462935.00	70748	193801.00	123598	0	0.00	269134.00
	TOTAL	**34151347.86**	**8074011**	**26341532.71**	**9125529**	**306**	**5449819.00**	**12521171.15**
	GRAND TOTAL	200055909.74	73070490	161092915.55	698662935	1551	##########	55548088.31

स्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका 6.15

Year - 2004-2005

S,No.	NPA Code	A/C	Out-standing	S.R.F/DICGC	Secured	Un-secured	Provision
1.	M	11385	337567374.70	7485522.00	292610966.35	37470886.35	819717
2.	SS	306	5449819.00	428963.00	4581640.00	439216.00	502086
3.	D1	700	11626852.30	727266.00	10748338.30	151248.00	2300916
4.	D2	431	4320640.70	266683.00	3967499.70	86458.00	1276708
5.	D3	455	3729699.30	172150.00	3434141.30	123408.00	2968827
6.	L	181	1214521.41	11000.00	815646.71	387874.70	1203521
	TOTAL	13458	363908907.41	9091584.00	316158232.36	38659091.05	9071775

स्त्रोत– छत्रसाल ग्रामीण बैंक वार्षिक प्रतिवेदन

उपर्युक्त सारिणी में बैंक की गैर निष्पादक सम्पत्तियों का वर्ष 2004 व 2005 के सन्दर्भ में विश्लेषण किया गया है जो सम्पत्तियां किसी भी खाते में 90 दिन तक अगर वसूल नही हो पाती तो वह खाता एन पी ए मे जाता है और बैंक उन पर ब्याज नही लगाता। कृषि के सम्बंध में एक साल तक की अवधि है। इस सारिणी में महोबा जनपद की शाखावार एन पी ए की राशि को दर्शाया गया है और प्रावधान की रकम के अन्तर्गत इसका प्रावधान बैंक द्वारा किया जाता है। महोबा जनपद में वर्ष 2004 मे गहरा की शाखा की सबसे कम एन पी ए है जिनके अन्तर्गत बैंक को 269551 लाख रूपये का प्रावधान करना हैवर्ष 2004 मे एन पी ए का कुल योग रूपये 34151347.86 था जिसमे बैंक को 8074011 का प्रावधान करना था और वर्ष 2005 मे कुल गैर निष्पादक सम्पत्तियां 26,341,532.71 थी जिसमें बैंक को 9125529 का प्रावधान करना है एन पी ए की राशि 2004 की अपेक्षा कम है जो कि 7809815.15 का अन्तर दर्शाती है जिससें प्रदर्शित होता है कि इस वर्ष वसूली 2004 की अपेक्षा अच्छी रही परन्तु इनके प्रावधानों में बढ़ोत्तरी हो गयी महोबा जनपद में कुल 306 खातों में शुद्ध गैर निष्पादक सम्पत्तियों की राशि 5449819.00 है 2004 के दौरान गैर निष्पादक सम्पत्तियो की रोकड़ वसूली खरेला की 155604.00 है और सबसे अधिक वसूली बछेछर लमौरा की 2084577 लाख रूपये है कुल वसूली 55548088.31 करोड़ रूपये है।

दूसरी सारिणी में गैर-निष्पादक सम्पत्तियों के कोड व खाते दिये गये है इसमें एक नम्बर के स्टैण्डर्ड खाते कहलाते है ये खाते ठीक माने जाते है दूसरे नम्बर के खाते 1 साल पुराने है तीसरे नम्बर पर 2 साल पुराने खाते आते है चौथे नम्बर पर 2 से 3 साल पुराने खाते आते है पांचवे नम्बर पर 5 वर्ष पुराने खाते आते है और छठवे नम्बर के खाते हानि वालेखाते की श्रेणी मे आते है अतः 181 खाते ऐसे है जो कि हानि मे जा चुके है और जिनके लिए 12,03521 का प्रावधान करना है।

वित्तीय सुविधा प्रदान करने में आने वाली समस्यायें एवं उनको दूर करने के लिए सुधार हेतु सुझाव –

भारतीय किसान साल दर साल उधार लेता है परन्तु वह उनका भुगतान नहीं कर पाता क्योंकि या तो ये ऋण बहुत ही अधिक होते है या उसका कृषि उत्पादन इतना

अधिक नही होता कि वह ऋण का भुगतान कर सके परिणामतः किसान का ऋण बढता चला जाता है इसे हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता में आने वाली समस्या कह सकते है भारत मे यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि "भारतीय किसान ऋण मे जन्म लेता है ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण मे जीवन त्याग देता है।" हम इस समस्या की सीमा कारणों एवं सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए किये गये उपायों पर विचार करेगें । यदि हम वित्तीय सुविधा प्रदान करने में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें तो सबसे पहली समस्या है –

1. किसानों का अशिक्षित होना

2. अशिक्षित होने के कारण ऋण लेने मे, ऋण की शर्तो का पालन करने में प्रपत्रों को सम्मिलित करने उनको सत्यापित या प्रमाणित करवाने में उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।

महोबा जनपद में कृषि उत्पादन में समस्यायें –

1. जनपद में सिंचाई की विशेष समस्या है रवी में मात्र 91100 है0 क्षेत्र में सिंचित दशा में खेती होती है जबकि शेष क्षेत्रफल वर्षा पर आधारित है। आच्छादन के सापेक्ष मात्र 41.69 प्रतिशत सिंचित दशा में खेती रवी मे की जाती है खरीफ की खेती पूर्ण तथा वर्षा आधारित है।

2. जनपद में कृषि योग्य बंजर भूमि 13092 हे0 है तथा कृषि अयोग्य भूमि 10304 हे0 है।

3. जनपद की भूमि मृदा कटाव से ग्रसित है जिसके कारण भूमि एवं जल संरक्षण की समस्या अति गंभीर है।

4. बेसल ड्रेसिंग के रूप मे उर्वरकों का कम प्रयोग होता है तथा सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग भी कम होता है। उर्वरकों की खरीफ एवं रबी में खपत प्रति0 हे0 क्रमशः 16.25 प्रति हे0 है।

5. जनपद में केवल दो राजकीय नलकूप है चरखारी विकास क्षेत्र में एक एवं कबरई विकास खण्ड में एक नलकूप है।

6. खरीफ फसलें सामान्यतः वर्षा पर ही आधारित है।

7. जनपद में खेती वर्षा पर आधारित् होने के कारण इस क्षेत्र हेतु प्रजातियों की आवश्यकता

है जो कि कम पानी मे अधिक उपज दे सकें तथा फसल की अवधि कम हो जिससे दो फसली क्षेत्र में वृद्वि की जा सके।

8. जनपद में वर्तमान स्थिति में पशुधन वृद्धि के बिना कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि करना सम्भव नही है। क्षेत्र में दुधारू पशुओं की हालत बेहद चिन्ताजनक है। समूचे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर पशु सुधार कार्यक्रम लागू किया जाय तथा इसके साथ-साथ चरागाहों का विकास भी जरूरी है।

9. जनपद में शुष्क उद्यानीकरण एवं वृक्षारोपण की प्रबल संभावनाओं के कारण अभी तक अपेक्षित स्तर तक इस क्षेत्र में प्रगति सम्भव नही हो पायी है। अतः नीबू प्रजाति के फलदार पौधे जैसे–संतरा, मुसम्मी एवं इसके अतिरिक्त आंवला बेर, जामुन, करौंदा आदि के फलदार पौधे बगीचों के जरिये लगाये जाये तथा वृहद वृक्षारोपण किया जाये जिससे नमी का संरक्षण किया जा सके मृदा का कटाव रोका जा सके।

10. जनपद में सब्जी की खेती का आच्छादन अत्यन्त कम है जिसके कारण आम जनता को दैनिक पोषण आहार एवं भोज्य आदतो में तत्वों का सन्तुलित समावेश नही होता जनपद में मिर्च टमाटर बैगन सौंफ एवं धनिया की खेती सम्बंधी विशेष योजनाओं को चलाये जाने की आवश्यकता है।

11. भूमि एवं सिंचाई के कारण खेती अत्यन्त पिछड़ी है तथा अन्य स्थानों के सापेक्ष कृषि तकनीकी में भिन्नता है यद्यपि भूमि में उत्पादन क्षमता विद्यमान है। परन्तु उन्नति तकनीकी न अपनाये जाने के कारण कृषि उत्पादन में जनपद अत्यन्त पिछड़ा है।

12. जनपद में नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुँचाने मे किसान सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जनपद मे 37 के सापेक्ष 37 किसान सार्थक कार्यरत है तथा जिसके द्वारा पूरे जनपद में कृषि तकनीकी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था परन्तु उन्हे शासनादेशो के अनुसार ग्रामीण पंचायत विकास अधिकारी के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया। जिससे कृषि नवीन तकनीकी का प्रचार प्रसार बाधित है।

13. जनपद में मृदा परीक्षण प्रयोगशालानही है अतः मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की आवश्यकता है।

14. खरीफ में खपतवारों की अधिकता के कारण खरीफ की फसलों का उत्पादन बहुत ही कम प्राप्त होता है। अतः फसलों के लिए तृणनाशक पर 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया जाये तथा कृषि रक्षा इकाइयों पर लाखों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी।

15. सोयाबीन एवं मूंगफली की कम अवधि शीघ्र पक कर अधिक उत्पादकता देने वाली प्रजातियां विकसित की जाये।

अतः उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु महोबा जनपद की छत्रसाल ग्रामीण बैंको में कृषि से सम्बंधित समस्याओं पर विचार करके इनका समाधान करना चाहिए। जिन चीजों की यहां आवश्यकता है जब तक उनकी पूर्ति नही होगी ये समस्यायें हमेशा बनी रहेगी।

वित्तीय सुविधा प्राप्त करने में आने वाली अन्य सामान्य समस्यायें

1. ग्रामीण बैंको की शाखाओं में वृद्धि तो हुयी लेकिन जरूरत मन्द ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्धता की स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

2. ग्रामीण बैंको की दयनीय स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें केवल एक कर्मचारी है तथा नियंत्रण की कोई व्यवस्था नही है।

3. इन बैंको में प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नही है तथा उन्हें ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नही था।

4. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए गरीबों को ऋण दिये तो जाते है लेकिन ऋण की वसूली ठीक ढंग से नही हो पाती है।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के हाथो मे होता है अर्थात वित्तीय स्त्रोतो के लिए ग्रामीण बैंक को निर्भरता सरकार पर होती है।

6. कृषि विस्तार एजेंसियों और क्षेत्रीय बैंको में तालमेल का अभाव पाया जाता है जिसके कारण कर्जदारों की आय बढ़ती है।

7. बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली जमाराशि की मात्रा काफी कम है।

8. बैंको पर ऋण वितरण के सम्बंध मे दबाव होता है कि वे निश्चित समय मे ही निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करे जिसके कारण बैंक ऋण पाने योग्य लोगों का चुनाव ठीक ढंग से नही कर पाता है राजनीतिक दबाव के कारण ऋण वितरण प्रक्रिया में स्वामित्व मानकों की

प्रायः अवहेलना की जाती है।

9. ग्रामीण बैंको द्वारा कृषकों को ऋण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर दिया गया है।

सुझाव –

1. केवल संस्थागत स्त्रोतों से ही ऋण उपलब्धता होना चाहिए गैर संस्थागत स्त्रोंतो पर ऋण सम्बंधी निर्भरता पूर्णतया समाप्त होनी चाहिए संस्थागत ऋणों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि धनी और निर्धन दोनों प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके इसके द्वारा कृषि कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ाना चाहिएं।

2. छत्रसाल ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों का प्रबंध व संचालन प्रशिक्षित निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए जिसमें संस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।

3. बैंको द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए किसानों के विभिन्न वर्गो के लिए ब्याज की अलग अलग दरें होनी चाहिए।

4. छोटे व सीमान्त किसान और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार की ऋण सुविधाये उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।

5. ग्रामीण बैंको को अपनी अधिशेष धनराशि की वैधानिक सरलता अनुपात की अनिवार्यता के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियों मे निवेश करने की प्रतिबद्धता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

6. ग्रामीण बैंको को भी व्यवसायिक बैंको की तरह सभी प्रकार के बैकिंग व्यवसाय मे शामिल होने की छूट होनी चाहिए।

7. बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देते समय जमानत देने पर अधिक जोर न दिया जाये बल्कि इस बात पर ध्यान रखा जाये कि ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।

अध्याय सप्तम

निष्कर्ष समस्यायें एवं सुझाव
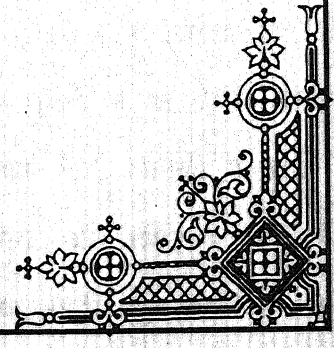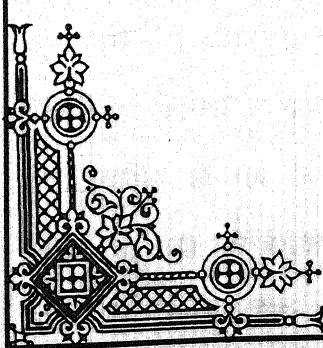
अध्याय–सप्तम
निष्कर्ष समस्यायें एवं सुझाव

देश के आर्थिक विकास में बैकिंग पद्धति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे आधुनिक समाज की आज कल्पना भी नही की जा सकती है जिसमें संस्थायें न हो उन्नत देशों में मुद्रा बाजार का आधार स्तम्भ बैकिंग संस्थायें होती है।

भारत का संपूर्ण आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र के कुशल क्रियान्वयन एवं प्रगति पर निर्भर करता है और कृषि क्षेत्र का विकास कृषकों एवं ग्रामीण जनता को मिलने वाली साख सुविधाओं पर होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का एक मात्र उद्देश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी अभाव से ग्रस्त है उत्तम किस्म के बीज रासायनिक खाद्य अच्छे औजार तथा कषि उत्पादकों के लिए विपणन सुविधायें कृषि उद्योग की प्रमुख आवश्यकतायें है इन सभी आवश्यक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है जिसका भारतीय कृषकों में सर्वथा अभाव है। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की ऋण सम्बंधी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए एक नयी योजना प्रारम्भ की इस योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीणों की प्रगति अपनी स्थापना से लेकर अब तक उत्साह वर्धक रही है यदि आंकड़ो के आधार पर देखा जाये तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की सेवा के विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है भारत सरकार ने ये बेंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के उपबन्धों के अनुसार स्थापित किये है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में केवल पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये और दिसम्बर 1975 में 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गये जिनकी 17 शाखायें खुल गयी जो धीरे धीरे बढ़कर 1976 मे 19 ग्रामीण बैंक हुये जिनकी 112 शाखायें हो गयी जिसमे 94 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रो में खोली गयी। यह संख्या बढ़कर 1980 में 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो गये दिसम्बर 1985 में बढ़कर 188 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनकी शाखायें 12138 हो गयी जो बढ़कर 1987 मे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गये। और 1987 के बाद कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नही खोला गया लेकिन शाखाओं की संख्या बढ़ती गयी जो मार्च 1995

में बढ़कर 14506 हो गयी मार्च 1997 में घटकर 14406 शाखाये हो गयी। जिसमें ग्रामीण शाखाये 12.003 थी जिनका 82.7 प्रतिशत था और मार्च 1997 के बाद इनकी कोई शाखा नही खोली गयी।

वर्तमान में भारत सरकार की अधिसूचना दिनाँक 1 मार्च 2006 को भारतवर्ष के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयन उनके प्रवर्तक बैंको के साथ कर दिया गया है। और वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सख्या 28 रह गयी है।

एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि वह शाश्वत उत्तराधिकारी तथा सामान्य मुद्रा वाला प्रथम निर्गमित निकाय होते हुए भी उस वाणिज्य बैंक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है जो उसकी स्थापना से प्रस्तावक का प्रायोजक होता है। वाणिज्य बैंक के आवेदन करने पर जब कोई केन्द्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है तो वह उन सभी सीमाओं का भी उल्लेख करती है जिनके भीतर उस ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है ऐसे अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर ही किसी भी स्थान पर वह ग्रामीण बैंक अपनी शाखाये एजेंसियां खोल सकता है।

ग्रामीण बैंक सामान्य बैकिंग कारोबार करता है अर्थात् बैकिंग का वह काम काज जिसकी परिभाषा बैकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 ख में दी गयी है। ग्रामीण बैंक उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा एक में वर्णित काम काजों को करता है ग्रामीण बैंक निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है।

1. कृषि कार्यो या कृषि प्रयोजनों या कृषि से सम्बंधित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को प्रथक–प्रथक अथवा समूह में और सहकारी समितियों को जिनमें विपणन सम्पत्तियां कृषि परिष्करण समितियों या कृषक समितियां सम्मिलित है ऋण तथा अग्रिम धनराशियाँ प्रदान करता है। ताकि वे ग्राम क्षेत्रों मे कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग विकसित कर सकें।

2. विशेषकर शिल्पियां लघु उद्यमियों या कम संसाधन वाले ऐसे व्यक्तियों को जो ग्रामीण बैंक के अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर व्यापार वाणिज्य या उद्योग या अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगे हों बैंक ऋण और अग्रिम धनराशियां देता है इस प्रकार इन बैंको की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधार कर्ताओं की आवश्यकता पूरी करना है। इनके द्वारा प्रदान

सहायता का काफी बड़ा भाग कमजोर वर्ग के लोगों को मिलता है।

प्रत्येक मामलों में मार्ग निर्देशन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों से होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष होता है 2 निदेशकों का मनोनयन केन्द्र सरकार करती है व एक निदेशक का मनोनयन वह व्यक्ति करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक में अधिकारी होता है। दो-दो निदेशकों की नियुक्ति प्रवर्तक बैंको के अधिकारियों द्वारा व दो-दो निदेशको का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और एक निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी को चुना जाता है इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 9 सदस्यों का संचालक बोर्ड होता है। और इन सभी की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष पूर्व पहले की जाती है। केन्द्रीय सरकार के गजट के अनुसार घोषित तिथि को या 31 दिसम्बर को अपनी पुस्तकें व आर्थिक चिट्ठे को बन्द करके अंकेक्षण करवाना होता है।

इस प्रकार की अधिकृत पूँजी 50 पचास करोड़ रूपये है इसकी समस्त समादत्त पूँजी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी है। रिजर्व बैंक का एक डिप्टी गर्वनर इस निगम का अध्यक्ष होता है।

प्रारम्भ में प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये थी जो 100.00 एक सौ रूपये के एक लाख अंशों में विभाजित थी इस पूंजी का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार ने 15 प्रतिशत सम्बंधित राज्य सरकार ने तथा 35 प्रतिशत प्रायोजक बैंक द्वारा प्रदान किया गया था।

अब बैंक की अधिकृत पूँजी पांच करोड़ रूपये तथा प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रूपये है। ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल उस निर्गमित पूंजी को रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंक से परामर्श कर तथा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर समय समय पर बढ़ा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन, मध्यमकालीन, व दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये जाते है। यह बैक अन्य बैंको की भांति प्राथमिक व गौण कार्य करके जन सामान्य को अनेक सुविधायें प्रदान करता है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक 30 मार्च 1982 को स्थापित हुआ था और बैंक को इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रवर्तित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होने का गौरव प्राप्त है। बैंक के कार्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश

राज्य के झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डलों के अधीन 3 जनपद जालौन हमीरपुर व महोबा आते है। बैंक का प्रधान कार्यालय राठ रोड उरई (जनपद जालौन का मुख्यालय में है) बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में सम्मिलित है।

वर्तमान अध्ययन में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वित्तीय स्थिति एवं महोबा जनपद में कृषि एवं ग्रामीण विकास में इस बैंक के योगदान को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है । वित्तीय स्थिति का आंकलन बैंक के चिट्ठे पर आधारित वित्तीय अनुपनातों के विश्लेषण पर आधारित है । प्रथमतः यह अध्ययन सन् 1998–99 से 2005–06 तक के आंकड़ों के अन्तर विभागीय विश्लेषण पर आधारित है । वित्तीय विश्लेषण वित्तीय अनुपातों पर आधारित है । यथा चालू अनुपात, स्वामित्व अनुपात, नकद समता अनुपात, पूंजी दर प्रत्याय अनुपात, स्थायी सम्पत्तियों का स्वामित्व कोषों से अनुपात, चालू सम्पत्तियों का स्वामित्व कोषों से अनुपात, तरलता या त्वरित अनुपात इत्यादि । इस अध्ययन में छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा के मुख्य कार्यालय जोकि उरई (जालौन) में स्थित है, द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रकाशित आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से बैंक का आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ–हानि खाते के आधार पर अध्ययन सम्पन्न किया गया है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ की अध्ययन विधि मे अनुपात विश्लेषण एवं अन्य तकनीकों की सहायता ली गयी है। प्रस्तुत अध्यन के मुख्य निष्कर्ष, अध्ययन विधि की सीमाओं एवं भावी शोध के लिए कतिपय प्रमुख सुझाव प्रस्तुत ग्रन्थ के इस अध्याय में सम्मिलित किये गयें है।

महोबा जनपद के कृषि एवं ग्रामीण विकास में योगदान के बारे में छत्रसाल ग्रामीण के योगदान के रूप का निश्चित रूप से निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना सम्भव नही है। क्योंकि ऐसे अध्ययनों की भी अपनी सीमाएं होती है। तथा अनेंक परिर्वतनशील विविध तत्वों या घटकों प्रभाव कृषि एवं ग्रामीण विकास व बैंक कार्यप्रणाली पर पड़ता है। क्योंकि उपलब्ध ऑकड़े वास्तविकता के धरातल से कई मायनों में मेल नही खाते है। प्रस्तुत शोधग्रन्थ इस सामान्य सिद्धान्त का अपवाद नही है बल्कि प्रस्तुत ग्रन्थ में महोबा जनपद के कृषि एवं ग्रामीण विकास में छत्रसाल ग्रामीण बैंक के विगत योगदान के रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। तथा उसके भावी विकास में बैंक का क्या योगदान हो सकता है? साथ ही बैंक समक्ष कौन-कौन सी कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है। जो कि बैंक के विकास, तथा जनपद के विकास में अवरोधक है। इसका वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में समाहित करने का प्रयास किया गया है यद्यपि निष्कर्ष वस्तुनिष्ठता पर आधारित है तथा पर्याप्त रोचक एवं भावी नीति निर्धारण हेतु उपयोगी सिद्ध होगें।

एक सामान्य स्तर पर निम्नलिखित घटक जनपद के कृषि एवं ग्रामीण में छत्रसाल ग्रामीण बैंक

के योगदान का वर्तमान चित्र प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते है।

1. जनपद मे छत्रसाल ग्रामीण की शाखाओं का अव्यवस्थित विकास हुआ है। लगभग 500 से अधिक आबाद ग्रामों वाले महोबा जनपद में छत्रसाल ग्रामीण की मात्र 17 शाखाएं है। जिनमें से मात्र 5 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार एवं तुरन्त कृषि एवं अन्य ज़रुरतों के लिए वित्त प्राप्ति में ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता को होने वाली कसक या टीस को समझा जा सकता है।

2. प्राथमिक समंकों के संकलन के पश्चात् यह तथ्य भी प्रकाश में आया है। कि जनपद में अशिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से भी कम होने के कारण लोगों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से भी अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है तथा सम्पूर्ण योजनाओं का लाभ जनपद के कृषक प्राप्त नही कर पाते है।

3. जनपद के लोगो में शिक्षा के अभाव के कारण लघुउद्योग स्थापित कर जोखिम लेने का साहस नही है। इससे भी आय के स्त्रोत परम्परागत है। तथा जनपद में गरीबी का बोलबाला है, लघुउद्यमों का अभाव है। तथा श्रम हेतु लोग महानगरों हेतु प्रस्थान करने के लिए विवश होते है।

4. कृषि बीजों व उन्नत तकनीकी व खाद पानी हेतु किसान केडिट कार्ड के माध्यम से यद्यपि कृषि ऋण सुलभ है। परन्तु इसकी प्रकिया से अधिकांश ग्रामीणों को दलालों का शिकार हो कर अपनी एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। तथा समय अधिक लगने पर कभी कभी ग्रामीण महाजनों व साहूकारों की शरण में जाना पड़ जाता है। महोबा जनपद में महाजनों व साहूकारों से आज भी बड़ी तादात में लोग ऋण प्राप्त करते है। जिससे उनका आर्थिक शोषण होता है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक, तुलसी ग्रामीण बैंक, विंध्यवासिनी ग्रामीण बैक, तीनों ग्रामीण बैक जो इलाहाबाद बैक की प्रायोजित थी इन तीनों ग्रामीण बैंको को मिला कर एक त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम रखा गया है। जिसका प्रधान कार्यालय उरई है। तथा बैक का कार्य क्षेत्र जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट , मिर्जापुर, सोनभद्र, जिलों के अन्तर्गत है।

भारत सरकार द्वारा इसका विलयन करने का निर्णय इसलिए भी लिया गया जिससे

कि बैको की संख्या कम हो और कैपिटल पूँजी का विस्तार हो सके।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अध्यायवाद प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् है:-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में शोध समस्या के बारे मे उसका महत्व, उद्देश्य, अध्ययन विधि शोध समस्या का स्वरूप व वर्तमान प्रसांगिकता समस्या के स्त्रोत तथा इसकी परिकल्पना को दर्शाया गया है।

महोबा जनपद 11 फरवरी 1995 से जिले के रूप में स्थापित हुआ इससे पूर्व यह हमीरपुर जनपद का अंग था। यह 25^0 – 26^0 अक्षांश से और 79^0 से 80.5^0 पूर्वी अक्षांश पर स्थित है इसके उत्तर में हमीरपुर जनपद, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पूर्व में बांदा जनपद तथा पश्चिम में झांसी जनपद की सीमायें मिलती है। इस शोध प्रबन्ध में द्वितीयक समंकों का प्रयोग अधिक किया गया है।

द्वितीय अध्याय में महोबा जिले की अर्थव्यवस्था उसका जननांकीय विश्लेषण आर्थिक आधार पर वर्गीकरण और वहां के मानसून कृषि व रोजगार के स्वरूपों का वर्णन करने पर प्रायः ज्ञात होता है कि जनपद की अधिकांश जनसंख्या निर्धनता के कुचक्र में फंसी हुयी है इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भर रहना और रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता भी काफी सीमा तक है महोबा जनपद की प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से अन्य विकसित जनपदो से कम है इस क्षेत्र में अल्प आय और नगण्य बचत के कारण पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है।

जनपद का भोगोलिक क्षेत्रफल 3072 वर्ग कि0मी0 है। व कृषि योग्य बंजर भूमि 13.09 हे0 है। तथा कृषि अयोग्य भूमि 10.304 हे0 है। जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 299589 हे0 है। खरीफ में मात्र 59354 हे0 व रबी की 190215 हे0 में बुआई होती है कुल जनपद मे 180 हे0 क्षेत्र खेती के अन्तर्गत आता है। जनपद मे चार प्रकार की भूमि है जनपद मे सिंचाई के साधन सीमित है लगभग 91/100 हे0 कृषि योग्य क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत आता है जनपद की नहरों की लम्बाई 455 कि0मी0 है जो पूर्णतः वर्षा पर आधारित है।

जनपद महोबा की जनसंख्या 2001 मे 708831 थी जिसमे 1000 पुरूषों पर 866 स्त्रियां थी पुरूषों की साक्षरता दर 66.83 प्रतिशत व महिलाओं की 39.57 प्रतिशत है।

महोबा जनपद को चार ब्लाकों में बांटा गया है इसमे तीन तहसीले है 7 नदियॉ है फ्रॅच प्रकार की मिट्टियॉ पाई जाती है इसकी प्राकृतिक वनस्पति दो प्रकार की है महोबा मे एक झील, 9 तालाब, व 3 बांध है इसके अतिरिक्त यहां पांच प्रकार के खनिज उद्योग है।

वर्ष 2004–05 में महोबा जनपद में आयुर्वेद के 11 चिकित्सालय व 10 डाक्टर है यूनानी सेवा में 1 चिकित्सालय पर केवल एक डाक्टर है होम्योपैथिक सेवा के अन्तर्गत 7 चिकित्सालय में 4 डाक्टर है परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 4 व परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र 116 है।

जनपद में कुल 7 ऐलोपैथिक चिकित्सालय, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

प्रति लाख जनसंख्या पर ऐलोपैथिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या वर्ष 2003–04 मे विकास खण्डवार पनवाड़ी 4.2 जैतपुर 3.6 चरखारी 2.2 व कबरई की 3.4 केन्द्रो की संख्या है इसी क्रमानुसार उपलब्ध शय्याओं की संख्या क्रमशः 30.4, 10.8 13.5 व 13.8 है।

जनपद में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण संस्थाओं में कुल नगरीय व ग्रामीण मे छात्र संख्या 73643 व छात्रायें 51146 है 6 से 8 तक की कक्षाओं में 17184 व 9336 विद्यार्थी है 9 से 12 तक की कक्षा में 10630 व 6098 तथा स्नातक कक्षा में 1394 व 1090 विद्यार्थी है। स्नातकोत्तर में 173 व 113 है जिसमे प्राथमिक विद्यालय में 720, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 184, माध्यमिक विद्यालय में 37 हैं । दो महाविद्यालय व 1 स्नातकोत्तर महाविद्यालय है । प्राथमिक विद्यालय पर 1782 शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर 580 शिक्षक व माध्यमिक विद्यालय पर 387 शिक्षक, महाविद्यालय पर 24 शिक्षक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर कुल 14 शिक्षक उपलब्ध थे।

इसके तृतीय अध्याय के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के विकास को दृष्टिगत रखा गया है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करना था क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र पूंजी के अभाव से ग्रस्त है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी तीन प्रकार के प्रबन्ध स्तरों में बंटा हुआ है शीर्ष प्रबन्ध मध्य प्रबन्ध व निम्नस्तरीय प्रबन्ध क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंकों की 14508 शाखायें देश के 500 जिलों में कार्य कर रही हैं इन बैंको की 12003 शाखायें तथा, 83.07 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में थी वर्ष 1999 मे 14508 शाखाओ ने 93672. 1 मिलियन का उधार लिया जिसमें 23597.1 मिलियन के जमा हुए और इसका ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत रहा इस अध्याय मे इसमें मुख्य उद्देश्यों का वर्णन किया गया है इसके साथ साथ इसके महत्व, पूंजी संरचना, निदेशक मण्डलों का गठन, उसकी बैठकों, प्रबन्ध व्यवस्था व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अन्य वाणिज्यिक बैंको से भिन्नता का वर्णन किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 1990–91 में 125 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण तथा 210 करोड़ रूपये का मध्य व दीर्घकालीन ऋण दिया गया था जिसका योग 335 करोड़ रूपये था । यह ऋण अवधिनुसार बढ़ते गये और वर्ष 2003–04 मे 4680 करोड़ रूपये का अल्पकालीन व 1400 करोड़ रूपये का मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण दिये गये थे जिसका योग 6080 करोड़ रूपये है 1950 मे ग्राम भारत में महाजन का सबसे अधिक महत्व था और संस्थानात्मक स्त्रोतों द्वारा कृषि उधार की कुल आवश्यकताओं का 3 प्रतिशत से अधिक नही जुटाया जाता था चूंकि महाजन अभी भी महत्वपूर्ण है परन्तु उनका एकाधिकार बीते हुए युग की बात हो गयी है विभिन्न योजनाओं के अधीन कृषि उधार के अधिकाधिक संस्थनीकरण के कारण अल्पकालीन एवं मध्यकालीन उत्पादक उधार का 30 प्रतिशत अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य बैंको की भांति प्राथमिक एवं सहायक कार्य तथा सामान्य उपयोगिता सेवाओं को भी प्रदान करता है इसमे बैंक का लेखा व अंकेक्षण का भी वर्णन है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के गजटानुसार घोषित तिथि को या 31 दिसम्बर को यह अपनी पुस्तकें व चिट्ठे बन्द करते है और इसका अंकेक्षण चाटर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा होता है जिसका अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

शोध के चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक की संरचना प्रबन्ध व्यवस्था उनकी पूंजी उसके द्वारा प्रदान की गयी सेवायें व उनके मूल्यांकन पर प्रकाश डाला गया है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा द्वारा जिन शासकीय योजनाओं को चलाया जा रहा है उनमें 6 योजनाओं को चलाया गया है वर्ष 2005 में एस0एन0एस0वाई0 मे 39 खातों के लक्ष्य पर, 32 खाते खोले। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मे शून्य खातों पर 139 खातों की उपलब्धि हुयी जिससे

इनका प्रतिशत शून्य रहा । सघन मिनी डेरी पर 360 खातो के लक्ष्यों पर 44 खातों की उपलब्धि हुयी जो 12 प्रतिशत है, के0वी0आई0सी0 ब्याज उपादान पर 2 लक्ष्यों पर शून्य उपलब्धि व के0वी0आई0सी0 मार्जिन मनी पर शून्य के लक्ष्य पर कोई उपलब्धि नही है यह पिछले वर्षो में थी परन्तु अधिक न चल पाने के कारण इस वर्ष नही है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 4624 खातों के लक्ष्यों पर 3353 खाते खोले गये जो कि 85 प्रतिशत है।

महोबा जनपद के प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत सबसे पहले अंचल प्रबन्धक फिर वरिष्ठ प्रबन्धक आते है इसके बाद इसे तहसील स्तर पर ग्रामीण स्तर की शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है तहसील स्तर पर 7 शाखाये व ग्रामीण स्तर पर 10 शाखाये आती है। तहसील स्तर पर सबसे पहले प्रबन्धक फिर दो अधिकारी, दो लिपिक व एक सन्देशवाहक की व्यवस्था होती है। और ग्रामीण स्तर पर एक प्रबन्धक, एक लिपिक व एक संदेशवाहक प्रबन्ध व्यवस्था को चलाते हैं।

प्रस्तुत शोध मे जिन वार्षिक कार्ययोजनाओं के लक्ष्यों व उपलब्धियों को दर्शाया गया है उनमे अल्पावधि कृषि के अन्तर्गत फसली ऋण लघु सिंचाई आदि आते है जिसके कुल वर्ष 2001 से 2005 तक के लक्ष्यो पर 489432 हजार की उपलब्धि हुयी है जो कि 263 प्रतिशत है।

सावधि कृषि के अन्तर्गत कुऑ, पम्पसेट, बैलजोड़ी आदि के लिए ऋण दिया जाता है जिसमे कुल 60769 हजार के लक्ष्य पर 120986 हजार की उपलब्धि हुयी है जो कि इसका 199 प्रतिशत है।

सहायक कृषि के अन्तर्गत भैंस, बकरी, डेरी, मत्स्यपालन सुअर पालन आदि के लिए ऋण दिया जाता है जिसका अब तक का लक्ष्य 35568 हजार रूपये था जिसकी उपलब्धि 57550 हजार रूपये है जो कि 161 प्रतिशतहै।

उद्योगों के अन्तर्गत लघु उद्योग छोटी इकाइयां, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण दिया जाता है जिसका अब तक का लक्ष्य 14825 हजार रूपये था जिसकी उपलब्धि 15638 हजार रूपये है जो इसका 105 प्रतिशत है।

सेवा एवं व्यवसाय के अन्तर्गत सर्विस, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि के लिए ऋण दिया जाता है जिसका लक्ष्य 33575 हजार रूपये रखा गया जिसकी उपलब्धि 62859 रही जो 187

प्रतिशत है।

प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त कुल योग आता है व गैर-प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं की जमाओं के आधार पर ऋण मिलता है जिसमें कुल लक्ष्यो के सापेक्ष उपलब्धि अधिक रही है जिसका यह 159 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रत्येक योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि अधिक रही है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने सर्वप्रथम जनपद महोबा के जैतपुर ब्लाक के अजनर गांव में तथा पनवाड़ी ब्लाक के महोबकंठ गांव में दिनांक 10 दिसम्बर 1982 को दो शाखाओं की स्थापना की थी। जिसमें अजनर मे वर्ष 2003 मे 755 हजार के लाभ अर्जित किये वर्ष 2004 व 2005 में क्रमशः 431, 993 के लाभ अर्जित किये जिससे स्पष्ट होता है कि यह शाखा सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है।

1983 में चरखारी ब्लाक के बम्हौरी कला गांव 28 मार्च 1983 को और कबरई ब्लाक के फतेहपुर बजरिया एवं ननौरा गांव में तथा चरखारी ब्लाक के रिवई गांव मे दिनांक 20 जून 1983 को तथा पनवाडी ब्लाक के भरवारा गांव एवं बेंदो गांव में 24 जून को शाखायें स्थापित की गयीं इस तरह 1983 में 6 शाखायें और स्थापित की । इन 6 शाखाओं में बम्हौरी कला की शाखा वर्ष 2001 में 242 व 2002 में 94, 2003 में 234 हजार की हानि पर गयी इस तरह की हानि होने के कारण 2004 में यह शाखा बन्द कर दी गयी। फतेहपुर बजरिया के लाभ 2001 से 2005 तक क्रमशः 889, 584, 1112, 748, व 1321 के हजार लाभ पर रही रिवई शाखा की हानि 2001 में 128 हजार रुपये की हानि हुई वर्ष 2002 में इस शाखा ने लाभ अर्जित किये जो कि 137, 14, 358 हजार पर हुये यह शाखा शुरू की स्थिति में हानि पर होते हुये इसने अपनी स्थिति को सुधार लिया

ननौरा शाखा के लाभ कमशः 5.0, 95, 137, 108, 198, हजार रहे पनवाड़ी ब्लाक के बेंदो शाखा लाभ वर्ष 2001 से 2005 तक कमशः 32, 26, 366, 103, व 677, हजार रहे।

1984 में जैतपुर ब्लाक बछेछर लमौरा गाँव में तथा कबरई ब्लाक के गहरा गाँव तथा सिजहरी गाँव 28 मार्च 1984 को तीन शाखाएं स्थापित की जिसमें बछेछर लमौरा के लाभ वर्ष 2001 से 2005 तक कमशः 216, 240, 49, 454, हजार रहें। गहरा गाँव की शाखा की स्थिति

वर्ष 2001 में एवं वर्ष 2002 में क्रमशः 60 हजार, 82 हजार के नुकसान पर गयी तथा 2003 में पाँच हजार के लाभ में वर्ष 2003 में 384 हजार की हानि में एवं 2004 में 3 हजार के लाभ पर रही।

वर्ष 1985 में जैतपुर ब्लाक के कुलपहाड़ में एवं चरखारी में दिनाँक 27 मार्च 1985 को पनवाड़ी ब्लाक के पनवाड़ी में दिनाँक 28 मार्च 1985 को तथा कबरई ब्लाक महोबा क्षेत्र में दिनाँक 27 अगस्त 1985 को शाखाएं स्थापित की इस तरह 1985 में 4 शाखाएं स्थापित हुयी कुलपहाड़ के वर्ष 2001 से 2005 तक लाभ क्रमशः 621, 539, 590, 468, 616, हजार रुपये रहे।

पनवाड़ी के लाभ क्रमशः 1017, 766, 1056, 452, 647 हजार रूपये रहे ।

महोबा के लाभ क्रमशः 5821, 3599, 7202, 5290, 6643 हजार रुपये रहें।

चरखारी के लाभ क्रमशः 2048, 1698, 2859, 2005, 1688 हजार रूपये रहे।

इस प्रकार उपर्युक्त शाखायें भी सफलतापूर्वक चल रही है।

1988 एवं 1999 तक छत्रसाल ग्रामीण बैंक मे कोई शाखा नही खोली केवल दिनांक 29 अगस्त 2000 को कबरई ब्लाक मे केवल एक शाखा खोली गयी और इसके बाद आज तक छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा ने कोई भी नई शाखा नही खोली। इस तरह कुल मिलाकर वर्ष 1982 से वर्ष 2000 तक छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा ने 18 शाखायें खोली गयी और चरखारी ब्लाक के बम्हौरी कला गांव की शाखा के मिले आंकड़ो के अनुसार वर्ष 1998–1999मे 211 हजार के नुकसान पर गयी और 2000–2001 में 242 हजार के नुकसान में गयी 2001 2002 मे 94 के नुकसान मे 2002–2003 मे 234 हजार के नुकसान मे जाने की बाद बम्हौरी कला की शाखा बन्द हो गयी इस तरह वर्तमान में जनपद महोबा में 17 शाखायें कार्यरत है। कबरई शाखा के लाभ 2002 से 2005 तक क्रमशः 253, –166, 1206, 1346, 1423 हजार रूपये रहे है जिससे यह शाखा भी सफलतापूर्वक चल रही है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने जनपद महोबा की वित्तीय स्थिति के इस आंकलन से स्पष्ट होता है कि बैंक ने अपने स्थापना वर्ष से अब तक लगभग सभी दिशाओं में पर्याप्त प्रगति की है साथ ही महोबा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कर रहे किसानों निर्धन वर्ग के लोगों

को समय समय पर उत्पादक एवं उपभोग ऋण प्रदान करके जनपद के आर्थिक विकास में गॉवों की उन्नति में छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा की भूमिका प्रशंसनीय रही है इस प्रकार इस अध्ययन हेतु निर्धारित परिकल्पना जांच के उपरान्त सही सिद्ध होती है।

शोध प्रबन्ध के पंचम अध्याय मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया गया है वित्तीय विश्लेषण की निम्नलिखित विधियां है। अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह, विश्लेषण, नकद प्रवाह विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण कार्यशील पूंजी विश्लेषण, परन्तु उसमे अनुपात विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया गया है इसके अतिरिक्त इस अध्याय मे उपर्युक्त विश्लेषण पद्धतियों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

किसी भी बैंक का वित्तीय विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले सभी मदों के अलग अलग खाते बनाये जाते है फिर लाभ हानि खाता बनाया जाता है इसमें लेखांकन अवधि के आगमन व व्यय मदों का विवरण होता है जिससे शुद्ध आय व शुद्ध हानि का पता चलता है इसके प्रारूप को चार भागों में विभक्त किया जाता है उत्पादन खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता व लाभ हानि नियोजन खाता। इसके बाद आर्थिक चिटठा बनाया जाता है जो बैंक की स्थिति को बताता है।

स्थिति विवरण को दो भागों में विभक्त किया जाता है जिसमें एक पक्ष दायित्व पक्ष व दूसरा सम्पत्ति पक्ष कहलाता है दोनो पक्षो मे मुख्यतः 5–5 शीर्षक होते है।

वर्ष 2000–2001 मे 10,000 की अंशपूंजी से अपेक्षाकी गयी जिसकी उपलब्धियां भी 10,000 हुयी इन वर्षो में प्रारक्षितियां यानि रिजर्व नही थे और अंशपूंजी जमा 143962 लाख थी इस लक्ष्य में 139694 लाख रूपये की उपलब्धि हुयी जो कि लक्ष्यके अनुसार 1298 लाख थी यही स्थिति 2005 तक रही वर्ष 2003–2004 मे कुछ रिजर्व भी थे वर्ष 2004–05 मे 1094,52 लाख के रिजर्व का लक्ष्य रखा गया था जिसमे केवल 585.89 तक की उपलब्धियां हो पाई।

इसकी जमा स्थिति के अनुसार वर्ष 2000 से 2002 तक कोई भी माँग जमा लक्ष्यों के अनुसार पूर्ति नही कर पायी परन्तु 2002–03 मे 1350000 लाख रूपये के लक्ष्यों पर उससे अधिक रूपये 1368334 लाख रूपये की पूर्ति की गयी जो कि अच्छी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है परन्तु वर्ष 2003–04 व वर्ष 2004–05 मे भी कमी का स्थिति रही।

राष्ट्रीय बैंक से जो उधार इस बैंक को मिला है वह उसका लक्ष्य वर्ष 2004–05 में 4502.15 लाख रूपये का था जिसकी उपलब्धियां 1885–86 रही और प्रवर्तक बैकों से मिला उधार शून्य रहा।

वर्ष 1997–98 से वर्ष 2004–05 तक बैंक के कुल निवेश क्रमशः 748999, 916085, 979584, 1151584, 1102556, 1266443, 1373605, 1104349 हजार रूपये थे इस निवेश की अर्जन दर क्रमशः 12.64 प्रतिशत, 11.85 प्रतिशत, 11.41 प्रतिशत, 10.77 प्रतिशत, 10.56 प्रतिशत 9.68 प्रतिशत, 8.38 प्रतिशत तथा 7.43 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार वर्ष 1997–98 से वर्ष 2004–05 तक बैंक की अंश पूंजी जमाराशि क्रमशः 1.15 , 1.36, 1.40 1.40 1.40, 1.43, 1.43 लाख रूपये थी जिस पर अर्जन दर क्रमशः 11.80, 11.42, 10.38, 10.32, 8.94, 7.40, 6.06, 5.84 प्रतिशत थी।

बैंक के अनुमोदित प्रतिभूतियों पर निवेश वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक क्रमशः 2.00, 2.00, 2.62, 3.26, 3.66 3.00 3.40 2.33 लाख रूपये थे जिनकी अर्जन दर क्रमशः 14.29 15. 55 14.85, 13.41, 13.89 13.08 12.06, 11.88 प्रतिशत रही।

बैंक के आय के स्त्रोतों का योग वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक क्रमशः 118283, 135578, 155133, 169560, 205206, 228292, 243337, व 252007 हजार थे जिन पर होने वाले व्यय क्रमशः 106915, 123331, 137194, 143894, 177033, 182895, 210050, 227872, हजार हुए इनका अन्तर क्रमवार, 11368, 12247, 17939, 25666 28173 45397, 33287, व 24135 हजार रूपये रहा।

इसी प्रकार यदि हम छत्रसाल ग्रामीण बैंक की लाभ-हानि को प्रदर्शित करे तो प्रायः 1998–1999 से वर्ष 2005 तक की लाभ हानि क्रमशः –128254, –116007, –98068, –72402, –44229, 1167, +34221 व +3683 हजार रूपये रही है जो कि पहले हानि पर थी परन्तु बाद में इसने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का चालू अनुपात वर्ष 1998 से 2005 तक क्रमशः .87:1, 93:1, 94:1, .97:1, 101:1, 83:1, .80:1, .76:1 है। स्वामित्व अनुपात क्रमशः .09:1, .09:1, .084:1, .071:1, .66:1, .57:1, .51:1, .63:1 है नकद समता अनुपात वर्ष 1998 मे 9.8:1 तथा 2005 मे 14.76:1 रहा इसी कम मे पूंजी दर प्रत्यय अनुपात 1998 मे 9.05 प्रतिशत व 2005 मे 15.67 प्रतिशत

रहा स्थायी सम्पत्तियों का स्वामियों के कोषों से अनुपात वर्ष 1998 में 1.34:1 व 2005 में .054:1 व 2005 तक 8.2:1 रहा। और तरलता अनुपात वर्ष 1998 मे .87:1 तथा 2005 में .76 :1 रहा। वर्ष 2005 मे चालू सम्पत्तियों का योग 1720168 हजार तथा चालू दायित्वों का योग 2291834 हजार है।

चिट्ठे पर आधारित कुछ वित्तीय अनुपातों की स्थिति वर्ष 2004–05 में निम्नलिखित रही है लाभ / हानि प्रावधानों से पूर्व + 38843, प्रावधानों के पश्चात् 24135, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय 134007, निवेश पर आय 96845, कुल व्यय 227872, वेतन पर व्यय 65436, कुल व्यय के सापेक्ष वेतन पर व्यय प्रतिशत 33.10, कुल व्यय के सापेक्ष प्रबन्धन लागत का प्रतिशत 29.93, कुल व्यय के सापेक्ष प्रबन्धन लागत का प्रतिशत 40.52, औसत जमा लागत 4.30, व अन्तशाखायी लेन देन पर ब्याज दर 8.00, प्रतिशत रही।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कार्यशील पूंजी वित्तीय आय, वित्तीय व्यय वित्तीय मार्जिन कार्यशील मार्जिन विविध व्यय कर्यशील लाभ जोखिम लागत व शुद्ध मार्जिन क्रमशः वर्ष 1997–98 में 1043511, 10.68 5.89 4.97 3.79 0.43, 1.43, 0.43 + 1.00 थी जिसमे बीच के वर्षो मे कुछ कमी वृद्धि होती रही जो कि 2004–05 में उपर्युक्त स्थिति क्रमशः 2904484 8.01 4.16 +3.85, 3.18, .67, +1.34, 0.51 +.83 रही है।

इसके अतिरिक्त इस अध्याय में छत्रसाल गामीण बैंको की स्थितियों में ग्राफों के माध्यम से दर्शाया गया है।

षष्ठम अध्याय के अन्तर्गत छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा का जनपद की कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में दिये गये योगदानों का मूल्यांकन किया गया हैं इस अध्याय के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को बैंक द्वारा मिलने वाली सुविधाओं व उनकी शर्तो का मूल्यांकन किया गया है बैंक द्वारा जिन योजनाओ को चलाया जा रहा है उनसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे है और उनकी वसूली बैंक किस प्रकार कर रही है का वर्णन है इस अध्याय के निष्कर्षात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि छत्रसाल ग्रामीण बैंक का यदि हम अन्य बैंको से तुलनात्मक अध्ययन करे तो किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि 72.52, प्रतिशत रही है जबकि बैंक आफ बड़ौदा की 66.91, प्रतिशत, इलाहाबाद बैंक की 130.68, प्रतिशत, स्टेट बैंक आफ इण्डिया की 143.20, प्रतिशत

ओरिण्टल बैंक ऑफ कामर्स की 102.20 प्रतिशत जिला सहकारी बैंक की 101.87 प्रतिशत व ग्रामीण बैंको की शून्य रही है उपर्युक्त बैंको से तुलना करने पर छत्रसाल ग्रामीण बैंक की स्थिति सन्तोषजनक है इसी प्रकार छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कृषि उपलब्धि मार्च 2004 में 2 व मार्च 2005 में एक थी जिसका विचलन +3 रहा रोजगार के क्षेत्र की इसकी उपलब्धि वर्ष 2004 में 4 व मार्च 2005 में 42 रही जिसका विचलन +2 रहा। इसी प्रकार कुल उपलब्धियां मार्च 04 में 691 व 2005 में 1721 रही व विचलन +1030 रहा। यह उपलब्धि 1028.13 लाख रूपये के लक्ष्य पर थी जिसका प्रतिशत 42.00 रहा।

अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत इस बैंक में 360 खातों का लक्ष्य रखा गया जिसमें 300 लोगों ने आवेदन किया इसमें 75 स्वीकृत किये गये व 51 वितरित किये गये जिसमें 24 लम्बित रहे और 225 खातों को निरस्त कर दिया गया।

खादी ग्रामोद्योग ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत 2 का लक्ष्य रखा गया 2 के आवेदन आये परन्तु एक भी स्वीकृत नही किये गये अतः दोनो ही पेन्डिंग पड़े है।

खादी ग्रामोद्योग मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत बैंक में कोई लक्ष्य नही रखा गया परन्तु फिर 5 लोगों ने आवेदन किया।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा की विभिन्न वार्षिक कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत अल्पसिंचाई, कृषि मशीनरीकरण, पशुपालन / दुग्ध विकास, पशुपालन/मुर्गीपालन, पशुपालन/अन्य, मत्स्य पालन, अन्य कृषि ऋण, अकृषि क्षेत्र/लघु उद्योग, अकृषि क्षेत्र व फसली ऋण आदि के लिए वर्ष 2003 में क्रमशः खांते खोले गये। 1,584, 94, 653, 15, 658, 8, 257, 332, 717 व 2964 लाख खाते खोले गयें जिसकी खाता वसूली क्रमशः 931, 60, 276, 10, 308, 3, 130, 132, 321, 2324 खातों में हुयी इसमे बकाया खातो की वसूली का प्रतिशत क्रमशः 49.37, 53,55, 26.55, 66.07, 29.53, 36.96 37.17, 28.99 78.26 प्रतिशत रहा है वर्ष 2003 मे सबसे अच्छी वसूली फसली ऋणों की हुयी है यह योजना सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रही है।

इसी क्रम में वर्ष 2004 की कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत वसूली का प्रतिशत क्रमशः 59.35, 56.64, 30.76, 35.37, 30.82, 31.58 40.75 39.73 27.90 79.92 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2004 में सबसे अच्छी वसूली फसली ऋण की ही रही है। सबसे कम वसूली अकृषि क्षेत्र/अन्य

प्राथमिकता क्षेत्रों की रही है।

वर्ष 2005 में वसूली का प्रतिशत क्रमशः 65.21 71.15, 43.17, 56.00, 40.54, 76.32, 47.92, 53.37, 84.53 प्रतिशत व 81.49 प्रतिशत रहा। इस वर्ष सबसे अच्छी वसूली अकृषि क्षेत्र की रही है।

वर्ष 2003 मे शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत एसजीएसवाई, स्पेशल कम्पोनेन्ट एससी/एसटी, महिलायें, अल्पसंख्यक, अल्पसिंचाई, अकृषि / सीसी लिमिट, अन्य सामान्य कृषि ऋण अकृषि ऋण सामान्य ट्रेक्टर, सड़क परिवहन आती है जिनकी वसूली क्रमशः 36.60, 36.07, 35.50, 44.86, 29.76, 50.92, 82.05, 71.91, 2.39, 52.14, 15.82, प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक अकृषि/ सीसी लिमिट की है।

वर्ष 2004 मे सबसे अधिक वसूली अकृषि सीसी लिमिट की 86.46 प्रतिशत व सबसे कम वसूली स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान की रही है जो कि 32.37 प्रतिशत थी।

वर्ष 2005 में सबसे अधिक वसूली अकृषि ऋण सामान्य की 95.08 प्रतिशत थी सबसे कम वसूली सड़क परिवहन सामान्य की 2.10 प्रतिशत रही।

महोबा जनपद में 17 शाखायें पिछले अध्ययन के अनुसार शाखावार इसकी मांग एकत्रीकरण के आधार पर इनकी वसूली का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वर्ष 1998 में सबसे अच्छी वसूली करने वाली शाखा चरखारी है जिसका प्रतिशत 81.32 है और सबसे कम वसूली करने वाली शाखा ननौरा है।

वर्ष 1999 में सबसे अच्छी वसूली का प्रतिशत चरखारी का ही है जो कि 81.66 है और सबसे कम वसूली बैंदो की शाखा का 28.70 प्रतिशत है इससे निष्कर्ष निकलता है कि चरखारी में यह बैंक सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

वर्ष 2000, 2001 2002 व 2003 में सबसे अच्छी वसूली शाखावार क्रमशः भरवारा, सिजहरी, कबरई, की रही है उपर्युक्त शाखायें इस कार्य को सुचारू रूप से कर रही है जिसका प्रतिशत क्रमशः 70.17 70.19 98.14 व 90.49 प्रतिशत है। और जो शाखाये अपनी वसूली मांग व एकत्रीकरण के अनुपात में नही कर पा रही है उनकी वसूली वर्षानुसार शाखावार क्रमशः सौरा 30.13 प्रतिशत रिवई 22.72 प्रतिशत पनवाड़ी 53.27 प्रतिशत व बम्हौरी कला 33.83 प्रतिशत है

जो ठीक तरह से वसूली नहीं कर पा रही है।

जनपद जालौन, हमीरपुर से महोबा की तुलना करने पर हम पाते है कि वर्ष 1998 से 2003 तक सर्वाधिक वसूली क्रमशः महोबा की 51.80, 50.95, 49.8, 49.64, 71.75 व 67.86 प्रतिशत रही है। परन्तु वर्ष 2003 मे जालौन की वसूली इससे अधिक 70.99 प्रतिशत है पिछले वर्षो की दृष्टिगत रखा जाये तो महोबा जनपद की स्थिति हमीरपुर व जालौन से अच्छी है।

इसी क्रम में जब हम गैर–निष्पादक सम्पत्तियों को देखते है तो वर्ष 2004 में सबसे कम एनपीए खाता खरेला शाखा का है और सबसे अधिक बम्हौरी कला की है।

वर्ष 2005 में सबसे कम एनपीए खरेला शाखा की है। व सबसे अधिक एनपीए बम्हौरी कला की है।

समस्यायें –

किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैकिंग पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ऐसे आधुनिक समाज में कल्पना भी नही की जा सकती है जिसमें बैकिंग समस्यायें न हो यद्यपि छत्रसाल ग्रामीण बैंक ने बैकिंग व्यवसाय की दृष्टि से काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी और निर्धन किसानों और खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सुविधा प्रदान करके आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है तथापि बैकिंग व्यवसाय के क्षेत्र मे समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में यह पूर्ण रूप से सफल न हो सका है। इसलिए ग्रामीण निर्धन कृषक महाजन एवं साहूकारों के चंगुल से पूर्णतया मुक्त नही हुए है छत्रसाल ग्रामीण बैंक के मार्ग में समय-समय पर अनुभव की गयी समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है –

1. सरकारी योजनाओं मे समय की अवधि व लक्ष्य निर्धारित ऋण वितरण के संदर्भ मे दबाव –

चूंकि इन बैंको में सरकारी योजनाओं में समय की अवधि लक्ष्यों के अन्तर्गत निश्चित अवधि में ऋण वितरण लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव होता है जिसके कारण ऋण पाने वाले पात्र व्यक्तियों का चुनाव ठीक ढंग से नही हो पाता है और अपात्र लोगों को ऋण प्राप्त हो जाता है और पात्र लोग उस ऋण से वंचित हो जाते है जिससे बैंको की वसूली प्रभावित होती है ओर ग्रामीण बैंक का धन असुरक्षित हो रहा है।

2. लक्ष्योन्मुख एवं अनुदानित ऋण वितरण की खामियां –

भारत सरकार ने खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनदानित योजनाओं के लिए ऋण वितरण करने हेतु बाध्य किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनता से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को किसी प्रकार की प्रतिभूति के बिना ऋण वितरण किये गये परन्तु ऋणी द्वारा ऋण का समुचित उपयोग नही किया गया तथा आय एवं उत्पादन बढ़ाने की क्षमता में कोई वृद्धि नही हुयी है इसके फलस्वरूप एकओर बैंक का ऋण वसूल नही हो सका है और दूसरी ओर ऋणी की स्थिति सुधरने के स्थान पर और भी दयनीय हो गयी है। ऋण के साथ अनुदान के लालच में ऋणों का मूल चरित्र ही बदल गया है। इसलिए ऋणी केवल ऋण प्राप्त करने मे रूचि रखता है और लौटाने मे उसकी कोई रूचि नही होती है। बैकों के बकाया ऋणों का अधिकांश भाग अनुदानित ऋण योजनाओं का है जिसकी वसूली संदिग्ध स्थिति मे है।

3. ऋण वितरण से पूर्व सर्वेक्षण जांच एवं तदोपरान्त परावर्ती कार्यवाही का अभाव

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण योजना बनाने से पूर्व जनपद में ऋण वितरण हेतु सर्वेक्षण सही नही किया जाता है तथा ऋण आवेदन पत्रों के साथ आवेदक की अच्छी तरह से जांच नही की जाती है और ऋण वितरण के उपरांत कार्यवाही जैसे ऋण का उपयोग एवं परिसम्पत्ति का सत्यापन नही किया जाता है जिसके फलस्वरूप ऋणों के दुरूपयोग की सम्भावना रहती है एवं ऋणों की वसूली संदिग्ध हो जाती है।

4. ग्राहक सेवाओं की कमी –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक का कार्य जनपद क्षेत्र के निश्चित गाँवो तक सीमित है अन्य व्यवसायिक बैंको की भांति बैंको की ग्राहक सेवा जैसे बैंक ड्राफ्ट मेल ट्रान्सफारमर बिलों का भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता जनपद से अन्रूत्र ट्रान्सपफर करने की स्वतंत्रता नही है जिससे बैंको की कुल कारोबार एवं आय प्राप्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और बैंक प्रगति की ओर नही बढ़ रहा है।

5. व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति –

विगत वर्षो में बैंक के कार्य कलापो में वृद्धि के साथ बैंक के व्यय में भी वृद्धि हो रही है जिसके फलस्वरूप आय का मार्जिन घट रहा है बैंक की व्यय की प्रमुख मदें निक्षेपों पर ब्याज तथा प्रबन्धकीय व्यय है जब कि बैंक को ऋण व्यवसाय एवं निवेश से आय प्राप्त होती है। प्रशासनिक व्ययों में हाल के दशक मे तीव्र गति से वद्धि हो रही है परिणाम स्वरुप बैंक के लाभ में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है।

6. कर्मचारियों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण का अभाव –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बैकिंग कार्य एवं ग्रामीणों से सम्बंधित तथा कृषि से सम्बंधित कार्यो के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था नही की गयी जो ग्रामीणों से सम्बंधित कृषि कार्य तथा कृषि से सम्बंधित कार्यप्रणाली के अनुरूप थे।

7. आन्तरिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था का शिथिल होना –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता कार्य तथा दक्ष कार्यप्रणाली हेतु उसकी आन्तरिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था अत्यन्त प्रभावकारी और पारदर्शी होनी चाहिए किन्तु इसमें शिथिलता के कारण बैंको के बकाया ऋणों दुर्विनियोग के प्रकरणों के कारण बैंक की निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्धि हो रही है जो बैंक की वित्तीय सुदृढता के लिए स्वस्थ्य लक्षण नही है।

8. विभागीय नियंत्रण अत्यधिक –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नाबार्ड बैंक, प्रवर्तक बैंक प्रदेश सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के काम काज पर पूरा नियंत्रण होता है। कभी-कभी तो बैंक को इनके अनावश्यक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है।

9. नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का कार्य में प्रयोग –

आधुनिक वैज्ञानिक युग में बैकिंग व्यवसाय में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे है व्यापारिक बैंको द्वारा नवीनतम सूचना प्रणाली कम्प्यूटर फैक्स इन्टरनेट जैसी विधियों से सूचनाये एकत्र करने व्यवसाय बढ़ाने हेतु और प्रशासन में सुधार लाने हेतु प्रयोग हो हा है जिससे एक ओर उनके कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर लागत घट रही है परन्तु छत्रसाल ग्रामीण बैंक इन नवीनतम तकनीकों का व्यवसाय में प्रयोग करने की दृष्टि से वंचित है इसलिए बैंक की

स्पर्धात्मक शक्ति का विकास नही हो रहा है।

10. सुरक्षा व्यवस्था में कमी –

संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था नही है दूरस्थ ग्रामीण अंचलो में बैंक के कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा के बैंक चलाते है सुरक्षा न होने से वर्तमान मे लूटपाट की घटनाये अधिक सुनाई दे रही है।

11. जमा राशि संग्रहण में बाधायें –

चूंकि ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता के कमजोर वर्गो को ऋण उपलब्ध कराते है तथा बैंक असाधारण तथा गरीब क्षेत्रों में स्थापित किये गये है जहां न तो ऐसे लोग बसते है जिनके पास न तो फालतू पैसा है और न ही कोई लाभप्रद उ़द्योग है और सरकार की कुछ ऐसी योजनाये है जिसमें गरीब जनता आकर्षित हो जाती है इस कारण यह बैंक पर्याप्त जमा राशि जुटाने में असमर्थ रहती है।

12. लाभकारी ऋण व्यवसाय का न होना –

यह जनपद उद्योग शून्य है व्यवसायिक गतिविधियां भी अपेक्षित स्तर की नही है कृषि अर्थतंत्र भी अविकसित एवं अलाभकारी होने के कारण ऋण की कुल मांग सामान्य रूप से कम पाई जाती है विगत वर्षो में बैंक का ऋण व्यवसाय मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों तक सीमित रहा जिस पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है तथा बैंक के लिए लाभदायक नही होती है छत्रसाल ग्रामीण बैंक अपने ऋण योग्य कृषि का उपयोग करने की दृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र नही होते है जिन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया नाबार्ड बैंक प्रवर्तक बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही ऋण स्वीकृत करना होता है जिसकी ब्याज दर बहुत कम होती है।

अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए वे अपने कोषों का नये क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत अधिक ब्याज प्रदान कर सकते है लगाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते है।

13. राजनैतिक दबाव –

राजनैतिक दबाव के कारण भी ऋण वितरण प्रकिया में स्थापित मानकों की प्रायः अवहेलना की जाती है क्योंकि ग्रामीण बैंक का स्वामित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का होता है

इसलिए वित्तीय स्त्रोतों के लिए ग्रामीण बैंक की निर्भरता सरकार पर होती है। इसके लिए भारतीय बैकिंग उद्योग के साथ साथ सरकारी नीतियां भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं कृषि एवं लघु क्षेत्रों के ऋणों की वसूली दर बहुत कम है यहां राजनैतिक रूप से संवेदनशील होने के कारण बैंक सकियता से अपनी अहम् भूमिका नही निभा पाती ऋण वसूली प्रकिया मे सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता है तथा साथ ही ऋण काफी योजनाओं से बैंको की वसूली प्रक्रिया प्रभावी होती है।

14. बकाया ऋणों की मात्रा में निरन्तर वृद्धि–

छत्रसाल ग्रामीण बैंक के बकाया ऋण की वसूली का दायित्व राजस्व विभाग को सौंपा जाता है जब ऋणकर्ता अधिक धनराशि का बकाया हो जाता है जिससे उसको जमा करने में बहुत कठिनाइयां होती है। और ऋणी कर्ता वसूली प्रक्रिया में शिथिलता व समय बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा अवैधानिक रूप से राजस्व विभाग के वसूली अमीनों को दे देता है ताकि वसूली में सख्ती न करे और कुछ समय का आश्वासन देकर टाल देता है इस दौरान ऋणीकर्ता न्यायालय की शरण में जाकर चौथाई या कुछ भाग जमा कर बैंको की अनियमिततायें बताकर स्थगना आदेश ले आता है और वर्षो तक अवैधानिक रूप से मुकदमें चलते रहते है मुकदमों के दौरान बैंक को अनावश्यक रूप से खर्च करना पड़ता है तथा ऋणी कर्ता और अधिक ऋणी हो जाता है। और बैंको की वसूली भी बन्द हो जाती है इस तरह ऋणों के बकाये में निरन्तर वृद्धि होती रहती है बढ़ते बकाया ऋणों के कारण जहां एक ओर बैंक की निष्पादित सम्पत्तियों में वृद्धि होती है वही दूसरी ओर बैंक का वित्तीय आधार भी कमजोर होताहै।

15. अनुत्पादक ऋण का अभाव –

कुछ बैंको ने गरीब लोगों के लिए अनुत्पादक आवश्यक ऋण की पूर्ति की है और कुछ बैंको ने गैर–अनुत्पादक ऋण जैसे शादी ब्याह, चिकित्सा व्यय, जन्म मृत्यु व्यय शिक्षा व्यय आदि ये सब अनुत्पादक ऋण है। किसानों को सामाजिक रीतियों के अनुसार ये सब कार्य करने पड़ते है जिनके लिए बैंक से ऋण उपलब्ध नही होता है और किसान को इन सब कार्यो के लिए साहूकार एवं महाजनों से अधिक ब्याज पर ऋण लेने की मजबूरी होती है और किसान साहूकार एवं महाजन के चंगुल में फँस जाते है और फिर भी उनके कर्जे से मुक्ति नही मिलती । कृषि व्यवसाय से इतनी अधिक आय नही होती कि किसान इन सब कार्यो को अच्छी तरह से कर सके।

सुझाव –

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की उन्नति का आधार ऋणों की सामाजिक मागों के अनुरूप वसूली है क्योंकि ऋण वसूली पर ही ऋण वितरण उत्पादन और भण्डारण आदि निर्भर करते है । ऋणों को उसकी आवश्यकता तथा क्षमता के अनुरूप ऋण प्रदान करना तथा समय से ऋण की वसूली करना एक दूसरे के पूरक कार्य है ऋणों की अवधि पार हो जाने के बाद प्रभावी कार्यवाही हेतु ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौंप दी जाती है। और बैंको की ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौपने के बाद राजस्व विभाग ऋणीकर्ता ऋण एवं ऋण पर लगे ब्याज की टोटल धनराशि के साथ 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त वसूल करता है। न देने पर उसे हवालात में बन्द कर देता है उस के कारण ऋण दाता ऐसी परिस्थितियों में साहूकार या महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेता है और उसके न चुकाने पर साहूकार या महाजन उसकी सम्पत्ति पर कब्जा कर लेते है या अपने यहां बंधुवा मजदूर बना लेते है और फिर वह आगे अपने भविष्य मे अपना या अपने परिवार का आर्थिक विकास नही कर पाता है।

छत्रसाल ग्रामीण बैंक की सफलता वास्तव मे सरकार की उपलब्धि है अगर सही समर्थन मिले लोच सहित दृष्टिकोण अपनाया जाये तो सरकार की कोशिश सफल हो सकती है सरकार के पास सर्वाधिक संसाधन है और वह ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है। जरूरत है सिर्फ कुछ नीतियों में परिवर्तन करने की और उसकी के अनुरूप इच्छाक्ति तथा राजनैतिक नेतृत्व और सरकारी तंत्र हर स्तर पर कठिन परिश्रम करे। अगर सही माहौल समर्थन और मागर्दशन मिले तो कृषक और समाज विकास और परिवर्तन के पथ पर चलने के इच्छुक है। छत्रसाल ग्रामीण बैंक महोबा की उपरोक्त एवं अन्य समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. ऋण वसूली को कारगर बनाने के लिए समयबद्ध कार्य योजनानुसार कार्य करना होगा जैसे–

क. ऋणी वार क्षेत्रवार शाखावार बकाया मांग सूचियों का संकलन करना।

ख क्षेत्रवार तथा शाखावार ऋण वसूली के लक्ष्यों का निर्धारण करना।

ग जनपद क्षेत्र की वसूली टीम बनाना।

घ. लक्ष्य पूर्ति की त्रैमासिक समीक्षा तथा तदनुसार कार्यवाही करे कार्यवाही केवल पत्रों द्वारा करने तक सीमित न रहे बल्कि ऋणकर्ता के पास वसूली की टीम स्वयं मौके पर जाकर ऋणी कर्ता से मिले और ऋण की किश्त जमा करने के लिए प्रेरित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि ऋणकर्ता ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है उसी मे प्रयोग किया है अथवा नही और समस्त निरीक्षण की रिपोर्ट उस क्षेत्र के शाखा प्रबन्ध को लिखित रूप से तथा किश्ते न जमा करने का कारण भी दे।

यदि इसके बाद भी ऋण की किश्त जमा नही होती है तो बैंक को केवल उतनी ही किश्तो की धनराशि की वसूली राजस्व विभाग को सौंप देना चाहिए जब कम रूपयों की वसूली होगी तो आसानी से वसूल हो जायेगी। इसमे न ऋणी को साहूकार या महाजन से ऋण लेना पड़ेगा ओर न ही बैंको की वसूली रूकेगी ऋण वसूली में इसी प्रकार की नीति अपनायी जाना चाहिए जब तक ऋण की पूरी धनराशि जमा नही हो जाती है।

2. भारत सरकार ने खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से लाभान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदानित योजनाओं के लिए ऋण वितरण करने में लक्ष्य सीमा अवधि निश्चित की है तथा प्रतिभूति नही ली जाती है अनुदानित ऋणो के लाभार्थियो का सबसे ज्यादा ऋण बाकी है उनकी वसूली अनुपात भी सबसे कम है। इस प्रकार की ऋण वसूली को कारगर बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन करना होगा। जो निम्नवत् है।

क. ऋणों पर अनुदान की अपेक्षा ब्याज पर अनुदान दिया जाना चाहिए जिसके आकर्षण से ऋण वसूली पर प्रभाव पड़ेगा और अच्छे परिणाम सामने आयेगें तथा ऋण की अदायगी नियमित रूप से होगी।

ख ऋण के विरूद्ध प्रतिभूति अवश्य ली जावे ताकि ऋणी कर्ता को ऋण चुकाने की चिन्ता रहे।

ग ऋण देने से पूर्व ऋणों का निरीक्षण साक्षात्कार तथा ऋण वसूली का आंकलन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए।

घ ऋण वितरण के बाद मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए ऋण कर्ता ने जिस उद्देश्य के लिये ऋण लिया है वह कार्य कर रहा है अथवा नही यदि नही कार्य कर रहा तो तुरन्त

आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर शाखा प्रबन्धक को देना चाहिए ऋणीकर्ता की किश्ते यदि समय से नही आती है तो ऋण वसूली की टीम को मौके पर जाकर ऋणीकर्ता से संपर्क करे तथा ऋण की किश्त जमा करने के लिए प्रेरित करे और इसके बाद भी किश्तें नही आती तो बैंक उतनी ही किश्तो की वसूली राजस्व विभाग को सौंप देना चाहिए बैंक को इसी प्रकार की नीति अपनानी चाहिए जब तक ऋणी को पूरी धनराशि जमा नही हो जाती है।

3. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की ऋण योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षेत्र में कृषि एवं कृषि से सम्बंधित तथा अन्य योजनाओं द्वारा किस किस कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता है और किस क्षेत्र मे ऋण वितरण उपयोगी होगा पात्रों की गहन जांच एवं ऋण वसूली का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

4. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की आय मुख्य रूप से कृषि ऋण व्यवसाय से होती है बैंको द्वारा अधिकांश ऋण कृषि क्षेत्र को आवंटित है जिन पर ब्याज की दर सामान्य रूप से कम होती है अतः व्यय की अपेक्षा आय मे वृद्धि करने के लिए व्यवसायिक बैंको की भांति सभी प्रकार के व्यवसायिक बैकों को ऋण स्वीकृति करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे बैंक अपनी पूंजी को उच्च ब्याज वाले ऋणों में निवेश कर सकें तथा अपनी निधियों को अधिक लाभप्रद एवं सुरक्षित ऋण वितरण में प्रयोग कर सके इसके अतिरिक्त व्यय में कमी करने हेतु आवश्यक है कि बैंक प्रशासनिक व्यय मे कटौती करने हेतु ठोस उपाय अपनायें।

5. छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए किसानों के विभिन्न वर्गो के लिए ब्याज की अलग, अलग दरें होनी चाहिए छोटे व कमजोर किसानों को ऋण देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृषकों के ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है आंकलन करना चाहिए और उसी के अनुरूप ऋण की वापसी की समय सीमा किश्तें निर्धारित करना चाहिए।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बै।क की शाखाओं का विस्तार जो कुछ ही क्षेत्रों / प्रान्तों तक सीमित है बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए जनपद से बाहर ड्राफ्ट मेल ट्रान्सफर की सुविधा की जा सके बिलों के भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता ट्रान्सफर की सुविधा

प्रदान की जा सके बिलों के भुगतान क्रेडिट कार्ड खाता ट्रान्सफर आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु इसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत करना चाहिए इसके फलस्वरूप बैंक का व्यवसाय बढ़ने के साथ-साथ ग्राहकों को सुविधा मिलेगी।

7. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था सूचना प्रणाली तथा कार्यप्रणाली के आधुनिकी की आवश्यकता है बैंक के प्रधान कार्यालयों को बैंको की शाखाओं तथा ग्रामीण बैंको की शाखाओं से सूचनायें संकलित करने तथा उन्हे सूचनायें प्रेषित करने के लिए नवीनतम तकनीकी इन्टरनेट का प्रयोग करना चाहिए। कम्प्यूटर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरण है इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा क्षेत्र की समस्त ग्रामीण शाखाओं का कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए तथा सुव्यवस्थित ढंग से आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

8. छत्रसाल ग्रामीण बैंक को छोटे व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए अनुत्पादक ऋण भी उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि किसानों को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते है जो उन्हे ऋण लेने के लिए बाध्य करते है उदाहरणार्थ सामाजिक रीतियों के अनुसार शादी ब्याह, चिकित्सा व्यय, मृत्यु आदि व्यय के लिए खर्च करने पड़ते है। सामाजिक और धार्मिक उत्सव हमारे गांव के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है इन पर किया जाने वाला व्यय किसानों को परामर्श देने से आसानी से कम नही किया जा सकता वास्तव मे इसके लिए कुछ न कुछ संस्थात्मक वित्त प्रबन्ध करना चाहिए।

शादियों, मृत्यु, धार्मिक खर्चो चिकित्सा व्यय शिक्षा आदि के लिये ग्रामीण बैंको ऋण उपलब्ध करना चाहिए ताकि लोगों को बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।

9. बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाओं के कारण ऋण वापसी मे चूक होने पर फसलों हेतु दिये गये ऋणों को 3 से पांच वर्ष तक सावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सावधिक ऋण हो तो उसके चुकाने का समय बढ़ाना चाहिए अथवा उसे नये सिरे से चरणबद्ध किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार प्राकृतिक विपदाओं के सताये उधार कर्ताओं के मामले में प्रतिभूति की मूल्य से अधिक ऋण की रकम को ऐसे सावधिक ऋणों में परिवर्तन किया जाना चाहिए जो एक उचित अवधि में प्रति संदेह हो इसके अतिरिक्त कार्यवाहक पूंजी भी उपलब्ध करानी चाहिए और

सावधिक ऋणों के अन्तर्गत देय किश्तो का समय बढ़ाना चाहिए या उन्हे नये सिरे से चरण बद्ध किया जाना चाहिए।

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रवर्तक बैंक इलाहाबाद बैंक अपनी ग्रामीण शाखायें इन बैंको के क्षेत्रो में चला रहे है इस कारण कई प्रकार के नियंत्रण एवं प्रशासन पर होने वाले परिहार्य व्यय कम किये जा सकते है ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्य बैंको के कार्य को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सौंप देना चाहिए।

11. छत्रसाल ग्रामीण बैंक की संपूर्ण भर्ती प्रकिया को सरल और कारगर बनाया जाये स्थानीय लोगों की वरीयता दी जाये तथा स्टाफ को ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जो छत्रसाल ग्रामीण बैंक के लिए उपयुक्त तथा ग्रामीण विकास की आधारशिला होगी।

12. बैंक कर्मचारियों को लगन निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसंगतियो सुविधाओं एवं प्रोन्नति सम्बंधी समस्याओं का निदान करना चाहिए ताकि वे सही दिशा में कार्य करें एवं जनता में बैंक की साख बनाये रखे।

13. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सेमिनारो तथा ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमो तथा गरीबी उन्मूलन की अवधारणा के बारे में जानकारी दी जाये तथा इसकी आवश्यकता के बारे में उत्साह पेदा किया जाये तथा अपने कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक बचतों को अपनी ओर आकर्षित करें।

14. छत्रसाल ग्रामीण में स्टाफ की संख्या का निर्धारण उस शाखा के निक्षेपों ऋण व्यवसाय की मात्रा या सक्रिय खातों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए तथा समय समय पर उसकी पुनः समीक्षाकी जानी चाहिए।

15. छत्रसाल ग्रामीण बैंक को केवल संस्थागत स्रोतों से ही ऋण उपलब्ध होना चाहिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर ऋण सम्बंधी निर्भरता समाप्त होनी चाहिए संस्थागत ऋणों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि धनी एवं निर्धन दोनों प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके और इसके द्वारा कृषि की कुशलता व उत्पादक को बढ़ाना चाहिए।

उपरोक्त उपायों को कियान्वित करने हेतु बैंक को अपनी उपविधियों मे उचित परिवर्धन

करना होगा तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड बैंक एवं प्रवर्तक बैंक से अनुमोदन भी कराना होगा यदि इन उपायों पर सही ढंग से अमल किया जाये तो बैंक ऋण वितरण में तथा ऋण वसूली के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर सकेगा बैंक कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी तथा बैंक के कारोबार एवं लाभ में अपेक्षित वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक महोबा जनपद में छत्रसाल ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका नाम बदल कर त्रिवेणी ग्रामीण बैंक महोबा हो गया है। इस बैंक की कार्य प्रणाली के बारे में ग्रामीण जनता से एक सैम्पल सर्वेक्षण किया गया जिसमें जनपद के चारों ब्लाक से दस-दस ग्रामों का एक प्रतिचयन यादृच्छिक आधार पर लिया गया जिससे कई रोचक तथ्य बैंक की कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में प्राप्त हुये उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है:—

1. नमूने में चुने गयें लोगों में से 90 प्रतिशत का मानना था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और अन्य व्यवसायिक बैंकों में नाम के अलावा अन्य क्या अन्तर है? इन बैंकों को खोलने का क्या उद्देश्य है? इस सबकी जानकारी उन्हें नही है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ग्रामीण जनता को प्रचार प्रसार, कार्यप्रणाली इत्यादि से अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सफल हुये प्रतीत नही होते है।

2. नमूने/प्रतिदर्श में चुने हुये लोगों में से 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता का मानना था कि बैंको को ग्रामीण कृषकों को कृषि ऋण के साथ ही साथ कम ब्याज दर पर शादी व अन्य धार्मिक रीति रिवाजों को सम्पन्न करने हेतु ऋण देना चाहिए जिससे कि वे साहूकार व महाजनों के चगुल में न फसें इस हेतु वे प्रतिभूति के रूप में कृषि भूमि व अन्य अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति की बात भी करते है। मेरे स्वयं के विचार से भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जनता को यह लाभ दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण महाजनों के जाल में न फँस सकें व आर्थिक उत्पीड़न की पीड़ा से मुक्ति पा सके।

3. नमूने/प्रतिदर्श में चुने हुये लोगों में 60 प्रतिशत लोग समय पर अपना ऋण चुकाते पाये गये जबकि 40 प्रतिशत समय पर ऋण का भुगतान नही कर पाये जबकि उनका आर्थिक स्तर नियमित भुगतान करने वालों की तुलना में किसी भी दृष्टि से कमजोर नही था बल्कि इस 40 प्रतिशत में लगभग 30 प्रतिशत लोग राजनीतिक दृष्टि से किसी न किसी दल से सम्बन्धित

रहे है। व ग्रामीण पंचायतों में प्रतिनिधित्व भी करते है या किया है। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि राजनैतिक दृष्टि या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली लोग बैक ऋणों का नियमित भुगतान करने हेतु ज्यादा सचेष्ट नही होते शायद बैंक वसूली से सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी उन पर अपना दबाव बनाने में कामयाब नही हो पाती हैं।

4. प्रतिदर्श के लोगों में लगभग 90 प्रतिशत की राय में कृषि के विकास हेतु ''किसान केडिट कार्ड योजना '' को श्रेष्ठतम मानते है।

5. सर्वेक्षण के दौरान अधिकाश ग्रामीणेां ने स्वीकार किया है कि विभिन्न योजनाओं हेतु ऋण लेने के लिए बैंक द्वारा पूर्ण करायी जाने वाली कागजी प्रक्रिया अनपढ़ ग्रामीण कृषकों की समझ से बाहर है। साथ ही बैक स्टाफ कार्यवाही में अनावश्यक देरी करते है। यद्यपि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कई कई बैंक अधिकारी उन्हें अच्छी प्रकार से सलाह मशविरा देते है परन्तु कागजी कार्यवाही को प्रकिया का अंग बता कर आवश्यक मानते है।

6. प्रतिदर्श के लोगों में 70 प्रतिशत अपनी जरुरतों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों व अन्य बैकों के अतिरिक्त अपनी अन्य अनुत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साहूकार/महाजन अपने निकटतम आर्थिक रूप से सम्पन्न रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करते है।

7. प्रतिदर्श में 80 प्रतिशत लोगों का मानना था कि बैकों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी हटाने हेतु योजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण देना चाहिए तथा उनकी उचित मोनीटरिगं भी रखनी चाहिए।

8. समग्र दृष्टि कोण अधिकांश लोग छत्रसाल ग्रामीण की कार्यप्रणाली से संतुष्ट दिखे लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में, जिनका कि मैं इस अध्याय में उल्लेख कर चुकी हूँ, अपनी बेबाक राय से इस अध्याय को सार्थक रूप प्रदान करने में मेरी मदद की।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में महोबा में अधारभूत संरचना का विस्तृत विवेचन किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महोबा जनपद में आधारभूत संरचना तो है परन्तु उसकी प्रगति अत्यन्त धीमी हैं यही कारण है कि जनपद में आज भी अशिक्षा, गरीबी बेरोजगारी व आर्थिक असमानता, निम्न स्वास्थ्य दशायें व उद्यमिता का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हैं इस सम्बन्ध में जहाँ तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के योगदान का प्रश्न है। तो इस सम्बन्ध में समस्त सरकारी विभागों के दोष बैकिगं कार्यप्रणाली में भी आ गयें है। बैक अधिकारीयों/कर्मचारियों की दोषपूर्ण मनोवृत्ति के कारण बैकों में भी कठोर

नियम वाधिता, अदूरदर्शिता, भ्रष्टाचार, व पारदर्शिता का अभाव इत्यादि बुराईया जन्म ले चुकी है। देश के ग्रामीण व कृषि विकास का काया कल्प केवल तभी सम्भव है जबकि योग्य एवं कुशल नेतृत्व के अन्तर्गत दूरी पारदर्शिता से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं हेतु पक्ति के अन्तिम सदस्य तक ऋण योजनाओं का लाभ पहुँचे इस हेतु अकल्पित आचरण, ईमानदारी, सामाजिक सेवा भावना तथा व्यापारिक प्रबन्ध के ज्ञान की ठोस आवश्यकता है यदि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना के उद्धेश्यों व लक्ष्यों को सार्थक करना है तो केवल इनका नाम बदल देने से कुछ भी होने वाला नही है। जब तक कि इनमें पूर्ण निष्ठा समर्पण व उच्च चरित्र वाले योजनाकारों, प्रबन्धकों, कर्मचारियों व नागरिकों का सहयोग नही हो अतः इस दिशा में सरकार को व समाज के सदस्यों को ठोस शुरूआत करनी होगी व इन बैकों को क्षेत्रीय जनता की मॉग व आवश्यकता के अनुसार ऋण योजना बनाने व उसके अनुसार वित्त पोषण करने के मामले में पूर्ण स्वायत्ता दी जानी चाहिए तथा अन्य प्रकार की शक्तियों बाहरी व राजनीतिक, हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(प्रश्नावली)

(कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में छत्रसाल ग्रामीण बैंक के योगदान का मूल्यांकन)

नाम :–

स्थायी पता :–

व्यवसाय :–

1. क्या आप ग्रामीण किसान की श्रेणी में आते हैं ?

   हां ☐ या नहीं ☐

2. क्या किसान को अशिक्षित होने के कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

   हां ☐ या नहीं ☐

3. बैंक द्वारा कृषि कार्यो के लिए दिये जाने वाले ऋणों से आप लाभान्वित है अथवा नहीं ?

   हां ☐ या नहीं ☐

4. क्या लघु उद्योगों के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है ?

   हां ☐ या नहीं ☐

5. किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से आप लाभान्वित है अथवा नही ?

   हां ☐ या नहीं ☐

6. क्या छत्रसाल ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की सुविधाओं से आप सन्तुष्ट है ?

   हां ☐ या नहीं ☐

7. बैंक द्वारा चलायी जाने वाली योजनाये आपके लक्ष्योद्वश्यों की पूर्तिनुसार हैं अथवा नहीं ?

   हां ☐ या नही ☐

8. क्या आप बैंक की कथनी व करनी में अन्तर पाते हैं ?

   हां ☐ या नहीं ☐

9. क्या बैंक द्वारा अनुत्पादक कार्यो शादी, त्यौहार धार्मिक कार्यक्रमों के लिए ऋण दिया जाना चाहिए।

हां ☐ या नहीं ☐

10. बैंक जिन शर्तो के अनुसार ऋण प्रदान करते है वे कठोर है अथवा सामान्य।

हां ☐ या नहीं ☐

11. क्या आप समय पर ब्याज देते हैं ?

हां ☐ या नहीं ☐

12. बैंक द्वारा ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाना चाहिए अथवा नहीं।

हां ☐ या नहीं ☐

13. बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कठोर है या सामान्य।

हां ☐ या नहीं ☐

14. बैंक द्वारा ऋण लेने जमा करने या पैसा निकालने के सम्बंध में वहां के कर्मचारी जानकारी प्रदान करते है अथवा नहीं

हां ☐ या नहीं ☐

15. क्या ऋण प्राप्त करने मे अधिक समय लगता है।

हां ☐ या नहीं ☐

16 क्या बैंक की नीति पक्षपातपूर्ण है ?

हां ☐ या नहीं ☐

17. क्या आप ऋण का पैसा समय पर चुकाते है ?

हां ☐ या नहीं ☐

18. जिस कार्य के लिए आपने ऋण लिया है क्या उसका उपयोग उसी कार्य में करते हैं ?

हां ☐ या नहीं ☐

19. यदि नहीं तो क्या आप ऋण का पुर्नभुगतान सही समय पर देते रहते हैं।

हां ☐ या नहीं ☐

20. बैंक के ऋण देने की पद्धति दोषपूर्ण है अथवा नहीं ?

हां ☐ या नहीं ☐

21. क्या ऋण लेते समय अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है ?
हां ☐ या नहीं ☐
22. कृषि के विकास हेतु आपको कौनसी ऋण योजना श्रेष्ठतम लगती है
कृपया अपनी पसन्दगी का क्रम अंकित करें
हां ☐ या नहीं ☐
23. क्या आपके गांव में लगे बैंक के अतिरिकत अन्य किसी स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं ?
साहूकार से ☐ महाजन से ☐ रिश्तेदारो से ☐
24. ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि के विकास हेतु आपकी राय में छत्रसाल ग्रामीण बैंक के कौन सी योजना चलानी चाहिए।
25. ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु बैंक के किस प्रकार की ऋण योजना चलानी चाहिए।
26. क्या आप छत्रसाल ग्रामीण बैंक को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको से अलग करते है
हां ☐ या नहीं ☐
27. क्या आपकी राय मे छत्रसाल ग्रामीण बैंक को प्रर्वतक बैंक में मिलाना उचित होगा
हां ☐ या नहीं ☐
28. क्या आपके गांव में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की शाखा की आवश्यकता होती है?
हां ☐ या नहीं ☐
29. आपकी राय में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली में क्या-क्या दोष है ? प्रमुख पांच लिखो।
1. 2. 3. 4. 5.
30. आपकी राय में छत्रसाल ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव दीजिये।

सूचनादाता
हस्ताक्षर **Respondent**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.	अमर्त्य के. सेन,	पावर्टी इनइक्वैलिटी एण्ड अनइम्पलीमेंट इकॉनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, वाल्यूम – 8
2.	अहमद ए0 एण्ड सिद्दीकी, एम0एफ0 (1967)	''क्राप एसोसिएशन पैटर्न इन दि लूनीवेसिन दि ज्योग्राफर वाल्यूम 14
3	अली मोहम्मद (1977)	''फूड एण्ड न्यूट्रीशन इन इण्डिया के बी पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4.	अली मोहम्मद (1978)	''सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल फूड एण्ड न्यूट्रीशन इन रूरल इण्डिया डेवलपमेन्ट स्टडीज नं0 3
5.	अहलूवालिया एम एम (1978)	''रूरल पावर्टी एण्ड एग्रीकल्चरल परफारमेन्स इन इण्डिया दि जनरल आफ डेवलपमेन्ट स्टडीज नं0 3
6.	अली मोहम्मद (1978)	''रीजनल इन वलेन्सिस लेवेलस एण्ड ग्रोथ ऑ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टविटी'' ए केश स्टडी ऑफ बिहार कन्सेप्ट पब्लिकेशन कमपनी दिल्ली।
7.	आई सी सी ए आर	हैण्डबुक एग्रीकल्चर
8.	इनेदी (1967)	''दि चेन्जिंग फेस आफ एग्रीकल्चरल इन ईस्टर्न यूरोप'' ज्योग्राफिकल रिव्यू 57 प्र0पी पी 358–72
9	ओल्डहम आर.डी.	''दि डीप बोरिंग एट लखनऊ रिकार्ड आफ दि जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया वाल्यूम 23 पी0 – 268

10.	ओल्डहम आर0 डी0 (1917)	"दि स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय एण्ड गेंगेटिक प्लेन" मैमोर्स आफ जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया वाल्यूम
11.	केन्डाल एम0जी0 (1939)	"ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आफ क्राप प्रोडक्टिविटी इन इंग्लैण्ड, जनरल काफ रायल स्टेटिक्स सोसायटी 102
12.	गांगुली बी0एन0 (1938)	ट्रेन्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड पापुलेशन इन दि गेंगेज वैलीलन्दन पी पी 39–94
13	जैदी सैयद साजिद हुसैन (1982)	"रूरल इण्डिया एण्ड माल न्यूट्रीशन कन्सेप्ट पब्लिकेशन कम्पनी, दिल्ली
14	तिवारी पी0 डी0 (1965)	"फूड इन्टेक सिस्टम एण्ड डिफीसियेन्सीज इन रूरल इण्डिया आफ म0प्र0 रूरल सिस्टम वाल्यूम 3 नवम्बर
15	दत्त एवं सुन्दरम (1992)	"भारतीय अर्थव्यवस्था" एस चांद एण्ड कम्पनी दिल्ली।
16	धींगरा ईश्वर (1991)	"ग्रामीण अर्थव्यवस्था" सुल्तानचन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
17	धींगरा ईश्वर (1991)	"ग्रामीण अर्थव्यवस्था" सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स नई दिल्ली, पी पी 159
18	धींगरा ईश्वर	"ग्रामीण अर्थव्यवस्था" सुल्तानचन्द्र एण्ड सन्स नई दिल्ली पी पी 85
19	धींगरा ईश्वर	"ग्रामीण अर्थव्यवस्था" सुल्तानचन्द्र सन्स नई दिल्ली, पी पी 86
20.	एन0 सी0 ए0 आई0 आर0	चेन्जिंग इन रूरल इन्कम इन इण्डिया।

21.	वी0एस0मिन्हाल	"रूरल पावर्टी लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड डेवलपमेन्ट इण्डियन इकोनोमिक रिव्यू, अप्रैल 1970
22	भाटिया एस0एस0 (1967)	"ए न्यू मीजर्स आफ एग्रीकल्चरल इफीसियेन्सी इन यू पी इन इण्डिया इकोनोमिक ज्योग्राफी
23	सिन्हा, बी0 एन0	"एग्रीकल्चरल इफीसियेन्सी इन इण्डिया" इन ज्योग्राफर वाल्यूम 15 स्पेशन आई जी यू वाल्यूम
24	सिंह सुदामा (1994)	"भारतीय अर्थव्यवस्था समस्यायें एवं नीतियां नील कमल प्रकाशन, गोरखपुर पी पी 269–70
25	सेन्सर डायरी (1985)	"स्टेटिकल डायरी" यू0 पी0 पीपी 116
26	विकास को समर्पित मासिक योजना	दिसम्बर 2005
	सामाजिक आर्थिक परिचय	डी0एन0 सहाय
	विकास के प्रतिमान	माणिक सरकार
27	शासन प्रशासन चले यथार्थ की ओर	कालिका प्रसाद
28	बर्नस्टेन,	लियोपोल्ड ए फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस, थ्योरी एप्लीकेशन एण्ड इण्टरप्रिटेशन रिचर्ड डी इरविन, इन्स होमवुड इलीनोइस 1978
29	ब्लेक, सी0	फाइनेन्शियल एनालिसेस फॉर डिसीजन मेकिंग पारकर पब्लिशिंग इन्स0 पी एच आई, 1981
30.	ब्रिलेड आर0 जी 0	और मैकफ, ए जी फाइनेन्शियल रेशन एन इम्पिरीकल स्टडी जनरल आफ बिजनेस

फाइनेन्स एण्ड एकाउंटिंग स्प्रिंग
1977

31 ब्रीब आर0 प्रोडक्टिवटी एण्ड मेजरमेन्ट ए मीन्स फार गोगिंग द स्फीसियेन्सी आफ लार्ज मल्सीयूनिट आर्गनाइजेशन, इण्टर फर्म कम्पेरिजन एन इन्सेन्टिव टू प्रोडक्टिविटी ओइ0वी0सी0 1957

32 ब्रोच, लीव, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसेस, ए फ्यू एप्रोच प्रिक्टिस हॉल, इन्स0 न्यू जरसे 1974

33 बेनिशहेरी हारकब्ल इकोनामिक इनफारमेशन ऑन फाइनेन्शियल रेशियो एनालिसेस 1971
एकाउंटिंग एण्ड बिजनेस रिसर्च

34 देव, आर0 एम0 साउण्ड मेजहर ऑफ प्रोफेटिविलिटी एजु रिवेल्डि वाइ क्लोस स्कूटिनी आफफ लिक्योडिटी रेशियो, कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स अप्रैल 1971

35 डोनेल्ड, ई0 मिलर, दा मीनिंगफुल इण्टरप्रिटेशन आफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स एप्लीकेशन मैनेजमेन्ट एसोसिएशन

Rao, V.C and Paranji Malya, Agriculture finances by commercial Banks Ashish Publishing House New Delhi. 1980

Rao, B.R Current Trends in Indian Banking Deep & Deep Publications New Delhi 1982

Sharma B.P the role of commercial Banks in India's Deveoping Economy s.chand & Co Pvt.Ltd. new Delhi.1974

Sharma D.P and Desal V. rural Economy of India Vikas Publishing House Pvt.Ltd. new Delhi 1980

Sharma M.D and Chosal s.N Economic Growth and Commercial Banking in a Developing Economy Scientific Book Agency culcutta 1965

Sharma O.P Rural Reconstruction in India, Anmol Publications Delhi 1987

Subrahamanya K.N. Modern Banking in India Deep & Deep Publication new Delhi 1985

Sharma H.C Growth of Banking in a Developing Economy Sahitya Bhawan Agra 1969

Subrahamanya s. Banking in India Deep & Deep Publication new Delhi 1986

Subrahamanya s. and Sundaram I.S Growth of Agriculture and Rural Development in India Deep & Deep Publications New Delhi 1987

Timberg Thomas A The Marwaris Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi 1978

Tokhi M.R and Sharma D.P Rural Banking in India Oxfore and IBH Publishing co. new Delhi 1975

Verma. M.L rural Banking in India Rawat Publication jaipur 1988

Wadhva Charan D rral Banking and rural Development Macmillan company of India Ltd.new Delhi 1980

journals magzines reports dailies etc.

Banker Rao B Ramachandra rural Banking for rural Development Vol.xxxi No. 6 August 1984

Bank of Baroda, Weekly Review Issue before RRBs August 1977 PP.1-2

Commerce Hrushikesava Rao P Regional rural Banks. Problems and perspecties 33(3) Sept.1980

Thinglaya N.K The Regional Rural Banks and Agriculture 139(377) Annual Number 1979 pp. 115-119

Regional rural Banks Vol 139 No. 3577 Annual Number

Viability of Regional rural Banks 143(3659) August 1, 1988 P. 232

Economic times Raj Panandikar V.A Regional Rural Banks June 26, 1982 II. pp 6-8

Rao Venkata B. Nabard and RRBs November 5, 1982 P. 7

Prabhu a.N RRBs in Red October 15 1984 P.4

Agrawal K.P Regional rural Banks Challenges Ahead December 19, 1985 P.1

Stengthen RBs April 18, 1990, Editorial

RRBs not to be merged with sponsor banks April 7, 1990 P. 1

Overmanning in RRBs April 19, 1989 Editorial

RRBs may be Merged with Sponsor Banks August 21, 1989

Dantwala M.L Rural Credit march, 31 , 1990 P. 9

Eastern Economist Vora, B.K Innovation in rural financing Vol. 71 No.11 September 15, 1978 pp. 534- 535

Daudamini Nagar, Regional Rural Banks Rajasthan Experience Vol. 72 No. 24, June 15, 1979 pp. 1281-82

Financial Express Regarajan V rural Vanking problems and perspectives July 2, 1985 p. 5

Prabhakar M.R Viability of RRBs april 24 , 1986 P. 5

Government of India Report of the Banking comision new Delhi 1972

Report of the working Group on Rural Banks (Narashimham commitee) 1975

Census of India and Raja than 1971, 1981

Report of the working Group of Regional Rural Banks (Kelkar committee), 1986

Government of Rajasthan Basic Statistics of Rajasthan 1981-83 India 1989

Journal of India Institute of Bankers Joshi P.N RRBBs Vol 47(2) April June 1976 pp 72-76

Joshi , Navin chandra Regional rural Banks Vol 53(2) April June 1982 pp. 67-71

Planning commission Five year Plans.

Prajnan- Patel k.V and Shete N.B Regional Rural Banks. performance and prospects Vol 9(1) January March 1980 pp. 1-40

RBI Annual Report 1981-82 Supplement to RBI Bulletin June 1982 p. 37

Monthly Bulletins

Regional Rural Banks Report of the Review Committee (Dantwala Committee) 1977

Agawal, A.N Indian Economy Vikas Publishing House New Delhi 1985

Agrawal H.N A Portrait of nationalished Banks. Iner India Publicatons new Delhi 1985

Ajit singh Rural Development and Banking in India Deep & Deep Publications New Deli 1985

Bhattacharya B.N Indian rural Economics Metropolitan Book co New Delhi 1983

Bilgrami S.A.R Growth of Public Sector Banks Deep & Deep Publictions

new Delhi 1982

Bapna M.S Regional rural Banks in Rajasthan Himalaya Publishing House Bombey 1989

Brahmananda P.R Dimensions of rural Development of India Narayan B.K & Himalaya Publishing House New Delhi 1987

Choubey, B.N Agriculture Banking in India National Publishing House New Delhi 1983

Dang A.K Bank Credit in India Classic Publishing co. new Delhi 1986

Dasai s.S.M Rural Banking in India Himalaya Publishing House new Delhi 1986

Dasai Vasant Indian Banking Himalaya Publishing House new Delhi 1988

Dasai Vasant A Study of Rural Economics Himalaya Publishing House new Delhi 1983

Dhingra I.C Rural Banking in India Sultan chan & co new Delhi 1987

Elic A.N Operational Problems of rural Banking Vora & co. Bombey 1987

Eric L. Kohler A dictonary for Accountants prentice hall of India Private Ltd. New Delhi 1972

Ghatak Subrata Rural Money Markets in India Masmillan co. India New Delhi 1976

Goyal, K.G Rural Development and Banks. Prateeksha Publisations Jaipur 1987

Gupta shiv lal Money lendingsin Rajasthan Bafna Book Depot jaipur 1977

Ghosal, S.N Agricultural Financing in India, Asia Publishing House

Bombey 1966

Hoshiar Singh, Rural Development in India, Printwell Publishers Jaipur 1985

Hussain Farhat, Public Sector Commercial Banking in India Deep & Deep Publications New Delhi 1986

Joshi Naveen chandra Indian Banking Ashis Publishing House new Delhi 1978

Joshi Naveen chandra Indian rural Economy Young Asia Publications new Delhi 1980

Karkar, Gopal, Perspective in Indian Banking Popular Prakashan Bombey 1977

Kurulkar, R.P Agriculturalfinance in a backward Region Himalaya Publising House Bombey 1983

Lewis Arthur, W. Develoment Planning George Ajjen & Unwin Ltd. London 1970

Mathur O.P Public Sector Banks in India's Economy Sterling Publishers Pvt. Ltd. new Delhi 1978

Mehta, N.C and Panadikar V.A PaiRural Banking national Institure of Bank management Pune 1974

Nigam B.M.L Banking and Economic Growth Vora & co. Bombey 1967

Padhy Kishore C. commercial Banks and rural Development Asia Publication Services New Delhi 1980

Panandikar, s.G and Mithani D.M Banking in India Orient Longmans Ltd. Bombey 1974

Prasad, M.and Gangreja H.D rural Ecomonics B.R PublishingCorportion new Delhi 1984

रिपोर्ट एण्ड जर्नल्स

1. एनुवल सर्वे आफ इन्डस्ट्री – सेन्ट्रल स्टैटिकल आरगनाइजेशन डिपार्टमेन्ट आल स्टैटिक्स मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग, गवरमेन्ट आफ इण्डिया नयू देहली।
2. कामर्स एण्ड एनुवल नम्बर बाम्बे।
3. कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स जनरल आफ द डिपार्टमेन्ट आफ कम्पनी अफेयर, गवर्नमेन्ट इण्डिया न्यू देहली।
4. इकानॉमिक एण्ड साइन्टिफिक रिसर्च फाउण्डेशन रिसर्च टैक्नालॉजी एण्ड इन्स्ट्री न्यू देहली।
5. इकॉनोमिक टाइम, बाम्बे एण्ड न्यू देहली।
6. फाइनेन्शियल एक्सप्रेस रिसर्च ब्यूरन सीमेन्ट यूनिट प्रोफिट अप जनवरी 29–1978
7. फ़ाइनेन्शियल एक्सप्रेस न्यू देहली।
8. इण्डिया काउन्सिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च ए सर्वे आफ रिसर्च आफ इन इकानोमिक्स इन्डस्ट्री वाल्यूम 5 एलीड पब्लिशर्स
9. इण्डस्ट्रियल टाइम्स बाम्बे।
10. कोथाराइस इकनोमिक एण्ड इन्डसट्रियल गाइड आफ इण्डिया वाल्यूम 31 एण्ड वाल्यूम 32 कोथियर सन्स मद्रास।
11. रिजर्व बैंक आफ इडिया बुलेटिन, बाम्बे।
12. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स वाल्यूम 1 वाल्यूम 2
13. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सिलेक्टिड एण्ड अदर रिलेशन आफ प्राइवेट कारपोरेशन सेक्टर 1970–71 एण्ड 1975–1976 बाम्बे अक्टूबर 1978
14. नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च।
15. योजना मार्च 1996, अक्टूबर वर्ष 1999
16. साहित्य भवन प्रतियोगिता पत्रिका – मासिक जनवरी 2006
17. प्रतियोगिता दर्पण
18. द टाइम्स आफ इण्ड़िया
19. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बुलेटिन (मासिक)